20.09.2020

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2020/1942 (Saka) No. 07, Sunday, September 20, 2020/Bhadrapada 29, 1942 (Saka)

SUBJECT	<u>PAGES</u>
SUBMISSION BY MEMBER Re: Non-vacation of Rajya Sabha Chamber by Members of Rajya Sabha	12-18
PAPERS LAID ON THE TABLE	19-33
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	34-673
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
3 rd to 9 th Reports	674
STATEMENTS BY MINISTERS	675-677
(i) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 1 st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	
Shri Danve Raosaheb Dadarao	675

(ii)	Status of implementation of the recommendations
	contained in the 4th Report of the Standing
	Committee on Agriculture on Demands for Grants
	(2019-20) pertaining to the Department of Animal
	Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries,
	Animal Husbandry and Dairying

Shri Sanjeev Kumar Balyan

676

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Shri Arjun Ram Meghwal

677

ELECTION TO COMMITTEE

General Council of Rehabilitation Council of India

678

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2020- Introduced

679-688

MOTION RE:17TH REPORT OF THE BUSINESS

ADVISORY COMMITTEE

688

MAT	TERS UNDER RULE 377	689-693
(i)	Need for additional JEE, NEET entrance centres in Odisha	
	Shri Saptagiri Sankar Ulaka	689-690
(ii)	Regarding Minimum Support Price (MSP) for Cocoon	
	Shri D.K. Suresh	691
(iii)	Regarding construction of subway from Kongalamman temple to RTO road in Vellore Parliamentary Constituency	
	Shri D.M. Kathir Anand	691
(iv)	Regarding sanction of funds to develop a Tourism Circuit Hub in Kurnool	
	Shri Pocha Brahmananda Reddy	692
(v)	Regarding revision of Crop Insurance Premium	
	Shri Raghu Rama Krishna Raju	693
(vi)	Need to grant Central Assistance to complete Krishna-Marathwada Irrigation Project 2004	
	Shri Om Pavan Rajenimbalkar	694

DISCUSSION UNDER RULE 193

C	ovid-19 Pandemic in the Country	695-1004
	Dr. Shashi Tharoor	696-709
	Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	710-719
	Shri Dayanidhi Maran	720-727
	Shri Kalyan Banerjee	727-735
	Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	736-738
	Shri Shrirang Appa Barne	739-741
	Shri Rahul Ramesh Shewale	742-747
	Dr. Umesh G. Jadhav	748-751
	Shri Arvind Sawant	751-757
	Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	758-761
	Shrimati Raksha Nikhil Khadse	762-764
	Shrimati Riti Pathak	765
	Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'	766-771
	Shri Bhartruhari Mahtab	772-776
	Shri Devaji Patel	777-781
	Shri Shriniwas Dadasaheb Patil	782
	Shri Dushyant Singh	783-785
	Shri Girish Chandra	786-787
	Shri Nama Nageswara Rao	788-791
	Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	792-804

Dr. S.T. Hasan	805-806
Shri B.B. Patil	807-814
Dr. Amol Ramsing Kolhe	815-818
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	819-821
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	822-824
Shri Ramesh Bidhuri	824-832
Shrimati Supriya Sadanand Sule	833-839
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	840-843
Shri Karti P. Chidambaram	844-848
Adv. Ajay Bhatt	849-852
Adv. A.M. Ariff	853-857
Shrimati Aparupa Poddar	858-859
Shri Anna Saheb Shankar Jolle	860-863
Dr. Rajdeep Roy	864-877
Shri Hasnain Masoodi	878-881
Shri Unmesh Bhayyasaheb Patil	882-884
Shri Naba Kumar Sarania	885-886
Shri Jayadev Galla	887-890
Shri Jagdambika Pal	891-893
Shri P.P. Chaudhary	894-898
Shri Ritesh Pandey	899-901

Shri E.T. Mohammed Basheer	902-904
Shrimati Anupriya Patel	905-907
Shri Syed Imtiaz Jaleel	908-909
Shri Tejasvi Surya	910-913
Shri P.C. Mohan	914-917
Shrimati Locket Chatterjee	918-922
Shri Pradyut Bordoloi	923-924
Shri Hanuman Beniwal	925-927
Shrimati Navneet Ravi Rana	928-930
Shri Tirath Singh Rawat	931-932
Shri Malook Nagar	933-934
Shri Mohan S. Delkar	935-936
Shri P. Raveendranath Kumar	936-938
Shri M. Badruddin Ajmal	939-940
Shrimati Rama Devi	941-942
Shri Thomas Chazhikadan	943-945
Shri Suresh Pujari	945-947
Shri Deepak Baij	947
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	948-949
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	950-952
Dr. G. Ranjith Reddy	953-954

955-956
956-957
958-959
960-962
963-966
967-970
971-978
979-981
982-983
983-988
990
991-995
996-1004
1005-1014
1005-1009
1005
1006-1009
1010-1014
1014

RASHTRIYA RAKSHA UNIVERSITY BILL, 2020	1015-1023
Motion to Consider	1015-1019
Shri G. Kishan Reddy	1015
Shri Sunil Dattatray Tatkare	1016
Shri Abdul Khaleque	1016-1017
Shri Pocha Brahmananda Reddy	1017-1018
Col. (Retd.) Rajyavardhan Rathore	1018-1019
Clauses 2 to 53 and 1	1019-1022
Motion to Pass	1023
SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020- Negatived AND SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS	
(AMENDMENT) BILL, 2020 As Passed by Rajya Sabha	1024-1028
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1024-1027
Shri Nityanand Rai	1024-1029
Motion to consider	1027
Statutory Resolution – Negatived	1027
Clauses 2 and 3, 1	1028
Motion to pass	1028

BILATERAL NETTING OF QUALIFIED FINANCIAL CONTRACTS BILL, 2020

1029-1036

Motion to Consider 1029, 1035

Shri Anurag Singh Thakur 1029, 1033-1034

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 1030-1031

Shri Chandeshwar Prasad 1031

Shri Ritesh Pandey 1032

Shri Arvind Sawant 1032

Shri Anubhav Mohanty 1032

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 1033

Shri Prasun Banerjee 1033

Shri Pocha Brahmananda Reddy 1033

Shri Jasbir Singh Gill 1033

Clauses 2 to 11 and 1 1035

Motion to Pass 1036

*ANNEXURE - I

Member-wise Index to Unstarred Questions

*ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

^{*}Available in Master Copy placed in Library

20.09.2020

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

20.09.2020

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Sunday, September 20, 2020/Bhadrapada 29, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Fifteen of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नया मास्क लगाकर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

15.01 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Non-vacation of Rajya Sabha Chamber by Members of Rajya Sabha

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बात यह है कि आपके ही कहने पर हम सब सोशल डिस्टैंसिंग मेनटेन कर रहे हैं । अभी-अभी आपने कहा कि अपने मास्क ठीक से लगाकर बैठिए । हम सब आपकी बात मान कर चलते हैं ।

सर, इस समय कोरोना के संक्रमण के चलते लोक सभा और राज्य सभा एक साथ नहीं होती है । राज्य सभा सुबह में शुरू होती है और लोक सभा का काम दोपहर के बाद तीन बजे से शुरू होता है । लेकिन, अभी राज्य सभा में एक विधेयक को लेकर जिस तरीके से वहां एक स्टेलमेट पैदा हुआ है, जिसके कारण राज्य सभा अभी चल नहीं सकती । हमारे लोक सभा के मेम्बर्स राज्य सभा चैम्बर में कैसे जाएंगे क्योंकि इसमें सोशल डिस्टैंसिंग नहीं रहेगी । इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि राज्य सभा में जो स्टेलमेट चल रही है, उसे जरा खत्म होने दीजिए, तब तक यह सदन बंद रहना चाहिए, नहीं तो सोशल डिस्टैंसिंग का रखरखाव हम नहीं कर पाएंगे ।...(व्यवधान)

सर, हम आपसे यह विनती कर रहे हैं । राज्य सभा को रिस्टोर होने दीजिए, वहां नॉर्मेल्सी होने दीजिए । राज्य सभा के सामान्य होने तक, दयापूर्वक यह सदन बंद रखिए ।

माननीय अध्यक्ष: मैंने अधीर रंजन जी की बात सुनी है । मैंने सभी सदस्यों का मत भी जाना है । हम सब के लिए यह बात चिंता का विषय भी है और इस विषय पर आज हम लोग सकारात्मक रूप से चर्चा भी करने वाले हैं । सभी लोगों के मत जानते हुए मुझे नियम-384 के अन्तर्गत आपको सूचित करना है कि आज की सिटिंग में राज्य सभा चैम्बर, लोक सभा का पार्ट नहीं होगा ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं इसकी व्यवस्था दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, खड़े होकर नहीं, आप कृपया बैठ कर बोलें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम लोगों को डिसिप्लीन में सदन चलाना है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, प्लीज़, मेरी बात खत्म होने दीजिए ।

सर, लोक सभा के जो हमारे मेम्बर्स हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, बिल्क सभी पार्टियों के मेम्बर्स को आपने राज्य सभा चैम्बर में स्थान दिया है । लेकिन, अगर राज्य सभा में इस तरीके का घमासान जारी रहेगा, अगर इस तरह का स्टेलमेट जारी रहेगा तो लोक सभा के जिन मेम्बर्स का स्थान राज्य सभा चैम्बर में है, वे वहां कैसे जा पाएंगे? इसका मतलब कि सोशल डिस्टैंसिंग तार-तार होने वाली है ।...(व्यवधान)

सर, आप एक तरफ कहते हैं कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर सबको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन आप खुद अगर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो सबको यह भी बुरा लगेगा । इसलिए कम से कम स्थिति सामान्य होने दीजिए। हम आपसे यह मांग कर रहे हैं, विनतीपूर्वक मांग कर रहे हैं कि हालात के सामान्य होने तक आप हमें मौका दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुनी है। जो व्यवस्था मैंने बनाई है, आप निश्चिंत रहें, अभी लोक सभा की ऊपर वाली गैलरी पूरी खाली है। सभी माननीय सदस्यों से मैंने व्यक्तिश: आग्रह किया है कि जो सामाजिक दूरी का नियम है, उसी के तहत सदन चल रहा है।

आप चिंता न करें। आपकी चिंता हमारी चिंता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मेम्बर्स को राज्य सभा चैम्बर में स्थान आपने दिया है।

माननीय अध्यक्ष: हम चाहते हैं कि देश देखे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मेरे कहने का मतलब है कि इसे सामान्य होने दीजिए । वहां सभी पार्टी के लोग फँसे हुए हैं । यह कोई कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है कि हम मनमानी कर रहे हैं।

वहां सारी पार्टी के सदस्य, सारे सहयोगी, कुलीग हैं । आपके भी हैं और हमारे भी कुलीग हैं । आप हालात को सामान्य होने तक समय दें । हालात सामान्य होने तक सरकार हस्तक्षेप करे, हालात को सामान्य होने दें, फिर सदन चलाएं । हम तो बराबर आपको सहयोग करते हैं, हर दिन करेंगे । आपका मकसद पूरा करने में हम सब कटिबद्ध हैं, इसलिए हमारी आपसे गुज़ारिश है कि हालात सामान्य होने तक हमें मौका दीजिए । हम लोग मना नहीं करते, लेकिन हालात के मद्देनज़र मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात को सुना है । अगर ऐसी स्थिति बनेगी, ऊपर की दर्शक दीर्घा पूरी भर जाएगी और फिर कोई माननीय सदस्य बाहर बैठेंगे तो मैं सदन नहीं चलाऊंगा । आप इसे निश्चित मान लीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, यह नियम की बात है। आप खुद नियम बनाते हैं और खुद ही नियम* आपने खुद नियम बनाए हैं। ...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded.

20.09.2020

माननीय अध्यक्ष: सदन में नियम सामूहिक रूप से बनते हैं और सभी सदस्यों की सर्वसम्मित से पारित होने के बाद नियम प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। नियम में शिथिलता देने का अधिकार, क्योंकि नियम बुक मुझे दी गई है, इसलिए मैं आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी इसका उपयोग करता हूं।

आज की परिस्थित में जिस विषय पर चर्चा होनी है, वह विषय हम सबके लिए गंभीर विषय है। हम कोविड के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं आपकी भावनाएं जानता हूं। आप जिस समय कहेंगे कि सारी दर्शक दीर्घा भर गई है और अगर एक भी माननीय सदस्य बाहर खड़ा होगा, तो मैं निश्चित रूप से सदन नहीं चलाऊंगा। यह मैं वादा आपसे करता हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आज की चर्चा का प्रस्ताव हमारी तरफ से दिया गया है। कोविड की चर्चा मेरे ही नाम से है।

माननीय अध्यक्ष : आपके नाम से है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने जरूर इसमें इज़ाजत दी है । हम इस विषय पर बड़े सीरियस हैं, लेकिन मैं हालात के मद्देनज़र बात कर रहा हूं । हालात को थोड़ा सामान्य होने दीजिए । हम सब चाहते हैं कि हम आज इस सदन में इस विषय पर, इस चर्चा में शिरकत करें । यह हम सबके लिए गंभीर मुद्दा है । आप हालात के सामान्य होने तक थोड़ा वक्त दीजिए ।

आप हमारी मज़बूरी समझते हैं । आप हालात के मद्देनज़र हमें थोड़ा मौका दीजिए । आप हालात सामान्य होने दें, उसके बाद आप जो कहेंगे, हम उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हमारे यहां परंपरा और नियम भी है कि हम किसी भी सदन, दूसरे सदन की चर्चा अपने सदन में नहीं करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं?

...(<u>व्यवधान</u>)

कुछ माननीय सदस्य: जी, नहीं।

माननीय अध्यक्ष: यह नियम प्रक्रिया है । उस सदन की प्रक्रिया, संचालन की लोक सभा में झलक नज़र नहीं आनी चाहिए । अगर आप यह झलक यहां दिखाना चाहते हैं, तो यह गलत है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, अब यह टू इन वन हो गया है, अब यह अलग नहीं है। अगर टू इन वन हो गया है, तो आपको इसे बदलना पड़ेगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको व्यवस्था दे दी है ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप हालात सामान्य होने तक थोड़ा सा मौका दीजिए । आप हमारी बात समझते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: जिस समय दर्शक दीर्घा भर जाएगी और अगर एक भी माननीय सदस्य बाहर खड़ा होगा तो मैं सदन नहीं चलाऊंगा ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, आप बिल्कुल कानून के मुताबिक बात करते हैं, लेकिन संक्रमण के मद्देनज़र अब टू इन वन हो गया है । लोक सभा और राज्य सभा में अभी बिल्कुल फर्क नहीं है । दोनों मिलकर एक हो गए हैं । आपका जो रूल है, कानून है, यहां एप्लाई मत कीजिए । हमारी हालत और मज़बूरी के मद्देनजर आप हमें मौका दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, मैं विचार जान लेता हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री जगदिम्बका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं नियम 384 पढ़कर सुनाता हूं।

माननीय अध्यक्ष: इसे पढ़ दिया गया है ।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, from your chair, you just request all the hon. Members who have been assigned seats in the Rajya Sabha chamber to come here. Let them come here and occupy the vacant seats because we cannot go now. The House has started. Kindly make that request.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव दें कि कितने बजे से सदन चलाएं?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, कम से कम हालात तो सामान्य होने दें । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बताएं कि 15 या 20 मिनट?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप कृपया हमें एक बार बात करने का मौका दीजिए । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप उनसे गाईड मत हों।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: पहले चरण में एक घंटा दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: आप किसी से गाईड मत हों । आप इस सदन के नेता हैं । आप स्वयं निर्णय करें । मैं आपके निर्णय को मानूंगा ।

...(व्यवधान)

20.09.2020

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप पहले चरण में दो घंटे की मोहलत दीजिए । हम रात में 12, एक बजे तक बैठे रहेंगे । आप हमें दो घंटे की मोहलत दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, हम आपके खिलाफ नहीं हैं । हम रात में बैठे रहेंगे ।

माननीय अध्यक्ष: जोशी जी, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, आपने सदन को व्यवस्था दी है । यह एकदम पक्की व्यवस्था है, परफेक्ट है । जब ऊपर की गैलरी में जो सीट्स ऑलरेडी डेजिग्नेट की हैं, अगर सीट्स फुल होती हैं और चैम्बर की सीट्स भी फुल होती हैं, तो आप एड्जर्न कर सकते हैं । बहुत लोग कोविड पर चर्चा करना चाहते हैं । सेंस ऑफ द हाउस यही है । कृपया इसे आप आगे बढ़ाइए, यही मेरा निवेदन है । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आज आपकी बात मानता हूं ।

सदन की कार्यवाही चार बजे से शुरु करेंगे, तब तक के लिए सभा स्थगित होती है।

15.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

20.09.2020

16.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमित प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगणों, जो भी माननीय सदस्य राज्य सभा में बैठना चाहते हैं, वे वहां जाकर बैठ सकते हैं।

16.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 1 से 8, माननीय मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2020 जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1233(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2661/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) इंस्ट्रयूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
 - (दो) इंस्ट्रयूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 2662/17/20]

(2) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 58 तीसरा सत्र, 2000

[Placed in Library, See No. LT 2663/17/20]

2. विवरण संख्या ५० छठा सत्र, २००१

[Placed in Library, See No. LT 2664/17/20]

चौदहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 33 दूसरा सत्र, 2004

[Placed in Library, See No. LT 2665/17/20]

4.	विवरण संख्या 34	पांचवां सत्र, 2005
		[Placed in Library, See No. LT 2666/17/20]
5.	विवरण संख्या 36	सातवां सत्र, 2006
		[Placed in Library, See No. LT 2667/17/20]
6.	विवरण संख्या 28	आठवां सत्र, 2006
		[Placed in Library, See No. LT 2668/17/20]
7.	विवरण संख्या 33	नौवां सत्र, 2006
		[Placed in Library, See No. LT 2669/17/20]
8.	विवरण संख्या 26	ग्यारहवां सत्र, 2007
		[Placed in Library, See No. LT 2670/17/20]
9.	विवरण संख्या 26	पंद्रहवां सत्र, 2009
		[Placed in Library, See No. LT 2671/17/20]
		पंद्रहवीं लोक सभा
10.	विवरण संख्या 38	दूसरा सत्र, 2009
		[Placed in Library, See No. LT 2672/17/20]
11.	विवरण संख्या 31	तीसरा सत्र, 2009
		[Placed in Library, See No. LT 2673/17/20]
12.	विवरण संख्या 32	चौथा सत्र, 2010
		[Placed in Library, See No. LT 2674/17/20]
13.	विवरण संख्या 32	पांचवां सत्र, 2010
		[Placed in Library, See No. LT 2675/17/20]

14.	विवरण संख्या 30	छठा सत्र, 2010
		[Placed in Library, See No. LT 2676/17/20]
15.	विवरण संख्या 30	सातवां सत्र, 2011
		[Placed in Library, See No. LT 2677/17/20]
16.	विवरण संख्या 33	आठवां सत्र, 2011
		[Placed in Library, See No. LT 2678/17/20]
17.	विवरण संख्या 30	नौवां सत्र, 2011
		[Placed in Library, See No. LT 2679/17/20]
18.	विवरण संख्या 29	दसवां सत्र, 2012
		[Placed in Library, See No. LT 2680/17/20]
19.	विवरण संख्या 27	ग्यांरहवां सत्र, 2012
		[Placed in Library, See No. LT 2681/17/20]
20.	विवरण संख्या 25	बारहवां सत्र, 2012
		[Placed in Library, See No. LT 2682/17/20]
21.	विवरण संख्या 26	तेरहवां सत्र, 2013
		[Placed in Library, See No. LT 2683/17/20]
22.	विवरण संख्या 21	चौदहवां सत्र, 2013
		[Placed in Library, See No. LT 2684/17/20]
23.	विवरण संख्या 22	पंद्रहवां सत्र, 2013-14
		[Placed in Library, See No. LT 2685/17/20]

सोलहवीं लोक सभा

24.	विवरण संख्या 21	दूसरा सत्र, 2014
		[Placed in Library, See No. LT 2686/17/20]
25.	विवरण संख्या 21	तीसरा सत्र, 2014
		[Placed in Library, See No. LT 2687/17/20]
26.	विवरण संख्या 20	चौथा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 2688/17/20]
27.	विवरण संख्या 17	पांचवां सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 2689/17/20]
28.	विवरण संख्या 17	छठा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 2690/17/20]
29.	विवरण संख्या 15	सातवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 2691/17/20]
30.	विवरण संख्या 15	आठवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 2692/17/20]
31.	विवरण संख्या 14	नौवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 2693/17/20]
32.	विवरण संख्या 12	दसवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 2694/17/20]
33.	विवरण संख्या 12	ग्यारहवां सत्र, 2017
		[Placed in Library, See No. LT 2695/17/20]

विवरण संख्या 10	बारहवां सत्र, 2017
_	[Placed in Library, See No. LT 2696/17/20]
विवरण संख्या 9	तेरहवां सत्र, 2017-18
	[Placed in Library, See No. LT 2697/17/20]
विवरण संख्या 8	चौदहवां सत्र, 2018
	[Placed in Library, See No. LT 2698/17/20]
विवरण संख्या 7	पंद्रहवां सत्र, 2018
	[Placed in Library, See No. LT 2699/17/20]
विवरण संख्या 5	सोलहवां सत्र, 2018-19
	[Placed in Library, See No. LT 2700/17/20]
विवरण संख्या 4	सत्रहवां सत्र, 2019
	[Placed in Library, See No. LT 2701/17/20]
	सत्रहवीं लोक सभा
विवरण संख्या 3	पहला सत्र, 2019
	[Placed in Library, See No. LT 2702/17/20]
विवरण संख्या 2	दूसरा सत्र, 2019
	[Placed in Library, See No. LT 2703/17/20]
विवरण संख्या 1	तीसरा सत्र, 2020
	[Placed in Library, See No. LT 2704/17/20]
	विवरण संख्या 7 विवरण संख्या 5 विवरण संख्या 4 विवरण संख्या 3

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा **(**5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(5)/2016 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-1(3)/2016 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2705/17/20]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों की भर्ती) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/08/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/06/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/04/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2706/17/20]

- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1087(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (दो) आवश्यक वस्तु की कच्चे माल के रूप में घटकों तथा घटकों के मूल्य आदेश, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1169(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (तीन) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्डक हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1207(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्ड हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1197(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 2707/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 - (दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2708/17/20]

(3) विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2164(अ) से का.आ. 2172 (अ) जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में "वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह भिण्डा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपरवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह" के नाम जोड़ने के संबंध में है।

[Placed in Library, See No. LT 2709/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2710/17/20]

- (3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 10 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) काले सुवासित चावल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2711/17/20]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 1253 (अ) जो 11 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 1999 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3226(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।
- (तीन) का.आ. 2000 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए भारत में विनिर्मित की जाने वाली अनंतिम उर्वरक फॉस्फोजिप्सम (दानेदार) के संबंध में निर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है ।
- (चार) का.आ. 2001 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2002 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (छह) का.आ. 2003 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(सात) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

- (आठ) का.आ. 2325 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (नौ) का.आ. 2500 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है ।

 [Placed in Library, See No. LT 2712/17/20]
- (5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2713/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं वर्ष 2018-19 के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास को गित प्रदान करने और संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके अनुगामी प्रयोग तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्यकम के संबंध में 50वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2714/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्निलखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन ।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2715/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2716/17/20]

- (3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 - (दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 - (तीन) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (चार) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2717/17/20]

- (5) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2718/17/20]

16.01 ½ hrs

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Unstarred Question No. 1381 to 1610)

(Pages 34 to 673)

^{*}Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

16.02 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 3rd to 9th Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हुं:-

- 1. 'विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 2. 'संस्कृति मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में चौथा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 3. 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (माने गए)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 4. 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (न माने गए)' के बारे में छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 5. 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में सातवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 6. 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (माने गए)' के बारे में आठवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।
- 7. 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (न माने गए)' के बारे में नौवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 10.

20.09.2020 675

16.02 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations/observations

contained in the 1st Report of the Standing Committee on Food, Consumer

Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2019-20) pertaining

to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food

and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब

दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले, और

सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के

कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 11.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2719/17/20.

20.09.2020 676

16.03 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th

Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants

(2019-20) pertaining to the Department of Animal Husbandry and Dairying,

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying*

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) : अध्यक्ष

महोदय, मैं पश्पालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित

अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 12.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2720/17/20

20.09.2020 677

16.03 ½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th

Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants

(2019-20) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries,

Animal Husbandry and Dairying*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी की ओर से, मैं मत्स्यपालन

विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे

में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के

बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 13.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2721/17/20

16.04 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

General Council of Rehabilitation Council of India

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पिठत धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद की महा-परिषद के सदस्य के रूप में, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अविध के लिए या उनके उत्तरवर्ती की सम्यक नियुक्ति होने तक, जो अविध अधिक लंबी हो, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पिठत धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद की महा-परिषद के सदस्य के रूप में, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अविध के लिए या उनके उत्तरवर्ती की सम्यक नियुक्ति होने तक, जो अविध अधिक लंबी हो, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर - 14.

16.05 hrs

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2020*-Introduced

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं माननीय अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

" कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए ।"

में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस पर डिटेल चर्चा हो जाए ।

श्री मनीष तिवारी जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दें।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमित से यह जो एफसीआरए (संशोधन) विधेयक है, इसका विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1976 में जब यह कानून बनाया गया था तो दुनिया का जो सामरिक परिप्रेक्ष्य था, वह दूसरा था । खासकर जो विकासशील मुल्क हैं, उनके अंदरुनी मामलों में बाहरी ताकतों का दखल देना अमूमन स्वीकार्य माना जाता था । तब से लेकर अब तक जो दुनिया का परिप्रेक्ष्य है, जो सामरिक परिप्रेक्ष्य है, वह आज बदला है । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले छह वर्षों में यह जो एफसीआरए का कानून है, यह उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं । इस अमेंडमेंट बिल का जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजन्स हैं, उसमें यह लिखा है कि Over 19,000 FCRA permissions were

_

^{*} Published in the Gazette, Extraordinary, Part –II, Section 2 dated 20.09.2020

cancelled in the nine years between 2010 and 2019. Howsoever, what this Amendment Bill is silent about is as to how many criminal investigations actually fructified into convictions in an appropriate court of law after attaining finality and ascending the hierarchical pyramid of the court structure. I have four specific objections to this Bill, hon. Speaker, Sir.

Clause 3 of the Bill which inserts new Section 7 in place of the old one violates the Wednesbury Principle, which is intrinsic to Article 14 of the Constitution of India by making the bar on transfer of foreign contributions absolute.

My second objection is that clause 6 which inserts a new proviso to subsection 2, Section 11 gives unbridled powers of harassment and persecution to the Government by giving it the authority to conduct a summary inquiry to interdict foreign contributions. This turns the jurisprudential principle of 'innocent until proven guilty' completely on its head.

My third objection, hon. Speaker, Sir, is that clause 8 that amends Section 13 increases the suspension period of an FCRA certificate from 180 days to 365 days and no valid or cogent reason has been provided for this increase.

My final objection, hon. Speaker, Sir, is that clause 11 that amends Section 16 dealing with the renewal of FCRA permissions makes the process equivalent to applying for a new certificate itself.

Finally, Mr. Speaker, Sir, I would like to conclude by saying that the United Nations Special Rapporteur on rights to freedom of peaceful assembly has stated that the FCRA provisions and rules are not in conformity with international law, principles, and standards. Right to freedom of association includes the right to access foreign funding.

So, therefore, hon. Speaker, Sir, my request to the Government is that the FCRA provisions need to be relaxed rather than made stringent.

Thank you very much for your indulgence, Mr. Speaker, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020.

This is an another example of big brother watching, that is, the Central Government keeping an eye on all those who are receiving foreign contributions. It is mainly directed at minority organizations or institutions which receive foreign funding. There is an attempt to tighten the screw on all those organizations, NGOs, who receive foreign funding. Now, public servants are being excluded from accepting foreign funding. The administrative expenses have been reduced to 20 per cent. AADHAAR number is being made compulsory and in case of FCRA account, it is being specified that it will be done through State Bank of India, New Delhi.

The purpose of the Foreign Contribution Regulation Act was to have some control on foreign contributions, not to stop them altogether. But now this is an attempt where foreign contributions will be stopped altogether because very few people will be able to comply with the new regulations expected from this Act. Thus, the freedom of people who work in social organizations, do good work in the tribal areas and rural areas, will be prohibited or barred or hampered in accepting foreign contributions. As Mr. Tewari correctly pointed out, the idea should be to deregulate and not overregulate foreign contributions so that people can receive foreign contributions and do their work honestly. If somebody does fraud, if somebody does anything wrong, then criminal investigation can be initiated. But so far, no such criminal investigation has proved anything against people receiving foreign contributions. Sometimes we see that certain persons have been probed, but not a single conviction under this law has taken place so far. So, I fully oppose the introduction of this Bill which will hamper the freedom. especially of minority groups.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, under rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business, I do oppose the introduction of the Foreign Contribution Regulation (Amendment) Bill, 2020. Sir, before delving into the seeds of the legislation, I am seeking a little indulgence from you for a distraction from the core issue.

सर, कभी-कभी ऐसा लगता है कि सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष पर, जैसे कि हम विपक्ष में रहते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है । सवाल पूछने का अधिकार हमें है और जवाब देने का अधिकार सत्ता पक्ष को होता है । मेरी बात का एहसास कभी-कभी न समझते हुए कुछ लोग अल्फाज़ से मतलब निकालते हैं । मैं हिमाचल भूमि को अपनी देवभूमि मानता हूं ।...(व्यवधान) बंगाल के हर घर में आप किसी न किसी एक ऐसे शख्स से मिलेंगे, जो हिमाचल घूमकर आया है । हिमाचल हमारे लिए देवभूमि है ।

सर, आपने यह फैसला लिया था कि कुछ बातें रिकार्ड से निकाली जाएं । मैंने तुरंत कहा कि यह आपका फैसला है । मेरे खिलाफ ही किस तरीके की बात कल कही गई, उसे मैं थोड़ा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आपने जो विषय डाला है, मैं देखकर उसको निकाल दूंगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मेरे खिलाफ यह कहा गया कि मैं सीरियल ऑफंडर हूं । सर, मैं ऑफंडर नहीं, डिफंडर हूं ।...(व्यवधान) I am the defender of the nation; I am the defender of democracy; I am the defender of sovereignty. Furthermore, I am the defender of communal harmony of this nation.

सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि जवाहर लाल नेहरू जी के खिलाफ बेबुनियाद बात न उठाई जाए । मैं भी मोदी जी का सम्मान करता हूं । मोदी जी के जन्मदिन पर मैंने भी उनको शुभकामनाएं दीं । मुझे बाहर एक पत्रकार ने पूछा था कि आज मोदी जी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया में चर्चा पर हो रही है कि Day of National Unemployment.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब्जेक्ट पर बोलिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैंने कहा था कि 14 साल आप सत्ता में रहे। अगर नेहरू जी के समय में पीएमएनआर फंड में कोई गड़बड़ी रही हो, तो आप उसे

निकालिए । नेहरू जी के नेतृत्व में रिलीफ फंड से एक कौड़ी इधर-उधर हुई, तो मैं अपना यह पद त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आप सब्जेक्ट पर बोलें ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I come to the point. Section 12A is a violation of an individual's concerns and privacy of Aadhaar data. सर, मैं अब दूसरे पहलू पर आ रहा हूं । The Supreme Court judgement delivered on 22nd September 2018 stopped the Government from setting up mandatory provision for Aadhaar as an identification document. That is against privacy concerns of citizens and violation of the Supreme Court order. The Supreme Court bench chaired by Justice Dipak Misra said it is mandatory only for IT returns and PAN allotment.

In other cases, the Supreme Court had even struck down the national security exception under the Aadhaar Act, reiterating the importance of data privacy by restricting Government from accessing it. But Section 12(a) demands Aadhaar as a mandatory requirement for identification.

Secondly, arbitrary and unreasonable provisions are still existing in the Bill, for example Section 5 of FCRA, which confers power upon the Central Government to declare any organisation to be an organisation of political nature. This is contrary to the spirit of promoting foreign contribution and regressive towards democratic principle. The Government can turn an organisation political, and prohibit an organisation from receiving foreign contribution if they try to

respond to a political issue or dissent. This provision can be used as a tool to eliminate voices of dissent which is a part and parcel of democracy.

Current amendments are made in order to confer unnecessary power in the hands of Government and as a tool to suppress the opposition voices. This is the reason for my opposing the introduction of the Bill.

Sir, Before concluding, मुझे आप एक बार आपकी सराहना करने का मौका दीजिए । आज आपने जिस ढंग से विपक्ष की मदद की, यह आपकी जेनरोसिटी है, उदारता का सबसे बड़ा सबूत बन गया है । आपसे एक छोटी मांग की थी, आप चाहते तो हमारी मांग पूरा नहीं कर सकते थे लेकिन आपने हमारी मांग पूरा करके विपक्ष को जिस ढंग से सम्मान दिया, यह एक मिसाल के तौर पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में रिकार्ड रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, जितना वह सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : आज आप संक्षिप्त में बोल लें।

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ष 2010 की तत्कालीन सरकार ने विधेयक लाने के उद्देश्य से लोक सभा और राज्य सभा में उनके द्वारा जो वक्तव्य आया था, मैं उसकी चार लाइनें उनको याद कराना चाहता हूं । उस समय माननीय चिदम्बरम साहब 19 अगस्त, 2010 को एफसीआरए कानून लाये । मैं उनके भाषण के वक्तव्य की चार लाइन बोलना चाहता हूं ।

अब हम लगभग चालीस हजार संगमों पर कार्य कर रहे हैं । वास्तव में जुलाई, 2010 तक यह संख्या 40,171 थी । मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है, उन्होंने कहा, जब मैंने इस अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा कि आधे संगम विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ।

अभी माननीय सांसद मनीष जी बोल रहे थे कि यह अधिकारों का उल्लंघन है, चौदह के अनुरूप नहीं है । हम किसी के अधिकार का हनन तब करेंगे जब उसके क्रियाकलाप को रोकेंगे । जो भी संस्थाएं काम करती हैं, अगर वह संस्थान कानून और नियम के हिसाब से काम नहीं करती और अपने उद्देश्य से भटक जाती है तो हम उस स्थिति को नोटिस करते हैं, उनको सुनते हैं और उसकी जांच करते हैं, तत्पश्चात् जरूरत पड़ने पर कानून के हिसाब कार्य नहीं करते तो हम कार्रवाई करते हैं । इसमें उनके अधिकार का हनन कहां हो रहा है?

दूसरा, आधार की बात कह रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही अगर जरूरत पड़ी तो पहचान के लिए आधार को उपयोग में ला रहे हैं । उनके जो डॉयरेक्टर्स हैं, उनके विषय में हमारे पास पहचान रहे, वह कहां के हैं, उस आधार के हिसाब से पता क्या है, इसके लिए आधार का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही इस संशोधन की बात लाई गई है ।

ग्यारह में प्रिसिपल एक्ट की धारा सोलह संशोधन प्रस्तावित है, जिसके विषय में कह रहे थे । हम जब नवीनीकरण करते हैं, चिदम्बरम साहब ने नवीनीकरण के विषय में विशेष रूप से कहा था, पांच वर्षों के बाद अगर हम नवीनीकरण करते हैं तो उस समय किन-किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए ।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था । हमें नवीनीकरण से पांच साल की गतिविधियों के बारे में जांच करने का अधिकार मिलेगा । हम किसी भी संस्था का नवीनीकरण करें, लेकिन यदि हम उसके पांच साल की गतिविधियों की जांच नहीं करेंगे, जिनके क्रियाकलाप देश विरोधी जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से पैसे आए हैं, उसमें खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी जांच करने में किसी को क्या आपत्ति है? यह मंशा समझ में नहीं आ रही है ।

दूसरा, अभी माननीय वरिष्ठ सांसद सौगत साहब कह रहे थे कि यह विधेयक विदेशी अंशदान में भेदभाव बरतेगा । इसका मतलब वे धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों को या उसकी परिभाषा को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर तुष्टिकरण की भावना से कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कोई भेदभाव नहीं है । बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अवसर प्रदान है । एफसीआरए एक्ट, 2010 में धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदन के लिए जो अनुमित दी गई थी, उसी के आधार पर अभी भी उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, ...(व्यवधान) चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, इस कानून के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं । हमारा उद्देश्य यही है कि जो संस्थाएं विदेशी अंशदान प्राप्त करती हैं, वे अपने उद्देश्य से न भटकें, न किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हों, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को बाधित करता हो या कहीं न कहीं से वह बाधित करने का प्रयास करता हो या फिर हम राष्ट्रीयता के आधार पर कहीं से भी खतरा पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, हम इसी चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं । जिस उद्देश्य से पैसा आता है, वह उसी उद्देश्य में लगे ।

एक बात उन्होंने बैंक में खाते के बारे में कहा है । हिसाब-किताब रखना बहुत कठिन हो गया था । स्वयं चिदम्बरम साहब ने कहा था कि आधे संस्थान न तो रिटर्न दाखिल करते हैं, न हमें सूचना देते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई, उसमें भी सुविधा यह दी गई है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है । एसबीआई बैंक ने इस पर दो आश्वासन भी दिए हैं कि यदि आप अपने स्थानीय स्तर पर भी कागज जमा करेंगे, उसका खाता दिल्ली में खुलेगा, हम यहां से उसकी व्यवस्था करेंगे और भेजेंगे । वह संस्था अपने स्थानीय स्तर पर भी दूसरा खाता खोल सकती है । यह बिल्कुल स्पष्ट है । हमें इनकी मंशा समझ में नहीं आई । हमने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-15

श्री अर्जुन मेघवाल जी ।

16.24 hrs

MOTION RE:17TH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान) अधीर रंजन जी आप पढ़िए । माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी आप पढिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 19 सितम्बर, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 सितम्बर, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16.24 ½ hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापित: माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमित प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

(i) Need for additional JEE, NEET entrance centres in Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): National Testing Berhampur has selected seven places - Bhubaneswar, Cuttak, Balsore, Berhampur Rourkela and Sambalpur as entrance centres for JEE, NEET tests in Odisha. Approximately, 40,000 candidates appeared for JEE in these centres over 12 shifts, two shifts each day. Similarly, around 50,000 students appeared for the NEET.

For students of undivided Koraput District, predominantly tribal area, consisting of Koraput, Rayagada, Malkangiri and Nabarangpur - all aspirational districts, the centers are over 400-500 km away and it is difficult to travel with limited transportation available in the tribal areas. The financial condition of the students prevent them from booking private vehicles. Additionally, arranging accommodation is burden on poor tribal families.

-

^{*} Treated as laid on the Table.

I would urge upon the Ministry of Education to make Jeypore and Rayagada as JEE, NEET entrance centres.

(ii) Regarding Minimum Support Price (MSP) for Cocoon

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Sericulture is a main source of income for lakhs of farmers in the country. Silk industry is capable enough to provide jobs to lakhs of youth also.

Sericulture farmers have been facing problems due to the crash in Cocoon prices. Large number of farmers committed suicide in recent months.

Coronavirus even worsened the situation. The Govt had earned good revenue by exporting silk goods particularly from Karnataka in recent years.

It is the duty of the Government to help farmers in the times of distress and encourage more people to engage in sericulture which has the capability to provide employment as well as revenue to the country. Therefore, I urge upon the Government to declare an MSP for Cocoon at the earliest to help the farmers.

(iii) Regarding construction of subway from Kongalamman temple to RTO road in Vellore Parliamentary Constituency

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE) : I would raise issue regarding construction of subway from Kongaiamman temple to RTO road in my Vellore Parliamentary Constituency.

(iv) Regarding sanction of funds to develop a Tourism Circuit Hub in Kurnool

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Kurnool district is the fifth most popular city in the State of Andhra Pradesh. This district has many popular pilgrim and tourist places.

Srisailam Mallikharuna Swamy temple is one of the Dwadasa Jyothirlingas and goddess Bramaramba Dcvi temple is one of the Astadasa Shakti Peetams believed to be have self manifested. The unique feature of this place is the existence of Jyothirlingam and Shakthi Peetam at one place.

Srisaiiam is also included in the list of PRASAD Scheme of Ministry of tourism. Besides this, there are pilgrim places like Ahobilam, Yaganti, Mahanandi, Mantralayam etc. Tourist places like Adani port, Banaganapalli port, Belum caves, Orvakallu Rock Gardens, Rollapadu wild life sanctuary are the tourist attractions of the district.

Keeping in view of the pilgrim and tourist places in Kurnool district, I request the Hon'ble Minister for Tourism to sanction funds for developing a Tourism Circuit Hub in Kurnool.

(v) Regarding revision of Crop Insurance Premium

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARASAPURAM): I draw the attention of the Government towards the recent revision of Crop Insurance Premium, which has become a further burden on the financial condition of the state government.

With this decision, share of the premium of central government has reduced from 50% to 30%. It is posing a serious financial burden on states as they have to bear total 68% of the premium amount. Till now farmer, centre and state governments were sharing the premium amount as 2%, 49% and 49% respectively. But as per recent revision, central government will pay only 30% as against its 49% share . Remaining 68% has to be borne by state governments. It is becoming an extra burden on states. Particularly, Andhra Pradesh, is already reeling under funds crunch hence it has become an added burden.

Hence, I urge upon the Government of India to review the revision and consider request of states and revert to the earlier ratio.

(vi) Need to Grant Central Assistance to Complete Krishna-Marathwada Irrigation Project 2004

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मराठवाड़ा सूखाग्रस्त रहने के कारण उस्मानाबाद में हर साल पानी की समस्या पैदा हो जाती है, किसान काफी परेशान रहते हैं । मराठवाड़ा का महत्वकांक्षी कृष्णा-मराठवाड़ा उपसाह सिंचाई योजना वर्ष 2004 से लंबित है । इस योजना के निर्माण से 92,141 हेक्टेयर क्षेत्र जमीन सिंचित हो सकती है । इस योजना में उस्मानाबाद जिले को दो स्वतंत्र उप-सिंचन योजनाओं द्वारा 19 टीएमसी पानी मिलना नियोजित है और बीड जिले को 2 टीएमसी, ऐसे कुल मिलाकर 21 टीएमसी पानी मराठवाड़ा को मिलना प्रस्तावित है । योजना को शुरू करना बहुत ही जरूरी है । इस योजना के पूरे निर्माण के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जनमानस एवं किसानों की रक्षा के लिए इस परियोजना के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता जारी कर इसको तुरंत पूरा करे, जिससे यहां की क्षेत्रीय जनता तथा किसानों को इसका लाभ मिल सके ।

16.25 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Covid-19 Pandemic in the Country

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के अविलम्ब लोक महत्व के विषय हैं, आज कोविड-19 वैश्विक महामारी की चर्चा और विधेयक पारित होने के बाद उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा । सबको बोलने का समय मिलेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज कोविड-19 सम्पूर्ण मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन चुका है । हम भी कोरोना वायरस के चलते असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं । जब भी देश के सामने कोई संकट आया है, इस सदन ने ही देश को राह दिखाई है । विषम परिस्थित में आयोजित इस सत्र से भी जनता को बहुत उम्मीदें हैं । मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े खतरों के बीच भी आप सदस्यों ने बड़ी संख्या में सदन में आकर पूरे देश को सकारात्मक संदेश दिया है । आज जब हम कोविड जैसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि यह चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए । हमारा एकमात्र प्रयास यह होना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने देशवासियों को इस महामारी से सुरक्षित कर सकते हैं । चर्चा और आपसी समन्वय से ही हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे । यह हमारा सामूहिक प्रयास और दायित्व है । सदन की चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । चर्चा के दौरान जो विचार सामने आते हैं, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को उससे दिशा मिलती है । सकारात्मक आलोचना मार्गदर्शन भी करती है । मेरा आपसे आग्रह है कि आज आप जो भी बात कहें, उसमें सुझाव भी दें तािक इस चर्चा से एक सार्थक समाधान निकलकर आए और देश में हम एक सुरक्षित माहौल तैयार करने में सफल हो सकें ।

लॉकडाउन के दौरान मैंने अनेक सदस्यों से फोन पर संपर्क किया था । मैं जिस भी माननीय सदस्य से सम्पर्क करता था, वे सभी माननीय सदस्य तमाम प्रकार के खतरों के बावजूद वंचित, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में व्यक्तिगत रूप से और सम्पूर्ण समाज को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे । इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को साधुवाद देता हूँ । अभिव्यक्ति हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कोविड-19 के समय आपने अभिव्यक्ति के साथ अपने क्षेत्र में जो अच्छे काम किए हैं, उसके बारे में अगर यहां अपने अच्छे प्रयासों का अनुभव भी साझा करेंगे तो पूरे सदन को आपके सद्प्रयासों से प्रेरणा मिलेगी । चूंकि चर्चा के लिए समय सीमित है, इसलिए हम यह प्रयास करें कि हम यहां जो भी बात रखें वह संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो । मेरा विश्वास है कि ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान संयमपूर्वक एवं संवेदनशील तरीके से आप अपनी बात रखेंगे और सदन का सहयोग भी करेंगे और हमारे सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 की इस महामारी के संक्रमण को रोकने में देश को एक नई दिशा भी मिलेगी ।

अधीर रंजन जी, क्या आपकी जगह डॉ. शशि थरूर जी बोलेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हाँ सर ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Respected Speaker, I thank you for granting this House the opportunity to discuss this topic that has undoubtedly attained singular importance in the national consciousness - the widespread impact of COVID-19 - and specifically, to lay bare this Government's mismanagement of this crisis. I have taken my own mask off to speak as I try to unmask this Government. वैसे इस बीमारी की वजह से सरकार के लिए एक अच्छी बात यह हो गई कि उसे मुँह छुपाने का बहाना मिल गया । But in any case, yesterday, September 19th

based on data of the World Health Organisation (WHO), India recorded a fresh set of 93337 cases compared to 42000 in the USA and tragically additional deaths of 1247 compared to 800 and something in the USA, effectively making us the country with the highest number of daily cases and deaths globally. It is a painful reflection of the grim times we live in and equally, a reminder of how important it is for us to take time and discuss this vital issue in this House.

Just as there are rules and conventions that guide the functioning of this august House, a set of principles and systems that are adhered to under your leadership and supervision, as you often remind us, Mr. Speaker, so too in any democratic country, there is an age-old contract between the citizen and the Government, which rides on certain fundamental expectations: the transparent functioning of the Government, the upholding of inalienable rights, the access to basic resources to sustain an empowered life, the sound management of our economy through competent policy making, a participative and democratic decision-making process, and above all, the conviction and capability of an elected Government to ensure that the safety and security of individual citizens is never compromised.

This context is important for all of us, who have gathered here, to recognise because we must understand the scale of the breath-taking violations of this basic compact by our Government during the last six months. The situation precipitated by the COVID-19 pandemic was certainly extraordinary in terms of its rampant

spread and impact across all walks of life. However, Sir, it must be said that such a situation of distress and vulnerability is precisely where our citizens would expect their Government to reaffirm their special contract that holds us together. But instead of mature and pro-active governance, we have collectively witnessed a fundamental break-down in government machinery in these past six months. Instead of clearly communicated protocols and comprehensive strategies, we have collectively witnessed an alarming lack of clarity, readiness and preparedness to tackle this virus. And above all, where the citizens of the country expected their Government to lead them out of this darkness, we have sadly witnessed an unconscionable betrayal of the concerns and aspirations of the people by the very Government they elect.

Respected Speaker, Sir, let us look at how things unravelled in the last six months. As early as in January there were compelling indications that the virus that had originated in Wuhan was far more complex and potentially devastating than we had earlier imagined. By January 30, the World Health Organisation had declared the COVID-19 virus as a public health emergency. A declaration that came on the same day that India too had its first documented case in the form of a student who had returned to Kerala from Wuhan. When this Government failed to produce any tangible reaction to these developments, on February 12, my colleague and an hon. Member of this House, Shri Rahul Gandhi, tweeted and publicly warned the ruling dispensation, I quote, 'the Coronavirus is an extremely

serious threat to our people and our economy. My sense is that the Government is not taking this threat seriously. Timely action is critical'. When the Government ignored this to host a crowded welcome to President Trump in Ahmedabad, Congress followed up an exhortation on March 3rd and 5th, which I am sorry to say, were ignored by the Government. They routinely prioritised partisan policies over constructive dialogue. Had they listened to Shri Rahul Gandhi's prescient warnings and of others like him, surely, the situation could have been managed better. Instead, driven by what appeared to be greater interest in toppling a State Government in Madhya Pradesh rather than national priorities, the present ruling dispensation continued to delay the implementation of a national strategy to clamp down on the spread of the virus. This, Hon. Chairperson, was the first failure of this Government -- I will mention five of them in due course -- a failure to adequately recognise the scale and complexity of the problem we were dealing with, compounded by unwillingness to listen to voices that warned us well in advance of the consequences of ignoring a problem of such magnitude.

Still, given at that point the number of cases were comparatively low in India, there was still time for the Government to execute a well thought out and comprehensive strategy to curb the virus. While experts may differ on details of lockdown strategies, they were all unanimous in their opinion that sufficient notice and advance warning are critical for a successful lockdown. Advance warning would have given critical time for our medical systems and frontline healthcare

workers to prepare for an onslaught of cases. Advance warnings would have given time for those who were, at that point, overseas to make it back to the country and prepare to hunker down. Advance warnings would have allowed those within the country, particularly economically vulnerable groups like our migrant workers, sufficient time to make it back to their respective home States, where they would have had necessary support systems to look after themselves. But, perhaps, above all, surely the provision of advance warning and transparent announcement is a basic courtesy that any Government should have extended to the people of our country. It is a moral responsibility, after all, of the Government to take the nation into confidence and not leave them in the dark.

What we have seen in these last years, Sir, is that this Government has a remarkable penchant for shock and awe tactics rather than mature leadership. Just as we witnessed during the sudden announcements of the disastrous decision of demonetisation in November 2016, once again this nation was betrayed by the whims and fancies of its leadership. Even though the people of this country were given three days' notice before locking down for a mere 17-hour *Janta Curfew* on a Sunday, when most individuals spend a lot of time at home anyway, a trial for a longer national lockdown, what followed was horrific. Riding roughshod over federalism with no pretence of consulting the State Governments, on the, on the 24th of March, the PM took to the air to announce a lockdown for 21 days from that midnight.

Planes, trains, highways and public transport were to be abruptly shut down three and a half hours after the PM finished speaking, a shockingly short window to prepare for three weeks of staying indoors, without any serious announcement of what support systems would be in place during the lockdown. It was inevitable that rampant chaos would follow this abrupt decree and that brings me to the second failure of this Government, Sir, the creation of a Government-made disaster that laid the foundations for the widespread distress and anguish that followed a series of events that should haunt each of us and has tarnished this Government's moral standing.

Across the country, we know about the long lines that immediately sprung up outside our kirana shops, as shocked citizens queued up to purchase critical rations to see this period through. Thousands took to our bus depots and railway stations. People made desperate attempts to make it back to their respective homes. Businessmen and women who had travelled to other cities for meetings were stranded by the PM's high-handed actions and those overseas suddenly were left with no way to return back to the country. Our migrant workers and daily wage workers, beside themselves in their distress, took to the roads and highways in a desperate attempt to make it back to their home States.

The very next day, the PM in his address to residents of his constituency likened the distress he had unleashed upon the nation to Kurukshetra. The Mahabharata, he said, took 18 days before victory was earned; tackling the

COVID virus would take 21 days. 180 days have passed. Our national caseload is the second largest in the world and heading for number one. Daily cases have nearly reached a lakh, higher than any other country. The economy is in tatters having suffered a contraction far more severe than any other country. Therefore, perhaps the analogy better suited to describe this Government is that of Emperor Nero who played the fiddle while an entire nation burned, or more accurately, here we have an Emperor who resorted to ताली बजाओ और दिया जलाओ, while a nation suffered beyond any conceivable measure.

"हम यह नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम यह बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, तैयारी से लड़ते तो हालात ऐसे न होते, रेल की पटरी पर वे प्रवासी न सोते, साइकिल पर बूढ़े बाप को बेटी नहीं ढोती, लाश पर मां की कभी बच्ची नहीं रोती, अर्थव्यवस्था इस तरह निपात न होती, शायद हमारी इतनी बुरी मात न होती, विश्व पटल पर हम कभी प्रथम नहीं आते, जितने मरे हैं लोग, वे मारे नहीं जाते, अच्छी सी कोई योजना हम रख सकते थे, मिल-जुल सलाह करते तो शायद बच सकते थे,

हम यह नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम यह बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी।"

In a country where according to most estimates, nearly 90 per cent of the workforce is employed in the informal economy, where 38 crore Indians out of 47 crores, who make up our totally employed workforce, are predominantly in jobs that offer a daily wage, surely this Government should have had the foresight to

understand the implications of the shock-and-awe style of governance on the livelihoods of its own citizens. Depending on which set of sources you refer to, the numbers that quantify the scale of the migrant workers' crisis vary. In June, the Chief Labour Commissioner estimated that over 26 lakh migrant workers were stranded in various parts of the country, while others estimate a reverse migration of up to three crore workers since mid-March.

The image of tens of thousands of our fellow citizens setting off on foot to make it back to their hometowns has been seared into the collective consciousness of our nation. If as little as a direct assurance to such marginalized groups, a clear promise of support followed through with policies to ensure that no worker would go hungry or would lose access to basic income or healthcare, if such had been given, much of the crisis that followed could have been averted. If this sudden announcement and the distress the Government caused to our people was to arrest the spread of the virus, then I am sorry to say that the approach was utterly misguided and has completely failed.

As highlighted in a letter addressed to the PM that was signed by distinguished medical experts of several national associations, and I quote: "Had the migrant persons been allowed to go home at the beginning of the epidemic when the disease spread was very low, the current situation could have been avoided. The returning migrants are now taking infection to each and every

corner of the country, mostly to rural and peri-urban areas in districts with relatively weak public health systems."

In other words, the third significant failure of this Government is that not only did their high-handedness result in widespread pain for our people but their role in fomenting such an exceptional displacement of migrant workers actively undermined any gains that were initially envisioned from a national lockdown.

As the virus continued to spread, the countermeasures of a lockdown persisted and this inevitably further laid low our already fragile economy. This is not a debate on the economy but the fact is that shutting down every productive activity in the name of flattening the curve meant only that, in the words of Rajiv Bajaj, we flattened the wrong curve. COVID rose but our economy collapsed. All our main indicators are in the red, with no end in sight causing sleepless nights for most Indians. We have already seen the 23.9 per cent contraction in Quarter I GDP compared to 9.1 per cent in USA and 9.7 per cent in Brazil. Most experts have suggested an overall contraction of ten to eleven per cent is likely to take place in this financial year.

Far more worrying is the impact the pandemic has had on the workplace. We, in this House, have seen how many MPs have now been infected. New cases are coming in every day. Let us face it that at least, we have a job thanks to our voters. We were already suffering record levels of unemployment under this Government's watch ahead of the arrival of the virus, but estimates suggest

that the situation has further deteriorated with the Centre for Monitoring of Indian Economy pointing out that about 21 million salaried employees lost their jobs during April-August with about 3.3 million jobs being lost in August and 4.8 million in July. The total number of salaried jobs in the country at the end of the last month stood at 65 million, having come down from 86 million in the previous fiscal year, 2019-20.

घर-घर में अंधेरा है, कहीं बहार नहीं है, बैठे हैं युवा खाली, रोजगार नहीं है।

Now, admittedly, the global economy has suffered significantly as well but across the world, we have seen instances where Governments have actively implemented countermeasures to mitigate the economic devastation of the COVID 19 pandemic. The United Kingdom for instance had rolled out a furlough scheme, the Corona Virus Job Retention Scheme, which encouraged employers to not let go of the workers, 80 per cent of whose salaries would be supported by the Government. In other words, the Government would pay to ensure that you could keep your job. Our Government's announcement of a Rs. 20 lakh crore economic relief package has inspired little confidence particularly when its fine print shows that new fiscal support amounted to only Rs. 1.86 lakh crore which is less than one per cent of the GDP. Much of the package had already been included in the Union Budget for 2020-21 or merely facilitates people's own borrowings.

As a result, Respected Speaker, India has carved a worrying but distinctive position for itself. In their response to the COVID 19 pandemic, the nations of the world have three kinds of report cards. In a handful of cases, they manage to get on top of the virus and their economy also thrived. The majority of countries however have managed one way or the other. They managed either to mitigate the healthcare effects of the virus at the cost of their economy or have kept the engine of the economy running while suffering an onslaught of the virus. India, on the other hand, has become a poster child for the worst-case scenario. We have the worst of both worlds. We have neither managed to stop or limit the spread of the virus nor have managed to keep the economy afloat. The GDP for the first time in 41 years will actually shrink and our employment crisis has become even worse than before. Small and medium businesses have been devastated, trade has crashed and our foreseeable national economic prospects are dire. In a panicky over reaction to economic failure, the Government is unlocking the country even as cases are shooting up. A lockdown imposed when we had 564 cases is being lifted when we are inching towards 54 lakh cases or to be precise 53,08,014 as of yesterday. What greater indication can we have, respected Speaker, of the fourth failure of this Government!

It took 135 days to reach one million registered cases or ten lakhs in the country; three weeks after, for 20 lakhs; 16 days, for 30 lakhs; 13 days, for 40 lakhs, and now just 11 days, for 50 lakhs or five million. At this rate, we will cross

60 lakhs by next week. Numbers offer a sharp indictment of the failure of this Government's strategies to curb the transmission of the virus.

Most of the challenges we as a nation are confronted by today stem from the manner in which the present ruling dispensation governs. I am sorry to say that there has been minimal effort by this Government to reach out and consult with other stakeholders, particularly the State Governments and the Opposition before embarking on many of their flawed plans.

As early as in May, the Indian National Congress, along with like-minded Parties, had come together and offered a series of constructive suggestions to this Government which were invariably ignored at serious cost to our fellow citizens. Eleven suggestions were placed before this Government, including a direct cash transfer outlined by the Indian National Congress under its NYAY Programme, which would support distressed communities, free distribution of rations, free transportation for migrant workers, greater consultation with State Governments, and within Parliament a revised and enhanced financial relief package, a genuine fiscal stimulus.

I have no doubt, had the Government adopted some of these ideas and consulted with Opposition Parties, we could have been better placed to mitigate the spread of the virus. Instead, we have the fifth and final failure of this Government, a failure to recognise the merits of a deliberative democracy of not consulting but dictating, and of not governing but ruling. मैं अन्त में गरीब किसान के मुद्दे

पर सरकार को विशेषण करना चाहता हूं कि ये मुद्दा आप पिछले मुद्दों की तरह टीवी पर कुछ और दिखा कर भटका नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीब किसान टीवी नहीं देखते हैं ।

Anyway, the unfortunate reality today, Sir, is of an India where tokenism and lip service have taken precedence over concrete ideas and deliberative governance, where no honest effort is made to overhaul the infrastructure deficiencies despite which our frontline healthcare heroes have worked heroically even at the cost of their own lives, though the Government sadly says that it does not have any data about this. ...(Interruptions) Sir, I am concluding in one minute.

Through you, Mr Speaker Sir, I would like to express the thanks of this House to all the healthcare workers for their services to this nation.

It is also an India where students have been forced to risk giving examinations that are vital to their future, at a time when even Parliament, the temple of democracy, may wind up ahead of schedule because of the virus; an India where basic healthcare services such as immunization programmes have been disrupted, particularly in rural areas; an India where the electoral fate of upcoming State Assembly Elections have transcended our national priorities; an India where the virus has been used to promote another lockdown, a lockdown on individual liberties and freedoms, as the activists who have been arrested under the draconian UAPA have realised.

To those in Government, let me say that there is still time left for you to recognise the follies of your current approach. While thanking all my colleagues in

this House for having braved this *Mahammari* in the service of this Parliament, I urge this Government to become more transparent in their functioning, to gather and release data to experts where required, to consult with all stakeholders before acting, and ultimately to take this nation into confidence because it is losing confidence in you, the Government.

Through you, Sir, I would like to assure the young people of this country that this Parliament will stand with them and their future. We will continue to argue for the best possible practices and policies so that we can overcome this crisis. I hope, Sir, this House will seriously offer suggestions to the Government, as I have done in my remarks, that might help it undertake a much-needed course correction.

Thank you, Mr Speaker. Jai Hind!

माननीय अध्यक्ष: डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी ।

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी जो कि एक वैश्विक महामारी है । यह केवल भारत का कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लोग इससे जूझ रहे हैं । आपने मुझे लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर में इस मुद्दे पर बोलने की अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं विशेष आभार अपनी पार्टी के नेतृत्व पर भी व्यक्त करता हूं । पार्टी के नेतृत्व ने ऐसे मसले पर मुझे पार्टी की ओर से बोलने की अनुमित दी है, उसके लिए मैं अपने आपको गौरवशाली मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सांसद होने के साथ-साथ, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, सर्जन हूं और एक डॉक्टर भी हूं । मेरी मेडिकल कार्यावधि करीब पांच दशक, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस करीब 50 साल पुराना है । इस दौरान मैंने कई सारे मेडिकल चैलेंजेज़ देखे हैं । मैंने कई सारी ऐसी महामारियां और बीमारियां देखी हैं, चाहे वह प्लेग, कॉलेरा, डिफ्थीरिया, टीबी, स्वाइन फ्लू या जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियां हों । मगर हम इस बार कोरोना महामारी के सामने जूझ रहे हैं । मैं समझता हूं कि हम सब पर यह आपदा आ गई है । मैं समझता हूं कि यह एक असामान्य स्थिति है ।

मैं समझता हूँ कि यह एक असामान्य परिस्थित है । यह एक अनिप्रसिडेंट महामारी है । इस महामारी के प्रति न केवल भारत, बल्कि विश्व के सभी देश चाहे वे कितने भी विकसित देश हों, सभी अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं । मेरे मित्र और कांग्रेस के विश्व सदस्य डॉ. शिश थरूर जी अभी बोल रहे थे और वे इस महामारी के लिए सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे, मैं उनको आइना दिखाना चाहता हूँ कि इस महामारी के कारण चाहे कितने भी बड़े लोग हों, कितना ही बड़ा देश हो, अमेरिका जैसा देश हो, जापान जैसा देश हो, इटली जैसा देश हो, इंग्लैंड हो या यूरोप के देश हों, ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश के लोग इस अनिप्रसिडेंट महामारी के कारण अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं ।

16.51 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

भारत में हमारा जो नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जन-नायक श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों में लेकर, स्वयं सरकार का मार्गदर्शन करके जिस प्रकार से अपने नेतृत्व का परिचय दिया है, सही अर्थ में इस समय नरेन्द्रभाई मोदी जी महानायक हैं । जिस प्रकार से, लोगों ने इनकी बात को स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ, शिश थरूर जी जा रहे हैं, उन्होंने अपने नेता का जिक्र किया, उन्होंने इस सदन के जो सदस्य हैं और कांग्रेस के जो पूर्व प्रमुख हैं, उनका जिक्र किया । उन्होंने बताया कि हमारे नेता ने फलां-फलां दिन इसको अवगत कराया था । वे हर दिन कुछ ट्वीट कर रहे थे । आज जब सदन कोरोना की महामारी के बीच में बैठ रहा है और जिन संयोगों में बैठ रहा है, मैं समझता हूँ कि सभी सांसद चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वे अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझकर सदन में चर्चा के लिए उपस्थित रहे हैं । ये अपने जिस नेता की बात करते हैं, हमेशा इस सदन को स्किप करके चले जाना, उनकी परम्परा रही है । मैं समझता हूँ कि हमारा नेतृत्व नरेन्द्रभाई मोदी जी के नाम पर न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने नेतृत्व की एक पहचान दिलाई है ।

कोरोना महामारी की चपेट में जब पूरा विश्व आया था, तब नरेन्द्रभाई मोदी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पहचान दिलाई और जो निर्णय उन्होंने लिये, चाहे लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे जनता कर्फ्यू का निर्णय हो, चाहे अन्य निर्णय हों । उन्होंने अलग-अलग निर्णय लेकर स्वयं उसका नेतृत्व किया है । मैं भारत सरकार और आरोग्य मंत्रालय के मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही संतोषप्रद तरीके से हम आगे हैं । इस महामारी के कारण भारत भी परेशान है । हमारी परेशानी की वजह इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ की जनसंख्या से ज्यादा का देश है । विश्व में जनसंख्या के आधार पर हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है ।

जहाँ तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या इसमें किमयों की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है, उसे साथ रखकर इस प्रकार की महामारी में आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ कि इसमें एक नेतृत्व का परिचय ही आगे बढ़ सकता है । इतनी असुविधाएँ होते हुए भी हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ निर्णय लिये । उन्होंने निर्णय लिये और पूरे देश ने इस निर्णय को स्वीकार किया । मुझे पता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक नारा दिया था, जब देश में चावल की कमी थी, तब उन्होंने कहा था कि लोग सोमवार के दिन चावल न खाएं और लोगों ने स्वयं ही चावल को तिलांजिल दे दी थी । इसके बाद अगर कोई नेता है, जिनके कहने पर देश के लोगों ने उनकी बात मानी है, चाहे एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की बात हो या इतनी बड़ी महामारी के कारण लॉकडाउन का पालन करने की बात हो, जिसे बहुत ही डिसिप्लिन से पालन किया गया है, तो नरेन्द्र मोदी जी ही दूसरे ऐसे नेता हैं, जिन पर लोगों का विश्वास आज भी है ।

मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी देश की जनता नरेन्द्र मोदी जी के साथ खड़ी है, नरेन्द्र मोदी जी पर उनको पूरा भरोसा है । इस भरोसे के कारण लोग आज भी नरेन्द्र मोदी जी का समर्थन करते हैं । मोदी जी जो भी बात करते हैं, जनता उसे स्वयं ही उठा लेती है और मोदी जी के साथ जुड़ जाती है । मैं इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं ।

सभापति जी, हमारे सदन में आज इस महामारी पर चर्चा हो रही है । मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ठोस कदम लिए, उन्होंने जो लॉकडाउन का निर्णय किया, वह लॉकडाउन का निर्णय भारत जैसे देश में करना, मैं मानता हूं कि it was next to impossible, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को सारी जनता ने उठा लिया, लोगों ने उठा लिया और लोगों ने उस लॉकडाउन में कोऑपरेशन दिया, वे स्वयं अपने घरों में बैठे रहे । मैं समझता हूं कि उनको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है,

मगर फिर भी लोगों ने नेतृत्व को सलाम किया है, वे नेतृत्व के साथ रहे हैं । मैं भारत सरकार, आरोग्य मंत्रालय, हर राज्य सरकार, जिसने इस लड़ाई में नेतृत्व किया है, लड़ाई में अपना जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं, मगर मैं विशेष बधाई कोरोना वारियर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज़, हेल्थ-कर्मी, सफाई-कर्मी, सिक्योरिटी दल के लोग, बायोमेडिकल वेस्ट्स के स्टाफ, आशा वर्कर्स, सब लोग कहीं न कहीं, इस महमारी के चलते इनके संपर्क में आते थे और संक्रमित होते थे, वे खुद संक्रमित होते थे।

आज मेडिकल एसोसिएशन का जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक सैंकड़ों डाक्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, फिर भी ये लोग इस महामारी से जूझते रहे हैं । एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस पर गर्व करता हूं । प्रधान मंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स को जिस प्रकार सम्मान दिया, चाहे उन पर पुष्प वर्षा करने का कार्य हो, चाहे उनके लिए कानून बनाने का कार्य हो, कि ऐसी महामारी में अगर कोई उन पर हमला करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी । इसके लिए भी मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं ।

हम मानते हैं, हमने देखा भी है कि युद्ध सीमा पर लड़ा जाता है । जब हमारा जवान युद्ध लड़ने जाता है तो उसके हाथ में गन होती है, उसके हाथ में बहुत शस्त्र होते हैं, मगर यह वैश्विक महामारी एक ऐसा युद्ध है, जो सीमा पर नहीं लड़ा गया, बिल्क हॉस्पिटल में लड़ा गया । जो लोग जहां निवास करते हैं, उनके बीच में लड़ा गया । इस युद्ध में लड़ने वाला सैनिक डॉक्टर, नर्स और हैल्थकर्मी था । उन्होंने सफेद एप्रिन पहना था, नर्सेज़ ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी और उनके पास स्टैथोस्कोप थे ।

सभापित जी, मैं समझता हूं कि यह युद्ध बहुत ही अजीब प्रकार का युद्ध था और इस युद्ध में जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स ने काम किया है, मैं उन सभी आरोग्य कर्मियों को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । इस महामारी में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई डॉक्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, मैं उन सभी को आपके माध्यम से श्रद्धांजिल अर्पित करता हूं । इस बीमारी से जिनका

निधन हुआ है, मैं चाहता हूं कि परम कृपालु परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे । जहां तक भारत सरकार के कदमों का सवाल है, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, उसका उद्भव चीन के वुहान प्रदेश से हुआ था । वहां से वह महामारी के स्वरूप में पूरे विश्व में फैला है । इसमें चीन की भूमिका शंका के दायरे से परे नहीं है । कोरोना महामारी की शुरुआत नवंबर, 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी । चीन ने उस वक्त डब्ल्यूएचओं को बताया था कि हमारे यहां एक ऐसी बीमारी फैली है, एक इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटिड न्यूमोनाइटिस हो रहा है, जो हमारी समझ से बाहर है और उसकी मोटैंलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं, on 17 January, 2020 Ministry of Health and Family Welfare ने कोरोना वायरस के बारे में प्रथम पुष्टि की और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू किया ।

17.00 hrs

उसके पहले भारत सरकार ने 7 जनवरी, 2020 को टेक्निकल ग्रुप की पहली मीटिंग की थी । हमारे मित्र बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है । मैं समझता हूं कि विश्व में जो पहला निर्णय लेने वाला देश है, उसमें भारत है और उसका मार्गदर्शन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी करते थे । उसको 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने महामारी के रूप में घोषित किया था । सरकार ने 8 जनवरी 2020 को स्थिति की मॉनिटरिंग तथा फॉलो-अप एक्शन करना शुरू किया था । भारत सरकार द्वारा चाइना तथा हांगकांग से आने वाली उड़ानों के लिए 18 जनवरी से थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई थी । भारत सरकार द्वारा कई सारे निर्णय लिए गए थे, चाहे वह सर्वेलांस का निर्णय हो, at the point of entry and at community level; focus on logistics; ensuring diagnostic support and ensuring availability of organisational health facility; ensuring availability of trained and oriented health staff; and, most importantly, managing this community since their

involvement is paramount in the management of infectious disease. This is a very highly infectious disease. भारत सरकार ने लोगों को सूचना दी थी कि लोग मास्क पहनें, लोग फिजिकल दूरी बनाए रखें, दो गज की दूरी बनाए रखें और लोग साबुन से हाथ धोया करें, क्योंकि यह जो कोरोना वायरस है, उस वायरस का जो वॉल है, that is made up of fat. अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वह फैट डिसइंटीग्रेट होता है और वायरस नष्ट होता है । भारत सरकार की ओर से इस प्रकार के कई सारे सुझाव दिए गए । लोग इकट्ठा न हों, इसलिए लॉकडाउन किया गया । इसके अलावा अन्य कई उपाय किए गए, लेकिन हमारे मित्र बोलते हैं कि हमारी सरकार पीछे जागी है । Ours is amongst the first of those countries to have come out with a concrete decision in this direction.

हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस प्रकार से डिसीज़न लिया है, चाहे वह टेस्टिंग का डिसीज़न हो या अलग-अलग डिसीजंस हों, हमारे देश में बहुत ही सटीक तरीके से निर्णय किए गए हैं। हमारी सरकार की ओर से रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, नेशन वाइड पूरी तरह से उड़ाने बंद कर दी गई थीं। पूरी तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग न जा सकें, इस प्रकार से बॉर्डर्स सील किए गए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया गया।

इसमें इकोनॉमिकल बर्डन की बात है, इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट की बात है । एक हेल्थ का साइड इफेक्ट होता है और एक इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट होता है । इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट के लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए और वह पैसा बांटा भी गया । वह पैसा लोगों के बीच में गया । इसमें इंश्योरेंस कवर किया गया । 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' में जो हेल्थ वर्कर्स थे, उनके लिए 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया गया ।

मैं अहमदाबाद से आता हूं । अहमदाबाद में कई नर्सेज और डॉक्टर्स का इस महामारी के चलते ट्रीटमेंट करते-करते निधन हुआ है, उनको सरकार की ओर से 50 लाख का चैक दिया गया है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच किलोग्राम अन्न देने का काम था, क्योंकि लोगों को अनाज मुहैया कराना था । इसमें खासकर गरीब और मार्जिनेलाइज्ड लोग, जो पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को पांच किलोग्राम गेहूं या राइस और एक किलोग्राम प्रेफर्ड पल्सेस नि:शुल्क तौर से दी गईं । वे लोग चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन हों या एबव पॉवर्टी लाइन हों, उनको 3 महीने तक राशन दिया गया था । प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक ऐसे लोगों को अनाज देने का जो निर्णय किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील निर्णय है । वूमेन अकाउंट्स होल्डर में 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' के अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह अप्रैल और जून के बीच दिए गए । मेरे यहां का एक मतदार है, वह गरीब है । वह अपनी पासबुक लेकर मेरे पास आई ।

साहब, मेरी पासबुक में यह पैसा कहां से आया है? उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के ज़रिए भारत सरकार ने उस गरीब महिला के जनधन खाते में 500 रुपया प्रति मास भेजा था । यह सब भारत सरकार ने देश की गरीब महिलाओं के लिए किया है । इसमें पूअर लोगों और फार्मर्स के लिए किया है । According to the Ministry of Finance, between 26 March and 22 April, 2020, approximately 33 crore poor people have been given financial assistance worth Rs.31,235 crore through bank transfer, direct benefit transfer. यह पैसा मोदी जी की भारत सरकार ने दिया है, मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं । इसमें किनको फायदा मिला है? इसमें उन विधवाओं, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और और फार्मर्स को फायदा मिला है । In addition to direct bank transfers, other forms of assistance have also been initiated. These include the following: 40 lakh metric tonnes of food grains

have been provided to 36 States and union territories; 2.7 crore free gas cylinders have been delivered to the beneficiaries; and Rs 3,497 crore has been disbursed to 2.2 crore building and construction workers. The Fund was managed by State Governments. जो फाइनैंशियल मैज़र्स लिए गए हैं, including extension of dates for payment of taxes for relaxation in norms ईएमआई भरने के लिए एक्सटेंशन दिया गया । इंटरेस्ट और पेनल्टी भी उनसे नहीं लेने का प्रावधान किया गया । PM CARES Fund के ज़रिए गरीब लोंगों. खास तौर से जो कोरोना से पीडित हैं. उनके लिए प्रधान मंत्री जी की ओर से. जहां भी वेंटिलेटर या दवाइयों की जरूरत है, दी गयी हैं । Under relief given by the Reserve Bank of India, there are many reliefs given to the borrowers in repayment of loan. एमपीलेड स्कीम के जो हर साल पांच करोड़ रुपये मिलते थे, all the funds are diverted to fight Coronavirus. There was a reduction of allowances of MPs and Ministers by 30 per cent. अपना अलाउंस स्वयं ही उन्होंने कम कर दिया है । यह एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किया गया है । फ्रीज़िंग ऑफ डीयरनेस अलाउंस किया गया और इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी से जुझने में किया गया । हेल्थ पर मैंने बोला कि the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated ताकि कड़े प्रावधान के साथ इस महामारी से हम लंड सकें।

जहां तक टेस्टिंग का सवाल है । कई लोग कहते हैं कि देश में टेस्टिंग कम होती है । Till today, around five crore tests have been done. करीब 1.33 करोड़ टेस्ट पिछले दो हफ्ते में हुए हैं । भारत सरकार की कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए एक पॉलिसी रही है- टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट । इन तीनों के जिए हम कोरोना महामारी को समाप्त करना चाहते हैं । ट्रैकिंग के बारे में हमारे मंत्री जी ने जो कहा था, वह वाक्य मुझे आज भी याद है कि करीबन पूरे देश में 40 लाख

लोग ऐसे हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं । ट्रैकिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोरोना के सम्पर्क में आ गया तो वह उसकी ट्रैकिंग करता है । कितने लोगों से वह मिला, उसकी फोन से ट्रैकिंग करते हैं ।

इस प्रकार से कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे काबिले तारीफ हैं । मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं ।

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए ।

...(व्यवधान)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: महोदय, मैं थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा । Restriction of export of medicines and medical equipments, जो कोरोना के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, उसे पहले अपने देश में रखना और उसको रेस्ट्रिक्ट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है । चाहे वह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का निर्णय हो । ऐसे कई सारे निर्णय लिए गए हैं । अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि हमारे यहां कोरोना के बहुत सारे केसेज़ हो रहे हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि this is a highly infectious disease. अगर इस संक्रामक रोग की वजह से परिवार का एक व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, तो उस परिवार के सभी व्यक्तियों को संक्रमित होने का पूरा भय रहता है । इस पर एलीगेशन करके निकल जाना यह कोई ठीक बात नहीं है । हमने इस बात को कैसे टैकल किया है, अमेरिका जैसे देशों को भी बहुत मुश्किलें हुई हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टेस्टिंग का काम किया है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इसके लिए अलग-अलग प्रावधान किए हैं, मैं यह समझता हूं कि बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। लोगों ने भी इसमें बहुत कोऑपरेट किया है। ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां और भी कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि यह रोग कब जाएगा, यह किसी को नहीं पता है। न तो इसकी कोई दवाई है। आज भी चाहे कितने भी डाक्टर्स हों, चाहे कोई भी हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, उसके ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकाल होता है। लेकिन कोरोना के ट्रीटमेंट का कोई फिक्सड प्रोटोकाल नहीं है। कोरोना की

वजह से लोग अपने अनुभवों पर रह रहे हैं । मैं स्वयं कोरोना पॉज़िटिव हुआ था । मुझे भी पता है कि मैं 17 दिनों तक अपने घर में होम क्वॉरन्टाइन में रहा था । मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया था । मैं डॉक्टर्स के संपर्क में रहा था ।

मैं इसलिए भी भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि एक डॉक्टर होने के नाते, शुरुआत में यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉज़िटिव होता था, तो उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता था । मैंने मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी दोनों को ई-मेल किया था । यह सरकार इतनी सेंसिटिव है, जैसे ही उनको मेरा ई-मेल मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमैटिक हैं, हमारे यहां करीब 80 प्रतिशत लोग एसिम्प्टोमैटिक हैं । उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहिए । प्रधान मंत्री जी और सरकार ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया था ।...(व्यवधान) उसको कंट्रोल किया, क्योंकि इसकी वजह से दो बातें होती हैं । पहली बात यह है कि अननेसेसरी बेड आक्यूपेन्सी नहीं होती है । जो हेल्थ वर्कर्स हैं, मरीज उनको संक्रमित कर देता है, टेलीफोन के जरिए उनका ट्रीटमेंट करना है । अभी-अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप अपना उदाहरण दीजिएगा और बताइगा कि हमने क्या किया है । हमारे सभी कार्यकर्ता, सदन में बैठे सभी सम्माननीय सदस्य कोरोना महामारी के चलते लोगों की सेवा में व्यस्त रहे हैं ।

महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । एक सरोगेसी महिला थीं । उन्होंने अपने उदर में किसी का गर्भ रखा था । वह गुजरात और महाराष्ट्र के बार्डर पर थीं । दो दिनों के बाद उनका सिजेरियन होने वाले था । लेकिन उनको वहां एंट्री नहीं मिल रही थी । उनके एक परिचित डॉक्टर मेरे मित्र थे । उन्होंने हमें बताया । हमने कलैक्टर और प्रशासन से रिक्वेस्ट की, तो उनको वहां से आने की परमिशन मिली । दो दिनों के बाद उनकी सर्जरी हुई, उनका सिजेरियन हुआ और उनको एक बेटा पैदा हुआ था । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, before I start my speech, I should like to thank all the hon. Members of Parliament cutting across partylines who were so helpful in trying to get stranded people of Tamil Nadu back to our State and especially our External Affairs Minister Shri Jai Shankar who really helped our people who were stuck outside the country and ensured that they came back home.

Sir, before I start blaming the Government, I would like to just read a *kural* from Thirrukural. It says:

"Idippaarai Illaadha Emaraa Mannan

Keduppaar Ilaanum Ketum"

It means if a King does not have good advisors who stop him and tell him that you are doing wrong; do not do this, he will fall into ruin.

This is a perfect example for our Government where no one has the guts or courage to go and tell the Prime Minister that you are doing something wrong. His own Cabinet has not got the courage.

Sir, I would like to ask something. We realised on the 3rd of February that the first case of Coronavirus was reported in Kerala. We should have woken up. We should have closed our borders. We should have started the checking. But what did we do? We had 'Namaste Trump' event because Trump was coming. It was a big photo opportunity moment for our Prime Minister to take photos and videos in Gujarat and to show off. So, what happened? We gathered people.

When Coronavirus started to spread, we were gathering people and we had 'Namaste Trump' event. In fact, the Parliament was convened. It was supposed to be closed in a week's time because of Coronavirus. But what to do? A big coup happened.

In Madhya Pradesh, the Congress Government was falling and you wanted to take over the power there. So, there was silence. No one spoke about the Coronavirus. Even the Members of Parliament were not allowed to speak about Coronavirus because the Congress Government in Madhya Pradesh had gone to the Supreme Court. If the Parliament is closed and if the country is closed, then the floor test cannot be done. So, what did you do? The Members of Parliament were not allowed to talk.

Sir, on 18th March, in Rajya Sabha, our hon. ... * asked a Member, who was wearing a mask, to get out and come without the mask. That was the attitude of this BJP Government.

The same thing happened here on 19th. Sir, I have all the respects for the Speaker. I rose in the 'Zero Hour' to speak about the subject of Coronavirus but ... *

It was because of your careless attitude that the Coronavirus was brought to its peak in India. What else did we do? You had announced the lockdown by giving only four hours' time to the people. ...(Interruptions)

_

^{*} Not recorded

माननीय सभापति : मारन साहब, एक मिनट रुकिए । देखिए राज्य सभा के ... * के बारे में जो टिप्पणी की है, वह बिल्कुल गलत है । आपको नहीं करनी चाहिए । उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए । प्लीज़, ज़रा सावधान रहिए ।

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I spoke about the ... * and not about the ... * HON. CHAIRPERSON: No, you did.

Now, it is over. You should not have done this. You please proceed now.

SHRI DAYANIDHI MARAN: All right. Let me speak. I do not know why the lockdown was announced in four hours' time for the people to prepare. Whenever our Prime Minister comes on TV at 8 p.m. only bad news comes. In 2016, he came and announced demonetisation and made every Indian to stand in the queue before the banks to take their own money. Similarly, he announced the lockdown on 24th of March and asked us all to stay indoors. This is without even planning. There was no strategic planning with the States. The States were unaware of it. We never expected such a big lockdown. What happened? It is chaos.

Again, our Prime Minister comes at 8 p.m. and says, okay, now we are in a lockdown; I want all of you to clap your hands, as if we have achieved something. What have we achieved? Ask the ... * Do we have to say anything about them?

_

^{*} Not recorded

Instead of clapping their hands in their balconies, they all gathered on the roads, spreading the Coronavirus because the Prime Minister had asked them to clap.

The worst thing is that we had one of the Ministers phrasing the words. I should thank him because he phrased the words, 'Go Corona; Go Corona; Go'. This became such a trending thing. We should thank him because it was said in English. Thanks to him, he was popularising English. Usually, you will be popularising Sanskrit or Hindi but this was a trending thing. Sir, can Coronavirus go? Was that the scientific approach?

Then, our Prime Minister comes and says, light up a candle; light up our lamp. What did they do? Everyone, including all the ... * joined and started bursting crackers on the road as if we have won the Coronavirus war.

I have respects for the Prime Minister. Then, the Prime Minister says today

I am going to honour all the health workers; we are going to allow the Army to
send the helicopters to shower flowers on them. Sir, one doctor friend of mine
said, "What is wrong with the Prime Minister?" They are asking us to stand one
hour before the event in the Sun because the Prime Minister is watching it on
television. So, we have to come out. That could be utilised to save the patients
who are dying in the emergency wards

^{*} Not recorded

Sir, this is what I said; and *Thirukkural* says, you should have some good advisors in the Cabinet to ask the Prime Minister what he is doing is wrong. But there was not a single person.

I do not know what the obsession of our Prime Minister is with Donald Trump. In New York, the situation was bad. They did not have hospitals. They have ships. So, Donald Trump arranged the warships and converted them into hospitals. In India, we have enough space and you know what our Prime Minister did. He converted train coaches into emergency units. Does it make any sense? Do not we have enough Government's buildings, which could be converted into emergency units. What was the cause?(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am the only Member from my party to speak on this issue. They disturb me. There is a lot to speak.

HON. CHAIRPERSON: There are only five minutes allotted to your party.

SHRI DAYANIDHI MARAN: No, Sir. You should give me at least 10 minutes.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Okay, continue your speech. But conclude it.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, you should not stop me.(Interruptions) This is what happens. You do not allow people to tell the truth. Someone should say it. That is what the Opposition is doing.

Sir, I am asking what we did during that time. We had a fantastic lockdown, the strictest lockdown. Did we utilize it? We failed. At that time, the Corona cases were only in thousands. We could have used the opportunity to develop the infrastructure to ensure that lockdown is much stricter. But we lost the time. We lost the golden window. We let the Corona spread everywhere. Now, when the Prime Minister and the Cabinet realized that the economy is shut and there is no money coming, you went with the same speed and opened up everything. This is the biggest joke.

The hon. Member who spoke before me said that the Government gave money to the people. That is one of the biggest lies. I have not seen a single person who got the money. The companies could postpone their loans and repay their card payments later. But it never happened. In fact, banks never listened to the Finance Minister.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I have just three more points to raise.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, when our Prime Minister came to announce something in this regard, people had great expectations because when the Prime Ministers of Canada, U.K., Australia, New Zealand, etc. came and announced, they asked their citizens not to worry. They asked them not to send the employees back home. They announced to give to their employees 80 per cent of

salary for next six months. What did we do? The first thing that we did was we cut 30 per cent salary of all the Members of Parliament. This is a good thing. We are ready to give even hundred percent of our salary. The message that went down the line was, if the Prime Minister could cut their salary by 30 per cent, why should they also not do it. Every private company reduced the salary of their employees by 30 to 40 per cent and even made many of them jobless.

Sir, we are talking about people who are working in companies. But in India we have a big population of middleclass people, who all depend on daily earnings. There are families which depend upon one man's salary. People who drive autorickshaws and people who work in Uber, have been left in the lurch for six months. What happened? Instead of helping them, our Government started blaming the Muslims. They blamed the people of Tablighi Jamaat in an incident. It happened because the Malaysian Prime Minister had accused the Government. Our Government said that the Muslims were spreading Corona. In fact, we all know the case. It was not true. At the end of the day, what was its effect? We arrested them; we tortured them. What did they do? They tortured all the immigrant workers, who were in Malaysia. Most of the them were from my State of Tamil Nadu. They were unnecessarily harassed because of the wrong attitude of the Central Government.

My State has 10 per cent of the most affected cases. We are struggling.

Money is not coming from the Centre. People are not able to do it. But my leader,

Mr. M.K. Stalin started a programme called *Ondrinaivom Vaa*, that is, Let Us All Get Together.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN: I am just completing my speech.

We served food to one crore of people and about 44 lakh people have been benefited.

Sir, vaccine is the only cure. But we cannot say when the vaccine will come. Maybe it comes by the middle of the next year. But our economy has to go on. As we opened up the lockdown, people think that Corona virus has disappeared. People in villages think that everything is normal.(Interruptions)

At this time, I only want to say that we should be sending a good message.

People should be worried about it because Corona virus has not disappeared yet.

Thank you, Sir.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, first of all, I salute and express my deep condolence to all those COVID-19 warriors who lost their lives fighting against the most infectious COVID-19 disease. I also express my condolence to the families of all the deceased.

I also express my heartiest thanks to the hon. Speaker who has made all these arrangements - making a tremendous effort – for running the current Session of the Parliament. We can see all the arrangements.

Sir, before I go into the merit of the debate, let me tell the hon. Health Minister one thing. Yesterday or day before yesterday, he made a statement that Ayushman Bharat Scheme has not been extended by West Bengal. Sir, on 9th September, 2020, our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee, wrote a letter to the Health Minister, wherein she stated:

"On different occasions, it is heard that the State Government in Bengal is not implementing the Ayushman Bharat Scheme launched by the Central Government.

In this connection, it may please be appreciated that much before launching of Ayushman Bharat by the Central Government, the State Government in Bengal had already introduced 100 per cent free treatment, medicines and diagnostics for all in all government hospitals.

Subsequently, the State Government launched the Swasthya Sathi Scheme that not only provides 100 per cent free treatment, medicines and diagnostics to all in government hospitals, but also free treatment,

However, Ayushman Bharat Scheme may be extended by the Government of India with entire 100 per cent expenditure for the scheme. In such a case, the entire funding for the scheme may be routed through the State Government."

Sir, yesterday, unfortunately, the hon. Finance Minister made a statement that the figures of total migrant labour have not been given by the State of West Bengal. In reply to an e-mail received from Secretary (Rural Development) of the Central Government, the Principal Secretary (Rural Development) of West Bengal on 23rd June, 2020 – I would request Shri Rajnath Singhji, who is here, to take note of this – had sent details of the migrant labour to the Central Government. The total is 13,84,693 with Alipurduar – 13,075; Bankura – 32,842; Birbhum – 45,884; and Cooch Behar – 1,43,073;

Sir, I have got all the figures. I will just lay them on the Table, with your permission.

माननीय सभापति: आपने टोटल फिगर बोल दी है, वह काफी है।

SHRI KALYAN BANERJEE: Therefore, I say that the hon. Finance Minister is having a very closed mind towards West Bengal. The inclusion, which would have benefited 164 districts, has not been done.

Sir, in COVID-19, the West Bengal Government's overall situation is this. Total number of tests is 27,44,862. Total number of cases is 2,21,162. Number of active cases is 24,648. Total number of deaths is 4,298. Positivity rate is 8.9 per cent while it is 8.53 per cent for India. Discharge rate is 86.86 per cent while it is 77.93 per cent for India. Death rate is 1.94 per cent while it is 1.65 per cent for India.

Now, I come to the status of test facilities. There are 76 laboratories – 53 government laboratories and 23 private laboratories. Of the total RT-PCR tests, 81 per cent are being conducted in government labs and 19 per cent in private labs. Average daily testing is 45,000.

With regard to infrastructure for COVID-19, there are 92 dedicated COVID-19 hospitals – 37 government hospitals and 55 requisitioned private hospitals. In addition to the existing dedicated government COVID-19 hospitals, some private hospitals have also been taken.

Oxygen beds and ICU facilities are there. We have made safe homes for COVID-19 patients. We have made 200 beds also. Several special initiatives like medical experts group, protocol monitoring team, external expert teams, expert committee for testing COVID-19 patients, plasma bank, COVID warriors club, special help lines, and integrated help lines, have been taken. We have introduced a special insurance scheme also. No State Government has launched a special scheme for healthcare workers. Police, ambulance, drivers, etc. were provided with a provision of one-time assistance of Rs. 10 lakh in case of death and a Government job under the Special Employment Scheme. If any COVID-19 patient care provider gets infected with COVID-19, he is provided free of cost treatment and Rs. 1 lakh as compensation amount. Till date, death compensation at the rate of Rs. 10 lakh has been provided to the next of kin of 26 persons who have died.

Insofar as the migrant workers are concerned, during the period of lockdown, in total 15.4 lakh migrant labourers came to West Bengal from various States, such as Kerala, Maharashtra, Delhi and Tamil Nadu.

We scheduled and received 326 special trains and hundreds of special State Transport buses. We had set up around 1,524 relief camps. We have also facilitated movement of around 4.5 lakh migrant labourers stranded in West Bengal to their home States by scheduling a large number of special trains.

Direct financial assistance was provided to stranded migrants through a special programme called 'Snehar Paras'. Under this Scheme, Rs. 36 crore were debited to bank accounts of around 4.6 lakh stranded labourers.

'Pracheshta' was another scheme for providing financial support to internally stranded labourers of West Bengal. Under this Scheme around 2.5 lakh persons were covered. Around 302 special quarantine centres were set up.

The Government has not taken much administrative measures to fight COVID-19. The Central Government should have done it. This is the biggest pandemic that has ever affected the world and it has caused a number of problems and a consolidated loss of livelihoods. COVID-19 infection is a cause of concern for the whole world. We have to fight it out unitedly.

I would request the Minister of Health and Family Welfare not to give the credit only to the Prime Minister. Please give credit to the entire nation. All health workers, COVID-19 workers, all Chief Ministers, should be given the credit. They

are all fighting against it. So, do not take only the Prime Minister's name. Take their names as well.

This Government wasted golden months to prevent COVID-19. The World Health Organisation first warned in December 2019 and said that China is spreading a mysterious pneumonia in the neighbourhood of India. Our Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, in March told, "I have asked the Centre to stop all international flights immediately." But this was not heard. Moreover, West Bengal is the first State in the country that started the first boundary sealing from 23rd March, 2020.

As on 19th September, our country has crossed the 54-lakh mark in respect of confirmed cases of corona infection with recovery of 43 lakhs of people. The spread of corona infection in Dharavi was a cause of concern for the whole country.

Today, I am not going to blame anyone. This is not the time to play blame game. This is the time when we should fight together and we should recognise the contribution of each and every one. The Central Government should recognise the work done by the State Governments and the State Governments should recognise the work done by the Central Government. That should be the approach.

I heard the speech of hon. Prime Minister. The Prime Minister stated that this is the fight of the entire nation. But unfortunately, our Minister of Health and

20.09.2020 733

Family Welfare has made it look like that this fight is being fought only by the

Prime Minister. It is not correct.

It is not correct. Even if the Prime Minister comes, he will never say that this

is the fight only by the Central Government. He will say that this is the fight for the

entire country.

Sir, all steps have been taken; everything has been done regarding the

problem of the conditions of the hospital. We do not know when this COVID-19

will be stopped. We together will have to fight beyond all politics, beyond all big

blames.

Sir, the person, yesterday, fixed up a match game for showing West Bengal

in a poor light. Today, I have given the answer. We have given information

regarding migrant labourers. The person, who did it, has never gone to his district.

He was in Delhi for five months. He is giving big, big speeches and bytes. His

name is ... * ... (Interruptions) who has never gone there ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, no.

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes. Maybe he has not gone there.

माननीय सभापति : यह एक्स्पन्ज हो जाएगा ।

माननीय सदस्य. आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

* Not recorded

SHRI KALYAN BANERJEE: No assistance was rendered by him ...(Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अभी आप ब्लेम गेम के लिए मना कर रहे थे । No blame game please.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, the crucial problem is fund. The fund is required. We not getting the share of GST. We are not getting any tax money. Therefore, this fund is required for meeting expenses on COVID-19. Even rupees one crore from my MP Local Area Development Fund has not been released yet.

Sir, therefore, I will request through you to the hon. Speaker. Hon. Speaker is inside. Kindly hear my voice. I will request you and also the hon. Speaker, Sir, that funds should be given to the States from the PM CARES Fund also. You should give it. Why will you not give it to the Chief Minister? Why will you not give it to all the States? Why should it be the discretion of some people only?

To fight the COVID crisis, the Central Government should pay the GST arrears to the State Governments which are already under tremendous financial burden, as they are not getting their due GST share.

Prime Minister always says 'न खाऊँगा और न खाने दूँगा ।' Then, why is there so much secrecy to publish the donors' name in the PM CARES Fund? ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, just two minutes. The present need is development. We are in the midst of the biggest economic crisis the world has ever seen. This pandemic has devasted economies around the world including the global trade.

The Indian economy mainly depends on manufacturing, services sector, exports, and foreign investment; and all of these four pillars, on which the Indian economy rests, are hit hard. So, the priority of the Government should be to ensure soft landing of the economy and livelihood during this inevitable contraction.

I request the hon. Finance Minister to review her views, taking the correct facts and allot the money to the State of West Bengal. Thank you, Sir, for giving me the chance.

माननीय सभापित: जो भी माननीय सदस्य इस विषय पर लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें । हमारे बहुत से माननीय सदस्य ऐसा चाहते होंगे, इसलिए वे इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this special discussion on the COVID-19 pandemic.

Sir, post lockdown of the country, the Central Government's approach of balancing lives and livelihoods has been much appreciated. By conducting regular meetings with Chief Ministers to discuss strategies to reduce the spread of COVID-19, hon. Prime Minister has also united the country emotionally.

Sir, in the wake of the unprecedented crisis, India has been able to work on its previously untapped potential. We have started to emphasise more on Indianmade goods and digital services which will help us to an extent.

The economy that was already slowing down has been affected badly due to it and we have come to see a decline of all economic indicators like never before. The supply chains are affected; exports have declined due to the global effect of the pandemic; and the domestic demand is also much lower than normal. The GDP growth rate is expected to remain in the negative territory as confirmed by the RBI Governor.

In this context, I have to mention about a few dynamic activities undertaken by our Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, in the State of Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh Government's strategy has been three-pronged, which effectively reduced the health suffering and also economic suffering of the people.

As regards testing for COVID-19, today Andhra Pradesh is testing more than 72,000 people per day, which has made it rank first in tests per million amongst the States with a population of more than three crore. As regards treatment for COVID-19, in our State of Andhra Pradesh, any one tested positive can get themselves treated cashless under YSR Aayogyasri Scheme under which patients with an annual income of up to Rs. 5 lakh are given free COVID-19 treatment. Further, to assist the patients, a system of help desks staffed by *Aarogya Mitras* have been setup.

The Andhra Pradesh State Government has planned to spend Rs. 15,337 crore for the entire State healthcare infrastructure. In the first phase itself more than 4,900 health sub-centres -- out of the total 7,458 health sub-centres -- will get new buildings while the rest 2,552 will be modernized. This will be the highest amount spent by any State on healthcare in the country. These best practices, which I have mentioned above and which are being implemented in our State of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, may be replicated throughout the country to efficiently fight the pandemic. Our Government has also provided hundreds of high-tech ambulances at every 50-kilometre radius in our State.

A wide cash transfer scheme should be in place at the Central-level like the one existing in Andhra Pradesh wherein the YSR Congress Party Government has also allocated Rs. 37,000 crore for several Direct Benefit Transfer schemes

such as YSR Pension Scheme, YSR Aasara, AmmaVodi Scheme and YSR Rythu Bharosa. The allocation for the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Castes is Rs. 1,800 crore and Rs. 7,500 crore respectively while the allocation for the welfare of Backward Classes is Rs. 23,400 crore. Our Government has also released Rs. 960 crore as incentives to MSME units under the Restart Package. All these schemes have helped the downtrodden and Below Poverty Line people to survive through the lockdown and also through the economic slowdown.

Before I conclude, I would like to mention that be it 1991 or 2008, India has always risen to the occasion of a crisis and the pandemic would be no different. I am also sure that India would return to the same-as-before situation or rather better-than-before situation and be a much better world. Thank you very much.

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): कोविड-19 के बारे में चल रही नियम-193 के अंतर्गत हो रही बहस में मैं अपनी बात रख रहा हूँ ।

कोरोना महामारी पूरी दुनिया से ले कर अपने देश में फैली है । कोरोना महामारी का मुकाबला केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, लेकिन यह महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है ।

कोरोना महामारी बढ़ने के कई कारण हैं । सरकार द्वारा सूचना देने के बावजूद लोग सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं । कई सारे लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं । इसका परिणाम सार्वजनिक तौर पर सभी को भुगतना पड़ता है ।

लॉकडाउन के पहले जब पहला मरीज 21 जनवरी को केरल में मिला, उसके बाद महाराष्ट्र में दूसरा मरीज फरवरी में मिला, तबसे कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती गई । तब 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई । लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले विभिन्न देशों से हवाई मार्ग से 75 हजार यात्री देश में आए और समुद्र मार्ग से 15 हजार यात्री देश में आए । इन सभी यात्रियों को अगर उसी समय क्वारंटीन करते तो कोरोना महामारी का आज का कहर निश्चि रूप से नहीं होता ।

दूसरी सबसे बड़ी गलती सरकार से यह हुई कि मरकज तबलीगी जमात का दिल्ली में एक जगह आए थे और यह सभी तबलीगी देशों के विभिन्न राज्यों से और विदेशों से भी आए थे । लॉकडाउन घोषित होने के बाद ये सभी वापस अपने-अपने राज्य में चले गए । इस तबलीगी की वजह से कोरोना का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ ।

दूसरे लॉकडाउन में लाखों मजदूर पैदल अपने घरों को जा रहे थे । लॉकडाउन की वजह से उनको कोई सुविधा नहीं थी । लेकिन दिल्ली में इकट्ठा हुए तबलीगी जमात अपने राज्य में कैसे पहुंचे, यह जानकारी सरकार को नहीं मिली ।

_

Speech was laid on the Table.

कोरोना महामारी के काल में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और कई सारे बेकार हुए छोटे दुकानदारों से ले कर बड़े व्यापारी संकट का सामना कर रहे हैं, इसको सुधारने में काफी वक्त लगेगा ।

लॉक डाउन के वक्त मजदूरों का बहुत बुरा हाल हुआ । कई किलोमीटर पैदल चल कर मजदूर अपने गांव चले गए, इसमें किसी का दुखद निधन भी हुआ । अगर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने में चार-पांच दिन का समय मिलता तो निश्चित रूप से मजदूरों का हाल ऐसा नहीं होता और कोरोना भी नहीं बढ़ता ।

लॉकडाउन खुलने के बाद हर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है और अनेक गांवों में इसी कारण कोरोना की महामारी चली गई है ।

देश में आज भी कई सारे जिले तालुका और गांव हैं, जहां आज भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है । यह आज तक की सभी सरकारों की किमयां हैं । मेडिकल, हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है ।

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है । आज भी महाराष्ट्र में रोजाना 23 से 25 हजार कोरोना के मरीज पाए जाते हैं । मैं जहां से आता हूँ, वहां पूना, पिंपरी चिंवड में रोजाना 5 हजार के करीब कोरोना के मरीज मिलते हैं । यह चिंता की बात है ।

महाराष्ट्र सरकार ने आज तक इस कोरोना महामारी का मुकाबला किया है । मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को धन्यवाद देना चाहता हूँ । एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी धारावी में जब कोरोना का फैलाव हुआ, उसे काबू में लाया गया । आज भी महाराष्ट्र सरकार कोरोना के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक सितम्बर से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को दी जानी वाली मेडिकल मदद बंद कर दी है । महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है । कई मरीजों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पाते । अगर केंद्र सरकार मेडिकल सहायता और कोरोना सेंटर बनाने के लिए मदद करती तो मरीजों का समय पर उपचार होगा और इस महामारी को रोका जा सकेगा ।

*श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अब जबिक कोरोना महामारी अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में भी दूसरे स्टेज की ओर अग्रसर है तो सदन में व्यापक रूप से इस गंभीर विषय पर चर्चा होना आवश्यक हो जाता है ।

कोरोना महामारी के विकराल रूप को रोकने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन किया गया, परन्तु उसके परिणाम आशा से विपरीत रहे । अचानक से सब कुछ बंद होने की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया । रोजगार बंद हो गए और कुछ गलतफहिमयों के कारण प्रवासी कामगारों ने अपने गांव के लिए महानगरों से पलायन कर दिया ।

सरकार के हर अच्छे प्रयास के बावजूद महामारी कम नहीं हुई, बिल्क लॉकडाउन खुलने के तीन महीने बाद अब सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है । 18वीं शताब्दी में जब स्पेन से स्पेनिश फ्लू महामारी सारे विश्व में फैली थी, तो लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी । संक्रमण कम हुआ तो यूरोप में लॉकडाउन खोल दिया गया । सभी लोग बाहर आकर जश्न मनाने लगे और यही घातक हो गया । अब इस स्थिति का डर है, तो सरकार का इस पर सोचना अति आवश्यक हो गया है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सेंट्रल में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है, जहां बहुत संकरी गिलयां हैं । एक कमरे में कम से कम 5 से 10 लोगों का परिवार रहता है । वहां कई तरह की इंडस्ट्री है । वहां कोरोना का प्रकोप सबसे अधिक हुआ । लॉकडॉउन के समय मैं और मेरी टीम ने संकल्प करके धारावी में लोगों को जागृत किया । सैनिटाइजर की मशीनों द्वारा वहां छिड़काव किया गया । कोविड-19 के मरीजों के उपयुक्त इलाज के लिए एक डेडीकेटेड अस्पताल बहुत कम समय में स्थापित किया गया । लोगों को भोजन और दवाइयां वितरित की और हमारे संकल्प के कारण हमने उस क्षेत्र को सम्पूर्ण कोविड-19 से मुक्त किया, परन्तु लोगों का जीवन रोजगार कम होने की वजह से अभी तक राह पर नहीं आया है । इसके लिए मेरा अनुरोध है कि पीएम केयर्स फंड से धारावी के

Speech was laid on the Table.

उत्थान के लिए विशेष राशि का आवंटन होना चाहिए । रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार की मदद करने की आवश्यकता है ।

कोरोना वायरस का प्रकोप होने पर यह नुकसान का आवेग फिर से उभर आया । 24 मार्च को रात 8 बजे आनन-फानन में भारतीयों को घर के अंदर रहने का आदेश देने के बाद, सरकार ने राज्यों के बीच अर्थव्यवस्था को जैसे उप्प कर दिया । कार्यालयों, कारखानों, सड़कों, गाड़ियों, सीमाओं को बंद कर दिया, वह भी कुछ-चार घंटे के नोटिस के साथ ।

लाखों भारतीयों ने तुरंत अपनी नौकरी खो दी । कई कारखानों में, निर्माण स्थलों पर या शहरी घरों में काम करते थे, वे ग्रामीण भारत के प्रवासी थे । भुखमरी के डर के कारण शहर की झुग्गियों को छोड़कर लाखों शहरी बड़े शहरों से बाहर निकल गए, हताश होकर अपने गांव वापस चले गए । शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक एक ऐसा उलटा प्रवास हुआ, जिसे भारत ने कभी नहीं देखा था । इसने 1.3 बिलियन लोगों के इस देश के हर कोने में कोरोना वायरस को स्थापित कर दिया ।

शुरुआत में कोरोना वायरस ऐसा लगता था कि यह मुख्य रूप से एक श्वसन बीमारी थी, कई रोगियों को बुखार और ठंड लगना थी, कमजोर और थके हुए थे और बहुत खांसी हुई थी । हालांकि कुछ लोगों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखते हैं । जो लोग सबसे बीमार थे, उन्हें निमोनिया या तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम था और पूरक ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी । अब तक डॉक्टरों ने कई और लक्षणों और सिंड्रोमों की पहचान की है । अप्रैल में सीडीसी प्रारंभिक संकेत गले में खराश, बुखार, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द की सूची में जोड़ा गया । आउटडोर समारोहों में कम जोखिम होता है, क्योंकि हवा वायरल की बूंदों को फैलाती है और सूरज की रोशनी कुछ वायरस को मार सकती है । खुले स्थान वायरस को संकेद्रित मात्रा में निर्माण करने से रोकते हैं और सांस के साथ बाहर निकलते हैं, जो तब हो सकता है, जब संक्रमित लोग लंबे समय तक एक सीमित स्थान में रह कर संक्रमण को समाप्त कर फैलने से रोक सकते हैं ।

कोरोना वायरस मुख्य रूप से आपके मुंह और नाक से बूंदों के माध्यम से फैलता है, खासकर जब आप खांसते या छींकते हैं । उस उपाय का उपयोग करने वाले संगठनों में से एक सीडीसी इस विचार पर छह फीट की अपनी अनुशंसा को आधार बनाता है कि खांसी या छींक आने पर अधिकांश बड़ी बूंदें जो लोग बाहर निकाल देते हैं, वे छह फीट के भीतर जमीन पर गिर जाएंगी । लेकिन छह फीट एक जादुई संख्या कभी नहीं रही है, जो पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देती है । लेकिन हर समय एक मुखौटा रखें, जब आपको लगता है कि आप बहुत अलग हैं । अब इस पर पीछे मुड़कर देखें, तो कई अर्थशास्त्री भारत के इंटरलॉकिंग संकटों, सर्पिलिंग संक्रमणों और विनाशकारी अर्थव्यवस्था की जड़ का पता लगाने का प्रयास करते नजर आते हैं ।

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और अब कॉर्नेल में एक प्रोफेसर कौशिक बसु ने कहा- 2020 की दूसरी तिमाही में भारत की शर्मनाक स्थिति पूरी तरह से लॉकडाउन की प्रकृति के कारण है । यदि उनका कथन सही है तो यह गहन चिंता का विषय है और भारत सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है ।

भारत सरकार की वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के लिए अपने गरीबों को उठाने और अपनी सेना को अद्यतन करने के लिए देश की जनता के ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं को तीव्र आर्थिक संकट, संक्रमण और भयावहता के एक विस्तृत अंधेरे में डुबो दिया गया है । गहराते आर्थिक संकट की भयावहता आज देश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर स्पष्ट रूप से छाई हुई है । रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हैं । मजदूर काम न होने की स्थिति में अपने गांव को लौट गए हैं । आखिर इस सबका ज़िम्मेदार कौन है? देश की इस दयनीय स्थिति को सिर्फ कोविड को तो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता ।

आप इसे उन परिवारों के दुबले-पतले चेहरों में देख सकते हैं, जो साड़ी पर फिनिशिंग टच को सिलने का काम करते थे, लेकिन इतने कम व्यवसाय के साथ अब सब्जियों और दूध पर भी कटौती

कर रहे हैं । आप इसे खाली नाई की दुकान और मोबाइल फोन की दुकानों में देख सकते हैं, जो दुकानदारों ने अपने अल्प बचत के रूप में कुछ भी नहीं होने के लिए उजाड़ दिया है ।

कुछ समय पहले, भारत का भविष्य पूरी तरह से अलग दिखता था । इसने एक जलती हुई अर्थव्यवस्था पर गर्व किया, जो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रही थी, आधुनिक महामारियों का निर्माण कर रही थी और गंभीर भू राजनीतिक गोलाबारी कर रही थी । इसका उद्देश्य अपने लोगों को एक मध्यवर्गीय जीवन शैली देना था, अपनी पुरानी विंटेज सेना को अपडेट करना और एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बनना था, जो किसी दिन प्रतिद्वंद्वी चीन को काबू करने की सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन सकती थी ।

अब भारतीय अर्थव्यवस्था किसी अन्य प्रमुख देश की तुलना में तेजी से सिकुड़ गई है । कुछ अनुमानों के अनुसार, 200 मिलियन लोग गरीबी में वापस आ सकते हैं । इसके सामान्य रूप से जीवंतता में से कई खाली हैं, लोगों को उद्यम के लिए प्रकोप से भी डर लगता है ।

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लगाए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बहुत नुकसान हुआ, जो अब विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने और वायरस फैलाने दोनों बहुत तंग और बहुत छिद्रपूर्ण है । भारत में अब सबसे तेजी से बढ़ता कोरोना वायरस संकट है, जिसमें हर दिन 80,000 से अधिक नए संक्रमण सामने आते हैं ।

राष्ट्र के ऊपर अस्वस्थता का भाव रेंग रहा है । महामारी से पहले भी इसका आर्थिक विकास धीमा था । सामाजिक विभाजन व्यापक हो रहे हैं । धर्म और जाति विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, आंशिक रूप से एक दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया अभियान की वजह से जो वायरस फैलाने के लिए किसी एक वर्ग को दोषी ठहराते हैं । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चीन तेजी से भारतीय भूभाग में घुस रहा है ।

आज भारत में चिंतन करते समय विद्वान उदासीन होकर चिंतित हैं कि देश का क्या होने वाला है? किस दिशा की ओर भारत अग्रसर है । जीवित रहने की क्षमता को तोड़ा गया है और उसके टुकड़े हवा में ऊपर तैर रहे हैं । कोई नहीं जानता कि वे कहां गिरने वाले हैं या वे कैसे गिरने वाले हैं और कितना समाज को तोड़ने वाले हैं ।

भारत में अभी भी ताकत है । इसमें एक विशाल, युवा कार्य बल और तकनीकी जीनियस के oodles हैं । यह एक ऐसे समय में चीन के लिए एक संभावित विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष विश्व का अधिकांश भाग खुद को बीजिंग से दूर कर रहा है । लेकिन गलत नीतियों के कारण दुर्भाग्य से दुनिया में इसका कद फिसल रहा है । पिछली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 24 प्रतिशत तक सिकुड़ गई, जबिक चीन फिर से बढ़ रहा है । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह खोने की स्थिति में आ गया है । जाने-माने अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह संभवत: भारत की आज़ादी के बाद की सबसे खराब स्थित है । लोगों के पास पैसा नहीं है । यदि कोई बाजार नहीं है तो निवेशक निवेश नहीं करेंगे और अधिकांश उत्पादन के लिए लागत बढ़ गई है ।

देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुम्बई के कई मोहल्ले जहां कम वेतन पाने वाले कामगार रहते थे । वे खाली टिन की दीवारों से टकराते हुए गर्म हवा के झोंके बन कर रह गए हैं । कुछ साल पहले जब अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत क्लिप में विस्तार कर रही थी, तो इन स्थानों में किराए पर जगह ढूंढना मुश्किल था ।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम केन्द्र सरकार के साथ खड़े हैं, पर सरकार को महामारी की लड़ाई के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने के उपाय करने चाहिए ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): I would like to express my views on COVID-19 pandemic that is facing the country.

As we all know, the first case of COVID-19 was found in Kerala on January 30, 2020 and the first death due to COVID-19 was reported on March 11, 2020 in Kalaburagi district of Karnataka, which falls in my parliamentary constituency. It was marked as the country's first fatality from the global pandemic.

The first ever COVID-19 case was recorded in China last year. Since then the virus has spread around the world and in January, 2020 it was declared as pandemic by the World Health Organisation.

I would like to tell the Government that a research had revealed that India may record nearly 13 lakh COVID-19 positive cases by mid-May, if the spread of virus is not contained by taking stringent measures and implementing restrictions. India witnessed 1,01,139 COVID-19 cases by 18th May, 2020. Initially, it was considered that India was dealing well in containing the number of COVID-19 cases by maintaining social distance and thereby a constricted transmission of the disease during lockdown period.

I would like to say that both the Central Government and the State Government of Karnataka are working intensely to keep the number of COVID-19 positive cases minimum. The Government is taking all necessary steps – by involving public, medical associations, nurses, NGOs, police forces including

_

Speech was laid on the Table.

paramilitary forces - to combat the challenges and threat posed by this growing invisible pandemic war. The earnest efforts on the part of the frontline workers, especially the doctors, nurses, healthcare staff, sanitation workers, police personnel, volunteers with the active support of people of India, have resulted in making the treatment of the patients possible and thereby in controlling this pandemic.

In March, we started with only few testing centres performing less than 100 tests per day. On 18th September, India has conducted over 10,00,000 tests in a single day and is having as many as 1764 COVID-19 testing laboratories.

The Union Government has announced a Rs.20 lakh crore recovery package to revive our economy. A small component of this was allocated to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act as well.

I would like to mention that NREGA has offered opportunity to the migrant workers, who were forced to return to their homes jobless, to earn their livelihood. In Kalaburagi district more than 55,000 migrant workers, who were working in the Capital and other major cities, returned home and around 1.2 lakh workers moved within the State. From 1st April, 2020 to 15th September, 2020, under NREGA there has been a huge rise in creation of Job Cards, and as many as 98,424 people have been enrolled for getting new Job Card. Under MGNREGA, approximately 1,40,750 families have been benefitted. From 1st April 2020 to 15th

September, 2020, 42,63,404 man-days have been generated. This number itself shows how MGNREGA has brought changes in the livelihood of many families.

This pandemic has also seen a huge rise in the number of people who have taken agriculture as the primary occupation for their livelihood. In any case, agriculture is arguably the least affected sectors of the economy. It is seen as the only bright spot in an otherwise dismal economic state, which is poised to gain and is likely to lead the economy's revival process.

The bumper rabi harvest is a good sign but farm labour economy has been adversely affected. There has been a large-scale reverse migration of workers from urban and rural work destinations. This will, at least in the short run, add workers to the rural work force.

In the short run, wages are likely to remain sticky and we will witness a significant increase in demand for work under MGNREGA, especially in source areas which are invariably the poorest. If implemented well, MGNREGA can paly an important role in making sure that workers find work and contribute to improving agriculture sector's outlook.

MGNREGA has another important role which becomes particularly crucial in COVID-19 pandemic. By adopting best practices, it acts as a beacon for establishing the terms of engagement for hiring labour in rural areas. In making an *Atmanirbhar Bharat*, an additional Rs.40,000 crore has been allocated to MGNREGA for creation of jobs in India's hinterland. Earlier, in the Budget for this

financial year, the Government had allocated Rs.61,000 crore to MGNREGA. Thus, for the first time ever the total allocation made to MGNREGA, for any financial year, comes to over Rs.1,00,000 crore.

Finally, the effectiveness of MGNREGA as a tool for post-COVID-19 rural economic recovery will depend on three things:

- Whether the local administration is equipped to implement it as a demand-driven programme;
- 2. Whether village panchayats are well-equipped to take advantage of it, and
- Whether useful assets are created that will boost local agrarian economy.

With this, I would like to conclude my speech. Thank you.

माननीय सभापति: आपका इसलिए आभार कि आपने बिल्कुल ठीक समय-सीमा में अपना संबोधन पूर्ण किया । थैंक यू ।

श्री अरविंद सांवत जी ।

श्री अरिवंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय चेयरमैन सर, कोरोना के इस महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमित दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । 24 मार्च को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने रात 8 बजे लॉकडाउन घोषित कर दिया और रात को कहा कि 12 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा । 4 घंटे में मुंबई जैसे शहरों में हम अपने सामने देख रहे थे कि लोग रास्ते पर आ गए । यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं, आगे चलकर क्या होने वाला

है? यह भीड़, मतलब जो मानवीय अंतर रखने की, सोशल डिस्टेंस रखने की जो बात आ गई, उसकी धज्जी उसी दिन उड़ गई । उसके बाद में जो हुआ, वह आपके सामने है, पूरे देश के सामने है । लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि लॉक डाउन करने के बाद में मुंबई सबसे पहला शहर था, जो संक्रमित होने लगा ।

जिस समय इसकी घोषणा हुई थी, अगर लोगों को समय देते, लोगों को अगर रेल सेवा उपलब्ध होती कि वह अपने गांव जा सकते थे तो उनको पता होता कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है । मुंबई शहर का आंकड़ा केवल सैकड़ों में था, आज हमलोग लाखों में आंकड़ा देख रहे हैं, वह उस वक्त नहीं होता । दुर्भाग्यवश रेल सेवा उपलब्ध नहीं हुई ।

जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त जितने लोग रास्ते पर नहीं गए होंगे, उतने लोग भीड़ में मुंबई शहर के रास्ते पर आए, अपने-अपने गांव जाने के लिए चलने लगे । केन्द्र सरकार को उस वक्त खासकर रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया । उसके बाद में क्या हुआ, आप जानते हैं कि रेल पट्टरी पर खाने के लिए बैठे लोग भी रेल गाड़ी के नीचे आकर मर गए । कितनी मौतें हुई; घर जाते हुए लोगों की मौत हुई । हमसे कहीं न कहीं गलितयां हुई हैं । गलती हुई, बाद में जब रेल शुरू की, उनसे पैसे भरवाने लगे । मेरे राज्य की सरकार ने उस पर करोड़ों रुपये खर्च किया और प्रवासी मजदूरों को अपने-अपने घर तक भेजा ।

चेयरमैन सर, इस स्थिति में प्रवासी मजदूर गए । उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, दीया जलाओ, हमने सब कुछ किया । हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास था । आज भी विश्वास है । वह जो कुछ कहें, अगर उनका उद्देश्य सही है लेकिन उद्देश्य क्या है? लोगों को कोरोना से मुक्त करना है, लोगों को चालना देना है, लोगों को ऊर्जा देना है कि इससे लड़ना है । हम उस ऊर्जा के साथ गए ।

महाराष्ट्र के मुंबई में तब हालात बिगड़ने लगे । हालात इतने बिगड़ने लगे कि हमारे मुख्यमंत्री जो न कभी नगरसेवक हुए, न कभी विधायक हुए, ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए थे । उन्होंने जनता के साथ जो संवाद किया, उन लोगों के हृदय सिंहासन पर जाकर बैठ गए । उन्होंने छोटी- छोटी चीजें कहा, जो परिवार का मुखिया कहता है । वह सारे राज्य की जनता को समझाते थे कि हाथ धो लो, मुंह पर पट्टी लगाओ, घर से बाहर न निकलो । अगर जरूरत पड़े तो ही घर से निकलो, इतना सब समझाते थे । लोग खुश हुए कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो हमारे परिवार का ही मुखिया लगता है, जो हमारी चिंता करता है और हमें सावधानी बरतने को कहता है । ऐसे मुख्यमंत्री का काम बाद में शुरू हुआ ।

चेयरमैन सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त हमारे पास पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों में तीस हजार पांच-छह सौ बेड थे । पहला आक्रमण वर्ली में हुआ । वर्ली हमारे युवा नेता और राज्य के पर्यावरण राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे जी का चुनाव क्षेत्र है । आक्रमण होने के बाद कुछ भी समझ नहीं आया । वहां घनी बस्ती है, झुग्गी-झोपड़ी है । एक आदमी को हुआ, इतना फैला कि पूछो मत । हमारे आदित्य जी ने आगे आकर नेतृत्व किया । महानगरपालिका के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड ब्याज और एम्बुलेंस सेवा देने वाले लोग सभी लोग साथ आए, मदद करने के लिए एक कन्टेनमेंट जोन बना दिया, प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया । उसके बाद हर घर पर दस्तक लगाई ।

सर, मैं कोविड योद्धाओं की बहुत सराहना करता हूं, अभी उनके प्रति श्रद्धांजिल अर्पित की गई, यह सही है । जब लोग डर रहे थे तब वे लोगों के घर पर जाकर जांच करने लगे । जांच करते-करते उनको इसका पता लगा । हमने घोषणा की, Chase the virus and break the chain. इसे लेकर हम लोग महाराष्ट्र में आगे चलते रहे, घर-घर जाते रहे, जांच करते रहें, रोजना आंकड़े भी बढ़ते रहे । जैसे ही वर्ली के कोलिवाडा में हुआ, यह मछुआरों का एरिया है, उसी तरह धारावी में भी हुआ ।

कितने लोगों को पता नहीं, चैनल पर जो आता है वह कुछ भी बात करता है, न कुछ पता है न कभी देखा है ।

धारावी ढ़ाई सौ स्कवायर किलोमीटर का एरिया है, वहां कितनी आबादी है । सेन्सस की आबादी छह लाख है लेकिन नौ लाख लोग रहते हैं । जब धारावी संक्रमित हुआ तो क्या हुआ होगा, आप सोच सकते हैं? उस क्षेत्र में इतनी घनी बस्ती में हम लोग जाकर दस्तक लगा कर लोगों की जांच करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे, उनको खांसी आती है कि नहीं, यह सब देखते रहे । दूसरी तरफ संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा । बेड की कमी होने लगी । उद्धव साहब ठाकरे जी नेतृत्व करके एक नई संकल्पना लाए, उन्होंने कहा कि हम फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे ।

15 दिन में 1000 बैड्स का फील्ड अस्पताल वैंटीलेटर और आईसीयू बैड्स के साथ बना दिया । बाद में नेस्को ने गोरेगांव, वाएकला, वर्ली में बनाया और पूरे क्षेत्र में सब लोगों को सुविधाएं दीं । इस दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने लूटना शुरु कर दिया । सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिग्रहीत कर लिया, उन पर पाबंदी लगाई, उनकी दरों पर पाबंदी लगी, सीमा रख दी, कैपिंग कर दी ।

महोदय, यहां सब लोग बोले होंगे, लेकिन ऐसे संकट के बारे में विश्व ने न कभी सोचा होगा और न कभी देखा होगा । युद्ध में भी कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा देश प्रभावित हो । दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब ऐसा नहीं हुआ । कभी भूकम्प आया, तब भी ऐसा नहीं हुआ । बाढ़ आई तो भी ऐसा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ हो । अब हम ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अदृश्य है । हमें पता ही नहीं चलता है कि शत्रु कहां है, कैसा है ।

मुम्बई में टास्क फोर्स बनाई गई । 3500 बैड थे, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में 3 लाख 61 हजार 83 बैड हैं । इसमें कोविड के लिए 2 लाख 6 हजार 827, कोविड में ऑक्सीजन के लिए 1 लाख 54 हजार 82, लक्षण वाले मरीजों के लिए 53

हजार 343 बैड और वेंटीलेटर 7 हजार 241 हैं। मैं माननीय हर्षवर्धन जी से कहना चाहता हूं, आपने वेंटीलेटर दिए। आप जांच कीजिए की उनकी हालत क्या है? ये चलते हैं या नहीं चलते हैं, इसे भी तो आपको देखना होगा। ये बहुत बुरी हालत में हैं।

सभापति जी, कोलीवाड़ा बाहर निकल रहा है, धारावी बाहर निकल गया । आपको सुनकर गर्व होगा कि धारावी, वर्ली कोलीवाड़ा जब कोरोना से मुक्ति पाने लगा तो वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकन अखबार ने इसकी सराहना की । फिलीपींस ने तो धारावी का पैटर्न ही स्वीकार कर लिया कि वे इसी तरह से अपने राष्ट्र में झुग्गी-झोपड़ियों में काम करेंगे । इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकॉस्टिंग कार्पोरेशन ने मुम्बई महानगरपालिका ने धारावी में जिस तरह से काम किया, उसकी रिपोर्ट प्रसारित की । डब्ल्यूएचओ ने इसे सराहा । प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में काम होता रहा, सहयोग मिलता रहा, जो अच्छा है, उसे अच्छा कहेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे । हम उनके नेतृत्व में आज भी काम कर रहे हैं ।

पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है । अब तक हमें 11 लाख 88 हजार 15 करोड़ रुपये मिले हैं । 8 लाख 34 हजार 472 लोग कोरोना मुक्त हुए लेकिन दुर्भाग्यवश 22 हजार 216 लोगों की मृत्यु भी हुई है । हमें दुख है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए । अब फिर पूरी दुनिया में कोरोना उछल रहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं है । ऐसी स्थिति में हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के साथ हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में चार दिन पहले संसद में भी कहा था कि लद्दाख की सीमा पर चीन के साथ जवान खड़े हैं, उनके साथ सारे सांसद खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है ।

हम माननीय प्रधान मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम जान कुर्बान करेंगे, आप जो कहेंगे वह करेंगे । लद्घाख की सीमा पर जो संकट है, उसी तरह सीमा के अंदर कोरोना का संकट है । इसका आप नेतृत्व कर रहे हैं । यह भी आपका ही परिवार है । हम

आपसे अपेक्षा करते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि वहां लोगों को इकट्ठा रहना है, इसी तरह यहां कोरोना के संकट में भी हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए ।

यह दुख की बात है, दर्द की बात है, दुर्भाग्य की बात है, जो सरकार हमें शुरूआत में पीपीई किट देती थी, वेंटीलेटर देती थी, डॉ. हर्षवर्धन साहब पता नहीं क्या हुआ कि आपने घोषित कर दिया कि महाराष्ट्र में आगे चलकर हम इन उपकरणों से सहायता नहीं कर पाएंगे । मुझे समझ में नहीं आता, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, क्या वहां की जनता माननीय प्रधान मंत्री जी की करुणा और ममता से वंचित रहेगी?

उनके उपकरणों और दवाओं के लिए वंचित रहेगी? यह किस तरह की सोच है, मुझे समय में नहीं आता । एक तरफ तो आप कहते हैं कि सहायता और उपकरण नहीं देंगे, दूसरी तरफ, आप जीएसटी भी नहीं दे रहे हैं और आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ।

सभापित महोदय, आप ही बताइए कि यह आत्मिनर्भरता कैसे आएगी? राज्य सरकार कैसे काम करेगी? आप न तो हमारी बकाया राशि देते हैं, न सहायता देते हैं, यह अच्छी राजनीति नहीं है । यह एक प्रकार से अनीति है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आत्मिनर्भरता से आत्मवंचना मत कीजिए । हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे । 'साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना' । हम मिलकर बोझ उठाना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री दोबारा इसका नेतृत्व करें । आज सेवा देने वाले थक गए हैं, लोग भी थक गए हैं, लेकिन कोरोना नहीं थका है । इसिलए, हमारे उद्धव साहब ने घोषण की है –'मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी ।' यह घोषणा कितनी अच्छी है कि यदि हरेक जन अपने-अपने परिवार की सुरक्षा करे तो देश की सुरक्षा होगी । हमारे प्रधान मंत्री जी के लिए तो पूरा देश उनका परिवार है और उनके परिवार के हम सदस्य हैं । हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के साथ सौतेला भाव मत रखिए । वे भी आपके बच्चे हैं । वे भी आपके राज्य हैं, राज्य की जनता भी आपकी है, वे भी

हिन्दुस्तान की जनता हैं । उनको भी परिवार की मुखिया की तरह ममता भाव से देखें और हमें सहायता करें । इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को सीमित करता हूं । धन्यवाद । जय हिन्द, जय महाराष्ट्र ।

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 20 सितम्बर 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख मरीजों के पार निकल चुकी है।

कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है.पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 92605 नए मामले के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5400619 हो गयी है. पिछले 24 घंटों में 1133 कोरोना रोगियों की मृत्यु हुई । अब तक देश में 86752 रोगियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है । परन्तु अच्छी रात की बात यह है कि प्रतिदिन 90 से 95 हजार तक कोरोना संक्रमित मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं ।

मेरे लातुर संसदीय क्षेत्र में भी कोरोना बीमारी का काफी प्रकोप रहा । मगर मैं अपने जिले के सभी डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और समर्पित कोरोना वारियर्स का धन्यवाद करता हूं कि वह विगत 6 महीनों से इस बीमारी से तन मन धन से लड़ रहे हैं । आज की स्थिति के अनुसार लातुर में 78724 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है जिसमें से 14059 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया । जिले में वेंटीलेटरों की उपलब्ध संख्या संतोषजनक है । मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री केयर फंड से 45 वेंटीलेटर हमारे लातुर जिले को उपलब्ध करवाये तािक करोना पीडितों का उचित उपचार संभव हो सका । जिले के सभी अस्पताल हमारे भरपूर प्रयासों के बावजूद हमारे जिले में कोरोना से अब तक 413 लोगों की मृत्यु हो चुकी है । मैं इन सभी के परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट करता हूं । लातुर विगत छह महीनों में सबसे मुश्किल लॉक डाउन का समय था । इस अविध में हमने यथाशिक सभी जरूरतमंदों को भोजन, सेनीटाइजर, मास्क तथा स्वाथ्स्य कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध करवाए और जिले में लगभग 25 हजार जरूरत मंदों को व्यक्तिगत तौर पर बाटा

^{*} Speech was laid on the Table.

है ताकि कोरोना बीमारी से डट कर मुकाबला किया जा सके । अभी भी 200 से 300 नये मामले रोज आ रहे हैं ।

नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ इक्के-दुक्के मामले सबसे पहले चीन में सामने आए और उसके कुछ माह बाद ही देखते-देखते इसने वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया । इस बीमारे के कारण आज दुनिया के कई हिस्सों में, सीमाएं बंद हैं, हवाई अड्डे, होटल और व्यवसाय बंद हैं, और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं ।

ये अभूतपूर्व उपाय कुछ समाजों के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ रहे हैं और कई अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छूट रही है और व्यापक पैमाने पर भूख की छाया बढ़ रही है । वास्तव में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है जिसके दो साल तक जारी रहने की संभावना है । जब तक इसकी वैक्सीन विकसित नहीं होगी तब तक यह वायरस एक खतरा बना रहेगा ।

पूरी दुनिया के साथ ही साथ देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में कोरोना के टीके की खोज हो रही है। हालांकि अभी तक कोई भी देश कोविड-19 को खत्म करने वाली वैक्सीन पर मुहर नहीं लगा पाया है। भारत में भी तीन अलग-अलग वैक्सीनों पर काम चल रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूरी तेजी से काम चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जल्द खुशखबरी मिल सकती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में राज्यसभा में कहा था कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीने से राज्य और केंद्र की सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचना मिली थी

कि चीन में कोरोना का केस मिला है । हमने 8 जनवरी से बैठकें शुरू कर दी थीं । इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी ।

कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए उसकी वजह से हमारी स्थिति बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर हुई है । हम चाहें अमेरिका से तुलना करें, ब्राजील से करें या फिर किसी अन्य देश से हमारी स्थिति बाकियों के मुकाबले बेहतर है । जुलाई-अगस्त में भारत में 300 मिलियन कोरोना मामले और 5-6 मिलियन मौतों की बात कही गई थी । 135 करोड़ के इस देश में हम रोजाना 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं । हमसे ज्यादा कुल 5 करोड़ टेस्ट अभी तक अमेरिका ने किए हैं । हम जल्द ही अमेरिका को टेस्टिंग में पीछे छोड़ देंगे । हमारी सरकार इस वायरस के नए संक्रमणों के चक्र पर काबू पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है परन्तु फिर भी आगे आने वाले काफी समय तक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दवाब बना रहेगा । वैक्सीन के विकास, इसके उत्पादन और न्यायसंगत वितरण की बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता है । गहन चिकित्सा की आवश्यकता वाले तेजी से बढ़ रहे रोगियों का इलाज करने के लिए मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक की जरूरी सामानों के उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति के लिए आपूर्ति शृंखलाओं को युद्ध स्तर पर तैयार रखा जाना चाहिए ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है । देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और आगे भी इसी तरह कठिन प्रयास करते रहेगे । अंत में मैं यही कह सकता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है।

हमारे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर सबसे कम है । जिसके लिए मैं अपने कोरोना वारियर्स जिनमें हमारे डाक्टर, नर्स, अन्य चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं सभी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना 24 घंटे कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं और देशे को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पहले की तरह हम सभी मिलकर इस वैश्विक बीमारी के संकट से शीघ्रातिशीघ्र उबर पाएंगे । मैं सभी का आह्वान करता हूं कि इस महामारी से डट कर मुकाबला करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों में तन-मन-धन से सहयोग करें ।

*श्रीमती रक्षा निखल खाडसे (रावेर): इस सदन के माननीय सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी व श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, इन्होंने जो नियम 193 के अधीनस्थ देश में कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के विषय पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में उठाए गई चर्चा इस सदन में उपस्थित की है, इस पर मुझे मेरे विचार सदन में रखने की अनुमित देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

कोविड-19 कोरोना वायरस से सारे विश्व को चिंतित एवं एक नए मोड पर जीने को सिखाया है. जिससे मानवीय आरोग्य पर ही नहीं सारी दुनियाभर में सब देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है । इस कोरोना वायरस के फैलावे की शरुआत दिसंबर 2019 से विश्व के जनआरोग्य पर गहरा परिणाम किया, जिसके चलते वायरस से प्रभावित मरीज के स्वास्थ्य लाभ न होने के कारण तथा बड़े तौर पर जान गंवाने का खंतरा मंडरा रहा है । धीरे-धीरे इस वायरस की खोज के बाद 5 से 6 माह में आजकल परिस्थिति में सुधार आने लगा है और देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से आपने कालचक्र पर विराजमान होने की स्थिति की शुरुआत हुई है । हमारे देश में अन्य विश्व के देश में इस वायरस का फैलावे को लगाम लगाने का काम हमारे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश की जनता को पूरे देश में जनता कफ्यूं तथा जनता बंद ऐसे अपील को कभी न मिलने वाली सफलता मिली । बार-बार मीडिया के माध्यम से अपील करने से शुरू से ही देश के लोगों में जागरूकता हुई और देश इस कोरोना वायरस के भारी मात्रा में फैलाव एवं सामना कैसे करना है, यह जानकारी जगह-जगह देश के विभिन्न क्षेत्र में अपनी-अपनी परिचित भाषा के इस्तेमाल करने से हम इस फैलाव को रोकने में कामयाब रहे हैं । देश की जनता ने भी माननीय पंतप्रधान जी की हर एक अपील को पूरी ताकत दी के सफलता पूर्ण किया ।

केन्द्र सरकार के माध्यम से हर एक राज्य में हर जिले व रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इस वायरस की संक्रमण पर रोक तथा उपाय योजन के लिए मेडिकल एम्पलाइज की मदद एवं सैनिटाइजर

Speech was laid on the Table.

व फेस मास्क की भारी मात्रा में सप्लाई किया, जिससे हर राज्य में हमें इस कोरोना वायरस की सर्वव्यापी महामारी के संक्रमण से राहत मिली है ।

इस कोरोना वायरस की सर्वव्यापी महामारी के संक्रमण से पर्यटन, सत्कार व विमानन क्षेत्र में भारी मात्रा में हानि/नुकसान हुआ है और यह क्षेत्र फिर से शुरु होने व उभरकर आने के लिए बहुत समय लग सकता है । इसलिए इन क्षेत्रों पर आश्रित बहुत से उद्योग व इससे जुड़े व्यापार के लोगों के लिए सरकार से उचित व पर्याप्त माध्यम खड़े करने की जरूरत है । मेरे सभी किसान भाइयों को भी इस विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है । एक तरफ कोरोना वायरस की सर्वव्यापी महामारी से बचने के उपाय करना और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल का ख्याल व रख-रखाव पर ध्यान देना, तैयार फसल को लॉकडाउन की वजह से बाजार उपलब्ध न होने से जो मिले उस भाव में बेचना, जिससे किसान को भारी मात्रा में हानि हुई है ।

आने वाले खरीफ सीजन के लिए बीज व फर्टिलाइज़र खरीद करने के लिए पैसों की आवश्यकता कैसे व कहां से करे । इसकी चिंता से परेशान किसानों को सरकार के माध्यम से आत्मिनर्भर भारत बनाने के लिए बड़े प्रावधान की उपायोजना के लिए मैं हमारे माननीय पंतप्रधान जी को इन किसानों की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूं । मेरे रावेर निर्वाचन क्षेत्र में केले की फसल लगभग 65,000 हेक्टेयर कृषि जमीन पर है । यहां के केले पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं । पहले ही कोरोना वायरस की मार से हमारे यहां का किसान परेशान था, क्योंकि केले की फसल की मांग आम का सीजन खत्म होते ही बढ़ती है, लेकिन इस साल किसानों को लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ होने वाली यातायात पर गहरा असर होने से यह किसान को अपनी तैयार फसल को अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसे भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है । दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा बारिश होने से Cucumber Mosaic virus (CMV) के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है । केन्द्र सरकार ने

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2012-13 में शुरु किए हुए प्रोग्राम के अंतर्गत केले का क्षेत्र KARPA रोग निर्मूलन कार्यक्रम हर साल करती थी । 2017-18 से बंद कर दिया है । इस बार ज्यादा मात्रा में इस रोग के फैलाव का असर हुआ है । महाराष्ट्र राज्य ने केले की फसल के लिए पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस के माध्यम से मिलने वाले नुकसान की भरपाई के मानक प्रमाण (Triggers for RWBCIS) को बदल कर ऐसे स्थापित किए हैं कि मेरे क्षेत्र का कोई भी किसान यह मानक प्रमाण पूरे नहीं करेगा और न ही उसे इंश्योरेंस कंपनी से कोई मुआवजा मिलेगा । मैंने राज्य सरकार से इस ब्लाक इयर तीन साल के लिए स्थापित मानक प्रमाण को बदलने के सुझाव रखे हैं । राज्य सरकार का कहना है कि यह मानक प्रमाण हमने केन्द्र सरकार के अधिकृत अधिकारियों के साथ मिलकर स्थापित किए हैं और अगर इन प्रमाण में कोई भी बदलाव करना है, तो केन्द्र के कृषि अधिकारियों से इसके बदलाव की अनुमित चाहिए । मेरे क्षेत्र के किसान को सभी तरफ से हानि पहुंच रही है । इसलिए मैं इस सदन में उपस्थित कोविड-19 नियम 193 के अधीनस्थ जो विषय रखा गया है, उस विषय में मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों को जो हानी हुई है, उसके लिए कुछ मांगे रखती हूं ।

- 1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2012-13 में शुरु किए हुए प्रोग्राम के अंतर्गत केले का क्षेत्र KARPA रोग निर्मूलन कार्यक्रम का पुनर्गठन करना ।
- 2. Cucumber Mosaic Virus (CMV) के प्रकोप जिससे मेरे क्षेत्र के केले को कृषि क्षेत्र जो भारी मात्रा में प्रभावित है, उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई/उपाय योजना की जरूरत ।
- 3. पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस के नए स्थापित मानक प्रमाण (Triggers for RWBCIS) को केन्द्र के कृषि अधिकारियों से पुनर्स्थापित करना ।

मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे नियम 193 के अधीनस्थ रखे गए देश में कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के विषय में भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमित प्रदान की गई।

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): आज कोरोना संक्रमण की महामारी पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में लगातार फैल रही है । ऐसे में जहां पूरे विश्व में असामान्य स्थिति बन रही है, वहीं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने संक्रमण से बचाव हेतु विशेष कदम उठाए हैं ।

संक्रमण शुरू होने के समय ही लॉकडाउन की घोषणा कर मास्क लगाने एवं दो गज की दूरी को आवश्यक रूप से रखने के निर्देश जारी किए । आदरणीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश से ही देश के कोने-कोने में फंसे हुए मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया गया और राज्यों को भी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया । साथ ही यह निर्देश दिया कि देश में किरायेदारों से किराया न लेने की व्यवस्था की जाए एवं मजदूरों की मजदूरी न काटी जाए । इस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की चोट झेल रहे हमारे देश को आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसारित किया । यहां पीपीई किट का निर्माण लोकल स्तर पर कराया गया । मास्क का निर्माण हो या टेस्टिंग किट का निर्माण हो, देश में निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे हमारी निर्भरता चीन जैसे देशों से खत्म हुई ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस संक्रमण काल में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने हेतु समय-समय पर देशवासियों के साथ कई कार्यक्रम किए । अध्यक्ष जी इस संकट से उबरने हेतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के कदमों की सराहना करती हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हम शीघ्र ही इस संक्रमण से निजात पाएंगे ।

Speech was laid on the Table.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): माननीय सभापित जी, हम वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा कर रहे हैं । जब हम इस वैश्विक महामारी की चर्चा कर रहे हैं तो आज इस अवसर हम अपने माननीय अध्यक्ष जी का अभिनन्दन जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में माननीय अध्यक्ष जी अपने सभी सदस्यों को लगातार फोन करके उनका हाल-चाल लेते रहे । मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने तीन बार फोन किया और हाल-चाल लेते रहे । आज हम उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं कि वे अपने सदस्यों के प्रति संवेदनशील रहे कि उनके सदस्य कहां तक सुरक्षित हैं ।

<u>17.58 hrs</u> (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

सभापति महोदया, जब हम वैश्विक महामारी की चर्चा कर रहे थे, मैं प्रारंभ से चर्चा स्न रहा था । वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम कैसी रणनीति बनाएं, किस प्रकार हम एकमत होकर एक राय से इस महामारी से लड़ें, उसकी बजाय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना में समय बिता रहे हैं। आप प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना में समय क्यों बिता रहे हैं? कोविड-19 की जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए यदि आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव है तो उसको सरकार के सामने रखिए कि उस सकारात्मक सुझाव के माध्यम से आप कोविड-19 से लड़िए । यह एक समस्या है कि ये प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की जितनी आलोचना करते हैं. उतनी ही उनकी पोपुलेरिटी का ग्राफ बढ़ता जाता है और इनका ग्राफ घटता जाता है । लेकिन, क्या किया जाए, ये लोग मजबूर हैं । चश्मा ऐसा लगाया है कि इनको किया हुआ काम दिखाई नहीं देगा । यदि ये चश्मे का पावर बदलकर और सही दिशा में देखने का प्रयास करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो इनको दिखाई देगा कि सरकार ने क्या काम किया है । पूरे विश्व में यह महामारी है । कौन-सा ऐसा विकसित देश है, जो इससे प्रभावित नहीं है । चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, कौन-सा ऐसा देश है? यह भी एक विवाद का विषय है, इस पर काफी चर्चा है, पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी सहमत होंगे या नहीं होंगे कि यह एक प्राकृतिक वायरस है या मानव निर्मित वायरस है?

18.00 hrs

यह भी एक सवाल है । पूरे विश्व में इसकी चर्चा छिड़ी हुई है । चूंकि हम लोग परिस्थिति को देखते हैं । हम देखते हैं कि दिल्ली में सक्रमण की संख्या कभी घट रही है, लेकिन फिर अचानक संख्या बढ़ने लगती है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां-जहां संक्रमण घटता है, वहां वायरस को बाहर से पुश किया जा रहा है । यह मानव निर्मित वायरस है या प्राकृतिक वायरस है, इसका पता नहीं चला है । यह दुनिया के सामने एक चर्चा का विषय बना हुआ है । अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन सरकार ने काम किया है । केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन का जो समय पर निर्णय लिया, उसका परिणाम यह है कि पूरे देश में कम्युनिटी स्प्रैड नहीं है । आप देखिए कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की क्या हालत हुई है, फ्रांस जैसे राष्ट्र की क्या हालत हुई है, यू.के. में क्या हुआ है? आप आज हमारे देश से तुलना करके देखिए । हमारे देश की मृत्यु दर और दूसरे देशों की मृत्यु दर देखिए । हमारे यहां पर जो रिकवरी रेट है, आप उसकी तुलना कीजिए । हम दुनिया से बहुत आगे हैं । केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन करके समय पर जो प्रयास किया, उसका परिणाम यह है कि आज हमारा देश बहुत हद तक सुरक्षित है । लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वे ठीक भी हो रहे हैं । ठीक होने का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है ।

माननीय सभापित महोदया, कई लोगों ने प्रवासी मजदूरों की चर्चा की है । हम तो प्रवासी मजदूर नहीं मानते हैं, क्योंकि यह देश सभी का है । यह देश प्रवास करने के लिए नहीं जाना जाता है । इस देश में किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार करने का अधिकार है । वह रोजगार की तलाश में जाता है । वह प्रवासी नहीं है । लॉकडाउन के बाद कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया । उसके बाद इन्होंने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की और जगह-जगह जो मजदूर फंसे हुए थे, वे स्पेशल ट्रेन्स से अपने-अपने प्रदेश वापस जा सकें । सरकार ने क्या काम नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया? आप कह रहे हैं कि रेल की पटरियों पर

सो रहे थे । यह तो न्यूज में चल ही रहा था । हम लोग उस पीरियड में भी देख रहे थे कि आगरा के बॉर्डर पर 5 हजार गाड़ियाँ खडी हैं और फोटो छप रही है । उसमें एक ही गाड़ी का पता चला और फिर पता नहीं चला कि स्कूटर का नंबर है या मोटरसाइकिल का नंबर है या कौन-कौन सी गांडियों का नंबर है तो यही सब चल रहा था । आप जब सकारात्मक रुख नहीं रखेंगे और नकारात्मक रुख रखेंगे तो ये समस्याएं होती रहेंगी । आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने क्या किया । इस देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को यह तो मालूम नहीं था कि यहां पर कोरोना वायरस आने वाला है । जाँच की व्यवस्था नहीं थी, किट्स नहीं थीं । हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं । उन्होंने दिन-रात मेहनत करके पूरे देश में लेबोरेटरी में जांच की संख्या बढ़ाई और उसका परिणाम है कि आज देश में बड़े पैमाने पर जांच हो रही है । इसका इलाज तो अभी नहीं है । पूरी दुनिया में वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है । हमारे देश में भी रिसर्च चल रही है । इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसका एक ही इलाज है कि आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, विटामिन सी खाते रहिए और व्यायाम करते रहिए । आज की तारीख में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है । वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है और वैक्सीन पर जब सफलता मिलेगी तभी मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है ।

माननीय सभापित महोदया, पूरी दुनिया में इस देश के लोग फँसे हुए थे । हर देश में हिन्दुस्तान के लोग फँसे हुए थे । केन्द्र सरकार ने उन सभी को वापस लाने के लिए पहल की । केन्द्र सरकार ने चार्टर विमान भेजा । चार्टर विमान से सभी को इस देश में वापस लाया गया । उनको क्वारंटीन सेन्टर्स में रखा गया । क्वारंटीन होने के बाद और जांच नेगेटिव आने के बाद जब वे स्वस्थ हुए तो उनको घर भेजा गया । आप केन्द्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यह आपका नजरिया है और यह आपका नजरिया है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है । नजरिया तो कोई बदल नहीं सकता है । मैं अपने प्रदेश की भी चर्चा करना चाहता हूं । केन्द्र सरकार ने अनाज बाँटने का काम किया है । चाहे एपीएल हो या बीपीएल हो, सभी को अनाज दिया जा रहा है । हम इसमें जरूर केन्द्र

सरकार से आग्रह करेंगे । हम आग्रह करेंगे कि इसमें जो परिवारों की संख्या निर्धारित है, वह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है । वर्ष 2011 की जनगणना से लेकर वर्ष 2020 में काफी अंतर आया है । परिवारों की संख्या बढ़ी है ।

सभापित महोदया, आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार को राज्य सरकारों से बात करके, वहां सर्वे कराकर जो वास्तविक परिवारों की संख्या है, उसे निर्धारित करके, उसके मुताबिक अनाज वहां देने का प्रबन्ध करना चाहिए । यह आग्रह मैं करना चाहूंगा ।

मैडम, मैं बिहार की बात दो-तीन मिनट में खत्म करूंगा, आपसे आग्रह करता हूं कि आप घण्टी मत बजाइएगा ।

मैडम, बिहार इस देश का आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश है । आज वहां क्या स्थिति है? राज्य सरकार ने काम किया है और राज्य सरकार के कामों का परिणाम है कि आज वहां मात्र 13 हजार संक्रमित लोग हैं । माननीय मंत्री जी के पास आंकड़े रोज आते होंगे, अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो वे उनका खण्डन करेंगे, लेकिन वहां आज की तारीख में संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 13 हजार बची हुई है । अब तक 54 लाख लोगों की जांच कराई जा चुकी है । बिहार का रिकवरी रेट 91.7 प्रतिशत है और मृत्यु दर मात्र 0.5 प्रतिशत है । अभी बाढ़ का समय था, उस समय खतरा था, क्योंकि बाढ़ प्रभावित लोग कम्युनिटी किचन में, जो रसोई का इंतजाम रहता है आते हैं या नाव पर चढ़कर आते हैं, उनके कारण कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा था । राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि जो बाढ़ पीड़ित नाव से उतरेंगे, उतरने के साथ ही उनकी जांच होगी और उसके बाद ही वे कम्युनिटी किचन में जाएंगे और जो लोग जांच में पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेट कर दिया गया । कम्युनिटी किचन में एक-एक किचन की जांच कराई गई, उसमें जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेट करके क्वारंटाइन में रखा गया । यही कारण है, राज्य सरकार का यह जो काम था,

यही कारण है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित लोग आए, फिर भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुई, संक्रमण की संख्या नहीं बढ़ी ।

जब बाहर से मजदूर आए, तब राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों में प्रति व्यक्ति पर 5300 रुपये खर्च किए । राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में 5300 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करके, उनको 14 दिनों तक वहां रखा, उनको बर्तन, कपड़े, बिछावन, खाने की मेन्यू आदि सारी चीजें बनाकर दी गईं । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने खुद उसकी मॉनीटिरंग की, एक-एक क्वारंटाइन सेंटर की वे मॉनीटिरंग करते रहे और आज सब लोग ठीक होकर घर चले गए, आज कोई क्वारंटाइन सेंटर में नहीं है । यह एक स्थिति है और अभी भी चेकिंग चल रही है, जागरण है । आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, केन्द्र सरकार ने जनजागरण पैदा किया, जिसकी चर्चा ये लोग कर रहे थे, कई लोग आलोचना में उसकी चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने जो थाली बजाने आदि के काम किए ।...(व्यवधान) ये सब जो भी उन्होंने किया, वह जनजागृति पैदा करने के लिए किया । जनजागृति पैदा करने के लिए हर व्यक्ति के, जन-जन के दिमाग में वह बात डालनी पड़ती है कि यही बात है, इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई उपाय तो है नहीं । इसका कोई रास्ता तो है नहीं ।...(व्यवधान) बैठे रहिए, ऐसे ही करते रहिए । बाद में और घटते चले जाइएगा, पीछे चले जाइएगा, चिन्ता मत किरए ।

आज यह स्थिति है, आज पूरे देश में, बिहार में हर चौक-चौराहे पर रैंडम जांच कराई जा रही है । किसी की गाड़ी रोककर उसकी जांच कराई जा रही है, रैंडम जांच कराई जा रही है और औसतन एक लाख से सवा लाख जांच प्रतिदिन की जा रही है । इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन आज जब कोविड-19 की चर्चा हम कर रहे हैं तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं — सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसवाले — जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, हम उनको सलाम करते हैं । उनको मेरा सलाम है । इसके साथ-साथ, जो लोग शहीद हुए, उनमें से कुछ लोग वीरगति को भी प्राप्त हुए, उनके प्रति हम श्रद्धांजिल अर्पित करते हैं ।

इसके साथ ही, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I would like to place my views in Odia. Odia is one of the Indian languages and I believe my speech in Odia can be properly interpreted. Today, we are fighting against an invisible enemy. When I say we, it does not mean only 'we', the Indians, but the entire global population. We all are fighting this strange invisible enemy which cannot be seen or felt. And nobody can predict when and whom it will strike. While humanity is fighting against this enemy, it has become quite clear that even science has a limitation. For the past 1000 years, we had this impression that science holds the key to all our doubts and solution to all our problems. For the first time we are in a quandary – we are still searching for a solution, but in vain.

Madam, that is why I want to state here that those of our brethren who are involved in scientific research and studies to fight this pandemic must be extended all kind of support. All of us must pray for their success in finding a vaccine, so that humankind can be freed from this catastrophe. A few days back I was having a conversation with an eminent personality in this House. I asked about the Spanish Flu outbreak of 1918 which was rumoured to have started from India and later spread to Europe and America. I wondered whether after 100 years of this disease any vaccine has been invented or not? Today we have Dr. Harshvardhan ji, Minister of Health amidst us. Maybe he can educate us in his speech if at all such a vaccine has been developed or not.

-

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Odiya.

We have seen in the past, how sometimes pandemics, suddenly break out and linger up to a year or two and gradually becomes less virulent and fades away. But that doesn't mean we sit quietly, wait and watch. should need to act and take some stringent steps. I believe 184 days have passed by when we first came to know about COVID-19 in our country. The first announcement about the pandemic was on 24th March. The Lockdown announcement took place on the 25th March. In fact, we have been fighting against this pandemic for the last 8 months continuously.

We keep on hearing how countries like Brazil, China, the USA and even Pakistan dealt with Corona and how we are tackling this disease. We have a Government at the Centre headed by the Prime Minister, his Cabinet and the Central administrative machinery on the one hand; On the other hand, we have 29 States and 6 Union Territories in tow. Both the set of governments have acted in tandem mostly, exchanging information and cooperating with each other. This has been the silver lining for me as Central and State Governments have communicated and cooperated wherever required as the magnitude of the problem is quite vast. However, sometimes our expectations from the Central Government have not been entirely fulfilled. But we continue to forge ahead with positivity.

Let us not forget that we are fighting a battle against this deadly global pandemic and we have to win and we will win most certainly. In the process let us

do something extraordinary which will make the next generation remember us with gratitude.

Madam, through you, I want to place a few proposals before the Government. Let me begin with expressing gratitude to all our healthcare workers, Arogya Karmis, Asha Karmis, social workers, and municipal workers. You people have been doing your duty relentlessly without waiting for recognition or appreciation. Let me emphasize that the entire nation respects you, prays for you, and is grateful to you in this difficult time for your service. But the government must design some social security schemes for these people who jeopardize their lives for us.

Madam, in the past 24 hours, around 93 thousand people have been affected by coronavirus, but more number of people have recovered. This is a very good sign. I had read a couplet somewhere which is so befitting here "Yeh lamha hi to hai, gujar jayega, waqat hi to hai gujar jayega." (This is only a moment and this time will pass) We should be optimistic and hope for a better future.

Today, we heard a lot about the PM-CARES Fund. Odisha has received only Rs.23 crores and 68 lakhs, from the PM-CARES Fund, but we have received more funds under SDRF (State Disaster Relief fund) Head. Just like other states of the country, we too have a share in the SDRF. Mercifully we had received the said fund in the month of April. But in a subsequent correction we were allowed by the Central Government to spend 35% of SDRF in Covid care which we did. On

the behalf of the State Government and my party BJD, I want to request the Central Government to enhance the SDRF allocation for Odisha. We need more funds as we are fighting this invisible enemy in every lane, every village, and in every city! We have to promote awareness on a big scale and prevent the spread of the disease. So, we need more money. So far, we have received only one thousand and seventy crores of rupees from the Central Government.

Madam, I need to highlight some more points. It seems that we are not getting rid of this coronavirus in the near future. In the last 24 hours total number of COVID-19 affected cases is 93,000 and total number so far is fifty lakhs. India has overtaken Brazil in this race. But something interesting has come to light. According to a research done by the Backforest Baptist Medical Research Centre in the USA, women in India have some kind of immunity from coronavirus owing to the existence of an Enzyme called S2. This is an Angiotensin Converting Enzyme that protects women from COVID-19. We need to do more research regarding this aspect. Madam, please allow me somemore time. I am talking about you, about the immunity of women.

According to a Report by UNICEF 46 crore and 30 lakh school children have been affected by coronavirus. They have been deprived of regular school education and forced into ignorance. This is unprecedented in human history. An entire generation of children are suffering. Similarly, poor people have lost their livelihoods. They have been pushed into abysmal poverty, starvation, and death.

Research is going on to find a vaccine for coronavirus. New Dehi AIIMS is carrying on experimentation. First it was tested on animals, then on humans. The research is midway and I hope hon. minister will throw some light on the progress so far.

Lastly, I request the Central Government to maintain a Data Register about the migrant workers/labourers, who have undergone the COVID-19 test, their status, state of origin etc., etc. which will be helpful in future to render help.

*श्री देवजी पटेल (जालौर): भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 20 सितम्बर, 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख मरीजों के पार निकल चुकी है । कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है । पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 92605 नए मामले के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5400619 हो गयी है । पिछले 24 घंटों में 1133 करोरोना रोगियों की मृत्यु हुई । अब तक देश में 86752 रोगियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है । परन्तु अच्छी बात यह है कि प्रतिदिन 90 से 95 हजार तक कोरोना संक्रमित मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं ।

आज देश व विदेश भर में लगातार फैल रहा है । ऐसे में सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर ब्रिटिश काल में बना हुआ, क्वॉरेंटाइन हाउस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है । साथ ही, यह भी प्रासंगिक हो गया है कि वर्षों पहले भी हमारे पूर्वज भी महामारी के लिए कितने अधिक जागरूक थे । वर्तमान में तो इस क्वॉरेंटाइन हाउस की स्थित बहुत ही खराब है । पूरी तरह से टूटा जीर्ण-शीर्ण व गंदगी से अटा पड़ा यह क्वॉरेंटाइन हाउस नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर ही कई प्रश्निचन्ह खड़े कर रहा है । साथ ही, इसी प्रकार की कई ऐतिहासिक धरोहरों के लिए नगर पालिका प्रशासन कितना संजीदा है, इसकी बानगी भी प्रस्तुत कर रहा है । वैसे क्वॉरेंटाइन शब्द का असल अर्थ तो आज के कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप व विश्वव्यापी महामारी में आमजन मानस को समझ में आया है । लेकिन इसकी व्यवस्था तो वर्षों पूर्व माउंट आबू में ब्रिटिश काल में ही हो चुकी थी । माउंट आबू के जानकार बताते हैं कि सबसे पहले माउंट आबू में साफ सफाई के लिए सफाई सिमित का निर्माण 1865 में हुआ था । उस समय से लेकर सन् 1898 में प्लेग प्रकोप बढ़ा तो मरीज इसी स्थान पर

Speech was laid on the Table.

लाकर रखे जाते थे । इसके बाद सन् 1900 में इसी स्थान पर पूरी तरह से क्वॉरंटीन सेन्टर बन कर तैयार हुआ, जो बाद में आई हैजा व टीबी के रोगियों को यहाँ पर रखा जाता था ।

मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों ने कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्था फैली हुई है । यहां पर भर्ती मरीजों के लिए न पीने का पानी का इंतजाम है न ही समुचित भोजन की व्यवस्था है । पिछले सप्ताह चाण्डपुरा के देवनारायण आवासीय विद्यालय में कॉरेंटीन हो रखे पावटी निवासी एक व्यक्ति की सांस में तकलीफ पर गत शुक्रवार को जलोर रेफर करने के दौरान मौत हो गई थी । मृतक कोरोना पॉजिटिव था । दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है । प्रशासन पूरी तरह से हाथ पर हाथ घर के बैठा है । जिले में पिछले दिनों एक साथ 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है । जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 43 तक पहुंच गया है । आज यहां के सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो गए हैं ।

कोविड-19 से जुड़ी ड्यूटी करने वाले एक एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर को एम्स अस्पतालों में 23,500 तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 20,000 हरियाणा में 17,000 पंजाब , बिहार और हिमाचल प्रदेश में 15,000 और जम्मू-कश्मीर में 12,300 रुपए मासिक भत्ता मिल रहा है जबिक राजस्थान में इंटर्न डॉक्टर को उसी काम के 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं ।

राजस्थान के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का सवाल है कि जब कोरोना वायरस महामारी किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर रही है, खतरा सब को बराबर है, तो इसके खिलाफ लड़ रहे इंटर्न डॉक्टरों के भत्ते में इतना फर्क क्यों? क्यों नहीं देश में इसके लिए वन नेशन, वन स्टाइपेंड की नीति अपनाई जानी चाहिए?

नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ इक्के-दुक्के मामले सबसे पहले चीन में सामने आए और उसके कुछ माह बाद ही देखते-देखते इसने वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया । इस बीमारी के कारण आज दुनिया के कई हिस्सों में सीमाएं बंद हैं, हवाई अड्डे, होटल और व्यवसाय बंद

हैं और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं । ये अभूतपूर्व उपाय कुछ समाजों के सामाजिक तानेबाने को तोड़ रहे हैं और कई अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और व्यापक पैमाने पर भूख की छाया बढ़ रही है । वास्तव में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, जिसके दो साल तक जारी रहने की संभावना है । जब तक इसकी वैक्सीन विकसित नहीं होगी तब तक यह वायरस एक खतरा बना रहेगा ।

पूरी दुनिया के साथ ही साथ देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं । भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में कोरोना के टीके की खोज हो रही है । हालांकि अभी तक कोई भी देश कोविड-19 को खत्म करने वाली वैक्सीन पर मुहर नहीं लगा पाया है । भारत में भी तीन अलग-अलग वैक्सीनों पर काम चल रहा है । कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूरी तेजी से काम चल रहा है । भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जल्द खुशखबरी मिल सकती है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में राज्य सभा में कहा था कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है । हमें उम्मीद है कि अगल साल की शुरुआत में भारत में वक्सीन उपलब्ध होगा ।

उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीने से राज्य और केन्द्र की सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है । पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है । 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचना मिली थी कि चीन में कोरोना का केस मिला है । हमने 8 जनवरी से बैठकें शुरू कर दी थी । इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी ।

कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र सरकार ने जो कदम उठाए, उसकी वजह से हमारी स्थिति बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर हुई है । हम चाहे अमेरिका से तुलना करें, ब्राजील से करें या फिर किसी अन्य देश से करें, हमारी स्थिति बाकियों के मुकाबले बेहतर है । जुलाई-अगस्त में भारत में

300 मिलियन कोरोना मामले और 5-6 मिलियन मौतों की बात कही गई थी । 135 करोड़ के इस देश में हम रोजाना 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं । हमसे ज्यादा कुल 5 करोड़ टेस्ट अभी तक अमेरिका ने किए हैं । हम जल्द ही अमेरिका को टेस्टिंग में पीछे छोड़ देंगे ।

हमारी सरकार इस वायरस के नए संक्रमणों के चक्र पर काबू पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है परन्तु फिर भी आगे आने वाले काफी समय तक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बना रहेगा । वैक्सीन के विकास, इसके उत्पादन और न्यायसंगत वितरण की बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता है । गहन चिकित्सा की आवश्यकता वाले तेजी से बढ़ रहे रोगियों का इलाज करने के लिए मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक की जरूरी सामानों के उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को युद्धस्तर पर तैयार रखा जाना चाहिए ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है । देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और आगे भी इसी तरह कठिन प्रयास करते रहेंगे । अंत में, मैं यही कह सकता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है । हमारे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर सबसे कम है, जिसके लिए मैं अपने कोरोना वॉरियर्स, जिनमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स, अन्य चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं, सभी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं जो अपने घर-परिवार की चिंता किए बिना 24 घंटे कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं और देश को अपनी अमृत्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पहले की तरह हम सभी मिलकर इस वैश्विक बीमारी के संकट से शीघ्रातिशीघ्र उबर पाएंगे । मैं सभी का आह्वान करता हूं कि इस महामारी से हटकर मुकाबला करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों में तन मन धन से सहयोग करें ।

*श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): मैं कोरोना महामारी के विषय पर अपने विचार रखता हूं ।

- 1. कोरोना महामारी के चलते परदेस में फंसे अपने भारतीय भाई-बहनों को अपने देश में लाने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने सराहनीय काम किया है । मेरे संसदीय क्षेत्र के बहुत से लोगों को विदेश मंत्री श्रीमान एस. जयशंकर जी के माध्यम से वंदे भारत मिशन के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं विदेश मंत्री जी और उनकी टीम का आभारी हूं ।
- 2. कोरोना महामारी में देश बहुत बदलावों से गुज़र रहा है । नए-नए आविष्कार और प्रयोग किए जा रहे हैं । इस गंभीर बीमारी से जूझने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी" मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है । इस अभियान में महाराष्ट्र के हर नागरिक की घर जा के आरोग्य चिकित्सा की जाएगी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वे काबिल-ए-तारीफ हैं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार को देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य हेतु मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी अभियान को पूरे देश में चलाना चाहिए ।
- 3. मेरे लोक सभा क्षेत्र सतारा, महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं । मास्क, चिकित्सा सामग्री और अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो करीब 200 की मात्रा में वेंटीलेटर्स की आवश्यकता है ।मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में 200 की मात्रा में वेंटीलेटर्स पीएम केयर्स फंड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं ।

धन्यवाद ।

Speech was laid on the Table.

*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I would like to express my views on "COVID-19 Pandemic in the Country" under Rule 193.

Firstly, I would like to thank our hon. Prime Minister for his vision and leadership to drive the country through the pandemic. I am sure, Speaker Sir, the worst of the pandemic is behind us. With declining growth of active cases and fatality ratio, the nation will emerge out stronger from the crisis.

It is sad to know that till now more than 85,000 people have died in the country due to the COVID-19 pandemic. But I would also like to mention that India is one of the few countries in the world with lowest mortality rate below 4 per cent even when the mortality rate peaked in April. I would like to mention that in the month of May at the global level, the mortality rate had peaked at more than 7 per cent levels.

It is due to the timely measures taken by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, that we have been able to maintain less than 3% of mortality rate and have successfully continued to reduce the mortality rate below 2 per cent levels today.

Today, in India, the rate of growth of active cases has fallen to 0.7 per cent, we can soon expect the growth rate of active cases to fall down close to zero per cent, which is essentially known as "Flattening of the curve" for active cases. India

.

Speech was laid on the Table.

has done appreciable job in reducing mortality rate as compared to the developed economies of the West. We all should unanimously appreciate and laud the Prime Minister for his quick decisions and guidance for the country.

It is really sad to see that some States, being one of the most developed States of the country, Maharashtra is failing to reduce Test Positivity Rate below 20 per cent. It is saddening to see one in every five persons tested, testing positive. Many States have done commendable job in increasing testing and maintaining lower test positivity rate and lower case fatality rate.

Secondly, we must appreciate the efforts made by doctors, nurses paramedical staff in such times. In such difficult times, the police forces, bureaucrats have been working overtime away from their family. I bow down to them for their service to the nation in such difficult times. There have been a lot of NGOs, thousands of volunteers, who have supported the efforts of Government in checking the spread of COVID-19 virus.

I have learnt that about 382 doctors have died on duty, the country shall forever be indebted to them for their service and sacrifice. I request the Government to acknowledge their sacrifice and provide them with appropriate compensation for their service.

Further, I also thank all my colleagues from Lok Sabha and Rajya Sabha for their service to the people of their constituency, the migrant workers and the citizens of India during the lockdown.

In my constituency of Jhalawar-Baran, along with the Karyakartas of Bharatiya Janata Party, our teams have distributed food packets, dry ration kits, ayurvedic kaadha, masks, sanitizers and even footwear to migrant workers irrespective of their cast and religion.

In Baran district, the Karyakarta of BJP have distributed 3700 ration kits, about more than 1.2 lakh cooked food packet, 15,000 people were distributed ayurvedic kaadha. We distributed about 32,000 masks in socio-economically backward regions of Baran district. In Baran, we even helped and supported the migrant workers passing through on feet. About 15,000 cooked food packets were distributed to the migrant workers and 300 pairs of footwear were distributed.

In Jhalawar district, the BJP Karyakartas have distributed more than 2 lakh cooked food packets, 27,700 dry ration kits and 270 pairs of footwear to the migrant workers.

I thank the volunteer who all worked hard towards supporting the people of Jhalawar-Baran.

माननीय सभापति : श्री गिरीश चन्द्र जी ।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कोविड-19 के विषय पर बोलने की अनुमित प्रदान की है । देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मी जी-जान से लगे हुए हैं । हम इन्हें सम्मान से कोरोना योद्धा भी पुकारते हैं । देश में पिछले दिनों स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर जिस प्रकार से हमले हुए हैं, उस पर महामिहम राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके एक अध्यादेश की मंजूरी दी है, वह स्वागतयोग्य है ।

माननीय सभापति जी, आज पूरे देश में कोविड-19 से गरीब, पिछड़े आदि सब लोग परेशान हैं ।

देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इस महामारी के विरुद्ध जारी संघर्ष में पीपीई किट के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बहुत-से मरीजों को परेशान कर रही है । आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है । उत्तर प्रदेश में बिजनौर को लें या जो हमारा लोक सभा क्षेत्र नगीना है, वहाँ पर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है । कुछ लोग ऑक्सीजन का भंडार इकट्ठा करके कालाबाजारी करने का काम करते हैं । कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ।

जिस तरह से सरकार ने अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था कराई, आईसीयू वार्ड्स की व्यवस्था कराई, लेकिन अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी होनी चाहिए, वह अभी कहीं नजर नहीं आ रही है ।

इस महामारी में बेरोजगारी के कारण गरीब, मजदूर अपनी जीविका चला सकें, सरकार को इस ओर भी ठोस निर्णय लेना चाहिए क्योंकि हर गरीब आज सिर्फ मनरेगा के तहत काम कर रहा है ।

आज जो बी.ए. पास है, जो डिग्रीधारक भी है, उसके पास जीविका चलाने के लिए सिर्फ मनरेगा ही सहारा है।

इसलिए मैं सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि मनरेगा के साथ-साथ कुछ दूसरे रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबों और मजदूरों को सहारा देना चाहिए, जो सरकार की पहली प्राथमिकता है ।

आज सरकार ने बहुत-से अच्छे कदम उठाने का काम भी किया है । मैं सरकार से चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ जो लॉकडाउन लगा, उस समय दो-ढाई सौ मरीजों से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज मरीजों की संख्या एक लाख के आँकड़े पर पहुँच गई है । ये आँकड़े और न बढ़ें, इस पर भी सरकार को गहन चिन्तन करके इसकी रोकथाम के लिए अधिक-से-अधिक कदम उठाने चाहिए ।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): Thank you Madam Chairperson for giving me this opportunity.

मैडम, कोरोना के कारण एक देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग बहुत तकलीफ में आ गए हैं । अगर हम लोग इंडिया में देखें, तो जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी गाइडलाइंस दीं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से गाइडलाइंस दी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिस तरह से गाइडलाइंए दी हैं, आईसीएमआर से जो गाइडलाइंस मिली हैं, उनके अनुसार हम लोग तेलंगाना स्टेट में काम करते हुए आगे बढ़े हैं । मगर हम लोगों ने जो भी सोचा है, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में हमारे देश में कोरोना के पेशेंट्स करीब-करीब हाईएस्ट नम्बर पर हैं, लगभग 98 हजार से एक लाख के बीच पर-डे कोरोना के पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं । यह कोरोना तो अभी रेजिंग स्टेट में है । यह कोरोना कब खत्म होगा, इस महामारी से अपना इंडिया, अपना स्टेट कब बाहर आएगा, यह पता नहीं है । इससे लोग बहुत तकलीफ में हैं । अभी वैक्सीन आने तक तकलीफ है । वैक्सीन के लिए हमारे देश में भी कोशिश हो रही है । इसके लिए वर्ल्ड में भी ट्राई किया जा रहा है । लेकिन अभी तक उसका रास्ता नहीं निकला है ।

कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ माइग्रेंट लेबरर्स को हुई है । देश में इस तरह की तकलीफ अभी तक हम लोगों ने अपनी आँखों से नहीं देखी थी । जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स तकलीफ में थे, लॉकडाउन के पीरिएड में हमारे स्टेट में, केसीआर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में एपिडेमिक डिजीज के बारे में एक रेगुलेशन लेकर आए हैं । उसमें पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को कवर करने के लिए, पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को बचाने के लिए, एक-एक माइग्रेंट लेबरर्स को चुनकर, तेलंगाना में जितने दिनों तक लॉकडाउन था, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं थी । उनको खाने की तकलीफ नहीं थी, रहने की तकलीफ नहीं थी । हम लोगों ने हर तरह से उसका

पालन किया है । माइग्रेंट लेबरर्स को हमने तेलंगाना का बेटा बोलकर, तेलंगाना के लोग बोलकर, उनके लिए सब कुछ किया है ।

उसी तरह से, अगर हेल्थ मेजर्स में देखें तो इसमें हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है । प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी रिक्वायरमेंट थीं, हमने उनको पूरा किया है । हेल्थ के वर्क फोर्स को, डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या को भी इम्प्रूव किया गया है ।

इसी तरह से हमने काफी रिलीफ मेज़र्स भी दिए हैं । फैक्ट्रीज़ में जितने भी टेम्परेरी वर्कर्स थे, उनको बचाने के लिए हमने फैक्ट्री वालों को बोल दिया है । ...(व्यवधान) मैडम, मुझे दो-चार मिनट का टाइम दीजिए । हमने माइग्रेंट लेबर्स के पालन के लिए काम किए हैं । उसी तरह स्कूल फीस भी न लेने के लिए बोल दिया है । जो लोग रेंट पर रहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम लोगों ने यह बोला है कि जो कोई भी रेंटल में है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसे रेंट देने के लिए प्रेशराज़ मत करो, जो भी है, उसे हम लोग देखेंगे । हमने यह बोलकर उन लोगों को भी बचा दिया है ।

इसी तरह से सैनिटेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ डिडक्ट कर के इस पैनडेमिक में सैनिटेशन वर्कर्स - डॉक्टर्स, नर्सेज़ की सैलरीज़ दस परसेंट बढ़ा दी हैं । इस तरह से हमने तेलंगाना में स्टेप्स लिए हैं । अब अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है । इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा । इसी तरह अभी जीडीपी की ग्रोथ 23.9 परसेंट, ऑलमोस्ट 24 परसेंट माइनस है, इस पैनडेमिक से पहले जीडीपी 5.5 परसेंट प्लस थी । इसे अगर पूरा देखें तो हम लोग अभी 30 परसेंट माइनस में चल रहे हैं । इसको कैसे आगे लेकर जाना है, यह सब हमें देखना पड़ेगा ।

सभापित महोदया, हाउस में हर टाइम जो बात करते हैं, उसी तरह तेलंगाना में भी वही बात आती है कि 'आयुष्मान भारत' तेलंगाना में इम्प्लिमेंट नहीं हो रहा है । अभी ऑनरेबल मिनिस्टर यहां हैं । मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से, पूरे हाउस से और पूरे देश से एक बात बोलना चाहता हूं । हमारे पास

आरोग्यश्री योजना है, यह आरोग्यश्री योजना वर्ष 2007 में, जब हमारी कम्बाइन्ड एपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब आरोग्यश्री योजना को लेकर आए थे । ...(व्यवधान) उसी आरोग्यश्री योजना को अभी तेलंगाना में कन्टीन्यू कर रहे हैं । उसमें ज्यादा डिज़ीज़ेज़ एड कर दी हैं और बाकी काम भी किए हैं ।

मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से यही बोलना चाहता हूं कि आप आरोग्यश्री योजना को पूरे देश में इम्प्लिमेंट कीजिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. एस. टी. हसन जी, आप बोलिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री नामा नागेश्वर राव: मैडम, बस एक मिनट और बोलने दीजिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय खत्म हो गया है । आपके सात मिनट पूरे हो गए हैं ।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्लीज़, आप अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने दीजिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री नामा नागेश्वर राव: मैडम, मैं एक मिनट में ही अपनी बात कनक्लूड कर दूंगा । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री नामा नागेश्वर राव: मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से यही बोलना चाहता हूं कि आरोग्यश्री योजना को जैसे हम लोगों ने तेलंगाना में इम्प्लिमेंट किया है, वैसे ही आप उसे पूरे भारत में कीजिए । अगर हम आपकी आयुष्मान भारत स्कीम को वहां इम्प्लिमेंट करें तो आरोग्यश्री में हम जितने आदिमयों को सुविधाएं दे रहे हैं, उसका 70 परसेंट घट जाता है और उसमें नंबर ऑफ डिज़ीज़ेज़ भी घट जाती हैं । इसे देखकर ही मैं आपको ऐसा करने के लिए बता रहा हूं । ...(व्यवधान)

इसी के साथ आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी का कम्पन्सेशन दिया जाना था, उस कम्पन्सेशन के बारे में हमने इस हाउस में पांच दफा बात की है । ...(व्यवधान) आप कम से कम यह पैसा रिलीज़ कीजिए । इससे कोविड-19 के समय स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका एक मिनट पूरा हो गया है ।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: इसी तरह से जो भी अन्य फंड्स पेंडिंग हैं, उन्हें देने से कोविड-19 के समय में हम सबको बचा सकेंगे । ...(व्यवधान)

*DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): COVID-19 is an imported disease and self-inflicted disaster. It was originated in China and spread to all countries through humans only. The first COVID-19 positive case was identified in Kerala on 31 January 2020. Thereafter, it started to rise through further arrival of foreign passengers and their immediate contacts. So, the Government and everyone knew about the veracity of COVID-19 by January and February 2020 itself. No one can dispute it.

By the time, that is, 18 March 2020, the Union Government had decided to stop all international passenger flights and banned the entry of anyone from abroad, almost an estimated 25 lakh passengers from abroad have entered and dispersed across various States, corners of India. Thus, the Coronavirus crisis started in India, a big blunder which could not be resolved till date.

If the Government acted in time, that is, January or February and stopped those arriving from abroad and isolated those arrived for a month or so, then the country might not get this virus entry into every corner of the country and the common man might not be at a receiving end. Due to lethargic and improperly acts of the Government the virus spread across the country. The Government should shoulder the responsibility as it failed to act in time and now crushing the common man who is vulnerable and unbearable to the situation. It is not even extending any sufficient relief to those in need. Several households are facing

^{*} Speech was laid on the Table.

food scarcity. I just leave it to the hon. Members sitting in this august House to understand and judge where, when and how it went wrong to reach this unbearable lockdown.

The life of migrant labourers is beyond all levels of suffering. The pictures of the migrant workers leaving the cities by foot with their luggage in one hand, holding the children in other, many young men carrying their aged mother or father on their shoulders, the small children walking along with their parents in sweltering heat without *chappals* will be etched in our sad memories forever.

The ghastly images of migrant workers smashed by a goods train in Maharashtra cannot be deleted from the dark pages of history which happened due to the inefficiency and incompetence of the ruling Government.

The Government at the Centre blaming the State Governments for their grave mistakes has become a common phenomenon. The ill effects and ground reality due to COVID-19 lockdown on the people of this country is still not ascertained properly. Barring the people who get a regular income monthly as salary or pension, all others are suffering a lot. Out of the 138-crore population, 100 crores are plunged into deep trouble. People working as daily wage labourers, those working in unorganised sector, farm workers, migrant labourers from various categories, lorry, tempo, taxi and auto drivers, domestic workers have suffered severely due to this self-inflicted COVID-19 crisis.

In India, there are around one crore drivers who earn their livelihood through driving vehicles from lorry, bus, car and auto rickshaws. The five months lockdown has destroyed their career beyond recuperation. Those who had borrowed loan from banks or private lenders for their taxis and autos were unable to pay their loan dues. They too have a family living in a single room house with aged parents, unmarried sisters, wives and children. We just cannot imagine the difficulties faced by them during the lockdown period.

All I want to say is that the Government has not applied its mind and have not done enough homework to be in the state of preparedness and readiness to fight COVID-19 crisis. The Government either failed to analyse the inputs reaching from China and other countries when the COVID-19 started there in December or it is the blatant failure of intelligence and diplomats working in China and abroad. Nevertheless, we had three full months of time to prepare and plan to combat COVID-19 but failed miserably to be prepared. This is due to the Government's preoccupation to prepare for the extravaganza related to the personal visit of US President during 23rd to 24th February, 2020.

Secondly, when the entire world was busy in preparation to fight COVID-19, the ruling Government was cunningly, cleverly and keenly focused only on dislodging the duly elected Government in Madhya Pradesh using unethical means. This greediness to derail the duly elected Government has made the Government insane and insensitive to the early warnings of some senior MPs and

leaders of opposition parties and the Government continued to run Parliament till 23rd March, 2020, when the Government mission was successfully accomplished a day before. Madhya Pradesh Government was captured and the very next day full lockdown was announced by the Prime Minister and it came into effect all over the country without any thoughts on the people, especially the migrant workers. That is why when COVID-19 started to spread in India, we did not have even testing kits with us or laboratories to check and ascertain the COVID-19 patients. There was very low production of protective gears, PPEs, masks, gloves and we lagged far behind in the supply of sanitisers too. That is the reason why India could not respond effectively to fight against Corona and the numbers got increased.

In India, regular testing started happening only in the first week of March after the emergence of the first few cases. Starting with just one laboratory, the Pune-based National Institute of Virology, that was testing samples at that time, India now managed to have a network of more than 1,100 laboratories that are conducting these diagnostic tests. More than two lakh samples are being tested every day. Considering the large population, the penetration of testing is still quite low. India's testing numbers per one million population are still low compared to many other countries.

The Government says that economy was badly affected during COVID-19 lockdown. Agreed. But was our economy booming in the previous years of this

Government? No. It is getting bad to worse and worse to worst in the last six years and has reached point of no return at the moment. Today, I have no hesitation in saying that our country's economy is pushed a clear 20 years back and it will take several years of herculean works to set it right and put it back.

In this precarious condition, the country's economy is reeling under tremendous pressure and distress. Our country's GDP will certainly show a negative growth. The humongous damage caused to our economy before and after COVID-19 has pushed us to years backward. It may take six years or more for our country to reach the same position India was in 2013. That too, if a steady 8-10 per cent growth in GDP is achieved in the next six years. But as of now, we have -23.9 per cent GDP. The internal debt of the country has crossed Rs. 100 lakh crore. This means we have already lost 12 years. I wish the Government do not commit any hara-kiri and also hope that there will be no more big calamities or any self-inflicted catastrophe.

On the financial front, actually, the Union government should have convened a Special Session of Parliament to recalculate and recalibrate the income possibilities and expenditure priorities as the already passed Budget is by now unrealistic. The Budget 2020-21 passed by Parliament looks unachievable due to the loss of time and opportunities. The priorities have changed drastically after the COVID-19 crisis. The provisions made for many projects could be modified, postponed or withdrawn accordingly. It is, therefore, very important to

have a Revised Budget 2020-21 with more emphasis on new initiatives with adequate financial provisions to mitigate the issues and problems encountered by the people aftermath of COVID-19 lockdown crisis. It is, therefore, my humble request to the hon. Prime Minister and the Finance Minister to convene a Special Session of Parliament and make suitable changes in Budget 2020-21 and make it practically achievable.

Government of India should openly announce the details of the trade and economic deals, bilateral treaties signed with China in the last six years and explain to the people of our country why the Modi Government has signed such deals with the brutal and treacherous country like China in the last six years in spite of heavy opposition from nationalists from various corners of the country.

The adamant behaviour of leaders of both countries fully know the imminent danger and disadvantages faced by our country due to these treaties and trade deals. For whose benefit these deals and treaties are signed? Order for an independent authority to probe and find the intricacies of the trade deficits and economic imbalances in these deals and treaties. It is high time for the Government to speak the truth with the common public. Otherwise History will punish the people who are responsible for this debacle beyond just words.

The COVID-19 crisis has left every profession and professional in the-lurch, be it a Doctor or Engineer or Lawyer, a category of people who have established their career and serving the society. The medical practitioners and their staff are

the most affected, and in fighting COVID-19, many in this medical field have lost their invaluable lives. The Engineering professionals and IT professionals were affected very much due to the COVID-19 lockdown.

The COVID-19 crisis has worsened the life of genuine lawyers and their clients who solely depends on justice to be delivered in time. Justice delayed is Justice denied. Courts in India are paralyzed by COVID-19 crisis and plagued by the shortage of Judges. The Union Law Ministry is on "Kumbhakarna Sleep Mode".

There are 60,000 cases pending in the Supreme Court, and 45 lakh cases in 25 High Courts in the country. At the District and subordinate court levels, the number of pending cases stand at a shocking Rs. 3.14 crore as of November 2019. 27 lakh of these cases are less than years old, 8.5 lakh are pending for more than five years but less than 10 years and 8.5 lakh are over 10 year old.

The COVID-19 crisis has paralyzed, and the lockdown has knocked down the Judicial System, and most of the genuine lawyers have literally knocked out of jobs, became incomeless, clients shed tears of blood. But as far as the Judges and court staffs like Registrars, Assistant Registrars, Court Marshals etc. are concerned, they enjoy a paid lockdown. There is not a single penny loss, though they work just 20-30 per cent to their capacity and capabilities.

COVID-19 has robbed the people three months of court proceedings and genuine open court arguments. In the absence of any personal interaction or

open court hearings, the Registry departments of Courts have become the Demi Gods and the Judges have literally turned into invisible Lords.

The Indian judiciary is already suffering due to the shortage of judges. Nearly 40 per cent of sanctioned number of Judges are still unfilled. Unfortunately, the Union Law Ministry and Ministerial people of State Governments are sleeping as if heavens are not going to fall. If the courts are not functioning to its full potential, the Government is least bothered of the dangerous consequences of paralyzing of our Judicial System not working to the fullest capacity and potential. When everything is lost, people look up on Judiciary and Justice, and if that Judicial System is not working to the desired levels, a kind of alleged Police excess and lawlessness in the society is inevitable. It is time to wake up or else expect a catastrophe. Hope the top ranks in the Government and Judiciary will discuss, deliberate and come up with some real solution to address this unprecedented lockdown in Judicial system.

If the COVID-19 situation is not going to improve, and if the Government of India does not intervene, next few months will witness that several lakh people packing their baggage permanently back to India. As per the recent data, there are about 1.5 crore NRIs and 2 crore PIOs living all around the World. The COVID-19 may force at least one quarter of this 1.5 crore NRI population and 10 per cent of the 2.5 crore PIOs return to India which means at least 50 lakh people who had a settled life would be unsettled and forced to come back. Countries like

Australia, Bahrein, Bhutan, Canada, China, Germany, Italy, Kuwait, Malaysia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, UAE, UK and USA have large NRI population. While Australia, Canada, Fiji, France, Germany, Guyana, Indonesia, Israel, Italy, Jamaica, Kenya, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Portugal, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, UK and USA have large PIO population.

The plight of those people who were to return to these countries to continue their education, business or professional work will not be permitted until and unless COVID-19 situation improves in India, thereby causing enormous stress and suffering to these people. The government should find a remedial solution to this crisis through the diplomatic routes. Otherwise, the life and career of these people will be lost.

COVID-19 crisis, if not for a comprehensive drug/vaccine to control the spread of the virus, would affect and alter the demography of the world countries in the coming months. Indian Diaspora is going to be the worst hit. I urge the Union Government to take all possible diplomatic and political administrative steps to stop or reduce this Demographic relocation.

The fishermen community in Tamil Nadu are one of the most affected communities in the country due to the COVID-19 crisis and the unprecedented and unplanned lockdown. Already, year after year, the fishermen of coastal Tamil

Nadu were battered by natural calamities as well as from indiscreet interference by the Sri Lankan counterparts. The COVID-19 has completely collapsed their livelihood. Export of Fish and marine products has paralysed beyond recuperation at this juncture.

The coastal corridor in Tamil Nadu consists of 13 districts with 15 major ports and harbours, sandy beaches, lakes and river estuaries. Tamil Nadu has a fishermen population of 2 million and the coast consists of three major fishing harbours, three medium fishing harbours and 363 fish landing centres. Unfortunately, there have been several incidents of fighting for fishing rights between Indian and Sri Lankan fishermen while fishing in the Palk Strait, where India and Sri Lanka are only separated by 12 nautical miles.

Fishing has to be recognised at par with agriculture. The fisher communities suffer very much due to natural calamities like cyclone, rough sea, heavy rains, heavy floods, hurricanes and tsunami. They need waiving of their loans by Government. COVID-19 has created a very bad situation for fishermen. Governments at both Centre and State together should provide Rs. 5,000 to about Rs. 50,000 to poor fishermen in Tamil Nadu to mitigate the Coronavirus lockdown crisis.

The continuous increase in the price of petrol/diesel during the COVID-19 crisis is like rubbing salt on the wounds. People sufferings have reached threshold levels. I urge the Union Government to act with compassion and common sense

to reduce the escalating petrol/diesel prices immediately. It is high time for the Government to reduce the petrol and diesel prices. Otherwise, people will suffer from an unprecedented agony and pain.

India's COVID-19 scenario is going from "bad to worse" stage to "worse to the worst" stage and our hon. Prime Minister is busy in feeding peacock, writing poems and continue his rhetoric speeches like his usual monthly Mann Ki Baat. It took 110 days for COVID-19 cases in India to reach one lakh while just 59 days more to go past 10 lakhs. India's COVID-19 cases rose from 10 lakh to 20 lakhs in 21 days and 20 lakhs to 30 lakhs in just 16 days. India's COVID-19 tally had crossed the 20-lakh mark on 7th August and went past 30 lakhs on 23rd August. From 30 to 50 lakhs, an addition of 20 lakh cases took just three weeks. At this current rate, we can presume that by the end of September, India's COVID-19 tally would easily cross 60 lakhs. With the death toll increasing steadily, there is no way we could expect normalcy by October or November. There could be possibility to impose the lockdown once again till a vaccine to curb COVID-19 is discovered and distributed for public use. Let us see the further 'Act of God' is benevolent and merciful.

COVID-19 has not spared anyone. Even in the high-profile Ministers and Members of Parliament are being affected. Take the case of our Union Home Minister. He is the second most protected person in the country. Only the designated and approved individuals are allowed to meet him or come into any

kind of physical proximity with him. Therefore, the hon. Home Minister getting infected by COVID-19 and that too when the country needs him 24/7, he was indisposed for several days. It needs to be probed to ascertain if there is any sabbatical move to curb the functioning of the all-powerful Minister. I urge the Government to initiate a fact-finding inquiry in this regard.

On one side, COVID-19 has become the biggest health hazard and on the other side the country's finance is shrinking like never before. When the finances drying up fast, with considerable decline in the revenue, the biggest problem for the Government will be, to fund its own projects in the coming months.

Sir, India is not an under developed country. But it has been ruined by underdeveloped minds. This Government has lost its focus and attention and drift away from economic priorities. But it seems to be happy to focus more on divisive religious ideologies and priorities. This Government is not a game changer but only a name changing Government. It is either a slogging Government or just a sloganeering Government. This Government needs mentoring on all aspects of politics, economy and public welfare. Electoral success will not guarantee a success in governance too. The real problem of the present Government is that if the pressing issues are not addressed properly, we might see a catastrophe in near future. What we need at the moment is a collective 'Save India' Movement not a 'Slave India' Movement.

I am really sorry to say that India has not only lost a golden opportunity to avert the COVID-19, but it has failed beyond the recovery in all other fronts. It will be an uphill task for the Government and the people of our country to come out of the COVID-19 crisis and its ill effects. As far as Tamil Nadu is concerned, we have great people but miserable rulers at the moment. Whatever happened we cannot stop now. The most pathetic thing is that people at the helm of affairs at the Government in Tamil Nadu have indulged in corruption and siphoning of the amount designated for COVID-19 crisis. People are the ultimate sufferers due the inefficient Governments at Centre and at State which has damaged the social fabric of the country, including Tamil Nadu. This is the harsh and bitter truth. The difficulties of the people may increase manyfold once the lockdown is lifted but at the moment, there is no way the Government can lift the lockdown as the COVID-19 cases in the country are increasing in lakhs each day and the death toll is reaching one lakh.

If this is the situation at the ground level today, I cannot imagine how bad it would turn out after two months when the cold weather and rains engulf the most of the country. COVID-19 crisis has left us with no other choice not because it is serious but because of the incapable, insensitive Governments at both Centre and State.

माननीय सभापति: डॉ. एस. टी. हसन – आप बोलिए ।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मैडम, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं । मैं आपसे और पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश बड़ी विषम परिस्थितयों से गुज़र रहा है, दोहरी लड़ाई लड़ रहा है । एक तरफ कोरोना की लड़ाई है तो दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर टेंशन है । जब देश लड़ाई लड़ता है, तब हम सब एक होते हैं । इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है । हम इस लड़ाई में देश के प्रधान मंत्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शामिल हैं, उनकी हर लड़ाई में हम सब लोग बराबर उनके साथ शरीक़ हैं ।

सभापित मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी मेहनत से काम किया । दिन-रात एक कर के उन्होंने वॉर-फुटिंग पर काम करने की कोशिश की, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में जब अनप्लान्ड लॉकडाउन हो गया, उस वक्त देश को बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा । हमारे माइग्रेंट लेबर्स, जो 1,500 किलोमीटर्स पैदल चले, उनके जूते घिस गए ।

उन्होंने अपने पैरों में पानी की बोतलें बांधी, हमने ये सीन्स देखें हैं । हमने देखा है कि चार साल के मासूम बच्चे को सूटकेस के ऊपर बैठाकर उसकी मां खींचकर ले जा रही है । बैलगाड़ी में एक तरफ इंसान लगा था, दूसरी तरफ बैल लगा था, हमने वे भी मंजर देखे हैं । हमने बापू के इस देश में दो जून की रोटी लेकर, जो लोग पटरी पर सो रहे थे, उन पटरियों पर बिखरी हुई रोटियां देखीं है, उनकी लाशें देखी हैं । ये सब कुछ किसलिए हुआ, क्योंकि अनप्लांड था । जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन ही यह कह दिया जाता कि तीन दिन बाद लॉकडाउन होना है, जिसको जहां जाना है, वहां पर चला जाए । हमारी संवेदनाएं कहां चली गईं । हमारे अहसासात कहां चले गए? एकदम से स्पेशल ट्रेंस क्यों नहीं चलाई गई, बसें क्यों नहीं चलाई गई और गरीब को उसके घर क्यों नहीं पहुंचाया गया ।

मैडम, हमने देखा कि कुछ लोगों ने कोरोना को भी कम्युनलाइज कर दिया । हमने देखा कुछ एंकर्स ने कोरोना जिहाद की बात की । जो लोग नफरत की सौदागरी करते हैं, क्या इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने एमपीलैड्स से वेंटिलेटर्स के लिए पैसा दिया और हमारे बहुत से साथियों ने दिया होगा, लेकिन उन वेंटिलेटर्स के लिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है । वे ऐसे ही पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन भी नहीं है । मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से दरख्वास्त है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दीजिए, तािक वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो सकें ।

मैडम, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि अब यह कोरोना एयरबाउंड डिसीज़ है । यह हवा में है, फ़िजा में है । चाइना की रिपोर्ट है कि यह 15 मीटर तक लोगों को इन्फेक्शन दे रहा है । ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे । मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से दरख्वास्त है कि अगर स्वदेशी वैक्सीन अभी नहीं बन पा रही है तो क्यों न हम जल्द से जल्द रूस की वैक्सीन को इम्पोर्ट करें, क्योंकि रूस की वैक्सीन साबित हो गई है कि वह इफेक्टिव है । सबसे बड़े जरनल द लैंसेट में एक लेख भी छपा है कि यह वैक्सीन इफेक्टिव है ।

महोदया, जिन लोगों ने माइग्रेट किया, जिन लोगों की मौतें हो गईं, जिन पत्रकारों की मौतें हो गईं, उनका कोई डाटा नहीं है । उनके कंपेन्सेशन का इंतजाम होना चाहिए । आज हमारी इकोनॉमी भी कोलेप्स कर गई है । उस कोलेप्स इकोनॉमी के लिए मेरी भारत सरकार से यह गुज़ारिश है कि रोजगार सृजन किए जाएं, लोगों की मदद की जाए । कोरोना से लड़ने के लिए हम सब एक होकर कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे और बॉर्डर की भी लड़ाई लड़ेंगे । हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हमारा देश दुनिया में नम्बर एक पर होगा । आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।

*SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): India's corona virus tally has raced past the 54-lakh mark as more than 93,337 COVID-19 cases were registered in the last 24 hours, according to the latest government figures.

The data also underlines that the death toll in the nation has crossed the 86,752 figure. With a vaccine fit for public circulation still at least six to ten months away, the pandemic continues to ravage the country as cases of cross-infection rise in the nation.

While global health experts and scientists have been warning about the onset of community transmission in India, the Government still maintains that there is "no community spread" in the country, currently.

Community transmission occurs when the source of the contagion is not known i.e., when you cannot identify the clear source of infection in a new community and the virus can infect anyone with no history of contact with affected people and areas.

In this scenario, it becomes impossible to trace the original source of infection back to a carrier.

At this stage of the transmission, where a person with no travel history or any contact with infected people can also catch the infection.

The national capital which was seemingly on a 'path of recovery' after hitting the supposed peak in the month of July, again started witnessing a sharp rise in the corona virus cases from the last week of August till now.

^{*} Speech was laid on the Table.

India has become the second worst affected nation by the COVID-19 pandemic. We might soon overtake the USA in the total number of infections next month.

So far, COVID-19 infections were heavily concentrated in large cities located in India's more prosperous States: Delhi, Mumbai, Chennai, among others.

The preparedness of the health system is much higher there than elsewhere. But recorded cases are now rising fast in India's poorer States where health services are very fragile.

As the COVID-19 crisis absorbs their meager resources, many public health centers have stopped providing routine services.

Even child immunization has been discontinued for months in many States. Some States paint a grim picture of missing doctors, unattended patients, broken equipment and stray dogs. Where are people with routine health problems supposed to go?

Not to forget the issues faced by disabled persons be it Financial difficulties, lack of access to essential services and little to no assistance from the government were and still is some of the difficulties that persons with disabilities have been facing during the COVID-19 and lockdown.

In India, there is one doctor for every 1,457 people as per the country's current population estimate of 1.35 billion, which is

lower than the World Health Organisation norm of 1:1000, as per the Government.

India's The other reason for а possible mortality spike is that prolonged lockdown national (from late March until unlock phases began in June) has destroyed millions of people's livelihoods.

Local lockdowns continue in many States and are likely to persist off and on for months. Unlike affluent countries, India has very little to show by way of a social security system, except for food subsidies and some relief work under the National Rural Employment Guarantee Act.

The employment crisis has already hit poor households really hard.

Extreme food insecurity during and after the lockdown.

Just to cite one, 78 percent of the 25,000 respondents in the nationwide CSDS (Centre for the Study of Developing Societies) survey said that they had found it "quite difficult" or "very difficult" to feed their families during the lockdown.

Acute food insecurity is very likely to translate into higher mortality.

For children, it also means lasting damage from malnutrition.

A recent survey of some 20,000 returning migrant workers found that 60 per cent were unable to ensure two square meals for all members of the family.

With the local economy in the doldrums, except for farming, casual workers are heading for a prolonged period of underemployment and hunger.

20.09.2020

With tax revenue a fraction of normal levels, State Governments are finding it difficult to provide more than symbolic relief. The Central Government is doing little to help them.

Without much help from the Centre our Telangana Government still has been taking several measures to tackle COVID-19 cases in the State and provide relief to the people of the State.

The Central Government did launch some limited relief measures during the national lockdown, such as free food-grain rations of five kilograms per person per month for two thirds of India's population.

But now it seems to have lost interest and left it to the State Governments to handle the crisis. Doctors and nurses critical of the Government's crisis response have been muzzled or harassed, as have many journalists been.

Muddled statistics are routinely invoked to reassure the public that all is well. In India its hurry to turn into а viswaquru (world leader). the Modi Government seems to have little patience for a humanitarian crisis. Yet, denying a crisis is the surest way to make it worse. There seems no one way of ending the pandemic in sight. We need to bring the focus on controlling the spread of the disease. It can only be achieved through a degree of herd immunity, following the social distancing norms and a safe and effective vaccine.

The combination of all three measures will only be helpful in slowing down the spread of the disease. However, delivering a vaccine is easier said than done. From

timely regulatory approvals to devising protocols for inoculation, in a country like India, with over 1.38 billion population, there can be quite a few challenges authorities will have to tackle.

Several countries have already drawn up plans to ensure priority access to any approved COVID vaccine for the essential workers like defence men, healthcare workers and teaching staff. Many also feel that the elderly need to be inoculated first. Indian authorities too need to figure out the priority groups which would need coverage first.

Smoothening out delivery details like this would get rid of confusion, and provide more security to those who could be at a higher risk than others. Phased out vaccination drive, instead of or random dosage would also work out for the best in a country with a sizeable population like India.

Steps taken by Telangana Government amid COVID-19:

Movement Restrictions:

For mitigating the spread of COVID-19 in the State, the Government of Telangana took the following measures for restricting the movement of people in the State.

Closure of commercial establishments:

On March 14, the Government ordered for the closure of cinema halls, amusement parks, swimming pools, gyms and museums until March 21 which was later extended to March 31.

Lockdown:

To further restrict the movement of people, the State and Central Governments announced lockdown in the State and country. The lockdown included: (i) closing down State borders, (ii) suspension of public transport services, (iii) prohibiting congregation of more than five people. The entities providing essential commodities and services were exempted from these restrictions.

Starting from April 20, the Central Government allowed certain activities in lessaffected districts of the country. However, on April 19, the State Government decided not to allow any relaxation in Telangana until May 7.

Health Measures:

counters for respiratory infections.

Telangana Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020: On March 21, the Government issued the Telangana Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020. The regulations are valid for one year. Key features of the regulations include: (i) All government and private hospitals should have dedicated COVID-19 corners, (ii) People who had travelled through the affected areas should be home quarantined for 14 days, (iii) Procedures to be followed in the containment zones among others. Private Hospitals: On March 22, for increasing the availability of healthcare facilities in the State, the Government issued an order prohibiting private hospitals from performing any elective surgeries. The hospitals were also instructed to have separate

20.09.2020

Increasing the health workforce in the State: On March 30, the Government issued notification for the recruitment of medical professionals on a short-term basis.

Prohibition on spitting in public places: On April 6, the Department of Health, Medical and Family Welfare banned spitting of *paan*, any chewable tobacco or non-tobacco product, and sputum in public places.

Welfare measures:

To mitigate the hardships faced by the people, the Government took various welfare measures. Some of them are summarized below:

Relief assistance: On March 23, the Government announced the following measures:

- 12 kg of rice will be provided for free to all food security cardholders.
- One-time support of Rs 1,500 will be provided to all food security card holding families for buying essential commodities such as groceries and vegetables.

Factories: On March 24, the Government directed the management of factories to pay the wages to all workers during the lockdown period.

Migrant Workers: On March 30, the Government decided to provide 12 kg of rice or atta and one time of support of Rs.500 to all migrant workers residing in the State.

Regulation of school fees: On April 21, the Government ordered all private schools not to increase any fees during the academic year of 2020-21. The schools will charge only tuition fees on a monthly basis.

Deferment of collection of rent: On April 23, the Government notified that house owners should defer the rent collection for three months. Further, the owners should

collect the deferred amount in instalments after three months.

Administrative Measures:

Deferment of salaries: The Government announced 75 per cent deferment of salaries of all the State legislators, Chairperson of all corporations and elected representatives of all local bodies. The Government employees will have salary deferment from 10 per cent to 60 per cent. Employees of the Police Department, Medical and Health Department, and sanitation workers employed in all Municipal Corporations and Municipalities are exempted from deferment of salary.

Chief Minister's Special Incentives: The Government granted special incentives to certain categories of employees as follows:

- Medical and Health Department: The employees of the Department of Medical and Health were given an additional 10% of their gross salary as an incentive for March and April;
- Sanitation personnel: The sanitation employees of Greater Hyderabad Municipal Corporation were given Rs.7,500 and the sanitation personnel of other local bodies were provided Rs.5,000 as incentives for March and April;
- Police: The police personnel were awarded an additional 10 per cent of their gross salary as an incentive for April.

With these few words, I conclude.

डॉ. अमोल रामिसंह कोल्हे (शिष्कर): सभापित महोदया, धन्यवाद । हम सब जानते हैं कि आज हम कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं । हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को पाया गया था । आज नौ महीने बाद क्या परिस्थित है? सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि रिकवरी रेट अच्छी है, मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, मैं इसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं । लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छुप कर हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज तक कोरोना की बीमारी की वजह से 90 हजार देशवासियों ने अपनी जान गवाई है । इसमें इनडायरेक्ट मौतें हुई हैं । लॉकडाउन की वजह से सड़क पर चलते हुए माइग्रेटं लेबर्स की मौतें, कारोबार चौपट होने की वजह से परिवार ने की हुई सामुदायिक खुदकुशियां आदि ऐसी मौतें इसमें शामिल नहीं हैं ।

आज इस देश की जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि जब कोरोना अपने देश में हाथ-पैर फैला रहा था, तब आप अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में मशगूल थे । जब देश की सेहत संभालने के प्रयास जरूरी थे, तब आप राज्यों की सरकारें गिराने के प्रयास में लगे हुए थे । आज इसका खामियाज़ा देश के हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है । अगर दूर दृष्टि दिखाते हुए आपने उसी वक्त हर इंटरनेशनल ट्रैवलर का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया होता तो आज यह नौबत नहीं आती । आपने सरप्राइज्ड इवेंट की तरह लॉकडाउन देश पर थोप दिया । लॉकडाउन लगाते वक्त यह नहीं सोचा कि फेज्ड आउट मैनर में भी लॉकडाउन किया जा सकता है । यह नहीं सोचा कि मार्च के महीने में कोरोना का स्प्रैड सिर्फ शहरी इलाकों में था, ग्रामीण इलाकों में नहीं था और आपने लोगों को तैयारी करने का भी अवसर नहीं दिया । आपने देशव्यापी लॉकडाउन थोप दिया । परिणामस्वरूप किसानों के हाथ से फसल चली गई, कई लोगों की रोजी-रोटी चली गई, माइग्रेंट लेबर्स को सैकड़ों किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा, लोगों ने बच्चों को बिस्कुट खिलाकर, पानी पिलाकर सुला दिया, लेकिन आप पर विश्वास रखकर उन्होंने उफ तक नहीं की ।

फिर आपने कहा कि तालियां बजाओ । हमने तालियां बजाई, थालियां पिटीं, घंटानाद किया, शंख ध्विन की, दीये भी जलाए, हमने सब किया और आप पर विश्वास रखकर किया । विश्वास यह था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से कोरोना की रोकथाम करेगी । आज भी ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की उपलिध्ध के आंकड़े जोर-शोर से बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज देश के आम आदमी को हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं । कई देशवासी ऐसे हैं, जिन्हें रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ा है । क्या देश ने आप पर जो विश्वास जताया था, उसका यही फल आपने देश को दिया है? आज नौ महीने बाद भी सर्वशित्तिशाली सरकार देशवासियों के दिलों से इस दहशत को उखाड़ नहीं पायी है । लोगों के मन में इनिसक्योरिटी है, अपनी जान को लेकर, अपनी सेहत को लेकर और अपने भविष्य को लेकर तो क्या यह हमारी विफलता नहीं है । आज कोरोना से मृत्यु की दर में हमारा देश विश्व में दूसरे पायदान पर है । सबसे तेजी से बढ़ने वाले केस लोड में हम लोगों ने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहला पायदान प्राप्त कर लिया, क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है?

सभापित महोदया, मैं सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश कम्युनिटी ट्रांसफर के फेज में है या नहीं? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो सरकार की सब पॉलिसीज़ फेल हो चुकी हैं, इसका यह सबूत है । अगर इस सवाल का जवाब ना है तो फिर प्रतिदिन एक लाख के करीब केसेज़ कैसे पाए जा रहे हैं?

सभापित महोदया, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमें पॉलिसीज़ में बदलाव की आवश्यकता है? इंडिविजुअल केस आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन के बजाय अब हमें जियोग्राफिकल स्प्रेड ट्रैकिंग और उस एरिया में पर्याप्त आरोग्य सुविधा डिप्लोय करने के बारे में सोचना चाहिए । आज कोरोना से जो युवा उभरे हैं, वे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रेडी हैं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आईसीएमआर का अब तक प्लाज्मा डोनेशन के लिए, प्लाज्मा थेरेपी के

लिए क्लीयर डायरेक्टिव्ज़ नहीं हैं । वही बात सराइवरी टेस्टिंग की है और वही बात औषधियों की दरों की है । आप फेबिफ्लू या रेमडेसिविर ले लीजिए, आम आदमी की जेब की पहुंच से ये दवाइयां आज बाहर हैं और इस पर विचार होना चाहिए ।

सभापित महोदया, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिन पर हमने कोविड वॉरियर्स कहकर फूल बरसाए, उनमें से कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स की कोरोना से मृत्यु हुई है? इसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है । जब मैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्यूशन की बात कर रहा हूं तो लक्षद्वीप के मेरे साथी सांसद फैज़ल जी का अभिनंदन करूंगा कि लक्षद्वीप में आज तक एक भी कोविड-19 का केस नहीं पाया गया है । उसी के साथ जब हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्यूशन की बात करते हैं तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मेरा महाराष्ट्र राज्य है । आज महाराष्ट्र में देश के कोरोना केसेस के 22 प्रतिशत केसेस हैं और 37 परसेंट डेथ्स हैं । ...(व्यवधान)

महोदया, मैंने अभी शुरू किया है । मैं अभी करेक्टिव मैज़र पर आ रहा हूं । मुझे सिर्फ दो मिनट और दीजिए । हमारे सांसद अरविंद सावंत जी ने जैसा कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है । आदरणीय शरद पवार जी के मार्गदर्शन में कर रही है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजे जी टोपे आए दिन फील्ड पर हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार नवंबर-दिसंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं और ऐसे में भारत सरकार ने 1 सितंबर से महाराष्ट्र सरकार को वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स और एन-95 मास्क की मदद को पूरी तरह से रोक दिया है । हमारे मराठी में एक कहावत है- "आई जेऊ घाली ना, अणि बाप भीख मांगू देई ना ।" ऐसा बर्ताव केन्द्र की सरकार महाराष्ट्र की सरकार के साथ कर रही है । क्या महाराष्ट्र के वासी देश के वासी नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र की जनता के प्रति केन्द्र सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र की सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब महाराष्ट्र सरकार को टेस्टिंग किट्स और अदर कंज्यूमेबल्स

की मदद मुहैया करायी जाए । उसी के साथ अनइंटरिंटड ऑक्सीजन सप्लायी के लिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मेन्युफेक्चरिंग मेगा यूनिट के निर्माण के बारे में सोचा जाए ।

सभापित महोदया, जब हम कोविड-19 की लड़ाई में रिसोर्सेज़ की बात करते हैं तो उतना ही अहम स्किल्ड मैनपावर है । मैडम, यह बहुत अहम मुद्धा है । देश के लिए बहुत अहम मुद्धा है । जैसा कि आरोग्य मंत्री जी ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आने में कुछ समय लगेगा तो इसके लिए हमें स्किल मैनपावर की जरूरत पड़ने वाली है । नेशनल हेल्थ मिशन के जो रेट्स हैं, उन रेट्स में आसानी से स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध नहीं हो सकती है । इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन के रेट्स को रिवाइज़ किया जाए ताकि और ज्यादा स्किल्ड मैनपावर इस कोरोना की लड़ाई में इनफ्यूज़ की जा सके । ...(व्यवधान)

*श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मुझे कोविड -19 महामारी पर नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 बीमारी वाला वायरस उन बूंदों से फैलता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस लेने से पैदा होती हैं। ये बूंदें बहुत भारी होती हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाती हैं और तुरंत ही फ़र्श या सतह पर गिर जाती हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत नज़दीक हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है, तो सांस लेने पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। अगर आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं और उसके बाद आंखें, नाक या मुंह छूते हैं, तो ऐसा करने पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं।

आज करोना महामारी पूरे दुनिया से लेकर अपने देश में फैली है । कोरोना महामारी का मुकाबला केंद्र और राज्य सरकार कर रही है लेकिन यह महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है । महोदय, लॉक डाउन के पहले जब पहला मरीज 29 जनवरी को केरल में मिला उसके बाद महाराष्ट्र में दूसरा मरीज फरवरी में मिला तब से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती गई । उस समय में संसदीय अधिवेशन चल रहा था । इसके बाद 23 मार्च को लॉक डाउन की घोषणा की गई, लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले विभिन्न देशों से हवाई मार्ग और समुद्र मार्ग से कई लोगों को स्वदेश वापस लाया गया । उन सभी यात्रियों को अगर उसी समय क्वारंटाइन करते तो कोरोना महामारी का आज का कहर निश्चितरूप से नहीं होता । दिल्ली में एक पार्टी, तबलीगी जमात में देश के विभिन्न राज्यों से और विदेश से भी लोग आये थे । लॉक डाउन घोषणा होने के बाद यह सभी वापस अपने-अपने राज्यों में चले गए, इसके कारण कोरोना का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ।

_

Speech was laid on the Table.

भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है । स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार निकल चुकी है । पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 92,605 नए मामले के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 54,00,620 हो गयी है । कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है ।

लॉकडाउन खुलने के बाद हर गाँव, शहर, कस्बे मे करोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है । देश में आज भी कई सारे जिले, तालुका और गाँव हैं, जहां आज भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा बढाने की आवश्यकता है ।

कोरोना के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है, उस्मानाबाद मे कुल 52,550 लोगों का टेस्ट हुआ है, उनमें से 10,058 लोग पॉज़िटिव पाये गए हैं । आजतक 289 लोगों की मृत्यु हुई है । आज की तारीख मे 7,051 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 2,718 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है ।

यहाँ पर इलाज के लिए काफी समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जाती रही है लेकिन आज तक यह मांग पूरी नहीं की गई है । अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाय ।

दूसरे लॉकडाउन कि दौरान लाखों मजदूर पैदल अपने घर गए । लॉकडाउन की वजह से उनको कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन दिल्ली में इकट्ठा हुए तबलीगी जमात अपने राज्य में कैसे पहुंचे यह जानकारी सरकार को नहीं मिली ।

अगर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने में चार या पांच दिन का समय मिलता तो निश्चित रूप से मजदूरों को कई किलोमीटर पैदल नही जाना पड़ता । उस समय अपने गाँव पैदल जाने के कारण कई लोगों का दु:खद निधन भी हुआ ।

इस कोरोना महामारी के काल में करोड़ों लोगो की नौकरी चली गई और कई सारे बेकार हो गए हैं । छोटे दूकानदारों से लेकर बड़े व्यपारी संकट का सामना कर रहे हैं, इसको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा । अत: प्रभावित लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर उनकी उचित मदद करने कि आवश्यकता है तथा जो भी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

आज महाराष्ट्र सबसे ज्यादा करोना से प्रभावित राज्य है । आज भी महाराष्ट्र में रोजाना 23 से 25 हजार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं यह चिंता की बात है । महाराष्ट्र सरकार ने इस कोरोना महामारी का उटकर मुकाबला किया है । मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे एवं उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आज उनकी एवं राज्य सरकार की कड़ी मेहनत से ही एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धरावी में कोरोना काबू में है तथा राज्य सरकार कोरोना के फैलाव को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है ।

इस करोना काल मे केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को दी जाने वाली मेडिकल मदद बंद कर दी है अत: यह मदद तुरंत जारी करे, जिससे महाराष्ट्र राज्य सरकार को मरीजों के इलाज करने में मदद मिलेगी । इस कोरोना की महामारी को विफल करने में सभी डाक्टरों, आशा वर्कर्स, शिक्षक,कम्पाउंडर्स, नर्सेंज, ड्राईवर्स, पुलिस के साथ प्रशासन अधिकारी और कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

*DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): It is very pertinent and appropriate at this time to discuss the effects of COVID-19 and the Government's handling of the situation.

I would like to go through the unfolding events in a chronological manner to remind the House of the events which unfolded. The first news of COVID-19 as a global threat started in November, 2019 from the news about a deadly disease killing several people in Wuhan, China. The Chinese Government announced lockdown in several regions progressively from 23rd January, 2020.

Other countries announced lockdown from as early as 12th March, 2020 and our hon. Prime Minister announced lockdown on 23rd March, 2020 which lasted for almost ten weeks. The sudden announcement of the lockdown threw the country in utter turmoil which created the following difficulties, starvation, unemployment, no access to medical supplies or help and migrant labour issues apart from complaints of discrimination and police excesses.

I would like to point out that a father and a son duo (Bennix and Jayaraj) were tortured to death by the Tamil Nadu Police and the opposition parties and public had to stage huge protests to bring the perpetrators to justice. This shows the extent of police excesses which prevailed in Tamil Nadu.

The medical facilities in the initial days of the lockdown were so unorganised that people were running from pillar to post to get admitted in the

Speech was laid on the Table.

hospitals, despite Tamil Nadu having one of the most robust healthcare infrastructures. Thanks to leaders like Perarignar Anna, Kalaignar Karunanidhi and M. G. Ramachandran.

The performance of the Governments both Central and the State were closely monitored by our Party leader, Thiru. M. K. Stalin and constructive suggestions were provided which were ignored. The Chief Minister of Tamil Nadu gave wrong information like the disease will come under control within a few days which led to carelessness by the people which further fomented the spread of infection. In addition, the deaths of several hundred people were overlooked with the dead bodies being handed over to family which further spread the disease among thousands.

Our leader Thiru. M. K. Stalin with his call for "Ondrinaivaom Vaa" which means 'let's unite' initiated the programme to feed almost one crore people and supply medical supplies for the needy. I, under the able guidance of my leader was able to feed several thousand families.

The efforts of the medical community has to be acknowledged and I would like to pay homage to hundreds, if not more, of medical personnel who lost their lives fighting this dreadful disease. It is said that the Government is unaware of the people who have laid their lives fighting this dreadful disease. I would like to urge the Government to list out the names and honour them, their efforts should not be forgotten as they are martyrs of this country.

The Government's support for the people has much to be desired. The socalled financial package was a joke with the people of this country. The poor, entrepreneurs and MSMEs were all left in the lurch to fend for themselves which led to starvation deaths, migrant labourers' deaths and closure of several thousand MSMEs.

The National Disaster Management Authority headed by the hon. Prime Minister should look into the Report of the Task Force to Review DM Act, 2013 which said that the present structure of various authorities under the DM Act are not conducive for carrying out the tasks it has been mandated to perform. Perhaps, if the PM had followed the report, the disaster could have been better managed. I hope, at least, now with lessons learnt from our shortfalls, the Government would strengthen the National Disaster Management Authority as the days ahead look gloomy with possibility of recurrence of these kinds of biological attacks manmade or godsent, and also with the precarious situation with our neighbouring countries.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): धन्यवाद सभापित महोदया, आपने मुझे एक ऐसे इश्यू पर बोलने का मौका दिया, जिससे पूरी दुनिया हाहाकार कर रही है । सबसे पहले मैं भारत के सवा सौ करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि इस काल में श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसे दूरदर्शी प्रधान मंत्री मिले, जिसके कारण से इस महामारी में दुनिया हिल गयी, लेकिन भारत अपनी जगह पर खड़ा रहा ।

सभापित महोदया, मैं आपके माध्यम से उन परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके परिवारों के सदस्यों को श्रद्धांजिल देता हूं । मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं । इस कोरोना महामारी के अंदर बहुत से लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं । हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इस मामले में नहीं भुला सकते हैं कि वे डायबिटीज से ग्रस्त होने के बाद भी, दिल्ली की स्थित में, दिल्ली में राज करने वाले लोग मैदान छोड़कर भाग गए और वह एलएनजेपी अस्पताल में खुद मौके पर जाकर, उन्होंने 20,000 बेड़ों की व्यवस्था कराई थी । मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा ।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि कोरोना है, तो कर्तव्य भी है । हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य बनता भी है, केवल राजनीति नहीं बनती है । बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपने आपको पढ़ा-लिखा कहते हैं । सामने पढ़ा-लिखा लिखवा रखा है, लेकिन वे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जैसे वे इन चीजों से अनिभन्न हैं, या उनको जानकारी नहीं है । यह संपूर्ण मानवता को झकझोरने वाली समस्या थी । इस पर सरकार ने जिस निष्ठा और कर्तव्य का परिचय दिया है, वह बगैर तथ्यों के संभव नहीं है । अभी हमारे मित्र शिश थरूर जी बोल रहे थे, फिर एनसीपी से डॉक्टर साहब बोल रहे थे । अगर आप तथ्यों पर जाएंगे, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि भारत दुनिया में कहां पर खड़ा हुआ है ।

सभापित महोदया, 24.03.2020 को भारत के अंदर 564 केसेज़ थे और केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई थीं । उसी तारीख में यूएसए के अंदर कोरोना के 46,450 केसेज़ थे और वहां पर 593 लोगों मृत्यु हो गई थीं । लेकिन उसके बाद जब हम 4 अप्रैल के आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि 24 मार्च को कोविड-19 के खिलाफ लॉकडाउन लगाकर प्रधान मंत्री जी ने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया था । उसके बाद भारत में 23,452 केसेज़ आए थे और अमेरिका के केसेज़ बढ़कर 8,80,000 हो गए थे, जिसको लोग वर्ल्ड पावर कहते हैं । यह प्रधान मंत्री जी की सूझबूझ थी कि एक महीने के लॉकडाउन

के अंदर भारत में केसेज़ की संख्या घटकर केवल 23,000 रह गई थी । जो लोग अभी अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे, मैं इन लोगों को उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा ।

एक महीने के बाद मई में भारत के अंदर 1,82,000 केसेज़ आए थे और मौतें केवल 5,000 हुई थीं । अमेरिका के अंदर आंकड़े बढ़कर 17,78,000 हो गए थे और मौतें 1,04,000 हो गई थीं । भारत से लगभग एक लाख ज्यादा मौतें हो गई थीं । ये आंकड़े हैं । मैं आगे उन आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा । अगर हम 30 जून के आंकड़े देखें, तो भारत में 5,66,000 केसेज़ थे और तब अमेरिका के अंदर 26 लाख केसेज़ हो गए थे । लोग अभी-अभी अमेरिका का परिचय दे रहे थे । पहले पायदान, दूसरे पायदान, अभी-अभी कह रहे थे । मैं उनके चक्षु खोलने के लिए जानकारी देना चाहता हूं । अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, वह भारत से चार गुना बड़ा है । अमेरिका में प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर केवल 33 लोग रहते हैं । लेकिन भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 567 लोग रहते हैं । अमेरिका की आबादी 30-32 करोड़ है । भारत की आबादी 132-133 करोड़ है । अगर उसके बाद यह सोच थी, तो देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण थी कि भारत इसको कनक्लूड करने में कामयाब रहा है ।

डब्ल्यूएचओ ने 22 मई को डॉक्टर हर्ष वर्धन जी को डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी चेयरमैन घोषित किया था । किस कारण डब्ल्यूएचओ ने ऐसा किया था? डब्ल्यूएचओ ने यह देखा होगा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इस कोरोना से बचाने का रास्ता दिखा सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही इसको कंट्रोल कर सकता है । हमें यह समझना पड़ेगा । अगर ये लोग यहां पर क्रिटिसाइज़ करें, तो सरकार को करें, लेकिन देश को न करें । दुनिया की पार्लियामेंट में अगर हमारे पार्लियामेंट की कार्यवाही की रिपोर्ट जाती होगी, तो क्या कहा जाएगा कि दुनिया तो कह रही है कि डब्ल्यूएचओ को चलाने वाले डॉक्टर हर्ष वर्धन कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे । ये कह रहे हैं कि मोदी

सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय आज क्यों लिया, कल क्यों लिया और परसो क्यों लिया । इस प्रकार ये लोग अपने आप में इफ एंड बट के आंकड़े पेश कर रहे हैं । यह देश का दुर्भाग्य है ।

अधीर बाबू, गौरव गोगोई जी, चले गए, अगर होते तो बड़ा मजा आता । आप अपने नेतृत्वों से पूछिए । ऐसा नेतृत्व है, जिनको ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वे विशेषज्ञ बनते हैं । माननीय अरुण जेटली जी ने एक बार था कि "The problem with Mr. Rahul Gandhi is, he is an expert without ...*". आज इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, मुझे लग रहा है कि वे भी उस कारण से संक्रमित हो गई हैं। अभी सहयोगी पार्टियां जो बयानबाजी कर रही हैं, they have also repeated the statement of Mr. Rahul Gandhi and they are following him. इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वे भी संक्रमित हो गए हैं।

ताली बजाओ, घंटी बजाओ, देखिए इस देश में लाल बहादुर शास्त्री के बाद, पहला प्रधान मंत्री मोदी पैदा हुआ कि सवा सौ करोड़ लोगों से अपील की और सवा सौ करोड़ लोगों ने कहा कि मोदी जी हमें आपके ऊपर विश्वास है । 50 साल तक घर चलाने वाले, घराने लोग इस देश को ...* रहे और आप थाली बजाने की कहोगे, तो हम हर चीज़ बजाने के लिए तैयार हैं । यह क्रेडिबिलिटी कहां से पैदा हुई? मोदी जी की कथनी और करनी के कारण यह क्रेडिबिलिटी पैदा हुई थी । मैं बता देना चाहता हूँ कि हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं - सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए । जब तबलीगी समाज, दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया कि 26 मार्च को कहीं पर इकट्ठी गैदिरंग नहीं होगी और वह केजरीवाल सरकार तबलीगी समाज को नहीं रोक पाई । 24 मार्च को जब लॉक डाउन लगाया गया, 25 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और जब मौलाना साद का जवाब आया कि हम नहीं हटेंगे, उनको हटाने का प्रयास किया तो ये सभी राष्ट्रीय भक्त जो अपने आप को बनते हैं, इनके मुंह पर ताले

^{*} Not recorded.

थे । अवार्ड वापसी ... * चुप था । तबलीगी समाज से इन लोगों का क्या रिश्ता है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो देश को बर्बाद कर देना चाहते थे । अभी ये बन्धु कह रहे थे कि फैजल जी के यहां अभी कोरोना का कोई केस ही नहीं हुआ है । अरे! वे तबलीगी समाज के लोग टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पॉज़िटिव निकल कर कहां से आएंगे । यह मैं पूछना चाहता हूँ ।

मैडम, इसीलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग इस देश को बर्बाद करने की नीयत से, केवल सत्ता पर बने रहने के लिए ऐसी हरकतें करने का प्रयास करते थे, उनको देश के 130 करोड़ चुन-चुन कर जवाब देने वाले हैं और दे भी रहे हैं जब बार-बार उनसे जवाब मांगा जाता है ।

मैडम, मैंने पहले भी कहा कि सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए भारत माता की जय बोली जाती है । जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पथराव हो रहा है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नर्सों के साथ अत्याचार किया जाता है, तो कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा था कि इस देश के 130 करोड़ आदमी थाली बजा कर, ताली बजा कर तुम्हारे साथ है । उनकी हौसलाअफज़ाई के लिए खड़े हो जाइए, प्रधान मंत्री जी ने कहा था । हम लोग जब बीमार होते हैं, बरामदे में खड़े हो कर दुआ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जल्दी हमारा परिजन ठीक हो जाए । क्या उसके कहने से वह परिजन ठीक होता है? ठीक तो डॉक्टर करता है, लेकिन परिवार के सदस्य और मरीज का मनोबल, उसकी इम्यूनिटी पॉवर, उसकी विल पॉवर बढ़ाने के लिए किया जाता है । वह थाली बजाने की बात कही थी या दीया जलाने की बात कही थी, तो वह कहा था, उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के लिए, उन पर फूल बरसाने के लिए । अभी मेरे एक बन्धु कह रहे थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना वॉरियर्स, जिनकी मौंत हो जाती है, उनके आंकड़े ही नहीं है । अरे! हमारे देश के प्रधान मंत्री ने सबसे पहले कोई घोषणा की थी पैकेज में, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए की

^{*} Not recorded.

थी कि अगर किसी की जान जाएगी, तो उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए पचास लाख रुपये दिए जाएंगे । यह घोषणा सबसे पहले की थी । पता नहीं कहां सोते रहते हैं या अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयान बाजी करते रहते हैं ।

मैडम, मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, कल्याण जी भी यहां से चले गए, वे भी इसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे । मैडम, 50 साल के शासनकाल में एक परिवार का व्यक्ति, एक खानदान राज करता रहा और उनके कहने से देश के दो पर्सेंट लोग हिल नहीं रहे थे । वे ... * दिखा कर बातें कर के सत्ता को प्राप्त कर लेते थे । लेकिन छह साल के प्रधान मंत्री के पीछे एक करोड़ 33 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, विदेश के लोग, दुनिया भर के लोग, जो बाहर बसे हुए हैं । इनको ताली का दर्द नहीं है, इनको दीये का दर्द नहीं है, इनको दर्द है कि मोदी जी की वजह से एक साथ लोग कैसे खड़े हो जाते हैं ।

मैडम, कोरोना फैलाने के पीछे, जैसे मैंने आपको अभी जानकारी दी, उस जानकारी के माध्यम से ही मैं यहां इन सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर जो निर्णय लिए गए, वे ऐसे एतिहासिक निर्णय थे, जो देश की सत्तर साल की आजादी में, 50 साल तक एक खानदान राज करता रहा, लेकिन वह दो पर्सेंट काम भी नहीं कर पाया । हमारे देश में पीपीई किट मात्र डेढ़ महीने में, विश्व में सैकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देश हमारा बन गया । जबिक हमारे यहां पहले पीपीई किट बनती ही नहीं थी । हमारे देश के अंदर आज साढ़े चार लाख पीपीई किट रोज बनाई जा रही हैं । मैडम, 30, जनवरी 2020 को प्रति दिन दस टेस्ट होते थे और आज 11 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, मोदी है तो मूमकिन है । ...(व्यवधान)

मैडम, मेरी पार्टी का समय बहुत है, मैं दूसरा वक्ता हूँ, प्लीज़ मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए । मैं दो मिनट में अपना भाषण खत्म कर दूंगा । टेस्टिंग लैब्स जो यहां पर नाम मात्र के लिए

-

^{*} Not recorded.

थीं, आज 1059 टेस्टिंग लैब्स हैं । डॉ. हर्षवर्धन जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनके 24 घंटे काम करने की मानसिकता से, प्रधान मंत्री कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 12-12 बजे बुला कर रिपोर्टिंग लिया करते थे । ये तो सरकारी लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स 700 अलग चल रही हैं । इस देश के अंदर पहले एक लैब नहीं होती थी । देश के अंदर 1055 हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटिड हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें 1.77 लाख बेड्स और लगभग 23,168 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई है ।

मैडम, ये आंकड़े मुझे बताने पड़ेंगे, इनके चक्षु कौन खोलेगा? आज देश को बताना पड़ेगा, ये लोग केवल राजनीति करते हैं और फैक्ट्स को रखने से डरते हैं । हम वेंटिलेटर इम्पोर्ट किया करते थे और एक आध कम्पनी अगर वेंटिलेटर बनाती थी तो इंस्ट्र्मेंट इम्पोर्ट करती थी । आज भारत 50 हजार वेंटिलेटर्स बनाने वाला देश है और जिसमें 30 हजार वेंटिलेटर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स, भारत सरकार की कम्पनी ने तैयार करके दिए । इसलिए आज रिकवरी रेट, जब यह कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तो रिकवरी रेट यहां पर 60.69 परसेंट था और आज 78 पॉइंट समधिंग रिकवरी रेट है ।

मैडम, मैं अपने साथियों, बंधुओं के लिए दोहराना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम अमरीका से ऊपर निकल गए। अरे, अमरीका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़ है। इसलिए जब उनके यहां रोजाना कोरोना वायरस के टेस्ट 11 लाख होंगे, तो आंकड़े बढ़ेंगे।

अभी यहां पर मजदूरों की बात कर रहे थे, प्रवासियों की बात कर रहे थे, यह वही सरकार है, जो विदेशों में फंसे लोगों को वंदे मातरम्, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिजन मेरे घर के अंदर रहे । अगर विदेश में है, तो उसको टेंशन होती है । मैडम, मुझे एक मिनट दे दीजिए प्लीज । मेरा भी बेटा बाहर पढ़ता है । लेकिन जब लगता है कि बेटा बाहर है और बीमारी फैल रही है, इस सरकार ने वंदे भारत मिशन के माध्यम से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से साढ़े 14 लाख लोगों को भारत में वापस लाकर उन्हें अपने घर-परिवार के साथ बैठाया था । जो लगभग 44 सौ ट्रेनें चलाई गई थीं, रेल

मंत्रालय, पीयूष गोयल जी के माध्यम से लगभग 80 लाख लोगों को उनके घर पहुँचाने और लाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ था । अब ये कहते हैं कि एकदम लॉकडाउन कैसे कर दिया? आप लोग तीन दिन का समय दे देते, वही नोटबंदी वाली आदत, सात दिन का समय देते, तो माल को हम लोग बदल लेते । इसलिए अगर तीन-चार दिन का समय दे दिया जाता...(व्यवधान) मैडम, छठ का एक पर्व होता है...(व्यवधान) मैडम, एक मिनट प्लीज, मैं समाप्त कर रहा हूँ ।

माननीय सभापति: आपका भाषण हो गया । आपको बहुत समय दे दिया ।

श्री रमेश बिधूड़ी: मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : बोलिए ।

श्री रमेश बिधूड़ी: मैडम, जब छठ का त्योहार होता है, तो लोग छ: दिनों के लिए बिहार जाते हैं, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती हैं । अगर उनको चार दिन का समय दे दिया जाता कि महामारी फैल रही है तो लोगों में अफरा-तफरी मच जाती । ये तो यही चाहते थे कि लोग अफरा-तफरी में जाकर भारत में इमरजेंसी केसेस लाखों की संख्या में हो जाए और मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए? मैडम, मैं बाकी और डिटेल के बारे में नहीं जाना चाहूंगा । मैं केवल एक जानकारी देना जरूरी समझूंगा कि जो विरिष्ठ लोग थे, दिव्यांग थे, आठ करोड़ लोगों को तीन माह तक एक हजार रुपया उनके खाते में डालने का काम किया । एक पूर्व प्रधान मंत्री कहा करते थे कि 100 रुपये जाते हैं और 15 रुपये पहुंचते हैं । 50 साल में उसको तीस रुपये नहीं कर पाए, दस साल तक सरकार रही । ये नरेन्द्र मोदी जी हैं कि सरकार में आने के बाद अगर 100 रुपये भेजे हैं तो 100 रुपये उस गरीब के खाते में पहुंचाने का काम किया । मैडम, आप मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रही हैं, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद ।

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): According to the World Bank Policy Note on 'Gender Dimensions of COVID-19 Pandemic', such pandemics are likely to affect women disproportionately more than men.

If we talk about gender implications for health, disease exposure in short term is more for women because of following factors: there is a larger share of women in the health sector, and as home and family caregivers, which makes them more exposed to contagion; occupational sex-segregation also results in different levels of exposure - women are more present in client-facing roles in retail, travel, leisure and hospitality; girls face constraints to access healthcare services - as per the report by the WHO in India, boys are more likely (and sooner) taken to a qualified health professional for treatment, than girls.

The recommendation is that providing protective equipment and materials and COVID-19 testing to higher-risk populations will be key to prevent their contagion.

As far as disruptions in reproductive health care services for women is concerned, the shift in resources towards addressing the public health emergency can entail disruptions to key health services for women, such as reproductive health services. There is for instance evidence of increase in maternal mortality due to lack of critical resources in similar crises. Pregnant women can be particularly vulnerable in this context.

Speech was laid on the Table.

The recommendation is that the pregnant women and maternity wards require particular attention during the containment phase.

Now, I am coming to gender implications for education. Given the fall in incomes of households during a pandemic, educational investment decisions are likely to be altered. Intra-household allocation of resources for schooling might be redirected to boys over girls.

The recommendation is that targeted measures needed for a section of girls with no access to ICTs (Internet and Communication Technologies).

The disruption of services with school closures can lead to an increase in the burden of care-related tasks - likely impacting girls more than boys. This will affect their ability to stay engaged in education in the longer term.

Possibility of an increase in child labour and dropouts - during the pandemic, the pressure to contribute to the family income may also increase with the tightening economic conditions, leading to permanent school dropout.

The recommendation is that financial incentive programs can help encourage families to send children back to school when the confinement phase is over.

There are gender implications for employment and economic conditions. Women will likely experience a significant burden on their time given their multiple care responsibilities as school closures and confinement measures are adopted, possibly leading to reductions in their working time and permanent exit from the

labour market. The over-representation of women among the inactive population, and in vulnerable forms of work (such as informal employment or domestic work) heightens their vulnerability to poverty in times of crisis.

The recommendations are, the effectiveness of social protection responses to the crisis can be improved if these gender dimensions are considered. Social messaging as part of the emergency response can contribute to a more balanced distribution of household responsibilities and resources between men and women. Cash transfer programs to the most vulnerable groups including women only households (for example, single mothers with children, widows or female farmers) will be necessary both as part of the emergency response and in the longer term. Specific programs to support women's return to economic activity will also play a central role. For example- public works, access to training and credit, direct provision of productive inputs to female farmers.

Gender implications within household – as regards domestic violence, an increase in gender-based violence (and its severity and frequency) due to confinement can be observed across countries. The stretched capacity of response services might reduce the protection and support available, contributing to a heightened perception of impunity among perpetrators.

The recommendation is that protection and support services need to be in place and increases in the capacity may be required. Innovative solutions to provide reporting mechanisms for women victims and to accommodate them and

their children will be necessary. Social awareness will be key, as well as engaging informal support networks and health workers.

There are some important concerns in the way the Centre handled the pandemic. The overall, India's response to the pandemic has been 'reactionary' instead of being 'preventive and precautionary'. The Centre failed to ensure sufficient availability of PPEs to frontline healthcare professionals. NGOs and State Governments responded better to the needs of citizens than the Centre. For example, as part of its efforts to ease distress caused by COVID-19, the Pratibha Foundation in association with the Yashaswini Samajik Abhiyaan has distributed protective masks, hand gloves, hand sanitizers and PPE (Personal Protective Equipment) kits to healthcare personnel at the forefront including police officers. Foundation also aided the needy households, who are strapped of their daily wage income, by providing them with basic necessities, food ration; and served prepared food daily to people stranded at the Daund railway station, Pune.

Until mid-July, 2020, there were only two laboratories in India to test and certify quality of Body-Coveralls for COVID-19. In an Unstarred Question on PPE suits (Q.No.935 on 18.09.2020), the Centre acknowledged that as of April 2020, "there were only two laboratories in the country which have the facilities as well as necessary approvals, for conducting tests on Body Coveralls (PPE) required for COVID-19. These are; South India Textiles Research Association (SITRA), Coimbatore; and Defence Research & Development Establishment (DRDE),

Gwalior. The Tests and Certifications of Body Coveralls (PPE) conducted at these two laboratories in India are the only officially recognized ones."

It was not until 16th July, 2020 that 9 other testing facilities were announced. Such lack of sufficient facilities to test PPEs could have contributed to the delay in PPE availability to healthcare workers. The High-Level Group on Health Sector, constituted by the Fifteenth Finance Commission in May 2018, headed by Dr. Randeep Guleria, Director, AIIMS, recommended shifting health from the State to the Concurrent List. During the times of a pandemic like COVID-19, effective coordination between Centre and the States, inter-state coordination is important to respond effectively to the pandemic. To enable this and to ensure a more active, responsible role for itself, the Centre can consider shifting health subject from the State List to the Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution.

The Fifteenth Finance Commission, High-Level Group on Health Sector and World Bank, met on 21st May 2020. To improve the health response mechanisms in India, the World Bank recommended focus on quality of care, centrally sponsored schemes, increasing per capita health spending among others. Given that COVID-19 primarily affects the respiratory system, it stressed that infectious diseases like tuberculosis need attention. What suggestions and comments made during this meeting, has the Centre included in its COVID-19 response plan?

India COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package (ER&HSP) was approved by Cabinet on 22nd April 2020 for Rs 15,000 Crores. How much of this Fund is actually released or spent on COVID-19 in past five months since April 20207? How much of this Rs.15,000 crore is released to the States and particularly to my State of Maharashtra? As per the data, Rs. 7500 crore has been allocated for emergency COVID-19 response; Rs. 4150 crore has been allocated for strengthening the national and State health system to support, prevent and preparedness; Rs. 1400 crore has been allocated for strengthening pandemic research and multi-sector, national institutions and platforms for one health; Rs. 1050 crore has been allocated for community engagement and risk communication; and Rs. 900 crore has been allocated for implementation, management, capacity building, monitoring and evaluation.

The Central Government has announced Rs. 20 lakh crore package to combat the impact of COVID-19 in the country. How much of this Rs.20 lakh crore was actually infused into the economy since March 20207? How much of this Rs.20 lakh crore was given to my State of Maharashtra?

The Centre was insensitive to the needs of an average citizen. After the lockdown was imposed, there was a total absence of any supporting action, to ramp up testing, expand the medical sector, to help the millions of stranded poor workers and to assist supply chain break. In an Unstarred Question on Migrant Workers, (Q.No.174 on 14.09.2020), the Centre answered that since it maintained

no data on migrant workers' deaths during pandemic, no compensation will be paid to the victim's family.

There are multiple, confusing rules and regulations issued by Central Government during lockdown. The Economist Magazine (June 13) estimated that India issued "well over 4,000 different rules" during the first two months of the lockdown, many of those rules being corrections of many of those rules. A large number of bureaucratic orders spelling rules and guidelines on a daily basis have also created chaos among many stakeholders, including businesses and the general public. According to PRS Legislative Research, there have been 4,130 executive orders from states and the Centre.

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I would like to place my views on the COVID-19 pandemic in the country. As the COVID-19 pandemic situation is going out of control day by day, the cases are increasing rapidly in tribal-dominated undivided Koraput district. Though Covid hospitals have been set up in every district, most of these hospitals are not equipped to treat serious or co-morbid patients. We have 10 ICU with ventilators in Jeypore and JK Pur Covid hospitals but these ventilators are mostly non-functional. We don't have Specialists, oxygen supply, anesthesiologists, etc. to make these ventilators and subsequently hospitals functional. After following with the State Government multiple times finally SLNMC&H has been declared as Covid hospital. I would request the Central Government to set up at least 50 ICU BED Covid hospital in Koraput and specialists deployed from outside to make these beds functional. I would also request that Covid hospitals be provided with sufficient advanced treatment to the Covid patients and constitute a team of doctors including Professors from Medical Colleges to treat the patients.

Another key issue is referrals. Patients have to travel 400-500 km. to Bhubaneswar by road which is very risky for serious patients. Hence, I would urge the Government to establish Air Ambulance leveraging the airstrip at Jeypore so that serious patients can be transferred to Bhubaneswar without risking their lives.

_

Speech was laid on the Table.

There was a draconian notification by Odisha State Government which discouraged patients from outside the State capital being referred to Bhubaneswar. Capacity has been built in Bhubaneswar, Cuttack to cater to treatments of patients from across the State. This notification prevents patients specially from tribal-dominated undivided Koraput district to avail treatment from specialised hospitals in Bhubaneswar, Cuttack. There should be clear cut directions from the Central Government to immediately stay such inhumane notifications.

COVID-19 outbreak and lockdown have impacted tribals and forest dwellers greatly. Now, the virus has spread to rural areas especially Scheduled Areas inhabited by tribals. Lack of information and awareness among the tribals and forest dwellers on the pandemic and required protective measures is a major issue in tribal areas. Tribal settlements are remotely located making it particularly difficult for information to reach these areas. The reverse migration from cities and urban areas also raises concerns about the spreading of virus in tribal areas.

Poor access of tribal and forest dwellers to PDS is reported from across the States. Provisions under the PDS are not adequately provided or are provided only to cardholders. Ensuring good and nutritious security during the lockdown in tribal/OTFD areas needs to be the highest priority. At this time PDS should be provided to all needy families and migrant workers including those who don't have any identity cards on humanitarian grounds. Insistence on Aadhar card must be

suspended during this period. Provision of ration, vegetables, cooking oil and other essentials should be made available at the doorstep.

The lockdown has affected collection, use and sale of minor forest produces (MFP) or Non-timber Forest Produce (NTFP) by tribals and forest dwellers. An estimated 100 million forest dwellers depend on MFP for food, shelter, medicines and cash income. The NFP collection season from April to June provides major income support to tribals and unfortunately it coincided exactly with the lockdown. The MSP, a major economic safety net has failed to deliver due to lack of implementation in most of the States and slashing of minimum support prices of many NTFPs by the Central Government.

The Ministry of Tribal Affairs (MoTA) has written a letter to States announcing revisions of MSP for 49 MFPs. However, what is most critical is the institutional support that does not exist for collection and procurement of MFPs with immediate payment. Proposal for providing support through Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs) and most of VDVKs are non-functional. The Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) are even more vulnerable, a special relief package for PVTGs comprising adequate grains, pulses, vegetables, oil, cash grant, soap and medicines should be provided. The migration and seasons access of pastoralists have been restricted due to the lockdown. Also, pastoral communities have been affected as the milk economy faces severe crisis as procurement and sale has been affected during the lockdown. Diversion of forest

land without the consent of Gram Sabha in violation of the FRA continues even during the lockdown. Even as COVID-19 spreads and livelihoods are affected due to lockdown there are reports of compensatory afforestation (CA) plantations being carried out on forest land used by tribals and other traditional forest dwellers including by fencing o such areas accessed for community rights. I would suggest to set up COVID Response Cell in MoTA, ensuring appropriate guidelines and instructions, raising awareness, and ensuring healthcare, ensuring food security, strengthening NTFP-based livelihoods, ensuing support to PVTGs and pastoral communities, support communities living in protected areas, prevent forest diversion and ensuring effective implementation of forest rights.

Thank you.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Madam, Chairperson. I hope, you will be as indulgent as you were to my previous speaker.

This subject is very personal to me and as I am one of the many millions who has contracted COVID and recovered from it. This is also even personal to me because we have lost a colleague from our State, Shri Vasanthakumar, to COVID. It is actually because of the relief work he was carrying out it is said, he contracted the virus and passed away. So, I would like to remember him once again before I start.

This Government's handling of the COVID-19 crisis has been a series of stumbles, blunders and missteps. It has been the story of strictest lockdown in the world. The smallest actual fiscal stimulus leading to the biggest plummeting of the GDP, only for us to become the world's COVID epicentre anyway. The Government failed to speak about the concerns of COVID in India long after the first case in January. The Government was in denial. As late as 13th March, the Government was saying that COVID was not a health emergency and, then we moved straight from inaction to an absolutely unplanned lockdown with no word on what would happen to lakhs of migrant labours stranded and no acceptance of the scale of the ordeal in which people were put through.

My eloquent colleague, Dr. Shashi Tharoor, very pertinently recollected the cycle journey, a young girl had to take with her father. Also, we have seen very

telling images of migrants walking hundreds of thousands of kilometers. In this moment, I would like to thank two of the Parliamentary colleagues from Maharashtra, Shri Shivachary of Solapur and Shri Sujai Patil. Even though both are belonging to another party but they were more than willing to help migrants from my constituency, who were working in that State, to come back to Tamil Nadu.

19.00 hrs

The Government locked down again and again. Then, again just as cases surged, they ended up opening everything. We were told to bang thalis and light candles. Perhaps, they were well-meaning gestures. But what was actually done for the Corona warriors whom this supposedly was for? Across the country, there were complaints of no necessary masks, and PPE suits for health care professionals who were being pushed to their very limits. To deal with the ramifications of the unplanned unlocks, there was no rationale in saying that this is going to be like the Kurukshetra which took place for 18 days and this will be one in 21 days. There are many sayings and there are many scholars amongst us in this House. They know the Mahabharata better than me. You know that there is no Krishna, no Drona or no Arjuna among you. If at all, there is only an inexperienced and impetuous Abhimanyu who got caught in the *chakravyuha*. This is exactly what this Government has done. Two of its decisions of the demonetisation and the unplanned lockdown have only been a chakravyuha

which Abhimanyu got in and could not get out alive. This is exactly what this Government has done.

We have no data on how many health care professionals and how many police officials have got Corona and have passed away due to Corona. Nor we know of how many migrant labourers are being affected because of this thing. We have no data on the suffering of the people of this country. Even the Gods in their battles against the worst demons have consulted each other. You all know the story of the Narasimha avatar when the Gods got together to consult on how to defeat Hiranyakashipu, but this Government, which is filled with sarvagyanis does not care to consult anybody, does not call for an all-Party meeting, does not take our views into account, and does not consult experts. All they do is in their own vortex of ignorance and they take decisions which affect everybody all the time.

Yesterday, the Finance Minister referred to number 23 and said that we need to be taking care of it. In fact, number 23 is very important. She needs to be worried about number 23. There is 23.9 per cent negative growth in the economy because of the unplanned lockdown. This is what she should be worried about. Instead of that, they are making political speeches pointing at us and asking us to be worried about certain things.

They say with great fanfare that they announced Rs.20 lakh crore package.

I do not even know how many zeros are there in Rs.20 lakh crore. This number is

a *maya*. In my opinion, even Shakuntala Devi will not know how many zeros are there. Not one person I know has benefited from this Rs.20 lakh crore. Who has benefited from this? This is just a complete *maya* which has been just announced with great fanfare. How much of this has actually reached people's hands? There is absolutely no data to suggest that this scheme is actually working on the ground.

The hon. Speaker in his opening remarks asked us to give examples of what we have done in our constituencies for this crisis. But you have taken away MPLADS. What can we do? We have no direct funds to do anything. We could have done something, if that fund was given to us. We could have directly intervened and helped our constituencies with the MPLADS fund. But this House and this Government have taken away those funds from us.

Making errors is understandable. This was an unprecedented situation, after all. The question is this. Has this Government learnt from any of the mistakes? Are lessons learnt from the costly mistakes made, to take informed decisions in the future? To this, I ask the hon. Health Minister whether we are really depending on the vaccine to get us out of this crisis. We do not know when the vaccine will come. What is the capacity of India to manufacture the vaccine? What are the plans we have to import the vaccines and how long will it take for us to get vaccines to vaccinate our entire population? What is the distribution mechanism you have to get the vaccine to everybody? Even the most

conservative estimates say that it will take up to 2024 for the vaccines to reach everybody in India.

Madam, the hop, skip, jump, and shuffle of this Government is no plan and strategy. People have no confidence in this Government. The only thing we can do is a pray. "Kadavulthaan kaapathanum." May God save us.

Thank you.

*एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमिसंह नगर): मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखता हूं । कोरोना वायरस के कारण आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा है । आज हम सब कोरोना वारियर्स, जिन्होंने कोरोना से लड़ने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें हृदय की गहराई से नमन करते हैं तथा उनके परिवारों को भी नमन करते हैं जिन्होंने यह देखते हुए भी कि एक के बाद एक कोरोना वारियर्स शहीद हो रहे हैं, फिर भी इस महायुद्ध में जाने से रोका नहीं । हम सब ऐसे कोरोना वारियर्स के माता-पिता, भाई-बहन, पित-पत्नी तथा बच्चों को दिल की गहराई से नमन करते हैं ।

भारत के दूरदर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का देश ऋणी है, क्योंकि जैसे ही 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के माध्यम से इस सूचना को प्राप्त किया कि वहां पर कोई नया कोरोना वायरस आया है, जो निमोनिया जैसे लक्षण रखता है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 24 घंटे से कम समय में यानी 8 जनवरी को ही विशेषज्ञों के समूह की बैठक द्वारा बचाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया था तथा 17 जनवरी तक पूरे देश को यानी सारे राज्यों को एडवाइजरी विस्तार से भिजवा दी थी, जबिक इस समय तक कोई भी कोविड का केस भारत में नहीं आया था । भारत में पहला केस 30 जनवरी, 2020 को आया । वह भी मेडिकल का एक छात्र जो चाइना से चला था । इस पहले केस के 162 कांटेक्ट ट्रेस किए गए । यह छात्र जहां-जहां गया, वहां-वहां हम पहुंचे । चाइना से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलूरू, बैंगलूरू से कोच्ची, कोच्ची से आगे 2 ट्रेन बदलकर इस छात्र के घर तक पहुंचे । इस बीच दो होटल, टैक्सी, प्राइवेट कार, जहाज के अंदर होने वाले कांटेक्ट को हमारी सरकार ने खोज निकाला । इस प्रकार से 30 जनवरी से कोविड देश में पहली बार प्रवेश किया ।

30 जनवरी, 2020 से आज तक 20 सितम्बर, 2020 तक चाहे आगमन का बिंदु हो, एयरपोर्ट हो, सीपोर्ट हो, जमीनी मार्ग से जुड़ने वाली हमारी सीमाएं हों, सब को जो देश में आए उन्हें सर्विलान्स किया तथा विदेश से आने वाले हर यात्री को क्वारंटाइन किया । पांच हजार गांवों के अंदर सभाएं

Speech was laid on the Table.

आयोजित कीं और जागृति के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी तब से लेकर आज तक लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग करके रोज रिपोर्ट ले रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी विशेषज्ञों की राय, राज्य के मुख्य मंत्रियों की राय के अनुसार पूरे देश को समय-समय पर संदेश देते रहे ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के राज्यों को कई हजार करोड़ रुपया कोरोना से लड़ने के लिए दिया । गृह विभाग, आपदा राहत कोष से 11 हजार रुपये हर राज्य को भिजवाया । देश में कोरोना टेस्ट करने की लैब सिर्फ एक ही थी । मास्क का नितांत अभाव था । पीपीई किट नहीं थी, बैड्स कम थे, वेंटीलेटर नहीं थे । आक्सीजन सिलेंडर कम थे लेकिन आज एक लैबोरेट्री के बजाय 1700 लैब्स से अधिक हैं । पीपीई किट 5 लाख रोज बन रही हैं । मास्क पर्याप्त मात्रा में हैं और हम निर्यात भी कर रहे हैं । टेस्टिंग किट का अभाव था । जगह-जगह परिवहन बंद होने से पीपीई किट भेजा जाना संभव नहीं था, परन्तु आज निर्बाध रूप से टेस्टिंग चल रही है । आज आईसीएमआर के अलावा पूरे देश में जगह-जगह टेस्टिंग हो रही है ।

पीपीई किट देश में न बनती थी और न ही बिकती थी परन्तु आज मात्र 110 कम्पनियां पीपीई किट बना रही हैं । मास्क बनाने के लिए 10 बड़ी कम्पनियां काम कर रही हैं साथ ही वेंटीलेटर बनाने वाली 25 कम्पनियां भी काम कर रही हैं । पहले जहां देश में 500 टेस्ट हो रहे थे, अब 22 हजार टेस्ट हो रहे हैं । इस महामारी का ज्ञान विश्व के देशों में ही नहीं था, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें । ऐसे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाया और इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण रखा । डब्ल्यूएचओ ने माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किए गए उपायों की तारीफ की । यदि माननीय प्रधान मंत्री जी चरणबद्ध तरीके से लाकडाउन नहीं करते तो आज जो स्थिति है, उससे बदतर स्थिति होती और 130 करोड़ के देश में पता नहीं कितना नुकसान हो जाता, इसका अंदाजा लगाना कठिन है । देश माननीय प्रधान मंत्री जी का हमेशा ऋणी रहेगा । हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग की । लाकडाउन के दौरान लगातार गृह मंत्रालय ने

समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर वह सब किया, जो अनिवार्य था । माइग्रेंन्ट वर्कर्स को ऐसे समय में रेल मंत्रालय ने उनके राज्यों को भेजा जिनकी करीब 64 लाख की संख्या थी ।

विपक्ष जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी में भी राजनैतिक अवसर तलाश रहा है, वह खेद की बात है । इस समय पक्ष-विपक्ष को भूलकर सबको माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए । यह वैश्विक महामारी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है । जो देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही उन्नत थे, उनके हौसले पस्त हो गए । आर्थिक तौर पर वे लड़खड़ा गए, क्योंकि इसकी दवा या वैक्सीन अभी तक कोई नहीं बना पाया है । ऐसे समय में प्रधान मंत्री जी ने देश को दुनिया के सामने बहुत ही गंभीरता से संभाला है । आज जहां विश्व की मृत्यु दर काफी अधिक है, वहीं भारत की मृत्यु दर बहुत कम है । यह भी हमारी सरकार का प्रबंधन और बीच-बचाव के साधनों के कारण ही हुआ है । यह हमारे लिए सुखद है कि हमारे देश में 92 प्रतिशत मामलों में रोग के लक्षण बहुत हल्के हैं, केवल 5.8 प्रतिशत में ही ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता हुई है । 1.7 प्रतिशत मामलों में ही रोग इतना गंभीर हुआ कि इसमें गहन स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकता हुई ।

प्रधान मंत्री जी ने मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा 14 मार्च, 2020 को आपदा प्रबंधन कानून के तहत कोविड-19 के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं पर 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया, जिसमें चिकित्सकीय आपातकालीन योजना, अस्पताल आइसोलेशन क्वारंटाइन सुविधा, रोग सर्विलांस एवं टेस्टिंग सुविधा, अनिवार्य चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मानव संसाधन का विकास एवं निर्माण, संभार तंत्र का प्रबंधन, निजी क्षेत्रों के साथ समन्वय, आर्थिक एवं कल्याण कर्मी उपाय, सूचना संचार एवं जागरुकता, प्रौद्योगिकी एवं आंकड़ा प्रबंधन, जन शिकायत, लाकडाउन से जुड़े कार्यनीतिक मुद्दों पर उचित निर्णय, जैसे पहलुओं पर पूरा ध्यान रखकर कोरोना की लड़ाई में जबरदस्त पहल हमारी सरकार ने की है । आज हमारे प्रधान मंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की तुरंत निर्णय की क्षमता के कारण देश को बहुत बड़े संकट से बचाया गया है । इसके लिए

माननीय प्रधान मंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है । हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु एवं स्वस्थ रहें ।

आइए आज हम सभी सदन के सांसद संकल्प लें कि इस दुख की घड़ी में हम सब अपने प्रधान मंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलें ।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Madam, as you know, the first case of COVID-19 in the country was reported in Kerala on 30th January this year and the patient was a medical student from Wuhan in China, where this outbreak happened first. After that, two more cases were reported on 2nd February.

From then onwards, Kerala has been at the forefront of the COVID-19 operations with the opening of a State Emergency Operation Centre.

As a result of systematic planning involving the State Disaster Management Authority and the Health Department, the State Government successfully resisted the spread of the disease in the first and second phases of the spread which was appreciated by the World Health Organisation, ICMR and even by the Central Health Ministry.

Madam, this envious achievement was possible only because of the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, ably supported by the Health Minister Smt. Shailaja Teacher and a high-level team involving the Chief Secretary.

Madam, my State stuck to five basic points – contact tracing, quarantine, isolation, hospitalisation, infection prevention, and control - to systematically prevent the spread of disease.

<u>19.05 hrs</u> (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

But Sir, all of us know Kerala has the largest number of emigrants to foreign countries in all parts of the world and other States of the country. Naturally, lakhs of people returned to Kerala from both outside and inside the country.

There was a natural increase in the number of COVID-19 patients in third phase in Kerala. The State also increased the number of COVID-19 tests gradually and as a result of the systematic implementation of the treatment plan, Kerala has become the State with the lowest COVID-19 death rate which is far less than 0.4 per cent. It is far less than the national average of 1.61 per cent.

Even in the number of tests conducted, Kerala is ahead of other States. While the case per million is 3,102 in India, it is just 2,168. Due to lack of time, I do not wish to present the statistics of other States.

If we take the deaths per million, then also Kerala is at the bottom with just 8.4 while the national average is 48. It is 11-fold in Tamil Nadu and 12-fold in Karnataka.

We constituted *Jagratha Samithis* in each and every ward led by the people's representatives of local bodies including the doctors, nurses, other health workers, police, and all those who are involved in this.

Sir, I am proud to remind all of you that only because of all these remarkable achievements, the United Nations honoured the Kerala Health Minister Smt. K.K. Shailaja teacher for leading from the front.

I will just take just two more minutes to bring to the notice of this House how the Government in Kerala tackled this pandemic which I hope will be an eye opener to the Central Government.

We are doing free testing and treatment to all the covid infected persons in Kerala. In addition to the treatment mechanism, Kerala could address all the problems of common people.

Relief package of Rs. 20,000 crore was announced by our State even before the Central Government's announcement. Free ration to all ration card holders were given irrespective of the BPL-APL category during the lock down period.

Food kit of essential commodities including cereals and oils for all ration card holders were given twice and it is to be continued for four more months. It will cover 80 per cent of the common people.

A rise of Rs. 1000 per month was made in welfare pension to benefit 60 lakh people. Special assistance for around 80 lakh employees registered under different employee welfare boards was also made. An amount of Rs. 4,000 crore package under 'Subiksha Kerala' project was also given to enhance the food security.

Free community kitchen in all local government institutions during lockdown was also provided.

What has the Central Government done so far to tackle this pandemic? Before the end of last session of Parliament on 23rd March, all the Members from Kerala have requested the Government to announce a financial package. But this Government has hesitantly announced a package of Rs. 1.7 lakh crore only and that too, only after a great criticism came from every corner.

What this Government has done was the sudden and unplanned imposition of nation-wide lockdown which forced lakhs of migrant labourers across the country to reach their homes by walking for days, many of whom died without food and water on their way.

The Government has also made a mockery of people by asking them to light lamps, clapping hands, make sounds beating plates and fly pigeons and kites and what not, so that COVID-19 will be thrown out of the country.

Some of the Ministers and some leaders of BJP Government have given messages of cowdung, cow urine and special pappads for containing the Coronavirus. Is it not a shame on our democracy because the Government which is bound to develop scientific temper is engaged in such a cheap publicity?

Actually, the Central Government should have become a model to the State Governments in this regard. Unfortunately, without giving the due share of the GST compensation and assistance from PMNRF and PMCARES to the States in

20.09.2020 857

time, the Government has again and again shown that it is a total failure in

helping the people of this country during this emergency situation.

I would request the Government to realize the problem of the common

people of this country now at least and take concrete steps to solve their multi-

faceted problems by following the example of effective governance shown by the

State of Kerala.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, we have a number of members to speak.

Now the time is seven o' clock. If the House agrees, the time of the House may be

extended up to nine o' clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): COVID-19, a biomedical disease, has serious physical and tremendous mental health implications as it is a rapidly spreading pandemic. Asian countries like India are currently facing issue of exponential growth in spread of transmission of COVID-19 in slum areas of urban cities like Dharavi in Mumbai and the under privileged localities of metro cities like Delhi.

During lockdown period in India, migrant workers had faced problems nation-wide due to sudden ban on travel, loss of income, food shortage and uncertainty about future. More than 300 migrant workers died due to lockdown with reasons varying from starvation, suicide, road and rail accidents, lack of medical care, etc. Due to COVID-19 pandemic, migrant workers faced multiple hardships. They should be provided special assistance by the Central Government as their families are facing problems to live their lives.

According to the psycho-social issues among migrant workers, they are suffering from high degree of anxieties and fears. There is no medical help from the Central Government side for the poor. People are jobless. More effective steps should be taken by the Government to prevent spread of COVID-19. Hand sanitizers and masks should also be provided to people in public places, and healthcare should be given free of cost to the common public.

_

^{*} Speech was laid on the Table

This is the time to fight COVID-19 together. Further, vaccine for COVID-19 should be given free of cost to the common man by the Central Government. In this COVID-19 times, I would urge the Central Government to give special financial package to Bengal and clear the pending amount, which West Bengal did not get from the Central Government. Our Chief Minister, Mamata Banerjee, is facing acute fund crisis. Still, she is fighting for the people of West Bengal in this COVID-19 situation.

Lastly, I thank all the doctors, nurses, and health workers who are really doing a good job. Thank you.

*SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): I would like express my views under Rule 193 regarding COVID-19 pandemic in the country. As we all are aware that the global spread of the coronavirus (COVID-19) followed by lockdowns has affected global economies including India. Government is taking several steps to ensure that we are well prepared to face the challenges and threats posed by COVID-19.

India recorded the first case of the disease on January 30, 2020. Since then, the cases have increased steadily. As on today, total 54,00,620 persons are infected. The number of deaths is 86,752. Of the total infected persons in the country, 43,03,044 patients were recovered. Globally, over 30.6 million have been infected, of which, nearly 21 million have recovered so far. At least 9,55,841 people have lost their lives to the virus so far in the world.

In order to protect the people and save the life of COVID-19 affected people, both Government hospitals and private healthcare centres in the country, particularly in Karnataka, have done great services. The doctors, nurses and all the staff including assistants worked on war footing day in and day out. They put their lives at stake to rescue the affected people from the Coronavirus; they are the real warriors. It is because of their sacrifice and sincere efforts, India has overtaken the US to become No.1 in terms of Coronavirus recoveries. As per the data, the recovery rate is 19 per cent of the total global recoveries. It is a

Speech was laid on the Table.

significant achievement of the country. I congratulate all the Corona warriors for their great service for the nation. The Union Government had also announced insurance for Corona Warriors, providing treatment free of cost if these warriors get infected by COVID-19 and in case of death, Rs. 30 lakh compensation is given to the kin.

The Union Government has taken immediate step to issue a clarification to use of CSR funds to tackle the COVID-19 pandemic. The companies were allowed to take up projects related to promotion of health care, including preventive healthcare, sanitation and disaster management.

Further, Companies (CSR Policy) Rules, 2014 were amended to enable companies to undertake CSR activities in their normal course of business for undertaking research and development of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for three financial years in collaboration with any of the institutes or organisations mentioned in item (ix) of the Schedule VII of the Act.

Apart from this, the Government of Karnataka has already converted Victoria Hospital, with 1,700 ICU beds, in Bengaluru into COVID-19 hospital. Private laboratories are already working with the Government. Further, the Government want to convert Indira Canteens in Bengaluru as fever clinics to house needy patients.

The Government of India has taken various steps for digital push in healthcare in the form of eSanjeevani and eSanjeevani/OPD. The eSanjeevani platform has enabled two types of telemedicine services viz. Doctor-to-Doctor (eSanjeevani) and Patient-to-Doctor (eSanjeevani OPD) Tele-consultations.

Under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan package, several measures were taken to rescue the overall sections of the people affected by the lockdown imposed by the COVID-19 pandemic. The package aimed at addressing lives and livelihood issues such as in-kind support like food and cooking gas, cash transfers, insurance coverage to healthcare workers, wage increase for MGNREGA workers, collateral free loans in support of MSMEs and tax relief measures to enhance the productive capacity of the economy.

Under Pradhan Mantri Garib Kalyan package, around 42 crore poor people have received financial assistance of Rs. 68,820 crore as on 7th September, 2020. Rs 3 lakh crore Collateral-free Automatic Loans for Businesses, including MSMEs and Rs 45,000 crore Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs are being provided. Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme for NBFCs/HFCs/MFIs has been sanctioned. Rs 30,000 crore Additional Emergency Working Capital Funding for farmers through NABARD is being provided. Borrowing limits of State Governments have been increased from 3 percent to 5 percent for 2020-21. Rs 50,000 crore liquidity through TDS/TCS rate reduction has been affected.

The Union Government allocated significant amount in the budget during the last six years for the Department of Health & Family Welfare. For the year 2016-17, Rs. 37,061.55 crore budget allocation was made; in 2017-18, it was Rs. 47,352.51crore; In 2018-19, it was Rs. 52,800.00 crore and in the year 2019-20, Rs. 61398.12 crore has been allocated.

With the constant efforts, the Union Government is taking all the steps to protect the lives of people of the country from COVID-19. It is the time we all need to join hands with the Union Government and our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji to combat this COVID-19 pandemic. With these words, I conclude my speech. Thank you.

*DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Assam is one of the eight North-East States of India, and often called the Gateway to the North-Eastern Region. With a population of 31.2 million (as per 2011 Census) spread over 33 administrative districts, Assam has vast geographical area of 78,438 square kilometres and shares international borders with Bhutan and Bangladesh. 2011, the literacy rate of Assam was 73.18 per cent (males - 78.81 per cent, females -67.27 per cent). The River Brahmaputra (identity for the State) traverses through various districts of state and finally joins Bay of Bengal. The core public health service in Assam is delivered through an institutional structure that includes seven functional Medical Colleges; twenty-five District Hospitals, fourteen Sub-Divisional Hospitals, 177 Community Health Centres, 946 Primary Health Centres, 54 Urban Primary Health Centres, 4,643 Sub-Health Centres (RHS 2018-19).

The Government of Assam has been successfully managing the COVID-19 pandemic adopting multi-pronged comprehensive health bv systems strengthening strategies with 3-Ts – Testing, Tracing and Treatment, fully in tune Government of India directives for COVID-19 with the management. complemented by different state specific safety net initiatives. These include need-based policies, professionalism of medical and para-medical fraternity, readiness of health facilities by bridging gaps, ensuring availability of logistics, strong support from community and frontline workers, engagement of private

_

^{*} Speech was laid on the Table

hospitals for managing non-COVID cases, technical assistance from different Development Partners, support of other Allied State Departments etc.

The strong political and administrative commitment shown by Sh. Sarbananda Sonowal, hon. Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, hon. Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam and Sh. Piyush Hazarika, Minister of State, Health and Family Welfare, a strong team of Senior Bureaucrats and Health Department Officials, Allied Department Staff and Frontline Warriors have ensured that all strategies and plans, as framed, are translated into efficiently implemented interventions. Technical support from different Development Partners such as World Health Organization (Regional Office), UNICEF, Jhpiego, Piramal Swasthya and SAATHI have been found very useful in designing need-based planning to fight back COVID-19 pandemic unitedly. In addition, plan execution partners like HLLPPT, APOLLO, GVK-EMRI, C-NES, Krsnaa Laboratories, Spandan, TBS etc. have also extended their wholesome support. All these comprehensive plans set the ground for rigorous Testing, Tracing, Isolating and Treating.

The State was able to limit the spread of the pandemic initially with only 100 cases till 17th May 2020 since the reporting of first COVID positive case on 31.03.2020. Thereafter, cases started increasing with the relaxation of lockdown and the return of many Assam's residents back to Assam, majority of them came from other COVID-19 hotspot States. To tackle the situation, Assam adopted

multi-pronged approaches with a policy which can be termed as "Assam Cares", under which the principle of very strict quarantine measure "Strict quarantine with a humane heart" has been followed. Different approaches adopted have been proved successful in managing COVID-19 pandemic.

As on 19.09.2020, Assam had 1,55,453 confirmed cases and 1,25,540 recovered cases of COVID with a recovery rate of 80.75 per cent (national 76.3 per cent) and case fatality rate of 0.28 per cent (national 1.84 per cent). (Table 1). Assam's weekly average of COVID testing in a day (period from 21-08-2020 to 27-08-2020 as in table 2) is 30,322 and the weekly average of confirmed cases in a day is 1,822, with an average positivity rate just about six per cent. The doubling time for the state is 21.8 days.

It is heartening to mention that as on 26th August the tests per million population (TPM) in Assam are 60,404 which is more than double of the national TPM of 26,685 and one of the best in the country with the mortality rate of 0.28 per cent as one of the lowest in the country.

Assam adopted an approach of 3Ts - Testing, Tracing and Treatment for management of COVID-19 pandemic in the State. This is in line with the national testing strategy aggressively, tracking comprehensively and treating efficiently. However, the State's approach is much more comprehensive and inclusive in

nature with a view to bend the curve of COVID. The broad specific actions, which are taken, are stated below:

- 1. Ensuring Sufficient availability of Personal Protective Equipment (PPE): The State ensured sufficient availability of PPEs (triple-layer mask, N-95 and PPE) to ensure that all COVID warriors feel confident to work in COVID management. The initial stock procurement made in March-April, 2020 helped us to tide over the period of absolute scarcity without significant difficulties.
- 2. Gap filling of health facilities: Gaps in health facilities, mainly Medical Colleges and District Hospitals, were assessed on a war footing scale, gaps were bridged, and facilities were made ready to manage COVID patients. The state has currently 25,750 isolation beds and 58,949 quarantine beds.
- 3. Safety and security of COVID warriors: The Health Department of Assam ensures that after every seven days of duty, each health care provider is quarantined for seven days at quarantine centers and the cost is being borne by the state. Each health care staff is tested before and after quarantine. The success of this is reflected in the low mortality of heath care workers from COVID in the state. Though approximately 1,900 plus health care workers have been infected so far, only six deaths have been reported among the health workers in Assam of which only three were associated with COVID-19 duties.

4. Training of staff, associated in clinical management of COVID: State on priority trained approximately 3,000 number of doctors, 11,000 para-medical staff and supporting staff etc. using virtual mode on clinical management of COVID and frontline health worker protection. The State also trained 700 final year MBBS students and 2,000 final year nursing students as back up COVID healthcare providers. Still continuous training is undertaken to keep them up to date in latest treatment protocols as COVID treatment protocols are evolving.

- 5. Massive IEC campaign for mass awareness of Public on COVID-19: For mass awareness generation, ASHAs are mobilized for door-to-door awareness campaign to inform community on DO's and DON'Ts of COVID-19. IEC Materials were distributed on signs and symptoms; preventive measures (use of mask, hand washing and social distancing) using different media platforms. Hon. Health Minister, Assam shares regular press briefings to inform people on COVID-19.
- 6. Active support from frontline workers in generating awareness on COVID: Support of all frontline workers (ASHA, ANM, MPW) has been found highly beneficial in reaching the last household with COVID-19 awareness messages. To ramp up testing, state started "Assam Community Surveillance Program (ACSP)" from 07th May 2020 in around 28,000 villages/wards of the State to look for SARI (Severe Acute Respiratory Infections), ILI (Influenza like Illness), fever, dengue, malaria, diarrhea cases and to carry out appropriate

testing (as per the signs and symptoms). Based on the encouraging feedback of 1st round of ACSP, state is carrying out 2nd round of ACSP with the name Assam Targeted Surveillance Plan (ATSP) - NISCHAYATA (ACSP-Phase II). Under NISCHAYATA, aggressive testing is carried out at potential hotspots, like market places, interstate truck terminals and parking lots, random testing of vulnerable people of Health department, Police, Transportation workers and Hotels staff etc. This aggressive testing approach "CHASE THE VIRUS" helped in identifying many COVID patients and starting their timely treatment.

- 7. Psychological support to patients: Understanding the psychological impacts of COVID-19 on the individual and the society, an active intervention named "Monon" meaning 'deliberate thinking', was initiated involving Psychiatry department Gauhati Medical College and LGB Regional Institute of Mental Health, Tezpur and a set of trained and committed volunteers to provide free of cost psychiatric counselling and treatment to the COVID affected persons as well as those who were quarantined. As on date, more than 32,000 patients have been contacted over phone to provide psychiatric assistance. In addition, free of cost online yoga training for patients in hospitals and Covid Care Centres is also given.
- 8. Universal screening and testing: Assam took a policy decision to quarantine everyone entering state (by air, train, and road) followed by testing and based on the test report, home quarantine is given to them, whose test report comes

negative and positive cases are taken to hospital for treatment. This approach of "Chase the Virus" was very useful in identifying many cases. Till May, 2020, Assam could test only 1.2 Lac but with the ramping up of testing facilities and testing, state could test 20.7 Lac till 26th August, 2020. From one laboratory in February 2020, now, state has 17 ICMR approved laboratories. Tests per million for Assam are 60,404 and the positivity rate is 7.38 per cent as on 19.09.2020. Of the tests being done, about 60 per cent are through RT-PCR while about 40 per cent are using the point of care rapid antigen tests. Given the low sensitivity of antigen tests, all symptomatic cases found negative in the antigen test are re-tested using RT-PCR and necessary actions are taken based on the test report. To give the facility of getting tested to people at Guwahati City, 105 COVID Screening and Counselling Centres (CCC) have been set up spread over in all the 31 wards of Guwahati. Similar facilities have been arranged in all other districts as well to facilitate public testing free of cost. These facilities provide testing and also counselling to COVID confirmed cases.

9. Setting up of Additional COVID Care Centres (CCC): Assam started setting up of additional COVID Care Centers (CCC) at different places in the state, because of the increasing COVID positive cases. Under this, existing colleges and convention centers, where available, were converted to COVID Care Centers to cater to increasing COVID positive cases. In addition, temporary

structure like German Hangers with facilities like individual cabins and toilets were prepared in war footing to admit and keep mild cases who could not practice isolation at home.

- 10.Increasing Oxygen production, storage and delivery capacity: As continuous supply of medical oxygen is one of the critical elements for treatment of COVID-19, the State Government is actively undertaking necessary steps to arrange for sufficient numbers of oxygen cylinders of various capacities to transport medical oxygen. Cryogenic tanks for keeping liquid oxygen are being established in GMCH and other medical colleges. Oxygen generation plants and oxygen concentrators are also being installed as per need. Infrastructure to provide oxygen through medical gas pipelines in hitherto unavailable areas within the hospitals is also being undertaken earnestly.
- 11. Scientific and evidence-based management of COVID-19 patients: As the COVID situation evolved, the treatment protocols also evolved in the last few months against COVID. From the initial consideration of azithromycin and hydroxyl chloroquine, treatment protocol of COVID has swiftly moved towards low molecular weight heparin, steroids, Inj Remdesivir, monoclonal antibodies like Tocilizumab and Itoluzumab, convalescent plasma etc. and the state has progressively and timely adopted all the modern treatment for COVID-19 patient management. Many COVID patients could be brought back from ICU and ventilators because of timely actions taken by the expert health providers.

12.Convalescent Plasma Therapy: Assam is one of the first states in India to bring in state of art Convalescent Plasma Bank with necessary facilities at five Medical Colleges. State has started motivating eligible cured COVID patients to donate plasma and to transfuse plasma to the needy at Medical Colleges of Assam. Till 19.09.2020, almost 1,000 people have received plasma therapy.

- 13. Participation of Private Health Facilities: In early phase, State took support from private health facilities in Guwahati, Dibrugarh and Cachar (districts with Medical Colleges) to manage all non-COVID cases while making the medical colleges functional as fully/partly dedicated COVID hospitals. Further, with the evolution of COVID-19 private hospitals are regularly supervised and kept in loop so as to ensure that standard treatment protocols are followed across the state irrespective of the status of the hospitals. In addition, free testing facilities are being extended to private hospitals also so that the citizens visiting these hospitals are not charged for testing COVID-19.
- 14.Field level COVID Warriors: Health care providers including managerial and support staff have been working selflessly towards surveillance, screening, sample collection, supply of logistics, transportation of samples to the laboratories and information sharing with the higher authorities. Continuous training and monitoring through district officials and Zonal Medical College faculties has helped in maintaining the high standards set by the Government in dealing with COVID-19 patients.

15.Facilitation of Home Isolation: State started a unique scheme of supplying necessary medicines and pulse oximeters to COVID positive patients who are asymptomatic or mildly infected and prefer to remain in home isolation. These patients are supported by telemedicine and video-consultations through esanjeevani with a tag name- SAMPARK. Over a period time, it is expected that most of the mild and asymptomatic cases will prefer to have home isolation. However, absolute awareness about the danger signs and proper knowledge about immediate steps to be taken from the patient side are very critical. Hence, efforts are being made to create awareness among public for early testing and treatment.

16.COVID Sero Survey: ICMR on request from the State, is conducting the sero survey to detect antibodies to COVID in the population to assess prevalence of the SARS-CoV-2 virus in three districts of Assam and the survey report is likely to be shared with State by early September, 2020. Depending on the feedback, the State is also planning to conduct sero survey for Antibody through ELISA-based tests in large scale, as per the requirements for future planning.

As explained above, the Government of Assam is undertaking a large gamut of activities in order to keep the citizens safe and healthy. Obviously, the Government of India policy is strictly followed with State's own innovative plans and implementation of the same. All these activities definitely have huge cost

impact and the State's own fund is not enough to meet all the expenses at the same time. Even with the Government of India's assistance the expenditure already made for COVID-19 management with the pending liabilities and future needs for this financial year alone is a huge burden on the State Government.

The major expenditures made by Government of Assam in Health Department and NHM Assam can be described as follows. COVID-19 pandemic is still continuing in the State of Assam. Audited statements from different districts are yet to be received. As such, it is not possible to provide actual expenditure done up to 15th of August, 2020.

- 1. However, State Government in Health and Family Welfare Department and National Health Mission Assam has released Rs. 1,99,72,20,000 to various districts for upgradation of existing hospitals, maintaining screening centres, quarantine centres including institutional and hotel stay, ensuring home quarantine through various methods including material assistance during home quarantine, Covid Care Centres including refreshments and sanitation, and also to combat COVID-19 at district level so far.
- State Government in Health and Family Welfare Department and National Health Mission Assam has released Rs. 3,85,50,000 to various Medical Colleges and Govt. Ayurveda College for various expenditures related to management of COVID-19.

3. National Health Mission, Assam has so far released Rs. 52,95,38,505 for incurring various expenditures on COVID -19 related testing including Rapid Antigen test kits, RPCR Test kits, RNA extraction kits, viral transport Media, outsourcing of testing to private labs etc.

- 4. National Health Mission, Assam has so far paid bills amounting to Rs. 75,81,95,087.30 for procuring various lifesaving drugs including Inj Remdesivir and other COVID specific drugs, personal protection equipment, gloves, masks, and other consumables which were used by front line healthcare workers and other departments involved in COVID related duties like Police Department, Transport Department, security forces and tea garden workers.
- 5. National Health Mission, Assam has so far paid bills amounting to Rs. 37,69,35,047 for procuring essential equipment including Ventilators, CPAP/BIPAP, Multi Para Monitors, Infrared thermometers, ICU Beds, Hospital beds and related furniture, oxygen cylinders etc.
- 6. National Health Mission, Assam has so far released Rs. 42,89,36,184 for transportation of patients (including 108 ambulance services, Adarani scheme), Mobile Medical units, health functionaries engaged in COVID duty, transportation of people from one district to another during lock down through ASTC, bringing cancer patients from other state to Assam, bringing

people from other state to Assam by Shramik Special Trains, for hiring fixed wing Aircraft etc.

- 7. National Health Mission, Assam has so far released Rs. 3,41,32,800 for undertaking various information education campaigns (IEC activities) related to COVID-19, through print and electronic media and 104 helpline especially to make people aware about COVID-19 protocols, social distancing, personal hygiene, and other COVID related information.
- 8. National Health Mission, Assam has so far released Rs 1,06,65,862 in relation to engagement of additional human resources, training and quarantine stay of frontline health workers including Doctors, nurses, lab technicians etc.
- 9. National Health Mission, Assam has so far paid Rs. 1,60,33,436 as administrative expenses including transportation of essential materials to different districts, sanitization, stationaries, computers, printers etc. in relation to COVID-19 management in the State.
- 10.National Health Mission, Assam has so far released Rs. 1,60,88,24,150 as direct beneficiary transfer for financial assistance to the needy people including Rs. 1,55,84,52,000 towards financial assistance for 3,89,613 numbers of persons stranded in different states of India during the lock down period in two installments of Rs. 2,000 each (total Rs. 4,000 per person), Rs. 4,30,25,000 as financial assistance to 889 number of Critical

Care patients at the rate of Rs. 25,000 each in two instalments (889 in first instalment and 832 in second instalment) and Rs. 73,47,150 financial assistance to 97 number of persons from Assam stranded in foreign countries @ 1,000 USD.

As indicated as above, so far the Government of Assam has released Rs. 5,79,90,31,071.30 for various expenses related to COVID-19. However, actual expenses and expenses to be incurred in the coming months for essential medicines, convalescent plasma and critical care can be finalised only after audited final report is available.

So far the State Government in Health and Family Welfare Department and National Health Mission, Assam has received Central Government funds of Rs. 72,73,00,000 for the FY 2019-20 and Rs. 1,19,10,00,000 from NHM, Government of India and Rs. 4,99,00,000 from Ministry of DoNER, Government of India, totalling to Rs. 1,96,82,00,000. In addition, Rs. 50,00,000 as insurance support have been released under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package to the family of one deceased COVID warrior already and four more are under active consideration.

HON. CHAIRPERSON: All right, the time of the House is extended up to nine o' clock.

Now, Shri Hasnain Masoodi

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब चेयरपर्सन साहब, मुझे इस बहस में शिरकत का मौका देने के लिए शुक्रिया ।

जनाब, पैन्डेमिक कोविड-19 के खिलाफ जंग का आगाज़ गफ़लत से हुआ और यह मिसमैनेजमेन्ट की एक दास्ताने-कहानी है । इसी मिसमैनेजमेन्ट की वजह से जो इंतिज़ामात किए गए, आज हमारा मुल्क ब्राजील को पार कर चुका है और अमेरिका के बाद अपने यहाँ कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस हैं । इसमें जो रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है, उससे हम सारी दुनिया में सबसे आगे चले गए हैं । कोविड-19 ने हमारे मुल्क में 31 जनवरी को दस्तक दी । जब पहली मौत हुई, जिसका पहले जिक्र हुआ कि वुहान से आए और उनका यहां देहांत हुआ और वे इसका पहले शिकार हुए । इसमें यह होना चाहिए था कि उसके फौरन बाद हमारी सारी तवज्जोह मरकूज़ होती, कोविड के खिलाफ इंतिज़ामात करने पर, उसके बजाय क्या हुआ कि हमने फरवरी का सारा महीना कुछ और मामलात पर ज़ाया किया, जिनमें 'नमस्ते ट्रंप' और कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स थे । इस पर हमारी जो क्षमता थी, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बढ़ाने पर कोई तवज्जोह नहीं दी । इसी वजह से जब लॉकडाउन का एलान किया गया तो हमारे मुल्क में करीब एक लाख से कम वेन्टिलेटर्स थे और पीपीईज़ और मॉस्क का कहीं पर नामोनिशान नहीं था ।

इसके अलावा, साढ़े तीन घंटे की नोटिस के बाद जो लॉकडाउन कराया गया, उससे तो सारा मुल्क और खासकर जो गरीब तबका है, वह एक मुसीबत में आ गया । हमारा जो मजदूर तबका है, जो माइग्रेन्ट मजदूर थे, वे बड़ी मुसीबत में आ गए । हमने जो मनज़िर देखें, वह दिल को हिलाने वाले

मनज़िर थे । हमने बच्चों की जो अम्बार देखी, हमने जो स्टार्वेशन डेथ्स देखी, वह एक अलग ही परेशान करने वाली कहानी है ।

अब जब हम जम्मू-कश्मीर के बारे में आते हैं, वहाँ के लिए 5 अगस्त, 2019 को जो कदम उठाया गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई । हम पहले से ही लॉकडाउन में थे । यह जो साढ़े तीने घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, उससे हमारे करीब एक लाख मजदूर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फँस गए । वहाँ पर उनके लिए सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था । उससे यह हुआ कि 8 हफ्ते तक उनके वतन वापस लौटने तक ताख़ीर की गई । उनमें से बहुत सारे अफेक्टेड हो गए और कोविड-19 की ज़द में आ गए । जब वे वापस कश्मीर पहुँचे या जम्मू के विभिन्न इलाकों में पहुँचे तो वहाँ और ज्यादा फैलाव हो गया, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेन्सिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था । वहाँ पर भी उनको पंचायत घरों और प्राइमरी स्कूलों में रखा गया । उसके बाद हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर दस से कम वेन्टिलेटर्स थे । ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं हुआ, बल्कि चाहे हमारे शेर-ए-कश्मीर मेडिकल इंस्टिट्यूट्स के डॉक्टर्स हो, चाहे जम्मू अस्पतालों के डॉक्टर्स हो, उन्होंने मेहनत से इसको काबू में लाया । आज तक 40,000 के करीब रिकवरी हुई हैं । अभी भी 62,000 के करीब हमारे पेशेंट्स वहाँ मौजूद हैं, जिनके लिए इंतिज़ामात किए जा रहे हैं । हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सारे के मेहनत के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आज भी काफी परेशानी है ।

इस वक्त जम्मू में आक्सीजन की कमी है । जम्मू में बेड्स की कमी है और जम्मू में मरीजों को एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ता है । एक लाख रुपये एक एम्बुलेंस वाला दिल्ली पहुंचाने के लिए और 30 हजार रुपये पठानकोट पहुंचाने के लिए लेता है । मैंने अपने एमपी लैड से डेढ़ करोड़ रुपये वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए दिए, उसमें भी ताख़ीर हो गई । यह नहीं है कि काम नहीं हो रहा है । मेरी

सूचना के मुताबिक हमारे यहां करीब 14 लाख टेस्ट्स हो चुके हैं, लेकिन इसको स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है ।

अब देखिए, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेज़ बंद हैं और सभी स्टूडेंट्स डिजिटल एजुकेशन पर डिपेंड हैं । जब फोर जी है ही नहीं, तो वे कैसे डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस करेंगे? जो ऑनलाइन क्लास हैं, उनसे वे महरूम हैं । एक जरूरत है कि जम्मू-कश्मीर की तरफ खास तवज्जोह दी जाए, तािक वहां जो भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह स्ट्रेंग्थेन हो जाए । इसके बजाए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । पैकेजेज़ के नाम पर जो नुकसान हुआ, उसका 10 पसेंट भी नहीं दिया जा रहा है । हमारे यहां 5 अगस्त से लंबा लॉकडाउन है । उसको नजर में रखकर वहां और भी प्रयास करने की जरूरत है । What happened when we were caught napping, उससे बाद में जो भी उपलब्धियां हुई, जो भी कामयाबी हुई, वह अपनी जगह पर सही बात है, लेकिन जो इनीशियल हमारी नेगलिजेंस हुई, जो गफलत इंश्योर हुई, उसी गफलत की वजह से उसी का हम आज खामियाजा भुगत रहे हैं ।

मेरी यह गुजारिश होगी कि एक तो फोर जी रीस्टोर किया जाए ताकि डिजिटल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल एक्सेस हो सके । ट्रेड बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है । HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

Now, Shri Jayadev Galla.

श्री हसनैन मसूदी:सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON: Okay, please conclude.

श्री हसनैन मसूदी: हमें टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है। खासकर जम्मू में, इस वक्त जम्मू सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो जम्मू में खासकर प्रयास करने हैं। वहां एक टीम गई हुई। श्रीनगर भी एक टीम गई हुई है, तािक काम में और ज्यादा प्रगति आ जाए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have already called the name of the next Member to speak.

श्री हसनैन मसूदी:सर, एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शुक्रिया करूं डिफेंस मिनिस्टर साहब का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब का और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने किर्गिस्तान, बांग्लादेश और ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: How much time do you need?

....(Interruptions)

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, just give me 30 seconds to thank them.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already over. I have allotted you some excess time also. But you are not completing. You are continuously speaking. What can I do?

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): I would like to place my views under Rule 193 on a matter of immense importance which not only concerns our country but also the whole world which has seen 31 million cases across the world.

I would like to thank our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji under whose leadership India has led from the front in our fight against this pandemic and Dr. Harsh Vardhan ji who has been working day and night to manage the situation in an effective manner.

The world and several institutions, including the WHO, are now looking up to India to lead the fight and the Indian model as an example to emulate. Apart from handling the health pandemic, India has also deftly dealt with the economic situation arising as a result, notable among them are the measures taken for the vulnerable sections of the society, who are the worst hit and are expectedly facing hardships.

India would now be playing a more prominent role at the World Health Organisation, WHO, with Union Health Minister, Dr. Harsh Vardhan set to take charge as Chairman of the WHO Executive Board at its 147th session.

India's response to COVID-19 has been "pre-emptive, pro-active and graded. The Government had already put in place a 'comprehensive response system" at the borders of the country, much before the World Health Organisation

_

Speech was laid on the Table.

declared the coronavirus as a public health emergency of international concern on January 30. Such a response ensured that there was no panic among the citizens and avoided inconvenience to the extent possible.

The Indian Government has also evacuated its citizens and those of its neighbours from high-risk countries, including China, Japan, Iran and Italy. The Government started screening of incoming air passengers, followed by suspension of visas and a ban on international flights were done much ahead of any other country. Italy and Spain started screening travellers 25 days and 39 days respectively after the first reported cases.

Equally noteworthy are the various public awareness campaigns. Prime Minister, Shri Modi has shown leadership in mobilizing the Heads of Governments of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and that of the G-20 to share reliable information, best practices and support each other in fighting this pandemic.

I will conclude with some suggestions to further bolster our fight against corona.

My first suggestion is, the scope of Ayushman Bharat, India's flagship insurance/assurance scheme launched with the vision of universal healthcare and leaving no one behind, should be expanded to include the 40 per cent 'missing middle' who are neither covered by private insurance nor by the Government so that any COVID-19 related expenses are covered by the Government.

My second suggestion is this. Businesses have a responsibility towards their employees. Those employees who are not on any permanent contract often become the first casualty of cost cutting measures and are the most vulnerable. It will be critical for businesses to ensure all such employees continue to get paid and that companies can partner with the Government to ensure their health coverage.

My third suggestion is this. The Constitution of India distributes the legislative powers between the Centre and the States under the Seventh Schedule. Services related to public health, sanitation, hospitals and dispensaries are categorised under Entry 6 of List II, and is the responsibility of the States. The rationale to entrust the responsibility of public health and sanitation to the States is because the health requirements vary from one State to another.

But when it comes to making effective response strategy for tackling pandemics that affect the health of the population around the country, it becomes imperative for the Union to spearhead the nationwide planning in consort with the State Governments.

In fact, given their inherent challenges, it becomes implicit for the States to look up to the Union Government for a direct intervention to mobilise their medical resources and devise efficient strategies for routing the resources where it is most needed.

With these suggestions, I conclude my speech.

*SHRI NABA KUMAR SARANIA (KOKRAJHAR): I would like to express my views on the COVID-19 discussion under Rule 193.

In my State, three Governments are functioning, namely, the Central Government, State Government and BTC. When the lockdown was declared, the BTC Assembly elections were going on. Later, on 27th April, 2020, the Governor Rule was imposed in the BTC. Till today, Model Code of Conduct is imposed there.

Yesterday, I came to know that Assam Government had written to the Election Commission of Assam to postpone the BTC elections. But I think, it is not the right solution. The people of the BTC have suffered so much during the lockdown and Model Code of Conduct. The BTC election procedure up to symbol distribution has been completed. Only six to seven days are left for competing the BTC Assembly Elections. I think, it is possible by maintaining all the COVID-19 protocols before 27th October, 2020.

So, I would request the Central Government to please advise the State Government to strictly maintain the COVID-19 guidelines in the BTC area because in their campaigning, so many parties have organised mass gatherings; and even some responsible State Ministers have participated there by violating the social distancing norms. Some were even not wearing masks.

Speech was laid on the Table.

_

So, these norms should be followed strictly. I will extend all the possible support to the State Government and the Central Government in this regard.

Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, let me start by appreciating all the frontline COVID-19 warriors, the doctors, the nurses, the healthcare workers, the Government officials, the police, the teachers, and all the essential service workers, who were attending to their duties even during the lockdown and even in the hotspots. On behalf of the entire Parliament and on behalf of the Telugu Desam Party, we salute them.

Sir, many hon. Members have already spoken about the efforts of the Government of India, the impact of the lockdown, and the migrant labour crisis, which is the biggest tragedy in this entire story. We need to introspect and ensure that it never happens again.

India is currently the second most infected country in the world after the US. The number of cases registered is the highest in the world and is only increasing by the day with no peak in sight. In terms of total deaths, we are at number three in the world after the US and Brazil. The impact on our economy has also been drastic when compared to other countries, as seen in year on year GDP figures from April to June, where we were at -23.9 per cent. Whichever way we look at it, we are facing a tough situation and need bold measures to come out of this situation.

Across the world, the stimulus responses varied from one per cent of GDP to even 25 per cent of GDP and our package was supposed to be somewhere in the middle of this. However, when the stimulus package to the tune of Rs.20 crore

was announced, we saw that most of the points were focused on resolving issues on the supply side. There was nothing to bring in additional demand.

Even at the highest estimate, the cost to Government is expected to be just ₹ 4,00,000 crore out of the ₹ 20,00,000 crore grand package which was announced. That is less than two per cent of GDP and not ten per cent as was widely publicised by the Government. There was no benefit to industry and to larger corporates.

Now, the industry and the people are looking for a second stimulus package which would focus more on the demand side. This should be focussed not only on reviving the sectors that are vulnerable and in distress, but also make cash available in the hands of the people, especially the poor migrant labourers and the daily-wage workers who have lost their livelihood.

We are all facing the same storm, but we are not sailing in the same boat. While some sectors have prospered during these pandemic times, others such as construction, travel, retail, restaurant, weavers and SMEs across all verticals have suffered the most. The package needs to be focussed on providing financial support to those industries which see the largest job loss.

Sir, the request that I would like to make here is that the insurance cover for our COVID-19 warriors is going to expire at the end of this month. As many scientists, epidemiologists and doctors have been saying that the virus is going to

stay for one or two more years, I request that the insurance scheme provided to COVID-19 warriors should be extended for at least one more year.

Finally, I come to my State of Andhra Pradesh. On 1st June, 2020 when the unlock was announced, Andhra Pradesh had only 3,600 confirmed cases in the State. After three-and-a-half months, if we look at the number of confirmed cases, it has crossed six lakhs and it is the second most infected State in the country. Why are we in this situation? It is because of the negligent behaviour of the State Government which is underplaying the severity of the pandemic. Sir, following the behaviour of their leader, the Ruling Party's Ministers, MPs and MLAs have called for huge rallies even during the lockdown period by violating the lockdown norms and guidelines.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, the Government of Andhra Pradesh has also continuously refused to supports its COVID-19 warriors, be it the doctors, nurses or frontline workers. Instead, anyone who raises his voice is harassed and arrested. A *dalit* doctor who asked for masks was beaten up by police and branded as a mad man. Another *dalit* doctor asked for increasing the number of beds in a review meeting in my constituency. The Collector has abused him and thrown him out of the meeting and threatened to arrest him. Doctors and nurses boycotted duty in Tenali in my parliamentary constituency for not being provided PPE kits. These are only some of the many incidents which depict the approach

20.09.2020

of the Government of Andhra Pradesh for controlling the COVID spread in the State.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jayadev Gallaji, it is not a political issue; it is a common issue.

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I lay on the table of the House the facts on the discussion under rule 193 on COVID-19 Pandemic in the country.

The Ministry of Health and Family Welfare acknowledged the emergence of a new coronavirus (COVID-19) that was spreading across China. The first Indian case of COVID 19 was reported on 30th January 2020. The Ministry of Home Affairs announced a 21-day lockdown to contain the spread of COVID-19 from March 25, 2020 to April 14, 2020. As the spread increased and more information about the virus was uncovered, the Central Government announced several policy decisions to contain it.

Further, measures were also announced to support citizens and businesses who were affected by such containment measures. India started point of entry screening of passengers at ports, airports and land border crossings. Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to provide relief against COVID-19, the Finance Minister announced a relief package of 1.7 lakh crore rupees for the poor. An Insurance cover of Rs.50 lakh was provided to health workers (such as doctors, nurses, paramedics and ASHA workers) who are treating patients of COVID-19. About 80 crore poor people got five kilograms of wheat or rice and one kilogram of preferred pulses were also provided for free every month. Women account holders under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana got Rs.500 per month and also free gas cylinders were distributed to the needy people.

-

Speech was laid on the Table.

The Reserve Bank of India (RBI) has constituted an Advisory Committee to review the Ways and Means Advances (WMA) limits for States and UTS. WMA limits refer to temporary loans given by the RBI to State Governments. Until the Committee submits its final recommendations, the WMA limit has been increased by 30% from the existing limit, for all States and UTs. The revised limits will be in force between April 1 and September 30, 2020.

Today's our Government has reached the level of more than 12 lakh COVID tests per day. This strongly demonstrates an exponential increase COVID-19 testing infrastructure in the country.

The country's testing capacities have multiplied manifold. From conducting merely 10,000 tests per day on 8th April, the daily average has crossed 12 lakhs today. In addition, for treatment of those affected by COVID, the Government is implementing Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana under which 601 coaches have been converted into Covid Care Centres by Indian Railways.

In all, 4621 Shramik Special trains have been operated between 1st May, 2020 to 31st August, 2020 carrying 63.19 lakhs stranded passengers to their home states. From Zero manufactures to 1100 indigenous manufacturing of PPE kits shows the Central Government achievement in tackling the problem of COVID–19. An amount of Rs.11,092 crore has been provided under State Disaster Risk Management Fund to all States to tackle COVID-19.

20.09.2020

I would like to request that 90% oxygen cylinders may be used for COVID patient and the rest 10% may be used for other chronic diseases. The steps taken by our Government to tackle the problem of COVID-19 pandemic is very praiseworthy. I am, therefore, fully satisfied and also appreciate the major allocation of funds to the States as well as to the poor people to overcome the problem of COVID Pandemic.

*SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): India's response to COVID-19 has been preemptive, pro-active and graded. The country has already put in place a comprehensive response system at its borders much before the WHO declared it as a public health emergency of international concern, which is January 30,2020.

Many of my friends are criticizing the announcement of lockdown. I would like to call their bluff and remind them if the lockdown was not announced in a sudden manner, it would have created a havoc. People distressed lining for tickets, price rise of essential commodities and travel plans, the crowded movement of masses would have spread COVID-19 from the urban to far flung distant corners of the country.

Under such extraordinary circumstances where we knew not what was the propensity of the threat from disease which originated in China, where even the WHO was misled, a good leadership leads with confidence, works for the betterment of situation and arrange for facilities needed. PM Shri Modi was able to announce the lockdown at such short notice because he had made arrangements prior to announcement, different from the Congress era when announcements were done with distant dreams of materialization in future which never happened.

Coming to PM Garib Kalyan Yojana, on March 26, when the Government announced a relief package of Rs.1.7 lakh crore under the Pradhan Mantri Garib

_

Speech was laid on the Table.

Kalyan Yojana for the poor, the Opposition was doing politics and bickering on social media tapping from the comforts of their air-conditioned homes and offices.

In pursuance of the pro-poor announcement made under the Pradhan Mantri Garib Kalyan package as part of the economic response to COVID-19, the Government of India had launched the scheme for additional allocation of foodgrains from the Central pool at the rate of five kilogram per person per month free of cost for all the beneficiaries covered under the Targeted Public Distribution System (TPDS) (AAY & PHH) including those covered under the DBT for a period of three months, that is, April-June, 2020.

Accordingly, about 121 LMT of foodgrain was allotted to approximately 80.96 crore beneficiaries entailing a subsidy outgo of nearly Rs.46,061 crore. Necessary orders were issued on 30.03.2020.

The scheme was further extended as part of economic response to COVID-19, for another five months from July to November, 2020 for distribution to all the beneficiary households under the National Food Security Act, 2013 (NFSA) at the rate of five kilogram per person per month free of cost for all the beneficiaries covered under the Targeted Public Distribution System (TPDS)/National Food Security Act (NFSA). Accordingly, about 201 LMT of foodgrains have been allotted to approximately 80.43 crore beneficiaries entailing subsidy outgo of nearly Rs.76,062.12 crore. Till June 30, 2020, Rs.18,000 crore has been transferred to the bank accounts of more than nine crore farmers and Rs.50,000

crore is being spent on PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan, which has been started to provide employment opportunities.

Coming to Aatma Nirbhar Bharat, we never took refuge behind COVID-19 pandemic to shy from our responsibilities but we saw this as an opportunity to develop India and launched the Aatma Nirbhar Bharat Scheme. Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi on May 12, 2020 announced the special economic and comprehensive package of Rs.20 lakh crore which is equivalent to 10 per cent of India's GDP, to fight the COVID-19 pandemic in India. India's self-reliance is ingrained in the happiness, cooperation and peace of the world, with the sacrosanct belief that this is the culture which believes in the welfare of the world, for all the living creatures and the one which considers the whole world as a family. Its premise is "माता भृमि: पुत्रों अहम पृथिव्य:' -the culture that considers the earth to be the mother. And, when the Bharat Bhumi becomes self-sufficient, it ensures the possibility of a prosperous world. India's progress has always been integral to the progress of the world. He gave a clarion call for Aatma Nirbhar Bharat or Self-Reliant India Movement.

To provide relief to the business, additional working capital finance of 20 per cent of the outstanding credit as on 29th February, 2020, in the form of a term loan at a concessional rate of interest would be provided. This would be available to units with up to Rs.25 crore outstanding and turnover of up to Rs.100 crore whose accounts are standard. The units would not have to provide any

guarantee or collateral of their own. The amount would be 100 per cent guaranteed by the Government of India providing a total liquidity of Rs.3 lakh crore to more than 45 lakh MSMEs.

After taking the Cabinet approval on 20.05.2020, the Department of Financial Services issued Operational Guidelines for the scheme on 23.05.2020 and the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) Fund was registered on 26.05.2020. In a short period of about one-and-a-half month, noticeable progress has been achieved in identifying units, sanctioning as well as disbursing of loans to MSMEs.

New front-loaded special refinance facility of Rs.30,000 crore was sanctioned by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) during COVID-19 to RRBs and cooperative banks. This special facility is expected to benefit three crore farmers, consisting of mostly small and marginal farmers in meeting their credit needs for post-harvest and kharif sowing requirements. When kharif sowing was already on its full swing, Rs.24,876.87 crore out of Rs.30,000 crore was disbursed as on 6.7.2020, out of this special facility.

The COVID-19 pandemic has resulted in reverse migration of urban migrants/poor in the country. The urban migrants stay in slums/informal settlements/unauthorised colonies/peri-urban areas to save cost on housing. They need decent rental housing at affordable rate at their work sites.

20.09.2020

In order to address this need, the Ministry of Housing and Urban Affairs has initiated Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs), a sub-scheme under the Pradhan Mantri AWAS Yojana-Urban (PMAY-U). This will provide ease of living to urban migrants/poor in industrial sector as well as in non-formal urban economy to get access to dignified affordable rental housing close to their workplace.

Hum Mante Hai Andhera Ghana Hai, Magar Diya Jalana Kaha Mana Hai Hum aise hi Bharat ke Vikas ke diye ki lo ko jalaye rakhenge, With this, I rest my speech.

*श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर्वप्रथम मैं बहादुर चिकित्सा सेवा कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और एसेंसियल सर्विसेज वर्कर्स की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं । यहां मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अम्बेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री एस.पी. गौतम, जो कोविड ड्यूटी में इसी बीमारी से ग्रसित होकर दिवंगत हुए, उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को यह भरोसा दिलाता हूं कि अम्बेडकरनगर सदैव उनका नाम प्रेम और गर्व से लेगा ।

हाल ही में स्वयं आईसीएमआर द्वारा 70 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे में यह उजागर हुआ कि मई, 2020 में ही 64 लाख से अधिक कोविड-19 के केसेज हो गए थे, जबिक ताजा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आज भी सरकार 54 लाख कोरोना केसेज ही बताती है । इसी सर्वे से यह भी स्थापित किया गया कि हर कन्फर्म्ड कोरोना केस के सामने 80 से 132 केस पकड़ में नहीं आए और इसी कारण कोविड देश के लगभग सभी जिलों में तेजी से फैल गया । ऐसा लगता है कि न तो पब्लिक को जानकारी है और न ही केन्द्र सरकार के पास जवाब है कि कोरोना की लड़ाई में देश किस पायदान पर खड़ा है । इन सबके बीच सरकार की भूमिका इस महामारी के दौरान स्पष्ट संचार और करुणा की नहीं थी, बिल्क सरकार ने इस महामारी को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बना दिया । जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी मजदूरों को राहत दिलाने के दौरान, अक्सर यही सुनने में आता था कि बाहर जरूरी सामान खरीदने जा ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस डंडे मार कर वापस घर को लौटा देती है । सरकार की यह कठोर लॉकडाउन पॉलिसी कोविड-19 को परास्त नहीं कर पाई, परन्तु तमिलनाडु के जेयराज और फिनिक्स को पुलिस की बीबरता द्वारा जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों मजदूरों को लाठी खाकर अपना पेट भरना पड़ा और अर्थव्यवस्था की पटरी को उतार दिया ।

मैं इस देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि कोविड-19 तो बस शुरूआत है । आगे चलकर ऐसी भ्रामक प्राकृतिक आपदाएं आना सुनिश्चित हैं । मैं हर बार जलवायु परिवर्तन से होने वाले

Speech was laid on the Table.

प्रकोपों को निरंतर इस सदन में उठाता रहता हूं और अब कोरोना महामारी ने देश की चिकित्सा व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है ।

पिछले साल सरकार ने 1.1 प्रतिशत जीडीपी चिकित्सा पर खर्च की, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये है, यानि हर नागरिक की चिकित्सा पर मात्र 1944 रुपये प्रतिवर्ष सरकार ने खर्च किए हैं। वहीं पर अमेरिका ने पिछले साल हर व्यक्ति की चिकित्सा पर 70,000 रुपये और चाइना ने हर व्यक्ति पर 28,000 रुपये खर्च किए। स्वयं की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार इतनी बेपरवाह क्यों है? क्योंकि आज नागरिक अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आंदोलित नहीं हैं और अगर होते तो शायद आज कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और तैयार होती, लाखों लोगों को इलाज के लिए दर-दर भटकना न पड़ता और हजारों लोगों को मौत के घाट न उत्तरना पड़ता।

देश में चिकित्सा व्यवस्था की यह दुर्दशा है कि गर्भवती महिलाओं को, डायलिसिस के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को सुचारू रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए । मेरे क्षेत्र के दुबौलिया गांव में ईंट के भट्टे में काम करने वाले झारखंड के एक मजदूर की बीवी को डिलीवरी के दौरान खून न मिल पाने से जच्चा और बच्चा, दोनो की मौत हो गई । जैनापुर गांव के एक पुरुष को एक्सिडेंट के उपरांत कोविड पॉजिटिव निकल जाने के बाद अस्पताल से ही निकाल दिया गया और मरीज की मृत्यु हो गई ।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें हेल्थ वर्कर्स का कोई दोष नहीं है । वे प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं । दोष व्यवस्था का है – हमारे देश में न पर्याप्त सरकारी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स हैं और न उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है । ऊपर से जनसंख्या का इतना दबाव है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पड़ जाता है । आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, मरीज भेड़-बकरी की तरह ठूंसे पड़े रहते हैं । वहां अनुकम्पा की घोर कमी दिखती है ।

सरकार को आज आगे की रणनीति स्थापित करनी पड़ेगी । क्या सरकार चिकित्सा सुविधाओं को लेकर प्रतिबद्ध है? क्या सरकार अपनी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी के सपने में चिकित्सा व्यवस्था पर 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो जीडीपी का मात्र 6 प्रतिशत होगा और अन्य विकसित देशों से फिर भी कम ही होगा? क्या मतदाता भविष्य में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार का आकलन करेगा और क्या वह अपने मत से अपना फैसला सुनाएगा?

यदि मतदाता यह नहीं करता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रकोप का हम कर्तई सामना नहीं कर पाएंगे । मैं यह अपील सरकार से न करके मतदाता से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिकित्सा व्यवस्था जब तक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर नहीं उभरेगा, जिस पर जनमानस प्रगतिशील कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर नहीं करेगा, तब तक देश के 130 करोड़ लोगों का अस्तित्व खतरे में रहेगा । सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए । सरकार के सीने में नहीं, तो जनता के सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri E.T. Mohammed Basheer.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, COVID-19 is spreading very fast in the country. We have heard the Treasury Benches, but what exactly is the truth? If we ask a question to ourselves whether the Government did what they were supposed to do, the reply will be in the negative. They have done nothing. They were taking only a lukewarm attitude towards the disease.

Sir, the WHO declared health emergency worldwide in January, 2020. When most of the countries were making maximum preparedness to meet the challenges, what were we doing here? We were putting the beautiful slogans 'Namaste Trump' and 'Hello Trump'. Their announcements for candle revolution, *diya* revolution and *bartan bajao* ended in a mockery. Their strategy of declaring the acclaimed lockdown at the midnight of 25th March, 2020 was a senseless thing. There are no words to explain the hellish experience our brothers, the migrant workers, had faced.

Sir, a loud thinking is required here. The most important thing is the need for scaling up of financial protection scheme for the vulnerable and the poor people. With regard to healthcare intervention, larger healthcare goals at minimum cost should be the motto of the nation. Then, increasing the overall growth rate of Indian economy and increasing the budget allocation for healthcare are interlinked. Have they ever thought of health sector related issues in this country? Poor healthcare spending is still continuing.

Poor health infrastructure is also a problem. Have you thought of widening the health insurance? Manpower shortage in the healthcare sector is also a burning problem. Your Government is having a handicap. Instead of admitting your mistakes and taking remedial actions, you are handing over the baby to somebody else.

I will give you an example. One of your Cabinet Ministers – I do not want to name him because that is against the procedure – described the whole Tablighi Jamaat people as Talibani Jamaat people. A Minister is coming out with this kind of senseless statement! Then, what happened? Finally, the Aurangabad Bench of Mumbai High Court has categorically said, "These are all meaningless statements". He got a befitting reply. I demand, in the light of Aurangabd Bench of Mumbai High Court remarks, this Minister should apologise for his senseless utterance. That is what I am demanding.

Now, we have to come to the ground reality. What is your team doing? Amidst this COVID-19 crisis, you are spreading communal violence. Two or three days back, an MP, who was a medical professional also, was saying that this country is going to face oxygen shortage. When I heard that, I was really shocked. ...(Interruptions) We have to be very careful. The treatment to this disease is connected with oxygen. But what is happening? If that shortage is there, kindly take timely action to have sufficient oxygen. I read your statement that India is oxygen surplus. So, you have to think of these things.

With your kind permission, I am going to conclude. Instead of making tall and false claims, admit the mistakes that you have committed and take remedial actions.

With these few suggestions, I shall conclude. Thank you very much.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय सभापित जी, कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई है । आज भारत में संक्रमण के आंकड़े 54 लाख के पार हो चुके हैं और लगभग एक लाख संक्रमण के केस रोज सामने आ रहे हैं । हमारी सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं ।

अब देश में दस लाख टैस्ट प्रति दिन हो रहे हैं और अब तक लगभग 6 करोड़ 37 लाख टैस्ट हो चुके हैं । मैं आज इस अवसर पर कोरोना वारियर्स **यानि** मीडियाकर्मी, सफाईकर्मी, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों का अभिनंदन करना चाहती हूं, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर इस महामारी का मुकाबला करने का प्रयास किया । जिन कोरोना वारियर्स ने इस महामारी के दौरान अपना जीवन गंवाया है, मैं उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करती हूं ।

महोदय, मैं तीन-चार बिंदुओं को उठाना चाहती हूं । The first point that I want to talk about is that. It seems India in this COVID-19 times is also moving towards a mental health emergency. I say this because the fear of coronavirus, the lockdown stress, the economic slowdown, and the loss of jobs have left people fearful, isolated and depressed. This depression is taking every age group in its grip, whether young or old.

You would be surprised to know that there has been an increase in the web search for the word 'suicide' in the past one month, which is like an emergency alarm. The WHO says that India is one of the countries in the South-East Asia region which has the highest rate of suicides.

The 2019 Report of the NCRB says 18 to 35 years of age group is the most vulnerable, and 36 to 45 years of age group is the second most vulnerable when it

comes to suicide. The Lancet 2019 Report also says that one in every seven Indians suffers from a mental health issue. So, in today's times, we are definitely moving towards a mental health emergency. I expect the hon. Minister of Health and Family Welfare to wake up to the cause and intervene immediately by not just building awareness about these mental health issues but also by addressing the 87 per cent glaring shortage of mental health professionals in the country. दूसरी बात कोविड-19 के लांग टर्म इफेक्ट्स के बारे में है । जो मरीज कोविड-19 पोजिटिव हुए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, रिकवर हुए, उनके अंदर भी लांग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं । इस बीमारी में सबसे ज्यादा लंग्स को नुकसान पहुंचता है । लंग्स खराब होने की समस्या भी देखने को मिल रही है । There is scarring of lungs or pulmonary fibrosis problem seen in patients who have recovered from COVID-19. Twenty to thirty per cent of the lungs are not functioning in case of such patients.

This damage is irreversible, if it is not detected in time. अगर, इसके बारे में हमें समय से पता चल जाता है तो हम इसकी गित को कम कर सकते हैं । इसके अलावा, कार्डियो वैसकुलर कांप्लिकेशन्स, डायबिटीज, अल्जाइमर, हेडेक कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल सिम्प्टम्स और सेंसर डिस्टबेंसेज भी देखे जा रहे हैं । It would be good, if we know about this; if we are aware about this and as a nation, we are prepared to deal with this next situation which is arising for us.

तीसरी बात, मैं कहना चाहती हूं कि कोविड-19 के दौरान बॉयो मेडिकल वेस्ट जेनरेट हो रहा है, उसको इकट्ठा करने वाले लोग भी बहुत जोखिम उठा रहे हैं । क्योंकि, ऐसे लोग प्रयोगशालाओं और अस्पतालों से बॉयो मेडिकल कचरा इकट्ठा करते हैं । हर रोज कई सौ किलो कचरा जलाने की

जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है । भारत के अंदर 20 लाख कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, जिनमें एक लाख बीस हजार के करीब चौदह वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं । ये सभी लैंडफिल साइट्स पर जाते हैं, बिना ग्लब्स और बिना मास्क के कूड़ा बिनते हैं, जिसमें बहुत सारा बॉयो मेडिकल वेस्ट होता है । उसमें कोरोना वायरस के टेस्ट कीट्स, पीपीईज और खून से लथपथ कॉटन होता है । ऐसे तमाम मेडिकल वेस्ट के कारण जीवन को खतरा है और जीवन की सुरक्षा की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है । इसको मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं ।

चौथी बात, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे बीच में सबसे बड़ी समस्या एसिम्प्टोमैटिक साइलेंट स्प्रेडर्स की है । बिना लक्षण वाले मरीज, जो बड़ी तेजी से और गुपचुप तरीके से, जिनको खबर नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है, वे हमारे बीच में घूम रहे हैं और वायरस के स्प्रेड को बढ़ा रहे हैं । इनका पता कैसे लगाएं, इसको लेकर सरकार के क्या प्रबंध हैं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चहूंगी । Sir, I am just concluding. सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं । Whether it was an 'act of God' or it was an act of human being, that is still debatable ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Nobody could have predicted it. But, now, all we need to do is to work collectively to win this battle against Corona virus and keep taking all precautions in terms of using mask, sanitizer and maintaining social distancing, building our immunity and upgrading our health structure. That is all I want to say. Thank you very much.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): सभापित महोदय, मुझे 8 मई, 2020 की वह सुबह आज भी याद है, जब सुबह-सुबह मुझे फोन आया और यह जानकारी मिली कि 16 मजदूर जो मध्य प्रदेश जाना चाह रहे थे, वे ट्रेन के नीचे आकर मर गए । मैं जब उस जगह पर पहुंचा, जहां उन मजदूरों की मौत हुई थी, वहां पुलिस वाले थे, मैंने पूछा कि कितने लोगों की मौत हुई, ये बॉडीज कहां पर और किस अस्पताल में ले जाई गई हैं? मुझे बताया गया कि ये लाशें अभी भी वहीं पड़ी हुई हैं । लाशों का मतलब यह था कि वहां पर छोटे-छोटे गोश्त के टुकड़े पुलिस वाले थैलों के अंदर भर रहे थे । उस दिन टेलीविजन के ऊपर यह खबर चलाई गई कि एक्सिडेंट के कारण 16 मजदूरों की मौत हो गई । लेकिन, मैंने उस दिन भी कहा था, आज एक बार फिर से यहां पर दोहराता हूं कि वह एक्सिडेंट नहीं था, बल्कि हत्या थी । उस हत्या के जिम्मेदार हम सब लोग हैं, जिन्होंने उन मजदूरों को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया था । यह महज एक इक्तेफ़ाक हो सकता है कि उसी दिन अखबार में यह खबर आई थी कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनके लिए विशेष प्लेन चलाए जाएंगे । क्या हमने उन मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि हमें इनकी याद सिर्फ इलेक्शन के वक्त आती है? जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए विशेष प्लेन का प्रबंध किया गया था ।

सभापित महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज छ: महीने के बाद क्या हिन्दुस्तान का एक भी शहर यह दावा करके कह सकता है कि हमारे पास पर्याप्त वेंटीलेटर्स हैं, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सक्षम है? आज भी जिस शहर के हॉस्पिटल में वेंटीलेटर्स हैं, वहां डॉक्टर्स नहीं हैं, जहां डॉक्टर्स हैं, वहां ऑक्सिजन नहीं है और जहां वेंटीलेटर्स हैं, ऑक्सिजन है और डॉक्टर्स भी हैं, वहां बेड्स उपलब्ध नहीं हैं । जब हमने आपसे वेंटीलेटर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा कि थाली बजा लो । जब हमने आपसे कहा कि डॉक्टर्स नहीं हैं, ऑक्सिजन नहीं है तो आपने कह दिया कि दिए जला लो, अंधेरा कर लो । आज जब जीडीपी इतनी गिर गई है तो हम सरकार की तरफ से एक फरमान सुनना चाह रहे हैं कि कब आएंगे वज़ीरे आज़म और यह ऐलान करेंगे कि अब सड़कों पर

निकलों, ढोल बजाओ और यह ऐलान करो कि उठ जीडीपी, उठ जीडीपी, जिस तरह हमने गो कोरोना, गो कोरोना का ऐलान किया था । हमने अपना मजाक पूरे मुल्क में नहीं, बिल्क पूरी दुनिया के सामने बनाया था । चाइना के अंदर इस बीमारी का जन्म हुआ । इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर यह पली-बढ़ी । जैसे ही यह भारत के अंदर आई तो इसने हिन्दू और मुसलमान की शक्ल इख्तियार कर ली । मंत्री जी, हमें बड़ा अफसोस होता है, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद यह कहते हैं कि यह बीमारी इस देश के अंदर तब्लीगी जमात की वजह से फैली । अगर कोई कसूरवार था तो वह आपकी सरकार है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए । लेकिन, इस प्रकार से ऐसे मौकों पर जब लोगों की जानें जा रही थीं, उस वक्त हम हिन्दू-मुसलमान कर रहे थे ।

सभी टेलीजिवन चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा था कि यह बीमारी अगर हिन्दुस्तान में फैली है तो सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से फैली है । अगर किसी की तरफ से कोई गलती थी तो आप बोलिए, आपकी ही सरकार है ।...(व्यवधान) आप मुझे दो मिनट और दीजिए ।

सभापित महोदय, आज हमें मालूम है कि संकट गहराया हुआ है । हम सरकार का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम विपक्ष में है तो हर चीज की आलोचना कर रहे हैं । आपने मेहनत की है, कोशिश की है, लेकिन जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, उनसे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुल्क के अंदर लोकतंत्र है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि तानाशाही है । आप चार घंटे पहले आकर कहते हैं कि चार घंटे बाद देश बंद हो जाएगा और देश बंद कर दिया गया । आज यही हालात रहे तो इस मुल्क के वजीर ए आलम को देखकर हम यही कहेंगे कि बोलें तो बोलें क्या और करें तो करें क्या, वाह मोदी जी वाह ।

*SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): At the outset, I wish to thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, for effectively handling the COVID-19 pandemic.

By taking speedy and seemingly harsh measures prioritising the health of the citizens of the country, PM Modi Ji has ensured that India has one of the lowest COVID-19 deaths per million population. An early lockdown called by the PM potentially saved upto 70,000 lives and more than 29 lakh cases. While India stayed indoors and obeyed the Prime Minister's call, he constituted the PMCARES Fund for supplying ventilators and improving the health infrastructure of the country. After India entered the unlock stage, Prime Minister Modi unveiled a slew of reforms in the form of the Atmanirbar Bharat Scheme to mitigate the economic hardship faced by MSMEs, street vendors, migrant labourers and practically every other citizen. Similarly, the PM Garib Kalyan Ann Yojana ensured that no citizen would go hungry despite the country experiencing the worst global pandemic in a century.

My State Karnataka, under the leadership of hon. Chief Minister Shri B.S. Yedurappa, has also managed to control the pandemic effectively. True to its tag of being the Tech Capital of the country, my city Bengaluru utilized technology and implemented unique solutions to assist citizens during the lockdown and beyond.

_

^{*} Speech was laid on the Table.

Soon after the lockdown was announced, we set up a Bengaluru South MP Coronavirus Task Force with the help of more than 4,000 dedicated volunteers to attend to citizens' emergency requirements. The Task Force volunteers are available 24/7 on the number 99464 99464. We formed area-wise WhatsApp groups to assist senior citizens, pregnant women, migrant workers and other distressed people during the lockdown period. They extended all non-COVID medical support in the form of assistance in procuring medicines and groceries, delivering food packets to the needy and also feeding stray dogs. They also provided free and compassionate psychological counselling. The Task Force also tied up with cab aggregator Ola to provide free taxi rides to hospitals for non-COVID medical emergencies.

During the lockdown period, the MP Coronavirus Task Force handled 5,000 individual requests, provided 2,600 free Ola cab rides to hospitals, served 4,50,000 meals served to underprivileged sections and migrant workers and handed out 35,000 free ration kits for the migrants and needy.

Bengaluru further proved its credentials of being the startup capital of the country when we established the Home Line, what is possibly India's first WhatsApp bot-enabled e-commerce platform.

The Home Line was a phone number (080 61914960) accessible both by call and WhatsApp set up for the home delivery of essentials from your nearest grocer or medical store in Bengaluru. We brought together 30 competing startups

from Bengaluru, mapped every retailer in the city and unleashed about 10,000 delivery executives to take essentials to the doorsteps of citizens. Using Cloud Calling system of Kaleyra, call center employees of (24)7.ai, working for the Home Line, would note the order for groceries or medicines and generate a ticket. The ticket would be passed on to a delivery executive from Dunzo, Swiggy, Rapido, Shadowfax or House Joy. The delivery executive would proceed to purchase the items from the grocer or medical store located closest to the caller and deliver the items.

During the lockdown period, the Home Line of Bengaluru received 17,059 orders on WhatsApp and 2,137 orders placed on phone. It enabled the delivery of 14,049 orders and served 30,000 people in Bengaluru.

Bengaluru finally opened up during the Unlock phase and we noticed an increase in the number of daily cars. We once again came up with a technology solution to handle the outbreak called COVID Raksha.

COVID Raksha can be accessed by phone and WhatsApp by using the same helpline number 080 6191 4960. Citizens can report COVID-19 symptoms, enquire about test, request for doctor assistance and expert advice and seek guidance on turning positive and take initiative to reach out for urgent care. It also facilitates the shifting of patients in distress to hospitals across Bengaluru.

The Office of the MP partnered with Swasth, Project Stepone, Kaleyra, Fortis Hospitals, (24)7.ai, ACT Grants, Cartoon Mango, SRL Diagnostics, Hey

Doc, Pharmeasy, Portea Medical, ITW Consulting and Spykke Technologies to power the platform.

Through COVID Raksha (as on 10th September), we have answered 10,700 calls from citizens on the coronavirus infection and conducted 3,465 sessions on WhatsApp. We have completed 1,698 triaging of symptoms on Swasth and facilitated 582 hospital transfers. The COVID Raksha so far has handled 96 advanced emergency cases and provided life-saving care to citizens in Bengaluru.

I would like to thank citizens for enabling us to serve them. I also would like to thank the Prime Minister once again for showing exemplary leadership during such times. Together, we will fight this pandemic.

*SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): I would like to place my views under Rule 193 regarding COVID-19 pandemic in the country.

The latest data shows that 54 lakhs 620 cases confirmed cases and around 86,752 deaths and 43,03,044 patients have already been cured as on today.

India is the second largest democracy in the world with the population of more than 135 crore. In such a big country to enforce a lockdown and prevent people to stop their daily activities and business is not a matter of joke. It is known to all of us.

Even then, our Union Government under the leadership of Shri Narendra Modi *ji* has taken very effective steps to impose the lockdown to protect people. As a Prime minister of the country, he has taken a very bold step. He did not think twice about the ill effects of the economic situation caused by lockdown. He gave top priority to save the lives of people of the country. He took the people of the country into confidence by interacting with them frequently through the National media and 'Mann Ki Baat' programmes. I congratulate the hon. Prime Minister for his bold initiatives. And I am thankful to the people of the country for showing their respect and honor the words of the hon. Prime Minister.

"In a landmark global achievement", India has overtaken the US to become No.1 in terms of coronavirus recoveries, accounting for close to 19 per cent of the

_

Speech was laid on the Table.

total global recoveries. It is because of the great sacrifice done by the healthcare service providers.

In order to protect the people and save the life of covid-19 affected people, both Government hospitals and private health care centers in the country particularly in Karnataka have done great services. The doctors, nurses and all the staff including assistances worked on war footing day in and day out. They put their lives at stake to rescue the affected people from the coronavirus. They are the real warriors. I am thankful to all the corona warriors for their great service for the nation.

This is reflected in the Government Response Stringency Index measured by Oxford University, which says that India enforced one of the most stringent lockdowns.

Our BJP Government in the Center and also in the state of Karnataka have taken several measure to manage situation risen out of the COVID-19 pandemic on a war footing, "Dedicated hospitals for the treatment of the infected, fever clinics and Covid care centres in Bengaluru and in all other district headquarters of the State were set up, apart from quarantine facilities to identify and isolate the infected persons".

On May 12, Government announced Atmanirbhar Bharat Abhiyana Package, a special economic and comprehensive package of Rs. 20 lakh crore - equivalent to 10 per cent of India's GDP - to combat the impact of

the COVID-19 pandemic in India. Later on, the lockdown was considerably eased in the months of July, August and September. Now there is a gradual improvement in growth of Manufacturing, core industries, E-way bills, Kharif sowing, power consumption, railway freight, cargo traffic and passenger vehicle sales, etc.

The Government has launched Ayushman Bharat program and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana for the people. Under this, the Government provides health coverage of Rs. 5 lakh per family, per annum, to more than 10 crore poor and vulnerable families, for secondary and tertiary care hospitalization. Our BJP Government is making all the efforts sincerely to augment the health infrastructure to combat COVID-19 pandemic in the country.

As far as the budget allocation is concerned, in the interim budget of 2019-20, around 2.2 per cent has been allocated to the Department of Health & Family Welfare. During the year 2015-16, Government health expenditure is 1.18 per cent of GDP. The allocation is constantly increasing during the BJP Government for the last six years. The National Health Policy, 2017 envisages increasing public health expenditure to 2.5 per cent of GDP by 2025. Our BJP Government is making all the efforts to achieve this target.

With the constant efforts and encouragement of the union Government a major achievement made by Tata CRISPR in finding an advanced test for Covid-

19. The Tata CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) test achieves the highest accuracy levels than the traditional RT-PCR tests. It takes quicker turnaround time and less expensive equipment and better ease of use.

With these words I conclude my speech. Thank you.

*SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Thank you Sir, during this COVID-19 pandemic, I am reminded of the 19th century era when plague spread in Kolkata, and Swami Vivekanada sent across the message that it was not the time for religion; the only religion would be service of humanity. He asked Sister Nivedita to dedicate herself for the service of mankind – no politics, no religion, only humanism. Today at the time of Corona virus, lakhs of Vivekanandas and Niveditas have dedicated themselves in serving the humanity.

Thanks to the foresight of Prime Minister Narendra Modi ji, India went for this early nation-wide lockdown following the overwhelming popular response to Janata curfew on 22 March, 2020. यह एक एतिहासिक सिद्धांत है कि करोड़ों-करोड़ों देशवासियों की जान बचाई है और उनको सतर्क किया है । From being an importer of PPE Kits in March, within the next couple of months, India became the world's second largest producer of PPEs, N95s, and other personal protective gears. The case fatality rate of 1.61 per cent and COVID-19 deaths per million population is one of the lowest in the world. हमने मोदी जी की दृष्टि से प्रेरणा लेकर आपदा को अवसर में बदला है । This vision of transforming negative into positive has laid the foundation for an Atmanirbhar Bharat Abhiyan. A Special Economic Package of Rs. 20 lakh crore was announced by the Government. Nearly, 80 crore poor people were given benefits of 5 kg wheat or rice per person and 1 kg dal; 20 crore women Jan Dhan

_

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Bangla.

account holders got Rs. 500 for three months; and free-of-cost gas cylinders were provided to eight crore poor families.

West Bengal was giving Rs. 191.19 crore in Grants-in-Aid for COVID-19, job cards and free rations were supplied to migrant workers. They were provided Shramik Special Trains for their return.

It is very unfortunate that Chief Minister of West Bengal commented that the Shramik Special Trains were actually Coronavirus special trains which were coming to spread Coronavirus. Just yesterday, Finance Minister Nirmala Sitharamanji said that the poor people of Bengal will not the benefitted from the Garib Kalyan Rozgar Yojana because the Government of West Bengal has not given any data with respect to the migrant labourers.

Rs. 2000 crores were provided under PMGKY to 8.7 crore farmers but the farmers of Bengal were deprived of the benefit. Under Ayushman Bharat Scheme when people are getting free of cost treatment, the Chief Minister is resorting to politics. उनके हिसाब से दिल्ली के दंगों पर से फोकस हटाने के लिए कोरोना का इश्यू लाया गया था । वे कहते है कि जैसे सरकार डेंगू से डेथ की संख्या हर साल छुपाती है, वैसे ही कोविड-19 से हुई डेथ की संख्या भी छिपा रही है । वे कहते हैं कि उन्होंने इसको छिपाने के लिए एक पांच सदस्यों की टीम बनाई थी जिसमें एक भी पेंडेमिक का डॉक्टर नहीं था । अगर बाहर से सेन्ट्रल टीम नहीं आती तो हम एक्चुअल पिक्चर नहीं देख पाते । Rs. 2,000 was provided under the PM- KISAN to 8.7 crore farmers. On the one hand she is drawing circles in the market and on the other, she is asking the world to come and see how medical treatment is

being provided in her state. Hospital bills are skyrocketing – Rs.10 lakhs, Rs.20 lakhs Rs.50 lakhs – and such bills were handed over to the poor patients for payment. To show a dead body, someone asked for a bribe of Rs.51,000 – this is so shameful. They have illegally sold the kidneys, pulled the dead bodies mercilessly through the road as unclaimed bodies. Everybody has seen the video but the Government is claiming that it is a fake video. The number of deaths has also been fudged.

In Bengal, lockdown violations got so common -- thanks to the populist appearement politics of Mamata Banerjee -- in pockets of Kolkata like Kidderpore, Rajabazar, Metiabrus, referred to as mini-Pakistan by Mamata Banerjee's Minister, that they witnessed rampant lockdown violations since April.

It is no surprise that Mamata Banerjee's Government is the only State Government to not furnish data on *Tablighi Jamaat* attendees to the Union Government. Even lockdown dates were changed because of Muharram. केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे राशन को ... * ने दुकानों पर बेच दिया । इसलिए लोगों ने टीएमसी के खिलाफ नया स्लोगन दिया । ... * यही स्लोगन वर्ष 2021 में टीएमसी को बंगाल से हटाएगा । टीएमसी के नेताओं ने ... * किया और ... * का किया गया । डेथ की संख्या को ... * द्वारा छिपाया गया था और ... * को गया था ।

* Not recorded.

एम्बुलेंस बुलाने से लेकर हॉस्पिटल में बेड लेने तक, पेशेंट्स को उठाने से लेकर उनकी बॉडी को जलाने तक, हर जगह पर टीएमसी ने \dots^* लिया है । A young boy of 18 years, Subhrajit Chatterjee did not get admission to any hospital and he died on the lap of his mother. His body lay on the road for one and a half hour. Police officers instead of helping agitated on that spot. The PPE kits sent by the Centre were returned only because they were orange in colour. Our doctor opposed on the social media and he was immediately put behind bars. The dead bodies were lying on the hospital beds, unattented. When these were made into viral videos, mobile phones were banned inside the hospital premises. Even women were not spared. They were raped, murdered, and burnt. Radharani Naskar was shot dead because her husband is a BJP worker. 15 BJP workers were killed even during the lockdown. I salute lakhs of policemen, doctors, nurses, and safai workers who are working tirelessly during these difficult times. I can only say in the words of Rabindranath Togore,

'O my lord,

Kindly remove all fear of people,

Fear of administration,

Fear of death from this unfortunate country.

This huge burden on the suppressed,

This continuous pain,

* Not recorded.

_

This prostration on dirt everyday,

Punishment every moment,

This disrespect of self,

Inside out,

This bondage of slavery,

Bowing down of head before others every now and then -

Sacrifice of human dignity -

Do away with this burden of shame.

Let us stand upright in the infinite sky line

Amidst liberal light and open air'

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Mr. Chairperson, Sir, COVID-19 undoubtedly has brought in devastating effects in every sphere of life. It has brought in untold miseries and sufferings to the people throughout the world but some had contained it with efficient management and some have bungled it with mismanagement.

Sir, the first case of COVID-19 was reported in India on the 30th of January. On the same day, the World Health Organisation also declared COVID-19 to be a public health emergency. Since the 30th of January, till the 22nd of March, there were no tangible measures taken by the Government of India. On the 22nd of March, there was of course 'Janta Curfew', followed by *Taali Bajao* Campaign, and *Diya Jalao* Campaign. Despite various prescriptions like *Bhabiji Pappad*, Patanjali *Baba* syrup, etc. COVID-19 grew stronger; it grew all the while as if with vengeance. As of today, India, my country, has 15 per cent active cases of the globe. It is frightening. If this galloping rate goes on, probably in one and a half months' time, India would touch one crore cases. This has to be taken very seriously.

In my State of Assam, we are facing the brunt of the COVID-19 menace. In my State, there are 548 reported deaths, out of nearly 1.56 lakh of cases, as of today. We have a low case of fatality rate - around 0.35 per cent. It is one of the lowest, though not the lowest. This is personally a cause of happiness, relief for

me and the State but certain new facts have emerged which challenge the existing data. I request you, Mr. Chairperson, Sir, to allow me to bring attention to these facts.

The fatality rate of Assam is apparently low because the Government has ignored the deaths of several people caused by COVID-19 on multiple occasions. The Death Audit Board set up by the State Government to help capture the unreported deaths has reportedly discounted the deaths that should have been considered COVID-19 fatalities. Such underreporting of deaths has caused pain and anguish to several families who have lost their loved ones to COVID-19 but the Government has failed to acknowledge their deaths caused by the virus by not adding their names to the list of COVID-19 deaths.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI PRADYUT BORDOLOI: What is alarming is that as many as 550 cases till yesterday have been omitted even after they were confirmed by the labs because the patients had other co-morbidities. Is it ethical that the COVID-19 cases confirmed by the labs have been discounted from the mortality list? Is it aimed to portray a better health management and efficiency? Or is it just another trick of the one-upmanship that we have in this country today? I would request the Government to look into this matter, and the Government should direct the Indian Council of Medical Research to step in because it might make people more complacent about the dreadful virus.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापित महोदय, आज कोरोना विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं एनडीए की सरकार को धन्यवाद दूंगा और प्रधान मंत्री जी तथा लोक सभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि कोरोना काल के अंदर दोनों सदन चले और पूरे विश्व में एक संदेश गया कि यदि आम आदमी कोरोना काल में सांस ले सकता है, तो हम सांसद, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और तमाम अन्य लोग भी ऐसे समय में देश के लिए काम कर सकते हैं । हमारे पूर्ववक्ता बिधूड़ी जी ने बताया कि गृह मंत्री जी ने अस्पतालों का दौरा किया । हमारे मंत्री डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने और हमने बधाई भी दी थी । मंत्री जी ने कोरोना काल में अच्छे प्रबंध किए । पिछले छ: महीने में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया और इस वायरस ने घुटनों के बल गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति को ला दिया । हम इस खौफ के दौर से गुजरे हैं । हमने देखा कि कई मंत्री, कई सांसद और कई विधायक तथा कई मुख्य मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए । अमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड जहां मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और जब भारत में कोरोना आया तो कहा जा रहा था कि वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज्यादा मौतें होंगीं ।

मैं प्रधान मंत्री जी का शुक्रिया करता हूं और हिंदुस्तान की जनता के साहस और हिम्मत को बधाई देता हूं कि हर मुश्किल स्थिति का सामना किया और हमारे यहां मौतों का आंकड़ा बहुत कम रहा । अमरीका ने हिंदुस्तान से हाईड्रोक्सीक्लोराइड दवाई मंगाई और कम से कम 150 देशों को हमने दवा दी और हम विश्व गुरु बन गए । भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था और अब फिर कोरोना के अंदर सारे विश्व ने फिर भारत लोहा मान लिया । डोनाल्ड ट्रम्प जी ने मोदी जी की तारीफ की, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान मंत्री की तारीफ की कि वे अच्छा काम कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी ने राज्यों को राहत पैकेज दिया । दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां विपक्ष की सरकारें थीं, उन्होंने पैकेज भी ले लिया और केंद्र के माथे ठीकरा फोड़ने का काम किया । मैं राजस्थान की बात करूंगा ।

राजस्थान की बात करते ही आप नाराज हो जाओगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से हैं । हमारे राजस्थान में मौतों का आंकड़ा 1704 मौतें हुई, उसकी जगह आंकड़ा 1293 दिया गया ।

उन्होंने 411 मौतें छिपा लीं । मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में 4,058 मरीज थे, लेकिन स्टेट उन आंकड़ों को 3,017 बता रही है । कोरोना काल में राजस्थान की जनता तकलीफ में थी, पूरा देश तकलीफ में था, लेकिन ... * राजस्थान की यह बानगी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ।

सभापित महोदय, प्रधान मंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया था, अगर उसके हिसाब से राज्य सरकारें चलतीं, पूरा देश चलता तो इस देश में कोरोना से इतनी भयावह स्थित उत्पन्न नहीं होती । कहीं न कहीं राज्य सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम भी किया है । मैं किसी समाज विशेष के खिलाफ बात नहीं करूंगा,...(व्यवधान) लेकिन 16 मार्च को तबलीगी जमात की जहां से बात आई थी, बिना परिमशन के तबलीगी जमात 23 मार्च को यहां पर इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने 24 मार्च को उनको हटाया ।...(व्यवधान) मैं नहीं कह रहा हूं कि कोरोना केवल तबलीगी जमात से ही फैला है, लेकिन 80 प्रतिशत कोरोना देश में तबलीगी जमात से ही फैला है ।...(व्यवधान) मैं हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not go into any controversy. Please conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, बोलने के लिए एक मिनट का समय दे दीजिए । मैं राजस्थान को छोड़ कर दिल्ली की तरफ आ रहा हूं ।

सभापित महोदय, जैसे ही प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया कि माननीय सांसद एक माह का वेतन सहायता कोष में देंगे । इन्होंने कोविड के लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष के नाम से अलग से फंड बनाया है । मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये इमीडिएट वेंटिलेटर्स, एन-95 मास्क और पीपीई

.

^{*} Not recorded.

किट के लिए मार्च में हाथों-हाथ स्वीकृत किए गए थे और एक महीने में सारा सामान खरीद कर पीएसी और सीएसी के पास पहुंचा दिया गया ।

इस मामले में अब हमें सोचना है कि चीन की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत थी, वुहान से वायरस निकला, जिससे वर्ल्ड में चीन की इज्जत खराब हुई है । लोग वहां से निवेश किया हुआ पैसा निकालना चाहते हैं, वहां से उद्योगपित भाग रहे हैं । ताइवान और जापान उनको अपने यहां न खींच पाएं, इंडिया में वे उद्योग निवेश करें, इसके लिए इंडिया को अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए, जो विदेश से ज्यादा से ज्यादा बड़े उद्योगपितयों को इंडिया में निवेश करने के लिए आकर्षित करें ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Your time is over.

श्रीमती नवनित रिव राणा (अमरावती): सभापित महोदय, इस महामारी में कोरोना वॉरियर्स, जितने भी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेज, वार्ड इंचार्ज, पुलिस डिपार्टमेंट, साफ-सफाईकर्मियों का कोरोना की वजह से निधन हो गया है, पहले मैं उन सभी को श्रद्धांजली देती हूं । आज जितने भी कोरोना वॉरियर्स हर अस्पताल में लड़ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूं । हमारी जान बचाने के लिए सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं, पर हम ने ऐसे सैनिक अस्पताल में खुद देखा है, जिनके परिवार के 18 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हों और वे अस्पताल में कोरोना से लड़ रहे हैं । पीपीई किट पहन कर आठ-आठ घंटे सिस्टर्स, वार्ड इंचार्ज और डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करते हैं । हमें अस्पताल में देख कर यह पता लगा कि आठ घंटे पीपीई किट पहन कर काम करने में कितनी तकलीफ होती है । जब फीमेल डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करती हैं, तो मैंने उनकी तकलीफ को देखा है । जब मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तब मैंने उनसे बात की है । मैं हेल्थ मिनिस्टर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी । I think I was the first person who wore a mask and came into this House to attend the session. हमारे सभापित महोदय कुछ नहीं कहते हुए भी सिक्योरिटी के लिए यह पहना है, you should wear it.

आज महराष्ट्र की बहुत बुरी हालत है । महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो मैं हेल्थ मिनिस्टर जी से विनती करती हूं कि हमारा क्षेत्र एक जिला होने के बावजूद वहां साढ़े दस हजार लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं । वहां बहुत कम प्राइवेट अस्पतालों को गवर्नमेंट ने एम्पैनल्ड किया है । मेरी आपसे विनती है कि हमारे पूरे विदर्भ में ऑक्सीजन की कमी है । अगर आप चार जिले में ऑक्सीजन का एक टैंकर सप्लाई करते हैं, तो जिनको ऑक्सीजन की सचमुच में जरूरत है, उन्हें आज ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है । आइनॉक्स एक कंपनी है । आपके माध्यम से उन्हें एक आदेश दिया जाए कि हर जिले में ऑक्सीजन का एक टैंकर रोजाना सप्लाई हो ।

जिससे मृत्यु की संख्या को रोका जा सके और जिन्हें ऑक्सीज़न की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सके । मैं आपसे विनती करती हूं । महाराष्ट्र में आज 10 प्रतिशत प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिजर्व किए गए हैं, उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, I have fought with this Coronavirus. So, let me please talk on this because I have known this personally. हम लोगों ने पहले दिन से हेल्थ मिनिस्टर जी और एक्सटर्नल अफेयर्स से बात करते-करते आज इन चीजों को यहां तक पार किया है । जिन 10 प्रतिशत हॉस्पीटल्स को रिजर्व किया गया है,I will definitely request the Health Minister कि महाराष्ट्र में उसे 50 प्रतिशत किया जाए, ताकि जो लोग बिना बेड, बिना ऑक्सीजन और बिना ट्रीटमेंट के मर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए आपकी मदद की बहुत जरूरत है ।

हेल्थ मिनिस्टर जी से मेरी एक कंप्लेंट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब हम इनिशियली कोरोना पॉज़िटिव होने पर एडिमट होते हैं, तो प्राइवेट हॉस्टिपिटल्स में डॉक्टर्स ने नहीं एस्पेशियली हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक का बिल हमारे रिलेटेड लोगों ने दिए हैं । यह बात मिनिस्टर साहब को भी अच्छी तरह से पता है ।

हॉस्पिटल्स में जिस वैक्सीन से हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक रेंडिसिवल और दूसरा टोसिला जुमैब है । मंत्री साहब मुझे यह बोलते हुए दुख होता है कि जिस हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट किया गया है, जिस वैक्सीन की कीमत केवल 4,000 रुपये हैं, I myself was the victim, I have paid Rs. 11,500 for that vaccine. Regarding Tocilizumab medicine, I have seen my family-related persons who have got this Tocilizumab medicine. What is the actual price of it? It is Rs. 38,000 and we have got it for Rs. 1 lakh. So, I just

wanted you to make a squad on that, जितने भी लोग इस दवाई को ब्लैक में सेल कर रहे हैं, उन पर कानून के तहत सजा का प्रावधान किया जाए । मैं आपसे यह मांग करती हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, one last minute please. I would not ask you anything else. महाराष्ट्र में कोरोना जिस तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसके लिए मैं आपसे मांग करती हूं कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र पर राष्ट्रपति शासन लागू करके केन्द्र उसे ओवर रूल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को महाराष्ट्र के लोगों को बचाने का काम केन्द्र करे । मैं दिल से यह विनती करती हूं ।

HON. CHAIRPERSON: You have to understand the limitation of the Chair.

*श्रीमती नवनित रिव राणा: हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मेरा गांव मेरी जवाबदारी है । महाराष्ट्र के ... ** मुझे उनसे एक प्रश्न करना है कि ... ** ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: How many times will you ask for one minute? Please conclude.

श्रीमती नवनित रिव राणा: सर, यह बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 वर्ष के होने के बावजूद श्री शरद पवार गांव-गांव में घूम रहे हैं।...(व्यवधान)

_

^{*} Hindi translation of the speech originally delivered in Marathi.

^{**} Not recorded.

*श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): आज कोविड 19 वैश्विक महामारी कोरोना चिंता का विषय है, जिससे आम व्यक्ति प्रभावित है । हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है । विभिन्न आपदाएं किसी क्षेत्र में आई हैं, लेकिन इस आपदा से पूरा देश प्रभावित है । मृत्युदर अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भी नहीं है । अमेरिका में 1.6 लाख थी । ईटली ने चार्टर विमान भेजे, ट्रेनें लगाई, बसें लगाई । अमेरिका जैसे संपन्न देश की स्थित गड़बड़ाई, उत्तर प्रदेश की जनंसख्या के बराबर अमेरिका की जनसंख्या है । वहां 1 ½ लाख से भी अधिक मृत्युदर होना आश्चर्यजनक है ।

भारत में टेस्टिंग बढ़ी, वेटिलेटर के माध्यम से अन्य देशों की भी मदद की, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद करता हूं । पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ । प्रधान मंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन किया, जिसके कारण 130 करोड़ आबादी के देश ने राहत महसूस किया ।

सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क लगावाने का काम किया गया । स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारियों ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए बढ़चढ़कर ड्यूटी दी । उनका सम्मान और अभिनंदन करना चाहिए जो अपने परिवार की चिंता न करते हुए लोगों को सुरक्षा, दवाई और स्वच्छता दे रहे है । जहां ज्यादातर उद्योग-धंधे बंद हो गए, वहीं लोगों की खाने खिलाने की चिंता की गई कि कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे । देश में स्थान-स्थान पर मोदी कीचन चलाया गया, कई संस्थाओं ने भी व्यवस्था की, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया, 5 किलोग्राम प्रति यूनिट चावल/ गेहूं, 1 किलोग्राम दाल दिया गया, जिस पर कुल खर्च नब्बे हजार करोड़ रुपये का खर्च आया है । दिव्यांगों के खातों में सीधे पैसा गया है ।

कई प्रदेश सरकारें व्यवस्था संभालने में फेल हो गई थी तो केन्द्र सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आगे आना पड़ा । दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि

Speech was laid on the Table.

बाहर स्टेट वालों के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है । यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था । स्थिति गड़बड़ाई, न ही टेस्टिंग हुई । माननीय गृह मंत्री जी और स्वास्थ मंत्री जी को आगे आना पड़ा तो टेस्टिंग बढ़ी, सभी के लिए हास्पिटल में व्यवस्था बनी ।

आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय पर लॉकडाउन के कारण राहत महसूस कर रहा है । अन्य देशों ने भी इसकी सराहना की है ।

*श्री मलूक नागर (बिजनौर): मैंने 12 मार्च, 2020 को पार्लियामेंट में कोविड-19 से संबंधित यह मुद्दा उठाया था कि अगर सरकार उस समय ध्यान दे देती तो देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह नहीं होता । मेरी 12 मार्च,2020 की छोटी सी स्पीच थी, जिसमें तीन मुद्दे थे । पहला यह था कि विदेश से आने वाली फ्लाइट्स को तुरन्त रोका जाए । दूसरा यह था कि जो भी विदेशों से लोग आ रहे है, उनकी एयरपोर्ट पर ही जांच हो और अगर कोई भी कोविड-19 से अफेक्टेड हो तो उन्हें सीधे क्वारंटीन किया जाए और तीसरा यह था कि कोरोना की महामारी के बाद सरकार देश की अर्थव्यवस्था व व्यापार को बचाने के लिए क्या सोच रही है ।

सरकार अगर उपरोक्त विषयों के बारे में सोच लेती तो विदेश से आने वाले तबलीगी जमात के लोग आते ही नहीं और यह बीमारी उनके द्वारा नहीं फैलती, लेकिन सरकार अपनी गलती मानने के बजाय पूरे देश के एक खास समुदाय को बदनाम करती रही है । 12 मार्च, 2020 को मेरे द्वारा मुद्दे को उठाने के बाद अगर मजदूरों को तुरन्त आठ दिन में अपने-अपने घर जाने के लिए बोल दिया जाता तो सभी मजूदर जो देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज (दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कलकत्ता) व देश की अन्य सभी जगहों से अपने घरों को चले जाते, लेकिन दिनांक 24.03.2020 की रात को अचानक जो जहां पर था, उसको वहीं पर रोक दिया गया । इससे जो लोग जहां थे, वे वहीं फँस गए । करीब दो माह बाद जब लॉकडाउन खुला तो देश के मुख्य-मुख्य राज्य, जो लेबर से जुड़े हुए थे, उनको खोल दिया गया । उसके बाद सभी मजदूर अपने-अपने घरों को जाने लगे, लेकिन उनको रास्ते में बहुत ही दिक्कतें हुईं, जिसको बयान करना बहुत ही कष्टदायक है ।

अगर दिनांक 12.03.2020 के आठ दिन बाद सभी को अपने-अपने घर भेज दिया जाता तथा दो महीने बाद देश के सभी कार्य, जिनमें मजदूरो की जरूरत पड़ती, उनको सरकार अपने खर्चे पर बुला लेती तो आज देश के सभी चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज व देश के अन्य सभी कार्य ठीक से चल रहे

Speech was laid on the Table.

होते । पूरे देश की बिल्डिंग्स जिनमें बायर्स की गाढ़ी कमाई का धन लगा हुआ था, वे प्रोजेक्ट भी बच जाते व देश के सड़कों के प्रोजेक्ट व सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर भी सही से चलते रहते और देश के सभी मजदूरों को भी बचाया जा सकता था । देश के किसानों को बंद करने के बजाय उनकी फसल बचाई जानी चाहिए थी । उनके दूध की बिक्री कराई जाती तो किसानों को भी बचाया जा सकता था । अगर सरकार उपरोक्त विषयों पर की तरफ ध्यान देती तो देश के सभी व्यापारियों, देश के किसानों तथा बीमारी को रोका जा सकता था । उन सभी को बचाकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता था । उससे देश में खुशहाली होती तथा देश का नाम विश्व के पटल पर उच्च शिखर पर होता ।

मैं, सरकार का ध्यान फिर से दिनांक 12.03.2020 की मेरी स्पीच की तरफ दिलाना चाहता हूं । आज फिर से यूरोप और खासकर इटली में कोविड-19 की शुरुआत हो गई है । इसलिए सरकार उस पर तुरन्त ध्यान दे तथा एडवांस में इसके लिए तैयार रहे, जिससे देश के लोगों को, व्यापार को, नौकरियों को और देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके ।

धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohan S. Delkar.

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे कोरोना महामारी जैसे गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, हम सब यह बात मानते हैं कि आज हमारा देश कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। करीब-करीब 90 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आज करीब 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यह एक गंभीर स्थिति है और हम इस बात को समझते हैं। हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा की भारत सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए गए हैं, अगर वह कदम न उठाए जाते, तो आज क्या स्थिति होती? हमें यह बात भी समझनी पड़ेगी। मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे देश में जैसे ही इस महामारी ने प्रवेश किया, उसी समय जितने कदम उठाए गए और खास कर लॉक डाउन, जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हुआ और इसके साथ ही हमारे कोरोना वारियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए जितने भी कदम उठाए गए, वह बहुत ही सराहनीय थे।

20.00 hrs

इसके साथ-साथ जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कदम उठाए गए, मैं समझता हूँ कि वे सारे सराहनीय कदम थे । 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या वाले देश में हम इसे कंट्रोल कर पाए, तो उसके पीछे भारत सरकार के ये सारे सराहनीय कदम हैं । इस मौके पर हमारे लोक सभाध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ । जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, हम सब अपने-अपने घरों में थे । उसी समय हमारे अध्यक्ष महोदय ने सभी एमपीज से कांटैक्ट किया, उनका हालचाल पूछा, उनके स्वास्थ के बारे में पूछा । आज भी जब यह लोक सभा चल रही है, लोक सभा शुरू करना भी हमारे लिए एक चैलेंज था । एक तरफ तो एमपीज के स्वास्थ के बारे में भी सोचना था और दूसरी तरफ लोक सभा भी चलानी थी । हम तो न्यूज में देख रहे थे कि

हमारे अध्यक्ष महोदय ने स्वयं पूरी लोक सभा की विज़िट की और देखा कि क्या सुविधाएँ हैं, क्या सुविधाएँ दे सकते हैं, इसके कारण आज हम यह चैम्बर भी देख रहे हैं । हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी बढ़िया सुविधा होगी । इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

सर, मेरा प्रदेश दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव है । दादरा नागर हवेली के जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ । उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा बल के कर्मचारी और टीचर्स हैं । मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । हम तो यूनियन टेरिटरी से आते हैं । हमारा यूनियन टेरिटरी सीधे गृह मंत्रालय के निर्देश से चलता है । यहाँ पर माननीय किशन रेड्डी जी बैठे हैं । मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जी और श्री किशन रेड्डी जी का, यहाँ पर माननीय स्टेट होम मिनिस्टर श्री राय साहब भी बैठे हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इनके निर्देश पर, भारत सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देश पर हमारे यहाँ कोरोना कंट्रोल में है । वहाँ अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं । हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स- डॉक्टर्स, नर्सेज, सुरक्षा बल के लोग और टीचर्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, Sir, first of all I salute all the warriors who worked in this COVID-19 pandemic. Those are doctors, nurses, policemen, sanitation workers and NGOs. Our State Government of Tamil Nadu has already incurred Rs. 7,200 crore on various relief measures and upgradation of health infrastructure and further a sum of Rs. 2000 crore is needed for which our hon. Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu have already requested the Government of India to provide Rs. 9,000 crore

as a special grant to Tamil Nadu out of Rs. One lakh crore loan raised by the Government of India from the Reserve Bank of India. Currently, more than 80,000 tests are performed per day at a cost of nearly Rs. 4 crore per day. Hence, I request the Central Government that at least 50 per cent of the cost of testing should be covered under PM CARES Fund as it is a more effective strategy to control the spread of COVID-19 virus. As far as Tamil Nadu is concerned, due to COVID-19, only 8,751 deaths have been reported. Out of five lakh cases found positive, 4.81,000 patients have been discharged from hospital after treatment. This is due to effective performance of our State Government and Health Department. In my view, good governance and key policy of our NDA Government led by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi will help the country in fighting against this unprecedented challenge and let us hope India will come out of this pandemic in near future. The hon. Health Minister is sitting in this House. I thank the Union Health Minister and Prime Minister for permitting the establishment of AIIMS hospital to be set up in Tamil Nadu. In one year, they have approved 10 medical colleges to Tamil Nadu. But our DMK colleague Mr. Dayanidhi Maran, during his speech, intended to create panic among Hindu-Muslim unity, thereby wrongly focusing that Muslim brothers were blamed for spreading this coronavirus.

I strongly condemn it. Our Prime Minister has been treating all Indians equally. On behalf of AIADMK Party, I would appeal you to compel him to withdraw his views.

Our Tamil Nadu Chief Minister and the Deputy Chief Minister have taken various necessary steps to bring back Tablighi Jamaat Muslims from Delhi to Tamil Nadu. I am thankful to the Union Government; the hon. Prime Minister, the Home Minister, the Railway Minister and all others. Thank you, Sir.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सीरियस इश्यू पर मुझे बोलने का मौका दिया । सब लोगों ने अपनी-अपनी बातें की, सारे लोगों के ख्यालात आपके पास आ गए हैं । मैं समझता हूं कि हमको कम से कम हैल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि लिमिटेड सोर्सेज़ के बाद यह ऐसी बीमारी आई, जिसका किसी को पहले से ख्वाब भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है और जब आएगी तो इतने लंबे समय तक रह जाएगी । अभी भी यह नहीं पता है कि यह बीमारी कितने दिन और चलने वाली है ।

अतः मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपने सोर्सेज़ को और बढ़ाइए । सर, आप यहां जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्टेट्स में उसका असर नहीं जा रहा है । मरने वालों की तादाद, जो आप लोग अपने टेलीविजन या रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, वह बहुत कम है । लोग बहुत परेशान हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम कितना लैक कर रहे हैं, इसका आपको अंदाज़ा इस वक्त हो रहा होगा कि कई हज़ार मरीज़ों के लिए हमारे पास एक डॉक्टर एविलेबल है । हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्सेज़ नहीं हैं, नर्सेज़ हैं तो मेडिसिन नहीं है और अगर मेडिसन भी है तो अभी महाराष्ट्र की महिला एमपी बता रही थीं कि वाकई एक आदमी का एक दिन का कितने रुपये का बिल आ रहा है । कल ही मेरे कुछ रिशतेदार गुवाहटी में एडिमट हुए, उनको रोज का एक लाख रुपये का बिल देना पड़ रहा है । ये गरीब लोग एक लाख रुपये कहां से लाएंगे? चाहे वे कुछ भी कर के ये पैसे लाएं और ज़िंदा रहें या फिर मर जाएं ।

इसलिए, इस किस्म की चीज़ों पर पूरे हिन्दुस्तान में आपको ध्यान देना है, पूरे हिन्दुस्तान में इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना है, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना है, हॉस्पिटल्स की कमी को पूरा करना है, जिन फैसिलिटीज़ की कमी है, उनको पूरा करना है । इसीलिए, मेरा आपसे आग्रह है कि हम, जो सारे यहां बैठे हैं, यहां विपक्ष के लोग भी हैं और पक्ष के लोग भी हैं । हमें हिन्दुस्तान को एक भी रखना है और इस बीमारी से मुकाबला भी करना है ।

हमारे कई बंधुओं ने तबलीग़ी जमात की बात की । मैं भी यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा मामला था, जिसको लेकर कम्युनल बात करने की जरूरत नहीं है । वह एक ऐसी जमात है, जो पूरी दुनिया में भलाई के नाम और भलाई के काम को फैलाती है । तबलीग़ी जमात के लोग पूरे इंडिया में एक लाख भी नहीं आए, क्या उन्होंने पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैला लिया? यह तो बिलकुल मानने की चीज़ नहीं है ।

चेयरमैन सर, इसी के साथ मैं यह कहूंगा कि बेरोज़गारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे इंडिया में फैल रही है और हमारे यहां असम गंवर्गमेंट ने, जो हमारे यहां सरकारी मदरसे हैं, उनमें कई लाख टीचर्स हैं और कई लाख बच्चे उनमें पढ़ते हैं, उनको बंद करने का ऐलान किया है । इसको सरकार जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करे । इसी तरीके से हमारे यहां दो ही इन्डस्ट्रीज़ हैं – एक नगांव पेपर मिल है और एक कछाड़ पेपर मिल है, जहां बेरोज़गारी बहुत हो रही है । कई लोगों ने फांसियां लगा लीं, कई लोगों ने खुदकुशी कर लीं । मुझे सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस बेरोज़गारी के ज़माने में इन चीज़ों को न करने का असम गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी, प्राइम मिनिस्टर इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उन लोगों की सैलरीज़ का जो करोड़ों रुपये बकाया है, वह उनको अदा करेंगे ।

इसी के साथ मैं आपको शुक्रिया देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक-यू वैरी मच।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): हमारे देश में एक ऐसा संक्रमित वायरस जीवन में पहली बार आया है और इसके भोगने के कष्ट ने सभी को डरा रखा है । लाखों लोग हम लोगों के बीच में बिना मास्क लगाये घूमते रहते हैं । सैकड़ों लोग मर गए हैं तथा इलाज के क्रम में हैं । हमारे पुलिस पदाधिकारी सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने काफी तैयारी की है । किसी ने भी ऐसी बिमारी कभी नहीं देखी थी और न ही इसके बारे में सोचा था ।

भूकम्प को बहुत लोगों ने देखा है और उस वक्त की स्थिति को जाना है । हैजा-प्लेग की बीमारी में लाखों लोग मर जाते थे तो 100 कोस पर दिया जलता था । इस कोरोना की बीमारी को कोई नहीं जानता था । हमारे प्रधान मंत्री जी को अपने हृदय में अनुभव हुआ और उन्होंने अनुभव के आधार पर लॉकडाउन करने का काम किया । उसके बाद लोगों के अन्दर एक शक्ति आयी और जिन्होंने स्वयं को सतर्क करके रखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ । कोरोना का वायरस तेज हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री जी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सभी अस्पतालों में जाकर जायजा लेने लगे । जहाँ बेड्स की कमी थी, वहाँ उचित व्यवस्था करने में उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी ।

कोरोना ने न गरीब देखा, न अमीर देखा और उसने सभी को परेशान किया । हमारे गृह मंत्री जी ने अपनी जान की कीमत नहीं समझी और वे भी कोरोना की चपेट में आ गए । डायबिटीज होने के कारण उन्हें दोबारा सांस लेने में तकलीफ हुई और वे अस्पताल में भर्ती हो गए ।

हमारे विपक्ष को सब पता था । जमाती लोगों ने आकर जान-बूझकर बीमारी फैलाई । हजारों लोगों ने चुपके-चुपके मीटिंग की । पता नहीं एक ही वर्ग है, जो हिन्दुस्तान को हर दंगे से तबाह करने पर तुला है । आतंकवादी लोग जो भी पकड़े जाते हैं, वे एक ही समुदाय लोग होते हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी सबका साथ और सबके विकास के लिए और सबका विश्वास जीतने के लिए जाने लगाये हुए हैं । विपक्ष उन पर गलत इल्जाम लगाता है । विपक्ष उन्हें जितना नीचे गिराने का काम करता है,

Speech was laid on the Table.

उतना ही उनका स्थान ऊँचा उठता जाता है । वह मानव के रूप में देश को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ।

कोरोना महामारी कब समाप्त होगी, यह किसी को पता नहीं है । आज डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी जान लगाकर काम कर रहे हैं । बहुत से लोगों की काम करते हुए मृत्यु हो गई है । हमारे बीजेपी के सांसद श्री दुर्गा प्रसाद जी, जो मेरी सामाजिक न्याय और अधिकारित संबंधी समिति के सदस्य थे, मैं उनके लिए बहुत दु:ख व्यक्त करती हूँ । मैं सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ ।

अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी सतर्क रहकर अपने को बचायें । इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है । अभी इस कोरोना वायरस की दवा नहीं बनी है । धन्यवाद ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak on this subject. Life has been brought to a halt all over the world due to COVID-19 pandemic. Millions are affected. People are dying by tens of thousands on daily basis. The entire world has joined together to fight it. There are over 50 lakh recorded cases in India, increasing by close to a lakh on a daily basis. India is just behind US in the tally of total number of cases.

Thousands of people are losing their lives every day. The economy took a severe setback due to a poorly planned lockdown. We recorded a 23.9 per cent fall in the GDP. The growth in the manufacturing sector is minus 39.3 per cent. In the construction sector, it is minus 50 per cent and in the hotel, transportation and communication sectors, it is minus 47 per cent. Millions lost their jobs across all sectors. Many are forced to scale down or completely shut down their businesses. Unemployment rose from 8.75 per cent in March to 23.52 per cent. The daily wage workers and migrant labourers bore the worst of the brunt of the lockdown. It is absolutely appalling that the Government does not even have any data on the deaths of the migrant labourers.

Sir, as far as Kerala is concerned, initially the spread of virus was under control, but after the lifting of the lockdown and return of the migrant workers from abroad and other States, cases are increasing rapidly. The total number of COVID-19 cases are 1,14,000, out of which, 31,000 are active cases. A total of

466 people have died because of this pandemic. Kerala receives close to Rs. 85,000 crore as foreign remittances annually.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, please give me one more minute. This is expected to fall by, at least, 15 to 20 per cent this year. In Kerala, nearly three lakh families will be affected because of this pandemic. The success of Kerala's Sustainable Development Goals has a lot to do with the high remittance flows from NRIs. This loss of revenue from remittances will affect the overall economy and social indicators of the State. The tourism sector accounted for almost a quarter of the employment in the State.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Please conclude.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, only one more point is there.

The only way to control the spread of this pandemic is the development of a vaccine. According to the reply of the hon. Minister to my question dated 18th September, nearly Rs. 78 crore has been allocated for the Department of Biotechnology and the Department of Science and Technology.

I feel that the allocated fund is not enough to facilitate the research and development required for the development of a new vaccine.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: The announcement by the Central Government of a stimulus package of Rs. 20 lakh crore was another hoax

because it was mostly in the form of bank loans and it is not enough to safeguard the interests of people in distress. The migrant labourers and daily wage earners are facing cash crunch and this is affecting their purchasing power.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): सभापित महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । लगभग तीन घण्टे हो गए हैं । मैं यह डिबेट पक्ष और विपक्ष की ओर से सुन रहा हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं । प्रतिपक्ष को सुनने के बाद मुझे लगा नहीं कि कोई जगह बाकी है, जिस पर उनका कोई सजेशन है, जिसे वे सरकार को देना चाहते हैं ।

महोदय, मैं खुद पॉजिटिव होकर आया हूं । पॉजिटिव होने के बाद जो मरीज होता है, मैं उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा । मेरा एकदम कंसट्रिक्टव प्रपोजल होगा । मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ओडिशा के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ओडिशा की स्थिति बिगड़ गई है । अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी अंत तक कोविड -19 से ओडिशा में 11हजार से ज्यादा लोग मरेंगे । मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली में सरकार नहीं कर सकी तो पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ने उठाई । मैं चाहता हूं कि ओड़िशा में भी ऐसा करना चाहिए ।

मेरी मंत्री महोदय को एक सलाह है कि एक बार कोई कोविड मरीज इलाज के लिए जाता है तो उसका इलाज कैसा चल रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसका पल्स रेट क्या है और उसका टेंपरेचर कितना है, यह सब परिजनों को पता नहीं चलता है । मैं 18 दिनों तक आइसोलेशन में रहा । उन 18 दिनों तक मैं परिजनों को व्हाट्स ऐप करता रहा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल इतना है, मेरी पल्स इतनी है, मेरा टेम्परेचर इतना है । लेकिन जो लोग इलाज के लिए जाते हैं और 10-12 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहते हैं उनके परिजनों को पता नहीं चलता है कि

उनका जो आदमी अंदर है, उसका स्वास्थ्य कैसा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सीसीटीवी के माध्यम से बाहर देखें और अंदर नहीं जा पाएं? वह बाहर हॉल में देखेंगे कि उनका जो पेशेंट अंदर है, वह कैसा है? उसका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? ओडिशा में हर दिन लोग मर रहे हैं । मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि कोविड से कोई मर गया । मैं इसलिए चिंतित हूं कि इलाज नहीं होने के कारण लोग ओडिशा में मर रहे हैं । यह चिंता का विषय है । अगर केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी रिपोर्ट नहीं मंगवायी जाएगी, क्योंकि ओडिशा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट में विफल रहा है । मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ओडिशा का जो कोरोना का विषय है, उसको केन्द्र सरकार सम्भाले, केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग सम्भाले । धन्यवाद । श्री दीपक बैज (बस्तर): धन्यवाद माननीय सभापित महोदय, आज कोविड-19 महामारी पर सदन में विस्तृत चर्चा हो रही है । इसके लिए मैं आपको और हमारे दल के नेता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता

माननीय सभापित महोदय, कोरोना महामारी का फैलाव पूरे देश-दुनिया में हुआ और पहला केस केरल में मिला था । इसके फैलने का सबसे पहले जिम्मेदार "नमस्ते ट्रंप", दूसरा जिम्मेदार, यह केन्द्र सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार को गिराने के लिए मुंह ताकती रही । जब पूरे देश में सौ केस थे, तब बिना प्लान के सरकार ने लॉक डाउन लगा दिया । उस हालत को पूरे देश ने देखा है और पूरा देश केन्द्र सरकार के साथ रहा । केन्द्र सरकार ने जो-जो बातें भी बोलीं, पूरे देश की जनता ने उसे किया । मोमबत्ती जलाओ, दीया जलाओ, टॉर्च जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ और शंख बजाओ । पूरी जनता ने शंख बजाया । माननीय प्रधान मंत्री जी एक ही चीज बच गयी कि नीम्बू और मिर्च बांधो । अगर वह भी बोल देते तो मुझे लगता है कि कोरोना को रोकने के लिए भारत की जनता वह भी करती ।

हूं ।

माननीय सभापित महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव था । अगर आपने ताली बजायी होता तो मुझे लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं रहते । पहली मार इस लॉक डाउन की मजदूरों पर पड़ी । करोड़ों मजदूर सड़क पर आ गए । ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है । उस समय भी इस तरह से मजदूर सड़क पर नहीं आए थे । इस सरकार ने मजदूरों को सड़क पर ला दिया । दूसरी मार रोजगार पर पड़ी । सारे लोग बेरोजगार हो गए । आज पूरे देश की हालत क्या है? जीडीपी माइनेस 2.4 परसेंट पर है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गयी है । मैं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी को समय पर बंद किया । बीपीएल और एपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री में राशन बांटा । लॉक डाउन में गरीबों को चावल बांटा । स्कूल, आश्रम छात्रावास और आंगनवाड़ी में बच्चों को सूखा राशन बांटा । निजी स्कूलों द्वारा फीस लेने पर उन्होंने रोक लगा दी । मजदूरों को खाने-पीने और चप्पल तक का सहयोग किया गया ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री दीपक बैज: माननीय सभापित महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं । आने वाले मजदूरों को ट्रेन की टिकट दी । दूसरे प्रदेश के मजदूरों को खाना और चप्पल दी । अगर अंत में मैं एक बात न रखूं तो मेरा भाषण अधूरा रहेगा । अंत में मैं एक बात रखना चाहता हूं कि पूरे देश में किसान न्याय योजना लागू कर छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पहला स्थान पाया है । यह किसानों के लिए सबसे बड़ी ताकत बना है । ...(व्यवधान)

माननीय सभापित महोदय, मैं अंत में एक और बात कहना चाहता हूं ।...(व्यवधान) महोदय, मैं तो कहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाए, तो पूरे देश में कोरोना समाप्त हो जाएगा ।...(व्यवधान)

*कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): नियम-193 के तहत देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा में मैं अपने विचार रखता हूं ।

130 करोड़ आबादी वाले देश भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के आने के साथ हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधान मंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ कार्य करने में संलग्न हैं । सीमित संसाधनों में 130 करोड़ देशवासियों को जिस भी प्रकार से अधिकतम स्रक्षित रखा जा सकता है, सरकार ने वह सभी प्रयत्न किए । कोविड केयर में संलग्न डॉक्टरों को सम्मान देकर मनोबल बढ़ाकर 24 घंटे नि:स्वार्थ सेवा को प्रेरित किया, या मैं स्वयं के विचार व अनुभव से कहूं तो 'परमार्थ सबसे बड़ा स्वार्थ' है, हमारे सम्माननीय स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी शहादत देकर दुनिया को बताया कि भारत के स्वास्थ्यकर्मी दिल से परमार्थ में लगे हैं । चीन में इस महामारी की शुरुआत हुई । इटली, स्पेन, ब्राजील आदि कम जनसंख्या वाले साधन सम्पन्न राष्ट्रों में यह पली बढ़ी । अनेक विकसित देश मिलकर भी इसे नियंत्रण करने में सफल नहीं हुए या नहीं हो पाए । तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह व एकमात्र लॉकडाउन को क्षणिक समाधान मानकर संक्रमण को रोक कर इस अनजान कोविड-19 की टेस्टिंग व रोकथाम की व्यवस्था में पूरे देश के स्वास्थ्य विभाग को देश के कोने-कोने में प्रत्येक जनपद, तालुका तक व्यवस्था करने का सफल प्रयास किया कि जब प्रवासी नागरिक अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे तो उपलब्ध श्रेष्ठ इलाज या दवा प्राप्त हो सके और यह संभव भी हुआ । भारत ने दुनिया को साबित कर दिया कि 130 करोड़ नागरिकों वाले देश में इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है । विश्व स्वारथ्य संगठन ने हमारे स्वारथ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन जी को सम्मान देकर मार्गदर्शक स्वीकार किया । हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, अन्यान्य लोगों के साथ-साथ हमारे मोदी जी, हमारी फौज, जनप्रतिनिधि, मीडियाकर्मी, ट्रक ड्राइवर आदि कोरोना वारियर्स बनकर देशवासियों के

Speech was laid on the Table.

स्वास्थ्य व जीवन रक्षा के लिए प्राण-प्रण से लगे हुए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने 80 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क राशन व्यवस्था करके दुनिया में यह साबित कर दिया कि भारत जैसा देश 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज कोविड-19 के लिए देकर मानवतावाद के सिरमौर साबित हुए हैं ।

समय की मर्यादा के कारण बी.जे.पी. के पूर्व वक्ता माननीय सांसदों द्वारा प्रस्तुत विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं एवं ईश्वर से देश ही नहीं, बिल्क पूरी दुनिया के समस्त व्यक्तियों, बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों के सुस्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं । भारत के समस्त नागरिकों से निवेदन करता हूं कि 'दो गज की दूरी, एवं मास्क है जरूरी' – के माननीय मोदी जी के आह्वान का पालन करते हुए स्वस्थ व सुरक्षित रहकर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के संकल्प के साथ अपना अधिकाधिक योगदान देकर स्वयं का जीवन सार्थक करें ।

धन्यवाद ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

Let me begin by thanking the doctors, the healthcare officials, sanitation workers, the police force, teachers, administrative staff who are in the frontline fighting this war on Coronavirus. I also offer my condolences to people who have lost their lives to Coronavirus, including our colleagues, Shri Durga Prasad, Vasanth Kumar and Shri Ashok. There is no certain playbook to contain this pandemic. This is something that we have not seen in our lifetime and we only hope that we do not see such a thing once again in our lifetime.

We have to learn hard lessons, introspect in many ways and plan ahead on many fronts. We have to re-think on how our Primary Health Care can be delivered better. We also have to re-think on how our Public Distribution System can be improved. The migrant labourers have to be protected. Immunisation and mid-day meal schemes will have to be strengthened. We also have to think as to how we can bring children studying in Government schools back to schools and also how to boost up the economy whose growth rate has fallen by almost 24 per cent. We have to think of creating jobs for millions of people who have lost their jobs. We also must think of providing insurance for people who have become unemployed so that the interests of unemployed youth are protected. We must

also think of reforming the banking laws so that businesses in the country can flourish.

Sir, coming to the State of Andhra Pradesh, we have done one of the highest per capita testing. We have the highest per capita recovery and the lowest death rate. We have done house to house survey twice by using our village volunteers. I have to thank those volunteers in the Parliament for their efforts. We have also provided healthcare centres with the maximum number of beds. We have covered this Coronavirus pandemic under the 'Arogya Shree' scheme where the treatment is completely free. We have also started producing indigenous testing kits and PPE kits in our Vizag Medical Devices park. We have facilitated lakhs of labour to move in and provided them with free shelter. Our State has supported the MSMEs and bought one of the highest quantities of agricultural produce to support the farmers. An amount of Rs. 20,000 crore has been transferred to the accounts of the needy under the Direct Cash Transfer scheme. But this is not enough. We need more.

Sir, in this season also we are going to purchase a lot of produce from the farmers and we need help from the Central Government for this. We need to bring PHCs under NRGS. We also want the MPLAD scheme to be restored so that where there are gaps we can fill those gaps with the help of this fund. We also want our GST dues to be refunded as soon as possible. More importantly, the people who have lost their jobs, the only way we can bring them back is by

investing on infrastructure projects on roads and irrigation. I hope, the Treasury Benches will give due importance to these infrastructure projects.

Thank you.

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

First of all, let us all pray for all the souls who have lost their lives in this pandemic and let their souls rest in peace. I would like to thank all people who are engaged in combating the COVID-19 pandemic. I would also like to thank my hon. Chief Minister, Shri K.C.R garu and the hon. Health Minister of my State and also all the healthcare professionals, police personnel, people in the Revenue Department who are all fighting this COVID-19 pandemic for the last nine months. I really do not want to suggest anything to the hon. Health Minister who is sitting here, who is a doctor himself. I would only like to mention what all we are doing in the State of Telangana so that he could suggest what more we should be doing to contain this pandemic.

Our Chief Minister was the first Chief Minister who suggested to the hon. Prime Minister to stop international travel from 18th March, 2020 to contain and control the spread of this virus. Telangana State was the first State to become a role model in creating 90 police teams and 150 health teams to test the people of one district, namely, Karimnagar. When this Covid was spreading very fast, it was our Chief Minister, Shri KCR garu who announced lockdown by saying `bratiki vunte balusaku tinavachhu'. He started giving 12 kg. rice to every individual till the month of June and after that he started 10 kg. of rice to individuals. Along with that the interest of 6.5 lakh migrant labourers were taken care of. After that, the

Government started giving Rs. 1500 every month to 82 lakh families. In addition to the rural areas, in GHMC and Hyderabad areas, the State has provided 1.56 crore meals through 634 centres. I want to give some statistics with regard to the State of Telangana. In the State the mortality rate is 0.6 per cent.

HON. CHAIRPERSON: There is no need to give any statistics. There is no time. Please conclude.

DR. G. RANJITH REDDY: It is one of the best performing States with regard to 'Test per Millions' and 'Test per Million cumulative'. We have 60 labs and 1076 locations for Rapid Antigen Testing. The only thing on which I would want a clarification from the hon. Health Minister is, along with Remdesivir why can we not have Dexamethasone and Ivermectin which are also available at cheaper price.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

DR. G. RANJITH REDDY: Give me one more minute. When it comes to the Government of India, it has given an affidavit to the Supreme Court saying that 4.14 core people migrated for work, whereas the Labour Ministry said that about 2.5 crore workers were registered as building and construction workers. What I would want to suggest is that, NSSO survey, which was done about 12 years back, had said that 14.8 crore people have lost their jobs. I would request the Government of India to please conduct one more survey, so that we can have the latest statistics also.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, Mr. Achyutananda Samanta Ji.

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमित दी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । कोविड-19 के ऊपर अभी बहुत चर्चा हो चुकी है । यह चर्चा सारे भारत में और दुनिया में होती रहती है । हम लाग ऐसे ही बात करते-करते बोलते हैं कि जितने करोड़ लोगें के पास मोबाइल फोन्स हैं, छह महीने के अंदर सब लोग कोविड-19 के एक्सपर्ट बन गए हैं । यह जो चर्चा चल रही है, इसमें मैं ओडिशा के बारे में बोलूंगा कि 16 मार्च को जब ओडिशा में पहला केस स्पॉट हुआ, उसी दिन से ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने सभी अरेंजमेंट किए, इतना एग्रेसिवली पूरे प्रशासन को लगाया । उसी दिन से अभी तक छह महीने के अंदर कोविड के ऊपर हर रोज माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं । उसकी वजह से आज ओडिशा में कोविड उतना नहीं बढ़ा, जितना बढ़ना था ।

सबसे अच्छी बात है कि पूरे देश के एवरेज के मुकाबले ओडिशा में डेथ रेट सबसे कम है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं । मंत्री जी को सब लोग धन्यवाद देते हैं । मैं भी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देता हूँ । माननीय स्वास्थ्य मंत्री डायरेक्टली हर राज्य के साथ मॉनिटर करते हैं । इससे बहुत अच्छा फलप्रद होता है । ओडिशा में सबसे अच्छी चीज़ अभी तक यह हुई है कि माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने, गरीब-अमीर सबके लिए फ्री कोविड ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है । पूरे राज्य में और हर जिले और शहर में कोविड हॉस्पिटल्स खोले हैं, कोविड केयर सेंटर्स खोले हैं । जिसकी वजह से कोविड केसेज़ थोड़े बढ़े हैं, लेकिन किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है । माननीय मुख्य मंत्री की दूरदृष्टि है कि अभी तक इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है । इसमें एक भी आम आदमी को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई । मैं खुद चार कोविड हॉस्पिटल्स, 12 सौ बेड के चला रहा हूँ । मेरी जो थोड़ी अनुभूति है, वह मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए करूंगा । एक तो जब कोविड

पेशेंट जाते हैं, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है । उसके लिए थोड़ा कुछ परामर्श करना चाहिए । ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the last point.

...(व्यवधान)

प्रो. अच्युतानंद सामंत: कोविड खत्म होने के बाद भी 10 पर्सेंट पेशेंट्स को तकलीफ होती है । पीपीई किट्स, मास्क वगैरह को यूनिफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो उसमें बहुत ब्लैक मार्केटिंग होती है और क्वालिटी बहुत खराब होती है । उसके बाद जो भी प्रबंध करेंगे, जो भी नियम करेंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के लिए करेंगे, क्योंकि कोरोना योद्धा सबके लिए समान हैं । अभी तो नवंबर तक राशन देने के लिए सरकार ने कहा है । इसको मार्च तक बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी की हालत अच्छी होगी । ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Ramshiromani Verma

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापित महोदय, आपने मुझे कोविड-19 महामारी पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । महोदय, इस वैश्विक महामारी के शुरूआती दिनों में ही सर्वप्रथम हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समस्त सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों सिहत आर्थिक रूप से मजबूत सबल कार्यकताओं को हिदायत दी थी कि ये सभी लोग बढ़-चढ़ कर सरकार के कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद करें । इसी के अनुरूप हम सभी सांसदों व अन्य ने अपने-अपने दायित्वों का निर्वाह किया और हम सब भी कर रहे हैं । कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों में किसान, दैनिक वेतनभोगी, मजदूर, छोटे-मझोले व्यापारी व प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग तथा छात्र-छात्राएं रही हैं ।

महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम व उन्मूलन हेतु सांसदों का वेतन कटौती सिहत विकास में लगने वाले धन को भी ले लिया गया । लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जरूरतमंद लोग आज भी कोविड-19 के लिए दी गई सहायता व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से वंचित रह रहे हैं । छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है । लेकिन गरीब छात्र-छात्राओं के पास इस महामारी में जब खाने के लिए रोटी तक नहीं है, तो इन परिस्थितियों में उनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक टेबलेट, लैपटॉप, फोन और इंटरनेट की सुविधा कहाँ से हो पाएगी?

महोदय, मैं लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती से निर्वाचित होकर आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है । यहां पर सर्वाधिक मजदूर अपनी जीविकोपार्जन के लिए बाहर अन्य प्रांतों में जाकर रोजी-रोटी कमाते रहे हैं । अब इनके पास रोजी-रोटी कमाने का कोई साधन नहीं बचा है । अत: लोग अधिकांशत: बेरोजगारी और भूखमरी के कगार पर हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिए ।

श्री रामशिरोमणि वर्मा: सर, बस कनक्लूड कर रहा हूँ । इनके खाने के लिए राशन अन्य मदों से पैसा देने का काम किया गया था । उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अब भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश के गरीब, मजदूर की जीविका, छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के लिए इंटरनेट सुविधा सहित लेपटॉप या फोन की उपलब्धतता कराई जाए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. सुभाष सरकार ।

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): सभापित महोदय, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ । घंटे भर से मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, लेकिन इस डिस्कशन में कोई सुझाव नहीं है । मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंचेज की साइड से केवल पीएम को टोकने की कार्यवाही चल रही है । इसके बारे में मुझे कहना है कि आपने नमस्ते ट्रम्प के बारे में आरोप लगाया, आपने तालियाँ बजाने, दीया जलाने के लिए आरोप लगाया । आप बताइये कि उसी दिन के तीन सप्ताह के बाद हमारी पॉजिटिव संख्या कितनी थी?

इसके बारे में आपका क्या ऑर्ग्युमेंट है, कोई ऑर्ग्युमेंट नहीं है । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले कुछ सुझाव देता हूँ । एक है- सारे देश में, हर स्टेट में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन्स हैं, उनका पालन करना ही पड़ेगा, डिजास्टर मेनेजमैंट एक्ट से गाइडलाइन्स लागू कर सकते हैं । बहुत सारी स्टेट्स इनका पालन नहीं करती थी । हर स्टेट से central line connectivity outlet कितने हैं?

Number of oxygen cylinders with respect to number of beds कितने है? Alternative electric supply to ICCU wards is very much important. A few days back, I have lost one of my relatives due to lack of supply of alternative power in a big hospital.

In the end, let me say that in my State of West Bengal the health infrastructure is in shambles. There is the world famous Eden Hospital and Medical College, which is regarded as a benchmark. That hospital has been converted into a COVID facility. However neither the COVID patients are being treated there properly, nor the non-COVID patients are given any treatment. Therefore, people are dying like anything; some are dying under tree shades, some are dying in the ambulances. Who will take this responsibility? The situation is so pathetic that if ambulance is called in the afternoon, it reaches at night. In my constituency, one doctor Sarkar required admission, but since no bed was available in any Government hospital, he had to be admitted to NICED in the end.

_

^{* *}English translation of this part of the speech was originally delivered in Bengali.

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hon'ble Chairman Sir, thank you for allowing me to participate in discussion under rule 193 on Covid-19 pandemic.

Sir, during this covid-19 pandemic, for the first time we all have frequently heard the terms such as lockdown and seal down during the last 6 months. Corona virus is the gift from China. For the last 4 to 5 hours we have been discussing it in this august house.

Sir, I would like to point out my observations based on my personal experiences gained during my participation in all preventive measures to combat covid-19 in my parliamentary constituency.

Chairman Sir, the Hon'ble Prime Minister had announced 45 days the lockdown for the first time in the country without having any preparedness. During those 45 days he only directed the state governments to combat the covid-19 situation. However the central government did not help the states to handle the pandemic situation.

During those 45 days the poor people and daily wagers of the country had suffered a lot. Many people died on roads without food and water. He did not make any arrangement for transportation of the people to reach their places. He left everything on the people to safeguard their lives.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Kannada.

20.09.2020 961

I would like to mention that situation in the country is worsening as the

number of Covid-19 positive cases are constantly increasing even now. The

situation is no different in the state of Karnataka. There is no beds available to

covid positive patients in the state. There is no oxygen. There is shortage of

ventilators.

Amidst all these pathetic conditions arisen out of this pandemic, there is

rampant corruption in purchasing of covid-19 equipments in Karnataka. Central

government has released funds under NDRF to SDRF to enable the state to

combat the situation. However there is misappropriation of the money in procuring

the covid-19 equipments.

Hon'ble Chairman Sir, The central government has announced that it had

give Fifty thousand Ventilators to Karnataka at the cost of Rs. 4 lakhs. However

the Ventilators are purchased at the cost around Rs. 12 lakhs to 18 lakhs. We can

see the rampant corruption in purchasing Masks and Sanitizers for patients.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.K. SURESH: Hon'ble Chairman, sir, it is not end here. Sir, there is

instances of mismanagement of food grains. The food grains meant for poor and

migrant workers were supplied to BJP workers. As a result the migrant workers

were deprived of their due share of food grains.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.K. SURESH: Sir, I urge upon the union government to conduct an enquiry commission to investigation of all the malpractices committed by the government of Karnataka during the covid-19 pandemic. The government should ensure that the funds released to the state government is utilized to achieve the objective of combating covid-19.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.K. SURESH: Sir, I will conclude in one minute. Please allow me sir. I would like to give a few suggestions to the union government.

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey ji.

SHRI D.K. SURESH: Sir, please give me one minute. I am concluding.

Sir I have written a letter to the hon'ble Prime minister to provide relief to the daily wagers, farmers, migrants and poor labors by announcing a special package to help them to earn livelihood.

With these words I once again thank you and conclude my speech.

^{*}श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मैं कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम पर सुझाव देना चाहता हूं । वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रतिकूल समय में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी कि सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय लिए गए । आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के विकास हेतु 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई, जो कि देश के जीडीपी का 10% है । जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(PMGKY) भी शामिल है । PMGKY के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का श्भारंभ किया गया तथा इस योजना को 'दीपावली-छठ यानी नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि गरीबों और प्रवासी मजदूरों को राहत मिले । उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल और पहले 1 किलो दाल/चना परिवार मुफ्त दिया गया है और आगे नवंबर तक दिया जाएगा, इस योजना से 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा है । लगभग 20 करोड़ से अधिक महिला जन धन खाता धारकों को उनके खाते में 500-500 रुपये की तीन किश्त. लगभग 8 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनैक्शन धारक 3 महीने मुफ्त गैस सिलेंडर, वृद्ध विधवाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अति 1000 रुपये का पेंशन, किसान सम्मान निधि से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को समय से पूर्व 2000 रुपये की राशि, दी गयी तथा 4 हजार से अधिक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों(छात्र एवं श्रमिक भाइयों) को उनके गृह राज्य व निवास स्थान पर पहुँचाया गया । 10 हजार करोड़ की राशि MFS के तहत निर्गत की गई, जिससे मिथिला में उपजने वाले मखाना के उत्पाद को लाभ मिलेगा । इसके तहत गरीब कल्याण, कृषि व किसान, एमएसएमई एवं उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर में रक्षा एवं अतंरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किये जा रहे है तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने हेतु RBI के द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर राहत प्रदान की

Speech was laid on the Table.

गई है । चौथे चरण के लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी देशवासियों स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया था और वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए स्वदेश उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कहा था ताकि देश अर्थव्यवस्था सुदृढ हो और भारत आत्मिनर्भ बनें, जिसे देशवासियों ने संकल्प के साथ अपनाया है ।

कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा सेवा से जुड़े अन्य लोग सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक और पोस्टल के कर्मचारी, मीडिया के साथी सिहत कई संगठन व समर्पित लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हम सभी लोगों के सुविधा व सुरक्षा हेतु निरंतर कार्य करते रहें है जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में संबोधित किया है, वे सभी बधाई के पात्र है ।

इस विपरीत परिस्थित में देश के प्रधानमंत्री जी ने एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों से 'ताली-थाली बजाने, दीप-टॉर्च जलाने' जैसी विशेष अपील की, जिसे देशवासियों ने सहज स्वीकार किया । प्रधानमंत्री जी दवारा लिए गए निर्णय का परिणाम है कि बांकी देशों की अपेक्षा में आज भारत, कोरोना से रिकवरी दर सबसे अधिक है और मृत्यु दर सबसे कम । यह परिणाम जनता एवं सरकार के आपसी सहयोग और संयम का स्पष्ट उदाहरण है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना वायरस संकट को लेकर अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हम सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती की गई तथा दो वर्षों, यानी वर्ष 2020 और 2021 तक के लिए सांसद निधि को अस्थायी तौर पर स्थिगत किया गया । इन दो वर्ष की निधि यानी 10 करोड़ की राशि सहित अन्य धन राशि को कोरोना वायरस के कारण उपजे संकट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य संसाधन जुटाने में दी गई ।

इन सभी फैसलों और कुशल नेतृत्व के लिए मैं समस्त मिथिलावासियों के तरफ से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सहित केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी,

स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी और श्री अश्विनी चौबे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं । वहीं इस विपरीत समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे. पी. नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के तहत लाखों फेस मास्क, कई हजार लीटर सैनिटाइजर, पीपीई किट सहित अन्य जरूरी चीजों का वितरण देश भर में भाजपा द्वारा किया गया तथा और फीड द निडी के तहत 24 करोड़ फूड पैकेट व राशन किट का भी वितरण देश भर में हुआ, जिसके लिए मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं ।

आम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से बिहार के लोगों को इस विकट समय में कॉफी राहत मिली, राज्य सरकार ने बिहार से बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 1000 रुपये की सहायता राशि देने का काम किया तथा इसके अतिरिक्त सभी राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये की सहायता राशि भी दी गई । इस आपदा के समय बिहार सरकार ने युद्ध स्तर पर लोगों का राशन कार्ड बनाया और वितरण किया, तथा राशन कार्ड बनाने के नियम में भी बदलाव किया गया तािक सभी लोगों को राशन कार्ड मिल सकें । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने क्वारंटाइन केंद्र का संचालन अच्छी तरह किया । क्वारंटाइन लोगों के सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया, उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन तथा आवासन की व्यवस्था देने के साथसाथ दैनिक जीवन से जुड़े सभी सामान अलग से राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन केंद्र पर दी गयी, इसके अतिरिक्त उन लोगों को सहायता राशि भी दी गई । इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

आपदा की इस विकट परिस्थिति में जिलाधिकारी, दरभंगा ने अविस्मरणीय कार्य किया है, जिस कारण आज दरभंगा स्थिति बेहतर है । घर-घर तक राशन व दैनिक जीवन के सभी सामानों को पहुंचाने के अतिरिक्त कई अन्य जरूरी सेवा का लाभ भी लोगों को घर पर जाकर दिया गया है, इसके

लिए जिलाधिकारी सिहत जिले सभी अधिकारी व पदाधिकारी को बधाई देता हूं । उन सभी ने पूरे धैर्य के साथ इस प्रतिकूल समय का सामना करते हए आम लोगों के हित में निरंतर कार्य किया है । इस महामारी के समय मैंने अपने एक माह के वेतन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में राष्ट्र सेवा हेतु दिया तथा अपने सांसद निधि से एक करोड रुपये की राशि कोरोना महामारी बचाव के लिए दरभंगा जिला प्रशासन निर्गत किया तािक महामारी से बचाव हेतु आवश्यक उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर, दवा छिड़काव की मशीन,आदि उपयोगी संसाधनों की दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कोई कमी न हो । इसके अतिरिक्त पार्टी के फीड द निडी कार्यक्रम में अपना योगदान देते हुए कुल 25 हजार फूड पैकेट व राशन किट का वितरण करवाया । 8 करोड़ मिथिलावासियों की ओर से नव भारत के विश्वकर्मा मिथिला के विकास में नया अध्याय लिखने वाले देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा कोरोना संकट के समय किए गए ऐतिहासिक कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूँ ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, धन्यवाद । मैं माननीय सभापति जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया ।

महोदय, जब से चर्चा शुरू हुई है, मैं लगातार चर्चा सुन रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं लैक कर रहा हूँ कि कोरोना में जिस तरह से सभी लोगों ने मिलकर काम किया, वह पूरे देश को बताने का सवाल था । लॉकडाउन हुआ, यहाँ घड़ी की बात हुई, घड़ियाल की बात हुई, शंख की बात हुई, ताली बजाने की बात हुई । प्रधान मंत्री जी ने किया, लेकिन क्यों किया, यह समझने की बात है । मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरे खुद के लोक सभा क्षेत्र में लगभग एक लाख मजदूर बाहर फंसे हुए थे । बचपन में हमने पंडित भीमसेन जोशी जी की एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी, जिसे उन्होंने गाने में कन्वर्ट किया था "कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा", वह मेरा उदाहरण है ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह विषय आगे बढ़ा । आज जहां हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं तो मैं देख रहा हूं कि 14 तारीख से यह पार्लियामेंट चल रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? जितने ऑर्डिनेंसेज, बिल्स, सब कुछ अगर पास कर रहे हैं तो केवल कोरोना के कारण जो इस देश में संकट है, वैश्विक महामारी के कारण जो संकट है, उस संकट से इस देश को कैसे उबारा जाए, इसमें पक्ष और विपक्ष एक साथ है । महोदय, मेरे पास इसके बहुत-से उदाहरण हैं । मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के एक लाख लोग बाहर थे । यदि मैं बात करूं तो यही एक ऐसा विषय था, जहां विचारधारा, धर्म, संस्कृति, जाति के सारे बंधन टूट गए थे । यदि मुझे तेलंगाना में अपने लोगों को खाना पहुंचाने की बात आई तो एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन लोगों को खाना पहुंचा रहा था तो दूसरी तरफ यहां के ही माननीय सांसद ओवैसी साहब खाना पहुंचा रहे थे । आप इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ओवैसी साहब यदि एक साथ एक मंच पर मौजूद थे तो उसका कारण यही कोरोना था ।

महोदय, यहां उदासी साहब बैठे हैं । संयोग से, हमलोग यहीं लॉकडाउन में फँस गए थे । यदि उसी कर्नाटक में एक तरफ येदियुरप्पा साहब और शोभा कारान्दलाजे थीं तो दूसरी तरफ आपके प्रदेश

अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार जी का भी मेरे पास उदाहरण है कि यदि मैंने उनसे मदद मांगी तो वे भी वहां साथ थे । तेलंगाना का उदाहरण है कि यदि एक तरफ चन्द्रशेखर राव साहब मुख्य मंत्री के तौर पर खुद एक्टिव थे तो उनकी लड़की कविता, जो यहां की पूर्व सांसद हैं, वे भी एक्टिव थीं । नामा नागेश्वर राव, जो यहां के संसदीय दल के नेता हैं, वे एक्टिव थे । भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बंदी संजय, जो यहां के सांसद हैं, वे भी एक्टिव थे । कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि पंजाब में एक्टिव थे तो उसी तरह हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी एक्टिव थे । यहां के मंत्री सोम प्रकाश जी भी एक्टिव थे । इसी तरह, हिरयाणा में यदि खट्टर साहब एक्टिव थे तो भूपिन्दर सिंह हुड्डा साहब और उनके बेटे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब भी एक्टिव थे । महाराष्ट्र में यदि हमारी मित्र सुप्रिया सुले जी लगातार एक्टिव थीं तो उसी तरह गोपाल शेट्टी एक्टिव थे । यहां श्रीकान्त शिंदे साहब बैठे हैं, वे भी एक्टिव थे ।

सर, कोई भी पार्टी या दल इससे अलग नहीं है । चाहे आप कहीं की भी बात करें । डी.एम.के. की किनमोझी जी, जो यहां बैठी हुई हैं, वे एक्टिव थीं । उसी तरह से ए.आई.ए.डी.एम.के. एक्टिव था । उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव थी । क्या यह देश को बताने की आवश्यकता नहीं है? इसे देश को बताने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने यह किया है । जैसे माननीय अध्यक्ष जी की बात है तो क्या यहां पर कोई भी ऐसा सांसद है, जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष जी से या अध्यक्ष जी के ऑफिस से एक सप्ताह में फोन नहीं गया कि आप कैसे हैं । यदि बच्चों की बात की जाए तो यदि हमारे बच्चे कोटा में फँसे से थे तो माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने खुद से pain िलया कि वे कैसे जाएंगे? उसी तरह से, यदि ट्रेनों की बात करें तो मेरे पास ऐसा उदाहरण है कि एक तरफ तो मुख्य मंत्री, राजस्थान, गहलोत जी एक्टिव थे तो माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी भी एक्टिव थे कि किस तरह से हमारे लेबर्स लोग चले जाएं । इसे देश को बताने की आवश्यकता है । इसमें सभी सीमाएँ टूट गईं । जाति के सभी बंधन टूट गए । विचारधाराओं के बंधन टूट गए । इसी कारण से, आज इस देश में इसकी मृत्यु-दर कम है । हम लोगों को बचा पाने की स्थित में आए हैं और यह सब किसके कारण हुआ है? उसी

माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जिन्होंने ताली बजाकर, शंख बजाकर, मोमबत्ती जलाकर पूरे देश को एकत्रित किया । एक तरफ शरद पवार साहब घंटी बजा रहे थे, दूसरी तरफ प्रधान मंत्री जी भी घंटी बजा रहे थे, यह बताने की आवश्यकता है । लेकिन, इसमें एक दर्द है । दर्द यह है कि लोग माइग्रेंट लेबर्स की बात करते हैं और यह पूरे पार्लियामेंट को जानने की आवश्यकता है । हमारे एक लाख लोग बाहर थे । वे माइग्रेंट लेबर्स कैसे हैं? इस देश में नागरिकता एक है । यह देश एक है । अनेकता में एकता है । यदि इस देश में नागरिकता एक ही है तो वे प्रवासी मजदूर कैसे हो गए? यदि कोई इंडस्ट्री बनी, यदि मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगालुरू जैसे शहर बने तो उसमें मजदूरों ने योगदान दिया । उसमें कैपिटल भी लगा और उसमें मार्केट भी आया । आप मजदूरों को प्रवासी मजदूर कह रहे हैं ।

सर, सौगत बाबू यहां बैठे हुए हैं । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यहीं माननीय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने कहा था कि हम इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं । उनका बड़ा प्रसिद्ध भाषण है कि पूर्वी भारत का जो सी.डी. रेशियो है, चाहे वह बिहार का है, चाहे झारखंड का है, चाहे बंगाल का है, चाहे ओडिशा का है, वह केवल 30 प्रतिशत है । बैंक हमसे 100 रुपये कमा कर ले जाते हैं और हमारे क्षेत्र में केवल 30 प्रतिशत इंवेस्ट करता है ।

वह 70 इन्वेस्टमेन्ट कहाँ होता है? वह मुम्बई में इन्वेस्ट होता है, वह चेन्नई में इन्वेस्ट होता है, वह हैदराबाद में होता है, वह बेंगलुरू में होता है तो क्या कैपिटल को आप प्रवासी कैपिटल कहते हैं । यदि हमारे पैसे को ले जाकर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो उसको आप प्रवासी कैपिटल क्यों नहीं कहते हैं । यदि कोई सामान बिकता है तो सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है । सबसे ज्यादा पैसा तो हम देते हैं और हम आपका सामान खरीदते हैं । हम सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं । आप उसको प्रवासी मार्केटिंग क्यों नहीं कहते हैं? आज इस पार्लियामेंट को सोचने का विषय है कि आप सबसे पहले माइग्रेन्ट लेबर की परिभाषा को बदलिए । यदि नहीं बदलिएगा तो इस देश में कोरोना ने

हम लोगों को जो सीखने का एक मौका दिया है, इस देश को यूनाइटेड करने का मौका दिया है, वह हमारे हाथ से चला जाएगा । गरीब अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा पाएगा, जहाँ लगेगा कि हमारी कोई स्थिति नहीं है, हमारे पास कोई वक्त नहीं है । उसी एक विचारधारा के कारण, उसी एक डर के कारण लेबर्स सारी सुविधाओं के बाद भी यहाँ से भागने को मजबूर हुए ।

महोदय, मेरे दो-तीन ही आग्रह हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि हम लोग फँसे हुए थे । मैं, उदासी जी और कमलेश पासवान जब अपने परिवार के साथ घूमते थे तो मैं देखता था कि 11-12 बजे तक माननीय अमित शाह जी अपने ऑफिस में बैठकर सभी को कोऑर्डिनेट करते थे । मेरा यह आग्रह है कि एक तो माइग्रेन्ट लेबर की परिभाषा बदलिए ।

दूसरा, इस तरह के जो विषय आए हैं, जितना काम आपने किया है, पार्लियामेंट में इस तरह की चर्चा करके, पूरे पार्टियों को डिवाइड करके, आइडियोलॉजी को डिवाइड करके मत बताइए । आप बताइए कि हम सब ने मिलकर इस देश को बनाने का काम किया है । यदि इस तरह का कभी भी कोई मौका मिलेगा तो पूरा देश, पूरी पार्लियामेंट, सारी पार्टीज और सारी विचारधाराएँ एक होंगी । हम सब एक हैं । अनेकता में एकता है । भारत एक है । जय हिन्द -जय भारत ।

*SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I would like to place my views on the discussion on COVID-19 pandemic in the country.

First of all, I would like to pay my tribute and pass on my condolences to the families of all the doctors, nurses, health workers, police, and to all those who have worked on a frontline and have lost their lives due to COVID-19 pandemic. I would like to thank the hon. Minister of External Affairs, Dr. Subrahmanyam Jaishankar Ji who has helped in bringing back people, who were stranded outside India and I would also like to thank all the State Governments who have helped in bringing migrants of Andhra Pradesh back to their homes. I would also like to thank all the MPs, who have worked tremendously in their constituencies during the crisis. Right now, they are fulfilling their constitutional duties in the Parliament. While we are discussing this, the COVID-19 cases have passed the 54-lakh mark with as many as 92,605 new cases reported today. The country has lost around 87,000 lives in the pandemic.

My State, Andhra Pradesh, has seen a total of 8218 new cases today and the total confirmed cases in the State is 6,17,776. The State's tally is the second highest after Maharashtra. My constituency, Srikakulam, has seen total of 30,000 cases and 280 deaths till now.

This discussion on COVID-19 should have been taken up during the Budget Session when we were aware that our country would have to face this

_

Speech was laid on the Table.

20.09.2020 972

pandemic. Having a discussion at that time would have helped us formulate our

response to tackle the crisis more effectively.

I would also like to commend the efforts of the Government of India and its

bold, if not timely, decision to implement the most comprehensive lockdown

anywhere in the world. Being one of the most populated countries in the world, we

needed it at that time to calibrate our responses to tackle the global crisis and

also to save our economy. We also needed it to upgrade the health infrastructure

and increase the capacity of beds to meet the demand that might arise due to this

pandemic.

After six months of the lockdown, when we are in the 4th stage of the unlock

process now, the question then arises, did we use the time on our hands,

effectively and efficiently?

If we look at the Annualised figures of GDP for April-June guarter, then the

scenario becomes more dire:

India: -75 per cent

UK: -59.9 per cent

Germany: -33 per cent

USA: -31.7 per cent

Japan: -27.8 per cent

China: -54.6 per cent

If we look at quarter-over-quarter GDP growth between April-June, 2020 over January-March, 2020:

India: -29.28 per cent

UK: -20.4 per cent

Germany: -9.7 per cent

USA: -9.09 per cent

Japan: -7.8 per cent

China: -11.5 per cent

During an interaction of the hon. Prime Minister with the Leaders of the Parliamentary Parties on 8th April, 2020, I had suggested that in order to come out of this lockdown and protect our economy, a stimulus package to the tune of, at least, 10 per cent of the GDP needs to be announced. This was accepted by the hon. Finance Minister and she announced a package in the same line on 12th May, 2020.

Of Rs. 20 lakh crore stimulus package announced, nearly 50 per cent of it is in the form of liquidity measures to help banks and NBFCs to increase lending business to stimulate growth. While demand was subdued due to COVID-19 situation, banks and NBFCs were also reluctant to lend due to potential NPA concerns. Therefore, the stimulus package announced for various MSMEs and small businesses was also not in the form of grants but in the form of loans, food supply for migrant labourers, and some infrastructural support. The actual

expenditure of the Government is negligible with most burden on the RBI and institutions like NABARD, etc.

The Government has also planned to tap construction workers fund, mineral fund, and compensatory fund, etc. The Government has just recycled its schemes and allocations already counted for in the budgetary allocations. As part of the COVID-19 package, of Rs. 5.4 lakh crore package announced for MSMEs, the actual cost to the Government is estimated at Rs. 25,000 crore only.

For this, as I have suggested previously, the Government should review its capital and revenue expenditure plans and classify them under three heads as critical, essential, and desirable. The one which is being required and is urgent, is critical; the one which is being required, but not urgent, is essential; and the one which is not being required and also not urgent, is desirable. The Government should delay the expenditure that is not critical and divert that amount towards the second stimulus package.

We are all facing the same storm, but we are not sailing in the same boat. While some sectors have prospered during these pandemic times, others such as, construction, travel, restaurant, MSMEs across all the verticals, have suffered the most.

If you look at the employment report -- recently released by CMIE, it states that during the April-July period, about 19 million salaried people lost their jobs in

India. While salaried jobs are not easily lost, but once lost, they are also far more difficult to retrieve.

The package needs to be focussed on providing financial support to those industries which see the largest loss in employment so that they have the funds to rehire or save the jobs of their employees. So, the financial support and stimulus package need to be directed to support the most vulnerable people and businesses.

While unemployment number is increasing, the businesses are also facing shortage of labour, which is becoming the cause for a concern. We need to figure out a way to get the right people to the right place in order to kick start the economic activity. For this, I suggest that the migrant labourers be provided some incentives to get back to their work sites. They should also be provided some travel incentives, increased healthcare facilities at labour camps to handle COVID infections, and mobile ration cards, etc.

During the lockdown period, we have seen many gains in terms of reduction in the levels of pollution, better sanitation, and hygiene and that needs to be sustained.

These measures would surely bring economy back on track in some time. However, for the welfare of the people, I would like to mention a few points. Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, insurance cover will be provided to 22.12 lakh health care providers, including public healthcare providers and private

hospital staff. The insurance provided will be above any other insurance cover being availed by the beneficiary and does not require any additional registration. The premium for it will be borne by the Ministry of Health and Family Welfare. The insurance scheme was operationalised on March 30 and will be in force till September, 2020 which is extended for a further period of time of 180 days. The claims of these workers should be processed quickly. The police officials, who are doing their duties during these Corona times, have no insurance. So, the Government should introduce a similar kind of a scheme for them as well.

After the COVID-19 pandemic, fishermen are in dire need of assistance. When the lockdown was announced, many fishermen were in the high seas and when they came back, there were no traders and the supply chains were crashed. It resulted in the severe loss of income to the fishermen. We are still in the middle of the pandemic and the demand of fisheries is still low and therefore, they are struggling hard to meet their day to day needs. As part of the Atmanirbhar Bharat package, Rs. 20,000 crore has been allocated to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, but it does not contain any provision for financial assistance to the hard hit fishermen. The fishermen are not even included in PM-KISAN Scheme which they have demanded for so long. I request the Government to constitute a Fishermen Welfare Fund and sanction a special grant to formulate schemes related to providing compensation during this tough time. Andhra Pradesh's economy is significantly dependent on fisheries and fishermen and

even Andhra Pradesh has significantly contributed in the total fish production in India.

Srikakulam is also a major source of outmigration of fishermen and other migrant workers and has recently witnessed all the migrants returning to home especially from Veraval in Gujarat and also from Chennai. The unemployment among them has increased the job demand under MNREGA and it is the highest ever after 2007. They need job and wages to meet their day-to-day needs very badly. The Gareeb Kalyan Rojgar Abhiyaan has been introduced to provide livelihood to migrants who are back home in 116 districts in 6 States of India, but Srikakulam has not been included in spite of being a backward district. In fact, not even one district of Andhra Pradesh has been included. Andhra Pradesh has seven backward districts out of total of 13 districts.

The number of COVID-19 cases could go up in Srikakulam due to limited availability of hospitals and COVID-care centres. Therefore, due to shortage of beds, patients with mild symptoms are sent back to their homes. I request to grant Rs. 50 crore from PM CARES Fund to establish new COVID care centre in the district.

Under the Pradhan Mantri Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi Scheme (PM SVANidhi Scheme) only the street vendors of urban local bodies are included. But in Srikakulam, in the State of Andhra Pradesh, many fish vendors, especially

women, work at the rural places as well. If they can also be included, it would be better.

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammed Faizal P.P. – Not present.

Now, Dr. Shrikant Eknath Shinde.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): महोदय, आज सभी लोग कोविड-19 महामारी के ऊपर बात कर रहे हैं । अभी एक माननीय सांसद महोदय ने बताया कि जब से कोविड शुरू हुआ, तब से सभी सांसद एक-दूसरे के संपर्क में आकर, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या कॉल हो, किसके चुनाव क्षेत्र में कौन-से माइग्रेन्ट लेबर्स फँसे हैं, उनको मदद करने का काम सभी सांसदों ने एक-दूसरे के साथ मिल कर किया । जब इस कोविड-19 की शुरुआत हुई, तभी से सभी सांसदों ने मिलकर काम किया । मुझे लगता है कि कई ऐसे भाषण थे, जो सिर्फ आलोचना और पोलिटिसाइज के लिए किए गए हैं । मुझे लगता है कि आज यह जो कोविड-19 का संकट है, इसे हम सभी लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं । इसमें सभी पार्टियों को एक साथ आकर काम करना बहुत जरूरी है । मुझे लगता है कि सिर्फ आलोचना करके हम इस कोविड-19 महामारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे । सभी लोगों को साथ में आना होगा और अलग-अलग सुझाव देने पडेंगे । मुझे लगता है कि चाहे सभी सांसद हो या कोई लोक प्रतिनिधि हो, विगत सात महीने से अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में हम सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ।

20.49 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, कोविड-19 महामारी कैसे कम हो, इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं । मेरे भी कुछ सुझाव हैं । आज मैं यहाँ एक सांसद के रूप में तो हूँ, लेकिन पहले मैं एक डॉक्टर हूँ । आज ग्राउण्ड लेवल पर जो परिस्थिति है, वहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके संबंध में मैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूँगा ।

महोदय, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, वह हॉट जोन में है । अगर आज कहीं पर भी सबसे ज्यादा कोविड-19 पेशेंट्स हैं तो वह महाराष्ट्र में हैं । वह मेरा चुनाव क्षेत्र है, थाणे जिला है और मुम्बई है,

क्योंकि वह मेट्रोपोलिटन शहर है । सभी जगह के लोग वहाँ पर रहते हैं । मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, वह काफी घनी आबादी वाला है । मुझे लगता है कि उत्तर भारत के जो सभी सांसद हैं या ओडिशा के जो सांसद हैं, उन सभी के क्षेत्र के लोग वहाँ पर रहते हैं । अगर सबसे ज्यादा माइग्रेन्ट लेबर्स कहीं पर रहते हैं तो वे मेरे ही कांस्टीटूएंसी में रहते हैं । हमने शुरू से ही उन्हें बाहर निकालने का काम किया है । आज हमने अपने चुनाव क्षेत्र में जो भी एक्सपेरिमेन्ट्स किए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ । अर्बन एरिया में हमने कोविड-19 के संसर्ग को कैसे कंट्रोल किया, आज हमने वहाँ पर बड़े-बड़े कोविड सेन्टर्स शुरू किए हैं । हमने वहाँ पर जम्बो क्वांरटाइन सेन्टर्स शुरू किए हैं ।

इससे कोविड पर नियंत्रण पाना आसान हुआ । इसी के साथ हमने फीवर क्लीनिक कांसेप्ट शुरू किया, जहां पर हम एंटीजेन टेस्ट करते हैं । जब हमने फीवर क्लीनिक वहां पर शुरू किया तो लोग उस फीवर क्लीनिक में जाने से डरते हैं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लोग एक स्टिग्मा की तरह कोविड-19 की तरफ लोग देख रहे हैं कि हम अगर फीवर क्लीनिक में जाते हैं, अगर हमें फीवर है, तो हमें तूरंत क्वारेंटाइन किया जाएगा । उस क्वारेंटाइन सेंटर की परिस्थित कैसी होगी? इसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है । लोगों में जन-जागृति करनी होगी कि जितनी जल्दी आप फीवर क्लीनिक में पहुंचेंगे, जितनी जल्दी आप डाइग्नोज होंगे, उतनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी । आज यह बीमारी पर सबसे ज्यादा असर, अगर बीमारी बढ़ती है, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट ट्र सीवियर, तो इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ा असरदार और कारगर इंजेक्शन पाया गया है । अगर इस इंजेक्शन को हम 7 से 8 दिन के भीतर पेशेंट को दे दें, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरह से होती है । लेकिन लोगों की पहुंच इस इंजेक्शन से बहुत दूर है, क्योंकि यह इंजेक्शन फ्री में नहीं पाया जाता । इसके लिए बहुत बड़ी राशि देनी होती है । ...(व्यवधान) सर, यह बहुत इंपोर्टेंट है । आज मैं पहले दिन बोल रहा हूं । इसकी राशि भी बहुत इंपोर्टेंट है । रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर लोगों को मिले तो बहुत लोगों की जानें बच सकती हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो सकता है । हमने अपने स्टेट में क्या

किया है? जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको हमने ताकत दी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस आप खरीदो और कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स में जो-जो पेशेंट्स एडिमट हैं, उनको फ्री ऑफ चार्ज रेमडेसिविर इंजेक्शंस दो । आज इसके कारण हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है और लोगों की जान बच रही है ।

सर, हम आरटीपीसीआर तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ सीटी स्कैन भी कर रहे हैं । आज सीटी स्कैन फ्री ऑफ चार्ज कहीं भी नहीं हो रहा है । सीटी स्कैन डायग्नोस्टिक है । कितनी बीमारी है, कितना पर्सेंटेज़ आपका लंग इनवाल्वमेंट है, वह सीटी स्कैन की रिपोर्ट से ही पता चलता है । सीटी स्कैन सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा हों और जो-जो पेशेंट हमारे क्वारेंटाइन सेंटर्स में एडिमट हैं, वहां पर सीटी स्कैन इन पेशेंट्स का होना बहुत जरूरी है । इससे मार्टेलिटी रेट और कितना इनवाल्वमेंट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, अगर जल्द से जल्द उस पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहां मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है ।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कनक्लूड ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं । इसी के साथ में जो डॉक्टर्स हैं, उनको हमने पचास लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया है । यह इंश्योरेंस कवरेज सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स तक ही सीमित है । प्राइवेट डॉक्टर्स भी उसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं । प्राइवेट डॉक्टर्स के परिवार को भी इंश्योरेंस की राशि देनी चाहिए । महाराष्ट्र में हमने इसे किया है । अगस्त में हमने जीआर पास किया है कि वहां प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इनवॉल्व किया जाए ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कोरोना के दौरान सभी सांसदों को, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर तीन बार फोन करके मेरा और मेरे परिवार का हालचाल, मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का हालचाल पूछा । इसके लिए आज सबसे पहले आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना जो है यह आपदा में अवसर, जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा, यह बिल्कुल सही शब्द है कि हमारे यहां जो मेडिकल इनफ्रास्टक्चर है, पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश और जिस क्षेत्र अमरोहा से हम आते हैं, अभी पिछले दिनों नीति आयोग का तो बाकायदा पेपर सर्कुलेट हो गया था कि जिला अस्पतालों को भी पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर बेच दिया जाए, उनके साथ प्राइवेट लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए । आज क्या हो रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम आठ लाख रुपये जमा कराये जाते हैं, अगर कोई कोरोना पेशेंट दिल्ली के अंदर जाता है । मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि सरकारी अस्पतालों का इनफ्रास्टक्चर क्रिएट किया जाए, उसे बढ़ाया जाए ।

मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी सत्ता पक्ष के एक सांसद निशीकांत जी ने बहुत अच्छा भाषण किया । अनेकता में एकता को बढ़ाने का यह मौका मिला है । यह सही बात है । यह मौका मिला है । मेरी आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से गुजारिश है, बड़ा अफसोस हुआ, जब एक जगह से, एक पाइंट से एक कम्युनिटी को टार्गेट करके सरकार आंकड़े बताती थी और पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया कि यह कोरोना जो है, इसे तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया है ।

मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, जब इसी सदन के अंदर आज भी सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि अस्सी प्रतिशत कोरोना इस देश में तब्लीगी जमात के लोगों ने फैलाया है । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए । चाहे तब्लीगी जमात के लोग हों, तिरूपित मंदिर के प्रिस्ट को कोरोना हुआ हो, अयोध्या के मंदिर के प्रिस्ट को कोरोना हुआ हो, चाहे किसी मिस्जद या

गिरिजाघर के प्रिस्ट को कोरोना हुआ हो, बीमारी मजहब देखकर नहीं आती है । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आज मेरा सिर शर्म से झुक रहा है । हमने पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा दिया । हमने सब्जी को भी मजहब को रंगों में बांट दिया, हमने बीमारी को भी मजहब के रंगों में बांट दिया । यह देश अनेकता में एकता का देश है । यह देश मिलीजुली संस्कृति का देश है । इसे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्ट ऑफ गॉड कहा, इससे हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में देश को बांटने की कोशिश नहीं की जाएगी । ऐसी संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र जात और मजहब से उपर उठकर इकट्ठा होंगे और इस बीमारी से लड़ने का काम करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there is an adage that a stitch in time saves nine. I think, our hon. Health Minister is one of the eminent doctors in the world. Not only that, he has been recently promoted as Chairman, Executive Board of World Health Organisation. So, he knows everything. I know that there is a severe time constraint. So, I do not want to elaborate anything. But on two or three points, I would like to draw the attention of the hon. Minister.

Since the beginning, everything has been done in a haphazard way. Haphazard travel restriction आपने किया, Shortage of emergency supplies and redtapism, यह एक बड़ा कारण है । Delay in ordering testing kits, यह आपके लिए बड़ी शिकायत है । The most important point is regarding the loss of life of health professionals and the response of the Government of India. यह कितने दु:ख की बात है । No country has lost as many doctors and healthcare workers as India has to the pandemic. The IMA recently said: "Doctors suffer four times the mortality of

ordinary citizens and private practitioners suffer eight times as much." The IMA demands that all the doctors should be given the status of martyrs and it has submitted a list of at least 382 doctors who died from COVID-19 across the country. But the Government denies of having any information of death of any doctor and health professional.

How can our Health Minister feign ignorance? He himself is a doctor. Who understands better than him? I just wonder if the Government has maintained the statistics of the total number of doctors and healthcare workers infected by COVID-19 and the statistics of how many of them sacrificed their life due to the pandemic. It loses the moral authority to administer the Epidemic Act 1897 and the Disaster Management Act. अभी तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि कम्युनिटी ट्रांसिमिशन हो रहा है । हम चाहेंगे कि हर्ष वर्धन जी इस बारे में हमें इनलाइटेन करें । मैं जानता हूं कि हमें बोलने के लिए कम समय है । फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम सोची समझी एक स्ट्रेटजी शुरू दिन से बनाते तो मुझे लगता है कि इस तरह के हालात शायद पैदा नहीं होते । The global and humongous dimension of epidemic is known to all of us. So, epidemic cannot be prevented but the intensity of epidemic, the intensity of pandemic could have been mitigated. The measure of mitigation was not up to the mark. I must raise this point.

Secondly, I have a little doubt insofar as the number of deaths taking place under Corona in our country are concerned. It is because, I think, there is a serious under-reporting of deaths in our country. I do not know how many

hospitals of our country can issue the medical certification of cause of death. सर हिन्दू पेपर के एक कॉलम में हेमंत दीपक शेवाडे और गिरिडर गोपाल परमेशरन लिखा था ।

21.00 hrs

According to the latest vital statistics of India based on the civil registration system, 86 per cent of the total deaths were registered out of which 22 per cent had a medically certified cause of death. This means 18.9 per cent of the total death was medically certified with a cause of death. To adjust for the prevailing under-registration of deaths and poor coverage of MCCD, we can multiply the reported COVID-19 deaths by a multiplication factor of 5.29 for India and calculated as the inverse of 18.9 per cent among total deaths based on 2018 CRS.

This estimated COVID-19 death per million population is higher than Russia. It is similar to South Africa. It is lower than USA. It is 99 per cent in (MCCD) Brazil. It is 100 per cent MCCD in Mexico. It is 95 per cent MCCD in Chile. It is 95 per cent in Spain. Even in Iran, it is 90 per cent MCCD.

Madhya Pradesh, West Bengal, UP, Bihar and Jharkhand constitute 43 per cent of national population. These States with 12 per cent MCCD coverage and less than 10,000 COVID-19 test per million contribute to 38 per cent of the total estimated COVID-19 death.

महोदय, डॉक्टर साहब, आप अंडर रिपोर्टिंग के बारे में एनलाइटन कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी मौतें होती हैं, जिनके बारे में पता नहीं चलता है । गांव में पंचायत के प्रधान सर्टिफिकेट दे

देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मरीज की किस कारण से मृत्यु हुई । इस बारे में आप हमें बताइए ।

दूसरी बात, कोविड के कारण देश में पीएम केयर्स फंड बना । पीएम केयर्स फंड से मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला था, यहां पीएम केयर्स फंड के बारे में चर्चा करना मुश्किल हो जाता है । जब हम जानना चाहते हैं तो वित्त मंत्री और उनके बलशाली साथी गुस्से में भर कर उठते हैं और नेहरू जी से सोनिया गांधी जी पर झूठमूठ इल्ज़ाम लगा देते हैं । हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं । हम बार-बार सत्ता पक्ष के लोगों को कहते हैं कि किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी के साथ गांधी का संपर्क छीन नहीं सकते हैं । गांधी परिवार एक विचारधारा है, आप विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते हैं । मेरा हैल्थ मिनिस्टर से सवाल है कि पीएम केयर्स फंड में आज तक मंत्रालयों और सूबों की सरकारों को कितना पैसा मुहैया कराया गया । आपके पास अगर इसकी कोई जानकारी है तो जरूर बताएं ।

मैं सदन में एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश में सूबों की सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं, इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि आईसीएमआर से लेकर सारी सैंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करने के लिए खड़ी रहें । आपने एडहॉक तरीके से एक टॉस्क फोर्स बनाई है, लेकिन टॉस्क फोर्स के पास इतने साधन नहीं हैं । सूबों की सरकार को इससे मदद नहीं मिलती है और जिस रफ्तार से मरीज को बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए था. नहीं लड़ पाते हैं ।

दूसरी लहर आ रही है, सब कहते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरी लहर आएगी । दूसरी लहर से पहले आप ठोस कदम उठाएं । हर सूबे की सरकार मजबूत रहे, इसके लिए साधनों की जरूरत है । उनके पास इतने साधन नहीं हैं । मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहता हूं कि वह इस विषय पर क्या सोच रहे हैं?

अभी निशिकांत जी माइग्रेंट लेबर्स के बारे में बात कर रहे थे । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि माइग्रेंट लेबर्स की अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए । पहली बार हमें इस तरह का तजुर्बा

हुआ है । माइग्रेंट लेबर्स हिंदुस्तान की हर स्टेट में है । हम बंगाल से आते हैं, हमारे प्रदेश से लोग लाखों की तादाद में बाहर काम करने के लिए जाते हैं । हिंदुस्तान में बड़े शहरों में बंगाल से लोग काम करने के लिए जाते हैं, कहीं राज-मिस्त्री, कहीं गोल्डिस्म्थ जैसे तरह-तरह के काम करने के लिए जाते हैं ।

लेकिन, अचानक जब यह लॉकडाउन शुरू हो गया, उसके बाद इन लोगों के अंदर त्राहि-त्राहि मच गई । लोग भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे । बीच में उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया । आज हम बड़ी-बड़ी बात करते हैं, लेकिन, उस दिन प्रवासी मजदूरों को मदद करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी हम सराहना कर सकें । इसके कारण हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है । पश्चिम बंगाल में 11 से 12 लाख प्रवासी मजदूर वापस चले गए । वहां जाने के बाद उनके पास कोई काम धंधा नहीं था । अब वे वापस जहां से आए थे, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं । प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखकर हम सबको बहुत दु:ख होता है । हम माननीय मंत्री से अनुरोध करेंगे कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं ।

मैं 'अनेकता में एकता' की बात मानता हूं । मैंने भी इसकी मदद ली थी । मार्टिन लूथ किंग ने एक बात कही थी- "If you cannot fly then run, if you cannot run then walk, if you cannot walk then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward." जब चारों तरफ सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, हमारे घर पर लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों के फोन आ रहे थे, क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, वहां बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं । एक ही डिस्ट्रिक्ट में लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर हैं । हम क्या करते? इस सदन में हमारे जो भी दोस्त हैं, उन सबको मैंने फोन किया । आज इस समय वे सब साथी, जिन्होंने हमारी मदद की, मैं बंगाल के

प्रवासी मजदूरों की तरफ से उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं एमपीज का नाम पढ़कर खत्म कर दूंगा ।

सबसे पहले, सर्वश्री जितेन्द्र सिंह, सुरेश कश्यप, डॉ, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, संतोष कुमार चौधरी, सत्यपाल सिंह, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, अखिलेश यादव, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, दर्शना जरदोश, विजय कुमार हांसदाक, अच्युतानंद सामंत, डॉ.राजकुमार सिंह, रिपन बोहरा, विनायक राउत, अरविंद सावंत, श्रीपद नायक, फ्रांसिस्को सर्दिन्हा, नामानागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी, डी.वी.सदानंद गौडा, प्रहलाद जोशी, डी.के.सुरेश, बालाशोवरी वल्लभानेनी, रघुराम कृष्ण राजू, कनिमोझी, दयानिधि मारन, ए.राजा, टी.आर.बालू, डॉ. के.जयकुमार, डॉ.बसंत कुमार, जिनकी मौत हो गई, कुनहलिकुट्टी, एस.सुधाकरण, एम.के.राघवन, के.सुरेश, टी.एन.प्रथापन, के.मुरलीधरन, हिबी इडन कुलदीप शर्मा और इसके साथ हमारे प्रिय लोक सभा के स्पीकर और साथ-साथ मैं आज जरूर यह स्वीकार करूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी हमारी बहुत मदद की है । इन सब के चलते ही हम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की मदद कर पाए, लेकिन, बंगाल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है । बंगाल में त्राहि-त्राहि मची हुई है । वहां लोगों को लूटा जा जा रहा है । वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस मौके का फायदा उठाकर मरीजों का गला कसाई की तरह काट रहे हैं । ...(व्यवधान) आप इस चीज को देखिए । बंगाल में बहुत सारी मौतें होती हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है । पूरे बंगाल में तानाशाही का राज है । तानाशाही के राज में लोगों की बात नहीं सुनी जाती है । इसलिए, मैं हर्ष वर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि बंगाल के बारे में कुछ ठोस कदम उठाएं । अंत में एक बात कहना चाहता हूं, हर्ष वर्धन जी यह बताइए कि वैक्सीन कब मिलेगी? पूरा हिन्दुस्तान वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहा है । हम सबको आप एक संदेश देते हुए भरोसा दें, तसल्ली दें, क्योंकि हिन्दुस्तान के आम लोगों को तसल्ली की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संक्षिप्त में सारी बात सदन में रख दें । आप सभी संक्षिप्त में सुनना चाहते हैं या पूरा सुनना चाहते हैं । दो घंटा सुनना चाहते हैं या संक्षिप्त में सुनना चाहते हैं ।

अनेक माननीय सदस्य: संक्षिप्त में ।

माननीय अध्यक्ष: सदन भी यह चाहता है कि आप संक्षिप्त में बोलें । सदन की तरफ से मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप संक्षिप्त में अपनी बात रख दें ।

*श्री प्रदीप कुमार सिंह (अरिया): मैं कोविड-19, वैश्विक महामारी पर अपने विचार रखता हूं।

मैं आज कोरोना काल की दुखद स्थिति पर ही कुछ कहना चाहता हूँ, यूं तो हमारी सरकार ने इस महामारी के खिलाफ सजगता व गंभीरता दिखाते हुए बहुत ही जल्दी इस विकट स्थिति को नियंत्रण में कर लिया । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉ. हर्षवर्धन जी का आभार व्यक्त करता हूँ ।

आज पूरे विश्व की अपेक्षा हमारे देश का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, ताजा जानकारी के मुताबिक यह करीब 75 प्रतिशत के आसपास है । इस वैश्विक महामारी से हमारा बिहार भी अछूता नहीं रहा । बिहार की जनता को केन्द्र सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग की वजह से वर्तमान में नीतीश जी की सरकार ने इसे नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है । बिहार का रिकवरी रेट करीब 92 प्रतिशत है, जो देश में सबसे ज्यादा है । बिहार में अब तक करीब 58 लाख लोगों को कोरोना चेक हो चुका है । इसके लिए मैं बिहार सरकार एवं वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ । लेकिन, महोदय इस जाँच को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है । मैं चाहूँगा कि इस जाँच को हमारे सीमांचल इलाके में ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए । हमारे संसदीय क्षेत्र अरिया में भी कोरोना के कई मरीज मिले हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है । इसलिए वहाँ जाँच जरूरी है, तािक लोगों के मन का डर खत्म हो सके । मैं सरकार से यह भी अपील करना चाहूँगा कि वैश्विक महामारी ने देश-प्रदेश के लोगों का कमर तोड़ रखा है । सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए, तािक उनकी जीवनशैली पुन: पटरी पर आ सके ।

Speech was laid on the Table.

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): I would like to express my views on the outbreak of Corona Pandemic in India. I would like to begin with paying my tributes to the Corona warriors which include doctors, healthcare workers, sanitation workers, police staff and everyone who has strengthened our fight against this virus.

I would like to place on record my appreciation and gratitude to our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji who has led from the front and with his decisive leadership, we have been able to successfully fight this battle. I also thank Dr. Harshvardhan Ji for spearheading the efforts of the Ministry of Health and Family Welfare.

It is pertinent to note that we are currently facing a crisis which has affected every single person and has brought not only the country but the whole world to a standstill, but our Government has been taking decisive steps at regular intervals to ensure that every section of the society is benefited. Decisions like Atma Nirbhar Package of Rs.20 lakh crore or PM Garib Kalyan Yojana which has benefited more than 80 crore people are testaments to our effective governance.

The Opposition has been regularly criticizing the decision of lockdown instead of supporting the government in the fight against Corona. It has been estimated that this decision prevented approximately 14 lakh to 29 lakh cases and 37,000 to 78,000 deaths.

Speech was laid on the Table.

Further, these four months were utilised to create additional health infrastructure, enhance human resource and produce within India critical elements such as PPEs, N-95 masks, and ventilators. A case in point is increase in dedicated isolation beds around 36.3 times and dedicated ICU beds above 24.6 times to what existed in March, 2020.

Whereas there was no indigenous manufacturing of PPE, with the requisite standards, at that point in time, we are now self-sufficient and, in a position, to even export the same.

I have few suggestions and recommendations:

Under the National Health Mission, the Government had in April 2020 announced significant investments to the tune of Rs.15000 crores for 'India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package'. The funds sanctioned will be utilized for immediate COVID-19 Emergency Response (amount of Rs.7774 crores) and rest for medium-term support (1-4 years) to be provided under mission mode approach.

For my Ahmednagar Lok Sabha constituency, a fund of about Rs. 16 crore has come under the National Health Mission. There are two things regarding that. Firstly, they have different provisions for purchase of equipment, beds and everything but, as of now, the situation is such that availability of beds are very less even if we put an order regarding central oxygen system or facilities you have advised along with no provision for a rental allowance. For example, if a hospital

is taken and the hospital has the entire facility of beds, central oxygen system, and ventilators, the District Collector or the District Administration does not have funds to give for that hospital.

It has been more than 3 months since this package was announced and even when its Centrally Sponsored, it is my personal experience that the concerned Member of Parliament is not taken into confidence regarding the utilization of these funds. The entire control has been vested with the Collector who is already overburdened with several other obligations.

I am a neurosurgeon and if representatives with specialized medical knowledge are included while deciding the disbursement of funds under this package, it will ensure a holistic and better decision making process.

I really appreciate that we have increased the testing. I would only make a few suggestions as to what I have realized in this RT-PCR machine. There are two systems. One is open and one is closed. There has been increased cases of variability in testing, with negative showing as positive and positive showing as negative, due to the kits being used in an open-based system of PCR. That is very clear evidence that I found in my lab. My recommendation would be that in districts which do not have RT-PCR labs and private labs are available, the government should provide free kits on the lines of government hospitals to ensure free investigation by private labs because we cannot bear the cost of the

kit but we are ready to bear the cost of the technicians, the electricity, etc. So, private labs could be wilfully coming forward to do these tests for free.

The large Indian population does pose challenges in terms of health service provision. However, in the context of Covid-19, India has two socio-demographic features that confer advantage. First, we have a demographically young population which is better protected against severe illness than older populations. Second, nearly two-thirds of India is rural. The virus spreads more slowly in rural areas than in urban areas due to less crowd density, shorter distances that most people commute to work and more open spaces. It is necessary, however, that we address the need of population stabilisation through a broad range of strategies.

There are two types of incentives: (a) removal of the hurdles and grievances that are impeding their work or endangering them; (b) positive incentives for boosting their morale and enhancing their performance.

From being reasonably self-reliant-both in drug formulation and API production, in the early 1990s, India had become mostly import-dependent in API. Last year, India imported roughly Rs.50,000 crore worth of APIs, and other intermediaries that go into production of finished formulations. About Rs.31,740 crore worth of these were from China alone, accounting for two-third of API imports. Of the top 20 imported APIs, amounting to Rs.3,610 crore, 68 per cent

were from China. For production of several medicines, import intensity from China is alarmingly high.

In case of streptomycin, used in treating tuberculosis (TB) and other infections, nearly all imports are from China. In case of penicillin, another critical antibiotic, 90 per cent of imports are from China. And, 70 per cent of rifampicin API (used for TB treatment), 63 per cent of erythromycin API (an antibiotic used especially for respiratory infections), 82 per cent of glutamic acid and its salts (treatment for nerve disorders), 80 per cent of aniline and its salts (for antioxidant formulations), are imported from China.

This Pandemic has brought an opportunity for India to regain its status as a self-sufficient manufacturer of Active Pharmaceutical Ingredients.

China has not only created tension at the border but there are also strong evidences to state that the COVID-19 virus is a lab made virus. Chinese virologist Dr. Li-Meng Yan has claimed that coronavirus COVID-19 was made in a Wuhan laboratory. Dr. Li-Meng Yan, who was associated with Hong Kong School of Public Health, had been researching on the coronavirus for a long time. The Chinese virologist claimed that during her research, she came across that coronavirus was developed in laboratory in China.

With these recommendations and suggestions, I thank the government and conclude my speech.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): सर, आपकी जिस तरह की भावना है, उसके अनुसार मैं आपके आदेश की पालना करने की कोशिश करता हूं । मैं सबसे पहले उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने हम सभी की प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहूति दी, उन सभी की पवित्र स्मृति को नमन करना चाहता हूं । आज भी जो कोरोना वॉरियर्स देशवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनको और विशेष रूप से उन सभी की माताओं को भी मैं आज इस अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं । देश में एक भी ऐसी माता का उदाहरण सामने नहीं आया, जिसने अपने घर से कोरोना वॉरियर को अस्पताल जाने से रोका हो ।

माननीय अध्यक्ष: हम सदन की तरफ से सभी को धन्यवाद दे देते हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश के 135 करोड़ लोगों ने, सभी मुख्य मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी स्वयं सेवी संस्थाओं ने, सभी धार्मिक संगठनों ने और देश के साधारण नागरिकों ने मिलकर पिछले 9 महीने से इस संघर्ष को बहुत ईमानदारी से लड़ा है । हमने जब यह कहा कि इस देश को प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए तो उसका अभिप्राय केवल यही था कि प्रधान मंत्री जी ने नेतृत्व प्रदान किया और सभी ने मिलकर उनका सहयोग किया । मुझे पिछले 9 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा, जब प्रधान मंत्री जी ने देश के हर एक व्यक्ति को इस काम में साथ न लिया हो । छोटी से छोटी बात के लिए कंसेंसस न बनाया हो । सभी ने मिलकर यह काम किया इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को करने के लिए देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं । यहां पर कुछ ऐसे बयान भी हुए, जिनके आधार पर मुझे लगा कि हम बहुत सारी बातें अपने स्मृति पटल से भूल गए हैं । मैंने इस सदन के अन्दर फरवरी महीने में और मार्च के महीने में भी डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया था । आपके सवालों के जवाब भी दिए थे । सरकार ने जो जनवरी और फरवरी मं काम किया था, उसके बारे में मार्च में आप सभी के बीच में चर्चा की थी । मैं केवल आपको स्मरण

दिलाना चाहता हूं कि विश्व स्वारम्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को सबसे पहले दूनिया को चेतावनी दी थी कि कोई ऐसी बीमारी आई है, जो एक इंटरनेशनल हेल्थ कंसर्न है, लेकिन हमने अपना काम 8 जनवरी को ही शुरू कर दिया था । हमने 17 जनवरी तक पूरे देश को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी दे दी थी । हमने पॉइंट ऑफ एंट्री सर्विलांस शुरू कर दिया था । कम्युनिटी सर्विलांस शुरू कर दिया था और जब भारत में 30 तारीख को पहला केस आया था तो सबसे पहले मैं सर्विलांस से जुडे हुए लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं । हमारे डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूं । दिल्ली में स्थित भारत सरकार के नेशनल सेन्टर फॉर डिजीज कंट्रोल को और देश के इंटिग्रेटेड डिजीज सर्विलांस सिस्टम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने उस पहले केस में 162 कॉन्टेक्ट्स की ट्रेसिंग की थी । आज तक भारत के अंदर 40 लाख लोगों को कम्युनिटी सर्विलांस में रखा गया है । एक करोड़ से ज्यादा लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हुई है । एयरपोर्ट्स पर 15 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है । नेपाल में जब पहला केस आया तो उस बोर्डर के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू हुई और 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई । आस पास के 5 हजार गांवों के अंदर ग्राम सभाएं हुईं। आप शायद यह सब कुछ भूल गए, क्योंकि इस विषय को बहुत समय हो गया है । जब कोरोना भारत में आया तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग तो दूर, डॉक्टर्स को और दूसरे लोगों को भी कोरोना के बारे में इतना विस्तार से ज्ञान नहीं था । दो से तीन मिलियन लोगों के बीच में जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स और डिफेंस से लेकर एयरपोर्ट्स के ऑफिशियल्स के लोगों ने इस पर काम किया, उनको भारत सरकार ने उसी दौरान ट्रेंड किया था । उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई ।

यहां पर लॉकडाउन के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई है । मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं कि 16 मार्च और 23 मार्च के बीच में देश में आधा दर्जन से एक दर्जन के बीच में सरकारें या तो पार्शियल लॉकडाउन कर चुकी थीं या टोटल लॉकडाउन कर चुकी थीं । यह प्रधान मंत्री जी का विजडम है, उसे नमन करना चाहिए कि उन्होंने जब 'जनता कर्फ्यु' घोषित किया, तब वह शायद इतना बड़ा इनोवेटिव

आइडिया था सारे देश को प्रिपेयर करने के लिए और यह देखने के लिए भी कि क्या देश इस बात के लिए तैयार है कि अगर हम टोटल लॉकडाउन करें तो किस प्रकार की स्थिति आ सकती है ।

लॉकडाउन के लाभ और हानि के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं । मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि पांच प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट स्टडीज में, किस प्रकार से कितने केसेज और कितनी मौतें उसके कारण प्रिवेंट हुई, उसके बारे में अलग-अलग स्टडीज में अलग-अलग बात की गई है । वह समय कितना भयानक था, अगर हम उसे स्मरण करने की कोशिश करें, उन विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ढाई हजार से ज्यादा लोगों को वुहान, इटली, ईरान, मलेशिया एवं अन्य स्थानों से यहां पर लेकर आई । हमारे लोगों को लाने के लिए लैब की टेस्टिंग की फेसिलिटी ईरान में नहीं थी, तो यहां से लैब तक हम लोगों ने ईरान के अंदर शिफ्ट की । बाद की परिस्थित में आपने देखा कि 12 लाख से ज्यादा भारतीय, जो सारी दुनिया में स्ट्रैंडेड थे, उनको 'वन्दे भारत' के माध्यम से भारत में लेकर आया गया ।

अभी कई लोगों ने देश के अंदर स्टिग्मा की बात की, हमारे साथी डॉक्टर श्रीकांत ने अंत में यह बात की । जब हमारे डॉक्टरों और दूसरे लोगों के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया था, लोगों को लगता था कि वे बीमारी लेकर आ रहे हैं । उनको कॉलोनियों में नहीं घुसने दिया जा रहा था, उनको फ्लैट में नहीं घुसने दिया जा रहा था और वे अपने ही घरों के अंदर, दूसरे स्थानों पर जाकर तकलीफ पा रहे थे । उस समय यह सरकार का विजडम था - इस पर कल चर्चा भी होगी – कि एपिडेमिक डिजीजेज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस लेकर आई । इसके आधार पर यह तय किया गया कि अगर उनके साथ कोई भी बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा, उनके साथ मार-पीट करेगा, क्योंकि पहले उनको चेज किया गया और बहुत तरह के अन्याय हुए, उसके खिलाफ काग्निजबल और नॉन-बेलेबल कानून बनाया गया । यह भी सरकार का विजडम था कि सारे देश में कहीं कोई भी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर तक को भी अगर कोरोना के लिए काम करते हुए किसी प्रकार से उसके प्राण जाते हैं तो भारत सरकार ने उसके

लिए 50 लाख रुपये के इंश्योरेंस की व्यवस्था की है । 22 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यह व्यवस्था है ।

बहुत सारे लोगों ने यहां हमारे मजदूर भाइयों के बारे में बात की है । मजदूर भाइयों को जो तकलीफ हुई है, उसके बारे में हरेके के मन में एक संवेदनशीलता का भाव है, उसमें कोई डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता है । गृह मंत्रालय ने उन विषम परिस्थितियों में सारी एसेंसिशल सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के व्यापक अरेंजमेंट्स किए । जब विषम परिस्थिति हो गई थी, लोग डेस्परेट हो गए थे, तब मत भूलिए कि इस सरकार के प्रयासों से ही 64 लाख मजदूर भाई-बहन श्रमिक एक्सप्रेस एवं दूसरी ट्रेन्स और बसों के माध्यम से अपने-अपने गन्तव्य स्थानों तक पहुंचे थे ।

अभी यहां पर वेंटिलेटर्स इत्यादि के बारे में बात की गई, मैं बताना चाहता हूं कि पीएमकेयर्स फण्ड ने हमारे मंत्रालय को 893.93 करोड़ रुपये 50 हजार 'मेक इन इंडिया' वेंटिलेटर्स के लिए दिए । नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड के माध्यम से सारे देश की सरकारों को 11 हजार करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की गई कि वे अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फण्ड को इस काम के लिए यूज कर सकते हैं । हमने अपने नेशनल हेल्थ मिशन में सारे फण्ड्स को किस प्रकार से वे रिएप्रोप्रिएट करके यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तुरंत ही 4200 करोड़ सारे देश में सरकारों को बांटा गया । आज जो प्रधान मंत्री जी की बड़ी-बड़ी कल्याण योजनाएं हैं, उनकी बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट है ।

कितने करोड़ों लोगों को उससे लाभ हुआ, उसकी चर्चा करना समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शायद संभव न हो । भविष्य में भी बड़े पैमाने पर कोई भी पैनडेमिक आए तो उसे कैसे सरकार हैंडल कर सकती है, इसके लिए प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की योजना के तहत 65 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के ऊपर आलरेडी काम शुरू हो गया है और विस्तार से सारे देश में ब्लॉक लेवल तक किस प्रकार से इनफेक्शियस डिसीसेज अस्पताल और लैबोरेट्रीज को ज्यादा विकसित

करने का काम शुरू हो गया है । आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों से हमने पीपीई सूट की शुरूआत की थी । चारों तरफ उसके बारे में चर्चा होती थी, शायद आप लोग भी फरवरी में उसकी बातचीत करते थे । डेढ़ करोड़ पीपीईज और साढ़े तीन करोड़ एन-90 मास्क, तीस हजार वेंटिलेटर्स और इसी प्रकार से एक लाख आक्सीजन सिलेंडर्स राज्यों की सरकारों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई कर चुके हैं । अधिकांश स्थानों पर सैचुरेशन प्वाइंट आया और राज्य सरकारें मना करती थीं कि हमारे पास इन सामानों को रखने की जगह नहीं है, इसलिए आप कुछ समय बाद हमें दीजिएगा ।

आप जानते हैं कि यदि लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल सही ने नहीं किया गया होता और राज्यों की सरकारों को ठीक प्रकार से सपोर्ट न किया गया होता तथा उनकी ठीक से मोनिटरिंग न की गई होती, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती । देश में जो डेडिकेटेड कोविड की फैसीलिटीज बनाई गई, जिसमें 18 लाख से ज्यादा (सभी प्रकार के) बैड्स हैं, देश में 13 हजार क्वारंटीन सैंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें छ: लाख से ज्यादा बैड्स हैं और हम जो बात बार-बार करते हैं कि हमारी एक लैब एनआईबी, पुणे में थी, जहां इसकी जांच हो सकती थी । आज जब मैं सितम्बर में बात कर रहा हूं, तो 1773 लैब्स हैं । ये 1773 लैब्स ऐसे ही नहीं बनी हैं, बल्कि उन विषम परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से चार सैंट्रल, 16 रीजनल डिपोज क्रिएट किए गए । आज देश में तीन किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक लैबोरेट्री लोगों के लिए उपलब्ध हैं । उसके लिए कितने प्रकार के मैटीरियल्स को जगह-जगह पहुंचाना था । उन विषम परिस्थितियों में सरकार ने ऐसा करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज 6.37 करोड़ टैस्ट देश में हो चुके हैं । शायद दुनिया में सबसे ज्यादा टैस्ट हो रहे हैं । कल भी हमने 12 लाख टैस्ट किए हैं । आप याद कीजिए वह दिन, हर टेलीविजन चैनल पर बोलते थे – टैस्ट, टैस्ट, टैस्ट । हमने जो टार्गेट्स तय किए, उन्हें समय से बहुत पहले पूरा करके आज 12 लाख टैस्ट एक दिन में किए । आप वह समय भी याद कीजिए, जब हम किट्स को इम्पोर्ट करते थे और वह बहुत महंगी होती थीं । वे किट्स चाइना से आती थीं या किसी दूसरे देश से आती थीं । आज दस

लाख से ज्यादा किट्स हम रोज बनाते हैं और 860 किट्स को हमने इवेल्यूएट किया है तथा 442 किट्स को रिक्मेंड किया है और इनमें से 308 इंडिजनस किट्स हैं, यानी इस स्तर पर देश के अंदर काम हुआ है।

मैं कुछ बातें वैक्सीन के बारे में भी बताना चाहता हूं। यद्यपि दुनिया में 145 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो कि प्रीक्लीनिकल इवेल्यूएशन में हैं और लगभग 35 ऐसे हैं, जो क्लीनिकल ट्रायल्स में हैं। भारत में हमने 30 कैंडिडेट वैक्सीन्स को पूरा सपोर्ट दिया है, उसके बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें और ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और उसमें से तीन केंडिडेट्स हमारे फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के एडवांस ट्रायल्स के अंदर हैं और लगभग चार से ज्यादा प्रीक्लीनिकल डेवलपमेंट, प्रीक्लीनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके एडवांस स्टेजेज के अंदर आलरेडी पहुंच गए हैं।

इसके साथ-साथ लोगों ने आने वाले समय के लिए भी बताया है, उसके लिए भी तैयार हैं । प्रधान मंत्री जी ने एक National Expert Group on Vaccine Administration बनाया है । जिसका चेयरमैनशिप मैम्बर नीति आयोग कर रहे हैं, जो हेल्थ के मैम्बर हैं । जैसे-जैसे भविष्य में वैक्सीन बनती है, उसकी उपलब्धता कैसे करानी है, वह सबसे पहले किन लोगों के लिए आवश्यक है, उसके लिए भी डिटेल्ड स्ट्रैटजी ऑलरेडी वर्कआउट कर ली गई है । ऐसा नहीं है कि हम केवल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में भेज रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वायरस पर रिसर्च का भी काम कर रहे हैं । आज जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा था कि हम दो हजार से ज्यादा वायरसेज का जिनोम सिक्वेंसिंग कर चुके हैं । एक प्रकार से वायरस की बहुत डिटेल्ड स्टडी हो रही है । चालीस हजार वायरसेज के सैम्पल्स की, हम लोग ने 15, 10 आईसीएमआर और पांच बायोटेक्नोलॉजी की रिपॉजिट्रीज बनाई है । हम लोगों ने वह उसके अंदर रख दिया है । देश में अनेक प्रकार के चाहे वे इंडस्ट्रीज हों, एकेडेमिया हो, यंग रिसचर्स हों, या स्टार्टअप्स वाले हों, उनके लिए वे रिसर्च करने के लिए और आगे बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध हैं ।

इसके साथ-साथ साइंस के अंदर जितनी भी बेसिक साइंटिफिक स्टडीज हो सकती हैं, behaviour transmission, effects of virus, mathematical modelling, academia R &D labs, industries, start-ups, DBT, DST, CSIR, ICMR सभी मिल कर हॉलिस्टिक तरीके से सारे एकेडेमिया के साथ मिल कर काम कर रहे हैं और इतने प्रकार के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं । वेंटिलेटर्स के ऊपर काम हो रहा है, diagnostic kits पर काम हो रहा है, वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, therapeutics पर काम हो रहा है, disinfectants पर काम हो रहा है, PPEs, मास्क, मोबाइल टेस्टिंग बुथ, anti-viral coating पर काम हो रहे हैं । बहुत सारी चीजों पर लगातार काम हो रहे हैं । इसी के साथ-साथ composite mapping of our entire start-up ecosystem, इन सारी चीजों पर काम हो रहा है । हम ने 110 टेक्नोलॉजी के स्ट्टिअप्स को इस दौरान इसी कोविड के काम के लिए सपोर्ट किया है, 20 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया है । 150 प्रोजैक्ट्स in all areas of virus behaviour और बहुत सारी चीजें जो artificial intelligence से जुड़ी हैं, उनके साथ भी मिल कर काम कर रहे हैं । विज्ञान के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक कोविड के खिलाफ जंग को कैसे सफल बना सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं ।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ थ्रू-आउट, चाहे वह कंट्री लेवल हो, रीजनल लेवल हो या ग्लोबल लेवल हो, हमारी सरकार का पूरा कॉर्डिनेशन है । वहां पर भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स सबके साथ मिल कर अपनी रणनीति बनाते हैं । सब प्रकार की एडवाइजरीज, सब प्रकार की गाइडलाइंस पर्याप्त मात्रा में हर विषय के ऊपर देश की सारी सरकारों को दी गई है । इसी तरह से पिछले समय जी-20 नेशंस, ब्रिक्स नेशंस में हमारी सरकार ने एक मेजर रोल प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, अपनी पॉलिसीज को शेप-अप करने में प्रस्तुत किया है । खासकर जो शार्क नेशंस हैं, उनको बहुत सिगनिफिकैंट किस्म की सपोर्ट दी है ।

अध्यक्ष जी ने कहा है कि संक्षेप में बात करनी है । मैंने आपको कुछ चीजें स्मरण कराई है । यह ऐसा विषय है कि आप इस पर बात करने के लिए तीन घंटा लगाए, तो मैं भी तीन घंटे तक यहां बात कर सकता हूं । मैंने बहुत सारी बातें आपको स्टेटमेंट के माध्यम से फरवरी और मार्च में और अभी जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें शेयर की है । आज कोविड का वायरस ज्यादा तेजी से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है । अभी मेरी आप सभी से एक ही अपील है कि कोविड के खिलाफ जंग में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है । यह आपने भी देखा है कि हमारे बीच भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं । उसका कारण एक प्रकार से इरिस्पॉसिबल बिहैबियर यानी जो कोविड के लिए बिहैबियर होना चाहिए, कोविड वाले बिहैबियर में बहुत बड़ी बातें नहीं कही गई हैं । मास्क से नाक-मुंह को ढ़क कर रखना है । अपने नाक-मुंह पर उंगली नहीं लेकर जानी है, अपने हाथों को चेहरे पर लेकर नहीं जाना है । हाथों की हाइजीन और रेस्परेट्री एटिकेट्स, जिसके बारे में बहुत खूबसूरती से प्रधान मंत्री जी ने कहा है – दो गज की दूरी ।

लेकिन जब से अनलॉक हुआ है, तो देश ने समझ लिया है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है । लोग रिलैक्स हो गए हैं । हम लोग पब्लिक रेप्रजेंटेटिव के रूप में जिस भी जूरिस्डिक्शन में काम करते हैं, अगर हम वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का नेतृत्व प्रदान करें, इसका आन्दोलन विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करें, तािक समाज में जहाँ भी आपको दिखाई दे कि लोगों का विहेवियर, जो कोविड के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम लोग बार-बार कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है, तो यही विहेवियर हमारी सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है ।

मैं आप सभी से यह अपील करना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अपील करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि स्पीकर महोदय भी सबसे अपील करें कि हम हमारे क्षेत्र में फील्ड में जाकर देखें कि कहाँ कोविड के अनुकूल विहेवियर नहीं है, कहाँ कमी है । अगर हमने इस कमी को दूर कर दिया, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में कोई

लम्बी यात्रा नहीं है । कोविड का ट्रांसिमशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है । कोविड हवा में जीवित नहीं रह सकता है । वह जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह सात-आठ दिनों के बाद डेड होता है । उसके पहले अगर वह दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसकी सायकिल मेनटेन रहती है । लेकिन उसकी सायकिल, उसके ट्रांसिमशन को ब्रेक करने के लिए यही प्रि-कॉशंस हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इन प्रि-कॉशंस के ऊपर गम्भीरता से ध्यान देंगे ।

मेरे मन की बहुत-सी भावनाओं को डॉ. निशिकांत दुबे ने व्यक्त की । जब तक मैं लोक सभा और राज्य सभा की डिबेट में नहीं आया था, तो पिछले आठ महीने में मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यह सारा देश मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है । जब यहाँ पर आकर दोनों सदनों में मैंने डिबेट्स सुनीं, तो मुझे पहली बार अहसास हुआ कि शायद कहीं कुछ कमी है । इसलिए डॉ. निशिकांत दुबे ने भी मेरी भावना को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है । मैं हृदय से आप सब के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपके क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर काम करें, इसी कामना के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी स्पीकर्स का, जिन्होंने आज इस डिबेट में कांट्रिब्यूट किया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद माननीय मंत्री जी । आपने संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से अपनी बात की, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह भी आपकी कला है ।

21.33 hrs

NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 17, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020.

में माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि आप इस पर थोड़ा-सा ब्रिफ कर दें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G.

KISHAN REDDY): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of hon.

Home Minister, Shri Amit Shah ji, I rise to move *:

"That the Bill to establish and declare an institution to be known as the National Forensic Sciences University as an institution of national importance to facilitate and promote studies and research and to achieve excellence in the field of forensic science in conjunction with applied behavioural science studies, law, criminology and other allied areas and technology and other related fields, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: आपने राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में बता दिया? श्री जी. किशन रेडडी: जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य, इस विषय पर क्वेरी करना चाहते हैं?

कोई नहीं करना चाहते ।

* Moved with the recommendation of the President.

*SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): I would like to express my views on the Bill. Whereas the Bill seems to be well intended, some of the areas either not so clear, or missing. Policing in India is a State subject which means there are large variations across the States. This includes forensic science facilities as well.

In a large number of cases the results of forensic science aspects are to be explained jointly with the observations relating to forensic medicine as in case of poisoning, firearm wounds, suicides etc. Hence, it is important that studies in Forensic medicines are also given due emphasis. A burning case in point is the case of alleged suicide by a Bollywood film actor being investigated and discussed in media.

Further, the regional aspects are also to be given due consideration. Every region or State has its own issues and problems, be it economic, social and cultural or such other factors or a combination of factors. Therefore, specific studies are important and may be promoted even by the institutes of national importance.

There are other institutions of State and Centre that are also engaged in similar works. These institutions, academic research centres, laboratories and other field units also need to be developed and integrated with these central and State universities. This will create synergy among them, make the outcome

Speech was laid on the Table.

qualitative and more purposeful. Such an arrangement will also make our effort more efficient and avoid duplication as well as highlight areas of focus.

It is suggested to create a knowledge-pool of the achievements of all such institutions, regional, Central or belonging to States. Such a sharing platform will benefit all these organisations and keep them updated.

To derive full benefit of the services of these institutions, facilities for early dissemination of knowledge is needed. This will also benefit in identifying the areas if studies to be given more focus or new areas to be studied.

The State of Telangana has opened three regional Forensic Science Laboratories. This has not only made collection of evidence from the scene of crimes faster but also saved evidences from destruction due to time gap. Further, the early expert opinion has resulted in faster completion of investigation of cases.

Under the able and dynamic leadership of our CM of Telangana, Shri KCR garu, the State police has brought various reforms in the Department for providing better policing for the sake of people. The State police are implementing a number of Information Technology (IT) initiative that helped police in detection and prevention of crimes in the State.

Vacancies have been filled up and the police have come up with several initiatives to engage with communities. People are now bringing issues to the notice of the police and throw up various facts, social media etc and their grievances are being addressed. They are delivering round the clock revises for

crime prevention, women safety and all other aspects. There have been no extremists and Maoist activities since the formation of the State.

The State Government has made a provision for a sum of Rs. 5852 crore for police Department in the financial year 2020-21. Telangana received special incentive funds of Rs. 7.69 crore under modernisation scheme of the Centre due to efficient implementation of police reforms in the State.

These achievements show that modernisation of Police Force of the State is important and the most important factor to strengthen the internal security. Hence, the Centre should allocate more and more funds under this scheme and continue the scheme as modernisation is an ongoing process. Also, the allocation under the scheme be made on the basis of need of the State than the population base so that the State police is able to achieve its modernisation targets early and people are benefited.

The most important aspect is how to take the benefits to the ground. Modalities may be developed to lay a mechanism for sharing of benefits by stakeholders as early as possible. Hon. Police Commission reports that even judicial guidelines could hardly be implemented due to various factors as stated above. Hence, it is important that the State police is strengthened and modernised.

Our society is fast changing and so are the needs and aspirations of people. Rapid advancement of technology is making the changes even faster. 20.09.2020 1009

Hence the needs, modes and ways of policing are to be dynamic. In this

background, such academic institutions are to be dynamic in their approach with

respect to academics and research. Only then they can meet the needs of the

society and keep pace with the change. Hence keeping the management able for

change is of utmost importance. Otherwise, studies and efforts may become

irrelevant.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक संस्था को

अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने तथा

अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध विज्ञान तथा अन्य

आनुषंगिक क्षेत्रों में और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्ता

की संस्था स्थापित और घोषित करने तथा उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक

विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जाना

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 परिभाषाएं

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इंडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इंडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

20.09.2020

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 6 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am moving my amendment.

I beg to move:

"Page 5, line 40,--

omit "Deoxyribonucleic Acid (DNA)". (7)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 10 से 13

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 से 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 14 से 17

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 14 से 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 14 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 18 से 38

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 से 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 39 से 44

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 39 से 44 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 39 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 45 से 56

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 45 से 56 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 45 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधयेक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

21.38 hrs

RASHTRIYA RAKSHA UNIVERSITY BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 18, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji, I beg to move *:

"That the Bill to establish and declare an institution to be known as the Rashtriya Raksha University as an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: क्या इस बिल पर कोई माननीय सदस्य क्वैरी करना चाहते हैं? ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित और घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

_

^{*} Moved with the recommendation of the President

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Mr. Speaker, Sir, after the 26/11 terrorist attack on Mumbai, the Maharashtra Government has taken precautionary measures for coastal security. Under the *Rashtriya Raksha* University, would the Central Government sanction funds for instrumentation research, studying police science including coastal policing, cybersecurity, and establishing and maintaining college and prescribing courses, holding exams, and granting the degree college in my Raigad district, which is located in a coastal area. I would request the Minister to kindly sanction the above.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I have two observations to point out. First, the passage of the Bill upgrades the existing Raksha University under the Government of Gujarat which was established in 2009 and second, it is only converting a State university into a Central University.

I do not see any reason why the Government is in a hurry to upgrade a State university which is only a decade old whereas so many State institutions of higher education across the country are demanding upgradation. There are so many autonomous and Central Government institutes of higher education. One of the recent additions in 2018 was National Rail And Transportation Institute in Vadodara. Why is the Government only considering to establish premier institutions in Gujarat alone? There are so many States with lesser number of higher educational institutes. We cannot put everything into one basket. There is a need to create a balance all over the country as far as education is concerned.

Establishing such institutes also leads to development of that particular area. I can understand that Gujarat is the home State of Modi ji and Amit Shah ji, but there are other States too. As one of the representatives of the people of North-East, I hereby demand the establishment of a campus of the university in Assam.

I have no reason to hide the fact that the very name 'Rashtriya Raksha University' is a bit deceiving. The Rashtriya Raksha University is proposed to be a multi-disciplinary university to create new knowledge through research and collaboration with different stakeholders and help to fulfil the need for a pool of trained professionals with specialised knowledge and new skill sets in various wings of policing, criminal justice system, and correctional administration. The university will have a linkage with world class universities in other countries which will be on need basis for the purpose of exchange of contemporary research, academic collaboration, course design, technical knowhow, training, and skill development.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Sir, this Bill seeks to provide for the establishment of the Rashtriya Raksha University and declares the University to be an institution of national importance. The Bill also repeals the 2009 Act. Our Party welcomes this initiative.

There is an urgent need for institutions to provide police and security services with the necessary academic knowledge, professional skills, and community orientation. At present, there are only a few institutions in the country

which provide the environment, infrastructure and specialisation for imparting education in police sciences.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने समर्थन कर दिया है ।

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY: Yes, Sir. I hope that this University will have a linkage with the world class universities in the other countries which will be on need basis for the purpose of exchange of contemporary research, academic collaboration, course design, technical know-how, training and skill development.

With these words, I support the Bill and congratulate the hon. Home Minister for introducing this Bill.

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सर, मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं । चोर-पुलिस की जो लड़ाई है, यह सदियों से चलती आयी है, लेकिन अपराधी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपराधी से जुड़ता जा रहा है । संक्षिप्त में मैं एक फारसी का शेर कहना चाहता हूं- "कुनद हम जिन्स बा, हम जिन्स परवाज़" यानी जो एक सोच के व्यक्ति होते हैं, वे अक्सर एक साथ रहते हैं ।

"कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़

कबूतर बा कबूतर बाज़ बा बाज़"

प्रधान मंत्री मोदी जी जो सदैव सजग, सदैव सतर्क और सदैव संरक्षक के रूप में रहते हैं तो उनकी पुलिस भी सजग, सतर्क और संरक्षक के रूप में रहती है और यह जरूरी है । उन्होंने वर्ष 2009 में जो राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात में शुरू की, उसके 14 स्कूल्स थे । मैं उन 14 स्कूल्स का अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन पूरा स्कोप कवर करते गए । अब जरूरी है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाए ताकि हर पुलिस के सेक्टर में रिसर्च हो सके । अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस जो नई

तकनीकों का यूज कर रही है, उस तकनीक का फायदा पूरे देश की पुलिस को हो और हम एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ नॉलेज बनें । आज हम दुनिया से इनफोर्मेशन ले रहे हैं । हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ नॉलेज बनें, यह काबिलियत भारत में है । भारत की जो पुलिस है, न केवल कोविड के समय में, बिल्क त्यौहारों के समय में पूरी सतर्कता और तैनाती से काम करती रही है । कुम्भ का मेला हो या क्रिकेट का मैच हो, वे पूरी सुरक्षा को बरकरार रखते हैं । मुझे दुनिया के अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जाने का अवसर भी मिला है । जब हम बंदूक लेकर चलते थे तो हमारी दूसरे देशों की पुलिस से बातचीत होती थी । मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में भारत की पुलिस का नंबर अव्वल आएगा और हमें उसे कायम रखना है और उसे और मजबूत करना है । मैं प्रधान मंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि वे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टेंडर्ड तक लेकर जा रहे हैं और उसे एक नेशनल इम्पोर्टेंस की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित और घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 4 विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 से 9

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – अनुपस्थित

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 10 से 12

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 6, line 3, -

for "Central Government"

substitute "Academic Council". (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 13 से 29

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – अनुपस्थित

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 से 29 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 13 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 30 विश्वविद्यालय निधि संग्रह

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – अनुपस्थित

प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३१ निधि

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY: Sir, I beg to move:

Page 10, line 18, -

for "Central Government"

substitute "Executive Council and Finance Committee". (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 31 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 32 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

21.50 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 - Negatived AND

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 2020

As Passed by Rajya Sabha

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 18क और 18ख, एक साथ लिए जा रहे हैं । श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) promulgated by the President on 9 April, 2020."

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद बोलिएगा ।

...(<u>व्यवधान</u>)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है ।"

और

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'Penny wise, pound foolish'. अर्थात् हम सामने से तो पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन वह पैसा पीछे से निकल जाता है। इसको 'Penny wise, pound foolish' कहते हैं। आप जो यह बिल लाए हैं, यह इससे मिलताजुलता है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से बचत करते हैं। मतलब 12 महीने में 10,800 रुपये की बचत होगी। सुनते जाइएगा। मंत्रियों की 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से बचत होगी, कुल 23 मंत्री हैं। 23 मंत्री 12 प्रति माह 600 रुपये के हिसाब से बचत करते हैं। इसमें कुल बचत 1,65,600 रुपये की होती है। 32 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। इन 32 लोगों के लिए हर महीने 300 रुपये की बचत होगी। कुल मिलाकर 300x32x12 अर्थात् 1,15,200 रुपये की बचत होगी।...(ट्यवधान) कुल बचत 2,91,600 रुपये की होगी। मंत्री जी, ठीक है।

गजट की प्रिन्टिंग करने और इस बिल को बनाने में आपके 4,00,000 रुपये खर्च हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने 4,00,000 रुपये खर्च किए हैं और 2,91,600 रुपये की बचत की है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि 'Penny wise, pound foolish'. आपने बचत करने की कोशिश तो की है, लेकिन वह पीछे से निकल गई है। मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र और माननीय सांसद अधीर रंजन जी भाव को नहीं समझ पा रहे हैं । मैं दो पंक्तियों की एक कहनी बताना चाहता हूं । एक जंगल में आग लग गई थी । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिहार और पश्चिम बंगाल पास-पास हैं।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, हम दोनों बार्डर्स पर एक-दूसरे से मिलते रहते हैं । जब एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सभी लोग आग बुझा रहे थे । किसी ने एक चिड़िया से पूछा कि क्या तुम्हारी सुन्दर सी चोच की दो बूंद पानी से आग बुझ पाएगी? तब उस चिड़िया ने कहा कि मैं भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहती हूं कि जब जंगल में आग लगी थी, तो मैंने भी अपनी सेवा दी थी । शायद वह इस भाव को नहीं समझ पा रहे हैं ।...(व्यवधान)

आप मेरे भाव को समझिएगा, शायद कुछ शब्द आगे-पीछे हो गए हों, तो हमने भी लगी हुई आग को बुझाने में अपनी सेवा दी थी और हमारा नाम भी इतिहास में दर्ज होगा ।...(व्यवधान) जो बचत की बात है, चूंकि जो सरकारी भत्ता है, जो उसका आकार है, उसका 30 प्रतिशत सभी में से जा रहा है । इसीलिए मंत्रियों के सरकारी भत्ते में से भी जाएगा । सांसद होने के नाते और चूंकि वे मंत्री भी हैं, तो सांसदों के वेतन में से जो जाएगा, वह मंत्रियों के वेतन में से सांसद के रूप में भी जाएगा । आप उस राशि को जोड़ेंगे, तो वह लगभग 4 करोड़ रुपये के आस-पास होती है । यह उन दोनों को मिलाकर है । इसलिए, आप इसके भाव को समझिए और उसको इस रूप में लीजिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, हम इसका भाव समझ गए हैं, लेकिन बात यह है कि आप जिस भाव की बात कर रहे हैं, वह भाव हमारे देश की इकोनॉमी में नहीं चलता है।

सर, यह बात होती हमारी अर्थव्यवस्था की । आप खर्चा करते हैं चार लाख रुपये और कमाते हैं दो लाख 61 हजार रुपये, तो इस भाव से अगर देश चलेगा तो कैसे चलेगा?...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अधीर रंजन जी, मैंने कहा मंत्री की कुल आय सांसद के रूप में देखेंगे तो लगभग-लगभग चार । ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हमारा एमपीलैंड का फंड आप ले लेते हो । ...(व्यवधान) हमारा एमपीलैंड का फंड देते तो हमें बहुत सारा फायदा होता, सारे हिंदुस्तान को फायदा होता । ...(व्यवधान) हमारे एमपीलैंड के फंड को आप वापस कीजिए । एमपीलैंड के फंड को आप ... * रहे हो । आप जबरदस्ती छीन कर ले लिए हैं । हमें बर्बाद कर के अभी क्या दे रहे हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

_

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए । श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

21.58 hrs

BILATERAL NETTING OF QUALIFIED FINANCIAL CONTRACTS BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष: अब आइटम नंबर-19 लेते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, क्या यह आज बिज़नस में था? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ था । आप बोल लेना अगर बोलना चाहें तो ।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER

OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG

SINGH THAKUR): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

"That the Bill to ensure financial stability and promote competitiveness in Indian financial markets by providing enforceability of bilateral netting of qualified financial contracts and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने और प्रतिद्वंदता का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं बोलना चाहता हूँ । The Bill only covers close-out netting. The current Bill fails to provide other kinds of bilateral netting practices; for example, netting by novation. Netting by novation is a contractual agreement whereby parties agree that all contracts between themselves will be consolidated into a single contract as soon as each new contract is entered into. It reduces counterparty credit risk by affecting a discharge of each individual foreign exchange contract or other obligation as it is netted. If the Bill is intended to truly widen the scope of the netting practice in India, it could have included methods such as netting by novation and payment netting.

My second point is that there is potential for money-laundering and tax avoidance. Netting is allowed for transfer of money without actual transfer of money. Therefore, netting becomes a potential bidding ground for trade-based money-laundering and tax avoidance practices. How will the Bill help in regulating and offsetting this risk?

Thirdly, it is an overambitious move. It is claimed by the Principal Economic Adviser Shri Sanjeev Sanyal in an interview that this Bill will act as an enabler to the corporate default swap market. This in turn will help lay the necessary condition to set up a liquid Indian corporate bond market. CDS is not a prerequisite for setting up a corporate bond market and there are major issues with regard to regulation and supervision of both the CDS and bond market which

will not be mitigated by the introduction of this legislation. What provision has the Government made to address the regulatory issues arising due to the legislation?

My last point is about the impact on bank capital. This Bill may not have a significant impact on the capital of banks. The ratio of market trade to the loan book of public sector banks is not so high as to generate considerable capital-saving from bilateral netting. Thank you.

22.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : कोई अन्य माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं?

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कोरोना महामारी के दौरान हो रहे संसद के इस सत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे द बायलेटरल नेटिंग ऑफ क्यूएफसी बिल, 2020 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से और नेतृत्व से बिहार तरक्की के पथ पर अग्रसर है । बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और हो रहे हैं । पिछले कई दिनों से केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को आर्थिक सौगात के कई पैकेज दिए जा रहे हैं । कल ही प्रधान मंत्री जी द्वारा रेल मंत्रालय की कई परियोजनाओं को दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 18.09.2020 को इस्लामपुर-नटेसर रेलखंड पर सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखा कर शुभारम्भ किया है । इस रेलखंड के चालू होने से नालंदा व गया जिले के 50 से अधिक गाँवों की 8 लाख से अधिक आबादी सीधे रूप से जुड़ जाएगी और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा । सर, बिल का समर्थन करते हुए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 का बहुजन समाज पार्टी पूरे मनोयोग से समर्थन करती है । एज ए कॉन्सेप्ट यह बिल जो पार्टीज़ को फाइनेंशियल कान्ट्रेक्ट में इनेबल करता है, जो एक दूसरे के विवादों को सैटल करने में मदद करता है, यह बहुत ही प्रगतिशील बिल है । हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यह देश में बिजनेस को और नेगोसिएशन्स को सैटल करने में काफी मदद करेगा । मैं आदरणीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ और हमें विश्वास है कि आगे चलकर इसमें तमाम बिजनेसेस को और फायदा मिलेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अरिवंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स मेन्टेन नहीं होते, बाद में उसमें झगड़ा होता है । एक पार्टी अलग कहती है, दूसरी पार्टी अलग कहती है । उसकी वजह से बैंकों का जो एनपीए बढ़ता है या बाकी सारी चीजों पर जो असर करता है, वह देख कर इस बिल का स्वागत करते हैं । इस बिल में जो प्रावधान किए हैं, उससे सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसी अपेक्षा करता हूँ । मैं फिर दोबारा इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुभव मोहंती, आप भी दो लाइन में समर्थन कर दीजिए ।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मुझे लगता है कि इस बिल से डिस्प्यूट सैटलमेंट में बहुत सुविधाएँ होंगी और वह ज्यादा आसान हो जाएगा । बाकी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूँ । मैं आशा करता हूं कि पिछले दिनों में इस बिल से जो-जो समस्याएँ रही हैं, उन सब समस्याओं से पार होकर आगे अच्छे दिन आने का इंतजार करेंगे और आपसे आशा और उम्मीद रखेंगे ।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से, तेलगु देशम पार्टी की तरफ से हम भी समर्थन की बात आगे बढ़ाते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रसून बनर्जी । बिलों पर सभी दलों का समर्थन होना चाहिए ।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): सर, इस बिल पर पूरा समर्थन है । अच्छे से काम करना होगा । एक साथ मिलकर चलेंगे । मेरा पूरा समर्थन है । हम आप लोगों के साथ हैं । देश को बड़ा करने के लिए सब को मिल कर चलना चाहिए । यही सबसे बड़ी बात है । हम लोग सब मिलकर चलेंगे ।

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी (नान्दयाल): सर, हम बिल को सपोर्ट करेंगे ।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): स्पीकर सर, यह अच्छा बिल है और आशा करते हैं कि सरकार ऐसे अच्छे बिल लेकर आएगी । हम भी समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: कोई और दल का माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। सभी दलों का समर्थन है। अब अनुराग जी, आप थोड़ा बिल के बारे में ब्रीफ कर दीजिए।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I would first like to thank all the hon. Members for supporting the Bill in the interest of the country.

Sir, let me say that this Bill proposes to provide a firm legal framework for netting of qualified financial contracts. This was spoken about during the Budget Speech by the hon. Finance Minister. This is to resolve unambiguous legal framework for enforceability of close out netting reduces. It is going to reduce the net exposure and it would also reduce the credit exposure of banks and other financial institutions from gross net exposure resulting in the substantial capital savings.

Sir, why I am saying about capital saving is because in today's time, I think, it is very important for the banks and the financial institutions. That is why we have brought this Bill. If you look at the main four key points of this Bill, you will find that the legal enforceability for netting of qualified financial contracts which are bilateral in nature will be taken care of. It will take care of designation of certain type of regulated financial contracts as qualified financial contracts; third will be the mechanism for close out netting in the event of default and it will also take care of imposing limitations on administration practitioners to enable smooth and expeditious close out netting.

महोदय, यह केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग 50 देशों में इस तरह का लीगल फ्रेमवर्क है और हमने आईएसडीए, जो international swaps and derivatives association है, उसके ही मॉडल नेटिंग एक्ट को ध्यान में रखकर यह प्रपोज्ड ड्रॉफ्ट बनाया है । शायद यही कारण है कि आज सभी सदस्यों ने, अलग-अलग राजनीतिक दलों से, आज भारत के हित में, तािक इससे जो लगभग सेविंग का अंदाजा है, लगभग 46 हजार करोड़ रुपये का उसमें दिखाया गया है । इसके अलावा इसका लाभ भी मिलेगा और जो जी-20 की रिकमंडेशन है, उससे भी इसकी स्ट्रेंगथिनंग होगी, मार्जिन सिस्टम के लिए ।...(व्यवधान) हाँ, वार्षिक होगी । इससे फाइनेन्शियल सिस्टम को लाभ मिलेगा ।

सभी माननीय सदस्यों ने इसको ध्यान में रखकर अपनी बात कही है । मैं आपके माध्यम से सभी दलों के सभी सदस्यों का एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसका समर्थन किया है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने और प्रतिद्वंदता का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 11

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

श्री के. सुरेश जी ने इस विधेयक पर संशोधन दिए थे, लेकिन वे अभी सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ ले रहा हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दो-तीन दिन से आप सब जिसका इंतजार कर रहे थे, आप अविलंब लोक महत्व के विषय, शून्य काल का इंतजार कर रहे थे, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वे सब अपने-अपने क्षेत्र के बुनियादी सवालों को उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं । मैं कोशिश करूँगा कि सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त समय नहीं, समय केवल एक मिनट मिलेगा ।

Hon. Members, please conclude in one minute. सब तैयार हैं । क्या सब इस बात से सहमत हैं?

अनेक माननीय सदस्य: जी महोदय।

माननीय अध्यक्ष : जिनकी लाटरी खुली है, पहले उनकी सूची लेंगे ।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप ।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप (आंवला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी उठाना चाहता हूं । मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र आंवला, बरेली और बदायूं जनपदों का हिस्सा है । मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में जनपद बरेली और आंवला के बीच रेलवे के समपार फाटक, समपार संख्या 359 और 359 ए हैं ।

22.10 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

मान्यवर, रेलवे, भारत सरकार के 32.81 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के 96 करोड़ रुपये को मिलाकर कुल 128.81 करोड़ रुपये इसकी लागत है । इसकी लम्बाई 952.42 मीटर है । इसमें 60 प्रतिशत काम हो चुका है । लेकिन, रक्षा मंत्रालय की कुछ जमीनें इस पुल के अन्तर्गत आ रही हैं, जिनकी एन.ओ.सीज़. अभी तक नहीं दी गई हैं । राज्य सरकार लगातार पत्राचार कर रही है और उनके कुछ हिस्सों में जो जमीन का हस्तांतरण है, वह नहीं हो पा रहा है ।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की जो 'इन-प्रिंसिपल एप्रूवल फॉर वर्किंग इन डिफेंस लैण्ड' अपेक्षित है, इस पुल के महत्व को देखते हुए कृपया रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पुल की एन.ओ.सी. जारी करने की कृपा करें ।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Sir, I thank you very much for giving me a chance to address a very important topic on the recent approval for National Recruitment Agency by the Union Cabinet for conducting the Common Eligibility Test in 12 Indian languages for all the non-Gazetted Government jobs which is most likely to be held from the next year, that is, 2021.

Sir, I welcome and sincerely appreciate the Cabinet decision to conduct the Common Eligibility Test in multiple languages to facilitate candidates from different parts of the country to participate in the examination in the language in which they are comfortable. However, to facilitate the candidates from different parts of the country to get equal opportunity, I would like to request the Minister to allow the National Recruitment Agency to conduct its recruitment examination in all the languages enshrined in the Eighth Schedule of the Constitution, instead of 12 languages, to help the candidates who have difficulty in competing due to the language barrier and grab a Government job.

As we know, Railways already conducted its examination in over 15 languages across India.

20.09.2020

Lastly, in the State of Assam, recently, a Bill was passed by the Assam State Assembly for directly conducting examinations by the Assam Public Service Commission only in three languages, that is, Assamese, Bodos and Bengali. However, Manipuri language which is included in the Eighth Schedule of Indian Constitution is not introduced even though Manipuri people have inhabited widely in 13 districts of Assam right from the 15th century having more than two lakh population and above.

HON. CHAIRPERSON: It is okay. You have made your point.

Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Kuldeep Rai Sharma are permitted to associate with the issue raised by Dr. R.K. Ranjan.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the NIA arrest of an inter-State module of Al-Qaeda operations at various locations in India including West Bengal and Kerala who were, as per reports, planning to undertake terrorist attacks at vital installations in India with an aim to kill people and strike terror is a very serious matter affecting the safety and security of the country.

This incident has further exposed the shortcomings of the Government as it has been ineffective in preventing the propagation of terrorist ideologies and functioning of terror modules in the country.

The three persons namely, Murshid Hasan, Iyakub Biswas and Mosaraf Hossen arrested from Kerala were engaged in various jobs in the State and it exposes the failure of the Home Department of Kerala Government and Kerala

Police in gathering intelligence and preventing infiltration by extremists under the guise of seeking employment.

Besides these inefficiencies, the Kerala Government is also at fault for not having documented the inter-State migrant labourers and, out of 34 lakhs of such labourers, only a fraction is issued Awas cards.

I would like to request the Government of India to seriously look into the matter.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kuldeep Rai Sharma is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

Now, Shri Pocha Brahmananda Reddy. Please conclude within one minute.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Hon. Chairperson Sir, Allagadda Assembly Constituency in Andhra Pradesh comes under my Parliamentary Constituency of Nandyal, and is not connected to any of the railway line networks till now.

Sir, through you, I would like to request the hon. Railway Minister to kindly sanction a new Railway Station at Mayaluru in the Nandyal-Yerraguntla section between the existing Sanjamala and Nossam Railway Stations, which can cater to the needs of Allagadda area and the hinterland. Mayaluru Station can serve the needs of the devotees visiting Ahobilam Lord Narasimha Swamy Temple,

Srisailam Lord Mallikarjuna Swamy Temple and Mahanandi Temple, which are major pilgrimage centres of South India.

Hence, I once again request the hon. Railway Minister to kindly sanction a new Railway Station at Mayaluru between the existing Sanjamala and Nossam Railway Stations of Nandyal-Yerraguntla section of South-Central Railways, at the earliest.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): सर, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र माल्दहा उत्तर में रेल सुविधा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

सर, मेरे संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा विभीषिका से त्रस्त है । वह अत्यंत ही पिछड़ा और गरीब इलाका है । लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है । ऐसी स्थिति में मेरे लोक सभा क्षेत्र के अधिकांश लोग दिल्ली और बेंगलुरू में नौकरी, रोजगार तथा इलाज हेतु जाते रहते हैं । रेल सुविधा सीमित होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि माल्दहा से पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तथा कानपुर होते हुए नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए । इसके अलावा, माल्दहा से बेंगलुरू के लिए भी सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए । इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री खगेन मुर्मु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदय, अपने संसदीय क्षेत्र दौसा के मध्य से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली—मुम्बई के संबंध में जो तकलीफ वहाँ के लोगों को हो रही है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहती हूँ। इसका निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है।

22.17 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, बांदीकुई के पास भोजवाड़ा और देलाड़ी गाँव सिहत आस-पास के 25 गाँव ऐसे हैं, जहाँ बांदीकुई बासवा रेल लाईन के पिलर संख्या 175 से 500 के मध्य अण्डरपास का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है । वर्तमान में बाणगंगा नदी में ग्रेवल सड़क है, उससे आवाजाही चल रही है । इसके अवरूद्ध होने से लगभग 40 गाँवों की एक लाख की आबादी प्रभावित होती है । इसके बनने से 45 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा । गाँवों के किसानों की जमीन रोड के दोनों तरफ आ जाने के कारण वे अपनी जमीन को नहीं साध पाएंगे । ऐसी स्थिति में भोजवाड़ा गाँव के पास अण्डरपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जनता की इतनी जबरदस्त माँग है, इस माँग के लिए आपके माध्यम से मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि यह अण्डरपास अतिशीघ्र बनाया जाए । यदि इसको बनाया नहीं जाता है तो इससे लगभग एक लाख की आबादी बहुत ही परेशानी में आएगी । ऐसा हो सकता है कि वे बाधा डालने के लिए आँदोलन भी करने को तैयार हो जाएं ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल तथा श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती जसकौर मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं आप सब से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि एक मिनट के बाद आपका माइक बंद हो जाएगा । इसलिए, मैं पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि एक मिनट के बाद आपका माइक आटोमेटिक बंद हो जाएगा । So, hon. Members, please conclude in one minute.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

In my Constituency, Srikakulam, because of the flow of river Mahendratanaya, around 20,000 population in 20 villages in Pathapatnam mandal are affected by an eternal problem of commuting from one side to another. Their constant demand has been for the construction of a bridge between Kaguwada and Romadala villages.

Sir, students, farmers, employees and other people in Romadala, Romprivalasa, Jagannadhapuram, Baidulapuram, Sunnapuram, RL Puram, Chakipalli and 15 other hamlet villages have to travel 20 kms. to visit their mandal headquarters in Pathapatnam and also have to take a road through Odisha as these villages are near the border of the State. If the bridge is constructed, the travel is going to come down by 20 kms.

Farmers from Kaguvada and Korasavada have farms upto 400 acres on the other side of the bridge. It is extremely difficult for them to cultivate these lands and to transport farm equipment and farm produce. As a temporary solution, the locals have been operating boats. But this has resulted in many deaths over the years.

Keeping this in mind, the then State Government of Andhra Pradesh has put up the construction of this bridge under RCPLWE Programme initiated by the

Central Government in December, 2016, which envisages improvement of road connectivity in Left Wing Extremism affected areas. My constituency of Srikakulam, which has been a constant victim of Left Wing Extremism, has been covered under this Programme and this Programme has been granted approval by the Ministry of Rural Development of the Government of India. Then, the previous State Government of Andhra Pradesh has issued administrative sanction for these works in March, 2019. A 120-metre long bridge was designed with an approximate budget of Rs. 7 crore. The soil testing has already been done. But then the 2019 elections happened and the construction could not take off. Since then substantial delay is being observed in starting the work. Even now the tenders have not been finalised and there are discussions on reworking the initial plan.

On behalf of the distressed villagers, I request the Central Government, through you, to ensure that the construction of this bridge starts without any further delay and the funds required for this project is also released on time.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

20.09.2020 1045

SHRI S. DHAIRYASHEEL MANE (HATKANANGLE): Hon'ble Speaker Sir, thank you very much for allowing me to speak. I want to draw your kind attention towards an important issue. This is regarding the fate of Maratha youths and it is known to everyone throughout India. They are about to get a new life through Maratha reservation. I hail from the district Shahu of Maharaj who had given reservation for the first time. But today, Maratha youths have to fight for reservation. Marathas are about 32% of the total population of Maharashtra and approximately 90% of them are economically poor and backward. I want to mention here that in Tamil Nadu, around 69% reservation has been given on the same line. But step-motherly treatment has been given in the case of Maharashtra. Hence, I want to appeal that instead of giving importance to Kangana Ranaut, we should focus on the issue of hard working Marathas. We need to take urgent steps to bring them to the mainstream.

Hence, I would like to request the Union Government to come forward and support this Maratha reservation to do justice to this community.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. सुजय विखे पाटील, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे को श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon'ble Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the highly sensitive issue of Maratha reservation. Maratha community have been demanding for Maratha reservation since 1989. Many Maratha youths sacrificed their lives for it. They organized successful silent and peaceful protests for pressing their demand. Finally, Government accepted their demand and they were given 16% reservation in November, 2018. But now the Supreme Court of India has given interim stay. Under Article 15 of the Indian Constitution the State Government has got a right to grant reservation to any backward community and it was also given on the basis of it. If 69% reservation is permissible in the State of Tamil Nadu, why is it not possible in case of Maharashtra?

Hence, I would like to request you that the Union Government should look into this matter urgently and the much awaited justice should be done to the Maratha community.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र और लोक सभा क्षेत्र अहमदनगर के किसानों के मुद्दे के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं । वाणिज्य मंत्रालय ने 14 सितम्बर को देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए और प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए नेफेड द्वारा बफर स्टॉक में रखे एक लाख टन को रिलीज करके मार्केट में लाया जाए ताकि डिमांड और सप्लाई की मांग को बैलेंस किया जा सके । किसान अपने ऊपर विदेशों में निर्यात करके लाभान्वित हो । इसके अतिरिक्त पूरी तरह से प्रतिबंध न लगाकर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी जाए । हमारी सरकार ने 2015, 2017, 2018 में भी लागू किया था जब प्याज के दामों में बढ़ोत्तरी हुई थी । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER): Hon'ble Speaker, thank you very much for allowing to speak in the Zero Hour. Hon'ble Sir, in my constituency and Northern part of Maharashtra like Jalgaon, Dhule and Nardurtoor, Banana is cultivated in around 1.25 to 1.5 lac hectares of land.

Union Government had started climate based insurance scheme for cultivation to protect and ensure this banana cultivation. But, the rights to frame the modalities for this scheme are given to the State Government. Under this scheme 60% share is borne by Union Government and 40% share is to be given by the State Government. During 2014-2019, this scheme was implemented very well. But, this time the newly formed Aghadi Government in Maharashtra changed it. Newly framed terms and conditions are favourble to the insurance companies and that is why the banana farmers will have to incur losses.

Hence, through you. I would like to request the Hon'ble Union Agriculture Minister that the instructions must be issued to the State Government to frame rules favourable to the farmers. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मराठी में रखना चाहता हूं । Hon'ble Speaker Sir, I would like to speak in Marathi. Sir, Marathas had to fight rigorously to get the benefits of reservations and after a long battle, the Maharashtra Government decided to give 16% reservation to the Maratha community. The High Court had ordered to give 12% reservation for education and 13% reservation for jobs to the Marathas on deciding on the petition filed against it. But somebody approached Supreme Court of India and now the Supreme Court has ordered a stay on it and referred to the Constitution Bench.

Sir, you must know that around 70% reservation is given in case of Tamil Nadu. It is a clear case of partiality as it is still kept pending with Supreme Court of India.

Sir, our Chhatrapati Shivaji Maharaj had brought all the sections of society together and our State Maharashtra is enriched with the great historical work done by Shri Phule-Shahu-Ambedkar. Most of the people from Maratha community are poor and backward and they need the reservation desperately.

Sir, Supreme Court of India has done great injustice to the Marathas.

Hence Union Government should come forward to support them and justice should be done to them. Jai Hind, Jai Maharashtra.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने आपके आग्रह पर समय को एक से डेढ़ मिनट कर दिया है । अब आप डेढ़ मिनट में अपनी मांग को पहले रखें और बाद में भाषण करें ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने गरीब, पिछड़े और आदिवासियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं । धारा 275(1) योजना, विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना, वन बंधु योजना, आदिम जनजाति विकास योजना, ऐसी सौ प्रतिशत केन्द्रीय अर्थ सहायता योजनाएं हैं । इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मूलभूत काम काम किए जाते हैं । जिससे आदिवासी क्षेत्र का विकास हो ।

यह विकास निधि केंद्र सरकार राज्य सरकार को वितिरत करती है । किन्तु, हमें खेद है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के आदिवासी विभाग ने इन योजनाओं की निधि के वितरण पर रोक लगाई है, जिसके कारण आदिवासी क्षेत्र के विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं । आपसे अनुरोध है कि आपकी ओर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि विकास निधि का वितरण तुरंत किया जाए, जिससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को न्याय मिले ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री कुलदीप राय शर्मा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon'ble Chairman Sir, cyclone hit on 3rd June, 2020, the Raigad and Ratnagiri districts of Maharashtra and due to this heavy financial losses had incurred. Hon'ble Prime Minister had promised our Hon'ble Chief Minister that the Union Government would help in this calamity. The State Government has already given Rs 550 crore in this regard but the NDRF did not change their modalities to provide assistance. Lord Ganesh Idol artisans who sculpt very fine Ganpati idols also need your help. They also suffered losses and a special package should be given to them. Fishermen, coconut and betal-nut cultivators also need financial help. Mumbai-Goa highway also needs repair and maintenance as it is in very bad shape. An NDRF base camp should be set up at Mahad as per proposal, as these kind of calamities occur repeatedly in this area. Thank you very much for giving me this opportunity to speak. Jai Hind. Jai Maharashtra.

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*SHRI KAPIL MORESHWAR PATIL (BHIWANDI): Hon'ble Speaker Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an issue in this Zero Hour. In my Bhiwandi Lok Sabha constituency, a new national highway number 548 A connecting Shahapur Murbad-Karjat-Khopoli was sanctioned by Ministry of Road Highways Transport and its construction work is going on for the last two years.

But, I am sorry to say that its construction is of very poor quality. This ministry is overburdened with work and that is why this project is handed over to MSRDC and Rs.850 crore have been sanctioned for it. But, the original contractor handed over this work to sub-contractor and now that sub-contrator has also sub-letted the work to another one after taking premium commission. Around 3 Talukas have been affected due to this substandard quality of construction.

In this regard, I would like to request the Ministry of Highways and Transport, to take this contract back and recall this work / project from MSRDC. A Fresh tender should be floated for this road project. Current contractor should be blacklisted.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का आग्रह आया है कि सबसे पहले महिला माननीय सदस्य को बुलाया जाए । लेकिन, उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आज अंतिम समय तक यहां पर रूकूंगी ।

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Hon'ble Speaker Sir, thank you. The issue of Maratha reservation has become a hot and sensitive issue in Maharashtra. The then BJP Government led by Devendra Fadnavis ji had given safe and secured reservation to the Maratha community after their protest for it. But, unfortunately Supreme Court has given stay in this matter. Hon'ble Sir, due to this Supreme Court decision, Maratha youths and students are very disappointed and highly agitated. Hence, through you Sir, I would like to request the Union Government to instruct the State Government to take immediate steps to find a solution for it through the legal route.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे और डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है । डॉ. जयिसद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए, मैं आपका हृदयपूर्वक अभिनन्दन करता हूं । भव्य भारत देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और विशाल दृष्टि के कारण शोलापुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है । मेरा संसदीय क्षेत्र शोलापुर आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ-साथ टेक्सटाइल, गारमेंट तथा युनिफार्म हब के रूप में जाना जाता है ।

इन इंडस्ट्रीज में उत्पादित उत्पादन की मांग केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण कोविड की इस आपदा के कारण टेक्सटाइल तथा गारमेंट इंडस्ट्री आर्थिक संकट से

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

जूझ रही है । इस इंडस्ट्री को भारत की ओर से विशेष आर्थिक पैकेज की अत्यन्त आवश्यकता है । आज की हालत के अनुसार इंडस्ट्री के उद्योजक बैंक से लिए गए कर्ज का हफ्ता भरने की स्थिति में नहीं है । इस इंडस्ट्री से लाखों परिवारों का जीवन जुड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उद्योजकों के बिजली का बिल एवं कर्ज राशि पर बैंक द्वारा लगाई गई ब्याज राशि को अप्रैल, 2020 से माफ किया जाए । यदि सरकार इन उद्योजकों को आर्थिक मदद करेगी तो सोलापुर टेक्टाइल तथा गारमेंट उद्योग फिर से सक्षम हो सकता है ।

*SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): In my city Pune, the ill effects of this Corona pandemic are growing day by day. Around 1500 to 2000 people are getting infected on daily basis. The mortality rate is around 70 to 80%. By considering the total population of Pune city, district and Pimpri-chinchwad, the people are very much scared due to growing number of patients. The State Government, Municipal Corporation are fulfilling their own responsibilities and I do not want to blame anybody.

Today, Pune is at number one position in Maharashtra. But, we really do not want to top this list of Corona patients as we have already topped in the sectors of IT, education and industry. The State Government has appointed 20 IAS officers in Corona management team. But, no concrete work has been done as they lack co-ordination. No sufficient number of ventilators, oxygen cylinders, beds and ambulances are available and that is why I would like to request the Union Government to set up a task force to take care of Corona patients and to save the residents of Pune.

Thank you.

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी को श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि हम लोग हजारों-करोड़ों रुपये सड़क के कामों के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन महज एक बारिश या दो बारिश में ही सड़कें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर न जाने कितने ही 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और उसका बंधनकारक होता है कि जहां पर भी सड़क बनाई जाती है, वहां पर बोर्ड लगाया जाता है कि यह सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई है । मैंने प्रधान मंत्री जी को, नितिन गडकरी जी को और नरेन्द्र सिंह तोमर जी को तस्वीरों के साथ सबूत दिया है कि सड़क तीन साल पहले बनी है और वहां पर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है । मैं सरकार के जरिए यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह समस्या सिर्फ मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद की ही नहीं है, बल्कि इसे पूरे मराठवाड़ा या पूरे देश की समस्या कह सकते हैं । हम जब तक ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और ठेकेदार ही नहीं बल्कि इसके साथ जो इंजीनियर होता है, जो इसका जिम्मेदार होता है और जो क्वॉलिटी कंट्रोल चैक करता है, उनके ऊपर जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक देश की सड़कें नहीं सुधरेंगी । हम गडकरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं । वे इस मामले में बहुत संजिदा है । लेकिन जब एक बारिश में पूरी सड़क बह जाती है तो कहीं न कहीं लगता है कि वहां पर कोई गलत काम होता है । आपको मालूम होगा कि हर व्यक्ति का कहीं न कहीं लेनदेन होता है, इस वजह से किसी को किसी का डर नहीं है । अगर उन्हें डर दिखाना है तो हम समझते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए, जिससे ठेकेदार के ऊपर एफआईआर हो और अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर हो तभी जाकर हमें अच्छी सडकें मिल पाएंगी

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, मैं आपकी आभारी हूं । आपने मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति दी है ।

* There is a growing unrest among the Maratha youths in Maharashtra. There had been a long pending demand for Maratha reservation and all the political parties came together to support their demand. That demand was fulfilled but now the Supreme Court of India has given an interim stay in this case.

I think, this is very rare and hardly in any case, Supreme Court of India has given stay for reservation in India. The reservation has been challenged in the State of Tamil Nadu too but the court has not given any stay to reservation even in that state.

All the political parties from Maharashtra have requested the Supreme Court of India unitedly to grant reservation to Maratha community with one voice. Hence, I would like to request our Hon'ble Prime Minister to come forward and support their demand. He should guide us what could be done in this matter. We need an immediate solution to this problem as the Maratha youth and students are facing acute problems in the field of education and jobs and we need to take care of this unrest at once.

Thank You. *

*

^{*....*} English translation of this part of the Speech was originally delivered in Marathi.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संजय जाधव (परभणी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के बेहद संवेदनशील मराठा आरक्षण के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर इंटरिम स्टे दिया है, इससे पूरे मराठा समाज में निराशा और क्रोध की भावना है । हमें फंसाया जा रहा है, यह समाज की भावना है । इससे पहले मराठा समाज ने आरक्षण की मांग के लिए पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मराठा मूक मोर्चा निकाला था । उसके बाद तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला लिया । माननीय उच्च न्यायालय ने भी मराठा आरक्षण पर मुहर लगाई थी, किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर इंटरिम स्टे दिया । मराठा समाज हमेशा त्याग और शौर्य के लिए जाना जाता है । किसी का आरक्षण छीनकर हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन आरक्षण को स्टे मिलने के कारण मराठा समाज के लाखों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में चला गया है ।

महोदय, इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप करें और मराठा समाज को न्याय दें, यह मेरा आपसे अनुरोध है । धन्यवाद ।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था । 9 सितम्बर, 2020 को देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए, संबंधित याचिकाओं को बड़ी बेंच को सौंप दिया । उल्लेखनीय यह है कि केन्द्र ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देकर 50 प्रतिशत की सीमा पार कर ली है । यही नहीं, कई अन्य राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण लागू है । मराठा समुदाय सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । सरकार का यह दायित्व है कि वह इस समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाए । मैं मराठा आरक्षण के संबंध में मराठा क्रान्ति मोर्चा की भावनाओं का सम्मान करता हूं और उन्हें यह आरक्षण मिलना ही चाहिए । उच्चतम न्यायालय के फैसले से पूरे मराठा समुदाय में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया है । इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और ऐसे कदम उठाए, जिनसे मराठा समुदाय को न्याय मिले तथा उनका सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । बहुत लम्बे इंतजार के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखण्ड के एनएच 75 की ओर दिलाना चाहूंगी । यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजधानी रांची से होते हुए बंद गांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, जैंतगढ़ होते हुए ओडिशा को जोड़ती है । आज के समय में इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि यहां से पैदल आना-जाना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है । यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा वह क्षेत्र माइनिंग इलाका है, वहां से ओडिशा और सरंडा के जंगल से हजारों टन लौह अयस्क सड़क के रास्ते होते हुए जाता है । ऐसी स्थिति में इस सड़क का निर्माण होता अति आवश्यक है । सरकार ने इसे फोरलेन के रूप में टेक-अप कर लिया है, लेकिन वहां अब भी सिर्फ रिपेयरिंग वर्क हो रहा है । वहां

के लोग काफी आक्रोश में हैं और आन्दोलन करने को मजबूर हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस सड़क को अविलम्ब बनाया जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती गीता कोडा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers to the immense problems being faced by the farmers of my State Odisha due to non-availability of Urea.

The hon. Minister Shri Dharmendra Pradhan Ji had also drawn the attention of the hon. Minister regarding the shortage of fertilizers in Odisha and in my Constituency, the farmers are purchasing bags of urea from the black market at an inflated cost of Rs. 1,000 instead of Rs. 266 per bag.

I would request the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers, through you Sir, to have this matter examined expeditiously in order to ensure adequate supply of fertilisers so that this artificial scarcity being created in the market is stopped at once. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): *Aadharniya Adhyaksha Ji,* I would like to point out here an issue related to the receipt of foreign aid from the United Arab Emirates- based Red Crescent for construction of houses under the Life Mission

Housing Project in Kerala. In reply to the Unstarred Question of hon. Member, Shri K. Muraleedharan, the Ministry of Home Affairs has stated that such a proposal from the Kerala State Government was not received by the Ministry. It is a shocking news. Two real estate companies from India have undertaken a housing project estimated at Rs.19 crore under the Life Mission Housing Project in my constituency by offering about ... * This is a hot discussion in the Malayalam media. I think the Government of India should conduct an inquiry into this matter.

If the Government of India or the Ministry of Home Affairs has not conducted an inquiry or registered any case relating to this serious issue even yet, then the Government should announce a detailed CBI inquiry to unveil the culprits behind the exploitation of the homeless and helpless flood-affected SC/ST and poor families.

I request you to include violation of code of conduct of the State also in this CBI inquiry. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को कुमारी राम्या हरिदास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

मैं गुजराती इंटरप्रेटर से आह्वान करूंगा कि वे यहां रहें।

^{*} Not recorded.

*SHRIMATI RANJANBEN BHATT (VADODARA): Hon'ble Speaker Sir, I thank you very much for giving this opportunity to speak. Sir, Vadodara is the third biggest city of Gujarat State. Sir, through you I request to the Ministry of Home Affairs and Ministry of Civil Aviation to start immigration and hub service in Vadodara city so that the passengers travelling abroad from Vadodara and Central Gujarat can avail this facility. Therefore, through you, I request to the Ministry of Home Affairs and Ministry of Civil Aviation to start immigration service at Vadodara at the earliest. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: जरदोश जी, आप भी गुजराती में बोलें।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): अध्यक्ष जी, आज के हालात में आपने जो व्यवस्था की है, उसके लिए आपको धन्यवाद ।

महोदय, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है । बैठे-बैठे बोलने की व्यवस्था शायद इसी सत्र के लिए है । आज कोविड-19 विषय पर चर्चा हुई, तब मैं अपने विषय को जोड़ना चाहती थी । माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना के समय के देश भर के श्रमिक अपने-अपने घर में जाना चाहते थे, तब उसके लिए उत्तम व्यवस्था की गई । इस कारण शायद भारत बहुत बड़े संकट से बच गया । इस कार्य हेतु सूरत शहर की ओर से आपको बहुत-बहुत अभिनंदन । आने वाले समय में दीपावली का त्योहार आने वाला है । यदि हम सही से संभाल लें तो उद्योगों को हम पटरी पर लाने में समय से पूर्व सफल हो पाएंगे । कौशल प्राप्त श्रमिकों की व्यवस्था शायद नामुमिकन है । सूरत से सिर्फ रेल के माध्यम से ही 700 से ज्यादा जगहों पर 15 लाख से ज्यादा श्रमिक गए हैं । आज आपके माध्यम द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जो ट्रेन शुरू की गई है, उससे

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

सीधे सूरत जाने की बजाय अन्य जगहों से वहां आने के कारण शायद सूरत के श्रमिकों का खर्च एवं ज्यादा समय लग रहा है । इस स्थिति में सूरत से सीधे ट्रेन के बारे में सोचना चाहिए ।

इस स्थिति में सूरत से ट्रेन की व्यवस्था के बारे में सोचना । ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से श्रमिक लाखों की संख्या में आते हैं । मेरी विनती है कि वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, दरभंगा, भुवनेश्वर, रांची, इन जगहों से सूरत के लिए डायरैक्ट ट्रेन चलाई जाए । अभी जो ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, उनकी ट्रिप बढ़ाई जाए । इसके लिए मैं आने वाले दिनों में आपका आभारी रहूंगी । माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री श्यामनारायण उर्फ रवि किशन को श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है । श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हुं । मेरे संसदीय क्षेत्र में एनएच-233 बन रही है, जो अम्बेडकर नगर से होते हुए वाराणसी तक जाती है । इस हाइवे का कार्य काफी वर्षों से चल रहा है और बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । हाइवे पर जो मुख्य बाजार है, जैसे मोहम्दपुर बिंद्रा बाजार, लालगंज, देवगांव आदि, जहां बाइपास बने हैं और हाइवे से जो लिंक रोड गांव से जुड़ी हुई हैं, वे बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं । सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क यह कह पाना मुश्किल है । क्षेत्रीय जनता उन गड्ढों में धान की रोपाई कर और मछली पालन कर अपना विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, परंतु उच्च अधिकारियों के कान पर जुं नहीं रेंगी है । अधिकारी कहते हैं कि यह एनएचएआई का काम है और एनएचएआई कहता है कि यह पीडब्ल्यूडी का काम है । इस झगड़े में क्षेत्रीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । इन मार्गों पर एक्सिडेंट का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है ।

अध्यक्ष जी, जैसा कि विदित है कि सांसदों की निधि पर दो साल तक के लिए रोक लगा दी गई है, तो हम जैसे माननीय सांसद जनता को जवाब देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन मार्गों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और साथ में यह

भी अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि माननीय सांसद जो भी कार्य अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, उक्त अधिकारी उसकी सुनवाई जल्द से जल्द करे । धन्यवाद ।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान झारखंड की ओर ले जाना चाहती हूं । पूर्व मध्य रेल के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत हजारीबारी रोड, रेलवे स्टेशन पर मेल व एक्सप्रेस गाड़ियां सभी गाड़ियों का ठहराव लॉकडाउन के पूर्व सामान्य रूप से था । परन्तु वर्तमान में चल रही रेल गाड़ी का ठहराव समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके कारण यात्रियों के साथ-साथ प्रवासी मजदूर जो वापस गए हैं, उनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है । इस संबंध में रेल यात्रियों तथा रेल यात्री संघ के द्वारा कुछ गाड़ियों के हजारीबाग रोड, रेलवे स्टेशन पर पूर्व की तरह ही ठहराव जारी रखने की मांग की गई है, जोकि रेल यात्रियों की समस्या को देखते हुए उचित भी है ।

अत: सदन के माध्यम से भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि आम रेल यात्रियों की समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए जनहित में हजारीबाग रोड, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13307/13308 धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस एवं पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-पूरी एवं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव पूर्व की तरह ही यथावत रखते हुए, सकारात्मक कदम उठाने का कष्ट करें । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करती हूं ।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के तहसील रूपबास, बंसी पहाड़पुर में प्रसिद्ध सफेद एवं लाल पत्थर मिलते हैं। विश्व प्रसिद्ध इमारतें, अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन एवं और भी कई प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण कार्य में यह प्रयुक्त हो चुका है। मेरे जिले के रूपबास क्षेत्र में कई खानें हैं, जहां पर सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास रूका हुआ है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि रूपबास में मिलने वाले सफेद पत्थर के खनन कार्य के सैंड स्टोन की 44 खान पट्टों को ईसी की अनुमित देकर खनन कार्य को चलाने की अनुमित प्रदान करें, जिससे खान के छोटे व्यापारी एवं मजदूरों को रोजगार मिल सके । इस संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को अनुरोध कर चुकी हूं । मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में पत्थर का ही व्यवसाय है । इसकी अनुमित से मेरे क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगी । यहां से ये पत्थर भारी मात्रा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जाना है । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजीता कोली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): धन्यवाद अध्यक्ष जी । मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह है कि सिरसा जिला शायद पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । हम देखते हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव में मेट्रो रेल चल रही है । जबिक हमारे यहाँ ठीक तरह से रेलवे भी नहीं पहुंची है । सिरसा स्टेशन लगभग डेढ सौ साल पुराना है, लेकिन अभी तक यह बहुत ही माली हालत में है । सिरसा से एलनाबाद तक ट्रेन चलाई जाए ।

मैं चाहती हूँ कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट वहां पर एक इंटरिसटी ट्रेन शुरू कर दे तो वहां पर लोगों को उसका बहुत फायदा मिलने वाला है । इतना पुराना रेलवे स्टेशन होने के बाद भी अभी तक उसकी देखभाल नहीं हो रही है ।

आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि वे थोड़ा-सा सिरसा जिले का ध्यान रख लें, जो अभी तक पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है, किसी ने अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है ।

आप यह देखें कि वहाँ से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मैं सांसद हूँ । इसलिए मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वहां पर एक छोटी रेल की व्यवस्था हो जाए । अगर यह आ गई तो समझ लीजिए कि पाँच सालों के बाद वहां पर कमल का फूल खिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है ।

माननीय अध्यक्ष: श्री रिव किशन एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण से लेकर मानव जीवन पर प्लास्टिक का बुरा प्रभाव सामने आ रहा है, फिर भी प्लास्टिक का उपयोग एवं उत्पादन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम प्लास्टिक को मौजूद पाते हैं। पहले से भी यह अनुमान लगाया गया था कि प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग वर्ष 2020 तक 13.4 मीट्रिक टन से बढ़कर 22 मीट्रिक टन होने की संभावना है।

कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के इस दौर में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है । कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनने वाले मास्क, गलव्स, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर की बोतल आदि में प्लास्टिक का उपयोग होता है । इनके इस्तेमाल में बेतहाशा वृद्धि हुई है । डब्ल्यूएचओं का अनुमान है कि हर महीने दुनिया में 89 मिलियन प्लास्टिक मेडिकल मास्क, 76 मिलियन प्लास्टिक एग्जामिनेशन मास्क, 1.6 मिलियन प्लास्टिक प्रोटेक्टिव चश्मे की आवश्यकता होती है । परन्तु, इन वस्तुओं के इस्तेमाल के बाद कचरे के रूप में इनका प्रबंध कैसे किया जाए, इसका उपाय नहीं हुआ है । जब विश्व की आबादी प्रतिदिन सिर्फ एक मास्क या गलव्स का उपयोग करती है, तो महामारी खत्म होने के बाद दुनिया में 129 बिलियन फेस मास्क और 65 बिलियन दस्ताने की बर्बादी हो सकती है । मास्क और गलव्स, पीपीई, किट्स का उपयोग करने के बाद सीधे कचरे में डाल देने से जहाँ एक तरफ वायरस के विस्तार का खतरा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक से निर्मित इन वस्तुओं के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था न होने से यह पर्यावरण के लिए

घातक साबित हो रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक किसी अन्य तत्व या जैविक चीजों की तरह पर्यावरण में नहीं घुलता है, बल्कि इसे अपघटित होने में सैंकड़ों साल लग जाते हैं।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए आवश्यक उपाय किए जाएं, जिससे वायरस की रोकथाम के बाद पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*SHRI PRABHUBHAI NAGARBHAI VASAVA (BARDOLI):Hon'ble Speaker Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak during zero hour. Today I want to speak about compensation given for land acquisition. Process of land acquisition is going on in South Gujarat for Delhi - Mumbai Express Way project and Ahmedabad - Mumbai Bullet Train project. These projects pass through Mandvi, Mangrod, Kamrej, Bardoli, Palsana and Choryasi talukas of Surat district in my constituency Bardoli. The farmers are ready to give their lands for these important projects which are very vital for economic development of the country. But the farmers are getting very less compensation for their lands. As per Land Acquisition Act 2013, four times amount of the market value of the land should be given to the farmers and 50% amount should be given for their rehabilitation. Despite these provisions, farmers are getting very low compensation. As per the present Jantri (rates fixed by government) the farmers are getting just 10 to 12 lacs for their lands whereas the actual market value of the same land is 50 to 60 lacs. Therefore it is apparent that the farmers are getting very less compensation for their lands.

Hon'ble Speaker sir, through you I request to the Government and concerned department to pay fair and just compensation to the farmers as per the market value. Thank you.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

माननीय अध्यक्ष: श्री रिव किशन को श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है ।

23.00 hrs

*SHRI RAMESHBHAI L. DHADUK (PORBANDAR): Hon. Speaker Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. A large area of my parliamentary constituency Porbandar in Gujarat is known as "Ghed Region" which has a shape like saucer. Water of most of the rivers of Saurastra like Ojat, Bhadar, Venu, Moj, Mesar, Sabli, Madhuvati and Vartur pass from this region and merge with ocean. But, as per topography our region has a shape like saucer, the water remains in this area for longer time due to its shape before merging with ocean. The area becomes an island in rainy season as water does not recede quickly. It causes extreme loss to agricultural lands and farmers have to suffer loss. Therefore, through you I would like to submit that the work of widening, deepening and fencing of the rivers is required. The Government has to pay compensation to farmers every year for their loss. In order to save this money for government and to stop the crops from being damaged or destroyed, fencing would be very helpful for both farmers and Government. Moreover, it will help to address the problems of farmers. It will also stop water from entering into villages. This work of fencing would cost huge amount and therefore, I request the Central Government to announce a package for this work and to do needful for the work of widening, deepening and fencing of the rivers.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to bring to this august House about the importance of setting up National Cultural Academy in Vizianagaram in my parliamentary constituency.

The Vizianagaram District was part of ancient Kalinga. Its history was bounded by Eastern Ganga ruled northern part of Andhra during medieval times. Historically, Vizianagaram is a known place to cultivate culture and arts. Vizianagarm became a place of learning for many famous personalities in the field of art and culture like Shrimati P. Suseela, renowned male singer Shri Gantasala Venkateswararao, Shri Adibatla Narayana Das, Pitamaha of Harikathas, and Shri Dwaram Venkateswara Rao, renowned violinist.

During the 18th Century, Vizianagaram became a stage for the world famous play 'Kanya Sulkam' whose author was Shri Gurajada Apparao. Though Vizianagaram is not his birth place, he spent his life in Vizianagaram. I am happy to inform to this House that tomorrow, i.e. 21st September, 2020 is his birthday.

Hence, I request the Government of India, through you, to sanction a National Cultural University in Vizianagaram District in Andhra Pradesh to improve further the field of art and culture. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री अबु हसन खान चौधरी 🗕 उपस्थित नहीं।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, महाराजगंज में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। उनकी निनहाल देवदह, समाधि स्थल रामग्राम तथा धातु चैत्य तथा गृह त्याग के पश्चात राजसी वस्त्राभूषण त्यागने का स्थान – कुंवरवर्ती स्तूप का स्थल महाराजगंज में है। ये स्थान क्रमश: बनरसिया, कन्हैया बाबा का स्थान तथा चिंउटहा गांव में स्थित है।

देवदह भगवान बुद्ध की निनहाल थी। यहां एक मंगल पोख्खरीण थी। इसमें केवल राज परिवार के लोग ही स्नान कर सकते थे। यह बनरिसया में आज भी स्थापित है। यहां भगवान बुद्ध के नाना महाराज अंजन के महल के अवशेष तथा ईटों से बने दो विशाल स्तूप भी हैं, जो संभवत: बुद्ध की मां महामाया तथा उनका लालन पालन करने वाली उनकी मौसी महाप्रजापित गौतमी के अस्थि अवशेष पर बनाए गए हैं।

रामग्राम का स्तूप भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष के आठवें भाग पर बनाया गया था। यह उनकी समाधि है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने रामग्राम की यात्रा की थी, उन्होंने वह यहां ईटों से बने विशाल स्तूप व उसके आगे मॉनेस्ट्री होने की बात लिखी थी।

कन्हैया बाबा का स्थान तथा ईंटों का बनाया विशाल स्तूप और उसके सामने लगभग 10 एकड़ मोनेस्ट्री के खंडहर तथा पुष्करणी आज भी देखी जा सकती है। यह स्तूप ह्वेनसांग द्वारा वर्णित किपलवस्तु से इसकी दिशा व दूरी से मेल खाता है। ज्ञातव्य है कि अभी तक रामग्राम के स्तूप की पहचान नहीं हुई है। इस स्तूप के पास कुषाण कालीन तांबे के सिक्के भी मिले हैं। वर्ष 1992 में यहां पुरातत्व विभाग की पटना इकाई के द्वारा उत्खनन किया गया था। इससे पहले वर्ष 2003 में भी उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की तरफ से इसका खनन किया गया है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन स्थलों का राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण व उत्खनन कराकर इन स्थलों को विधिवत चिन्हित कराने व पर्यटक स्थल के रूप में इनका विकास कराने की अनुकम्पा करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री सी.पी. जोशी और श्री जगदिम्बका पाल को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद । बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स कारोबार में नित नए-नए और बड़े-बड़े नाम उजागर हो रहे हैं तो यह केवल महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, अपितु पूरे देश की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए चिंताजनक है । चूंकि हमारा कुशीनगर क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है, पाकिस्तानी ड्रग्स बॉलीवुड तक पहुंच सके, इसके लिए हमारी भूमि का उपयोग किया जा सकता है । हमारी भूमि के प्रतिभावान युवाओं को पथभ्रष्ट किया जा सकता है । हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कल लिए गए साहिसक निर्णय का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं । बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान युवा कई वर्षों से जिस तरह अपनी कला को विकसित करने का लक्ष्य लेकर बॉलीवुड पहुंचते रहे हैं और अपने को शोषित करने का मार्ग प्रशस्त करते रहे । वहां न केवल उनकी कला को बिल्क उनके अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश में ड्रग्स के करोबार में धकेलने का कार्य किया गया । इसी नाते पूज्य योगी आदित्य नाथ जी महाराज ने घोषणा की कि देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण अब उत्तर प्रदेश की धरती पर होगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिभावान युवा अब अपनी कला को विकसित करने का लक्ष्य लेकर उसे बॉलीवुड में नहीं, 20.09.2020

बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर निर्माणाधीन बॉलीवुड पर अपनी कला को निखारने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रिव किशन, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री सी.पी. जोशी को श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

* SHRI VINOD LAKHAMSHI CHAVDA (KACHCHH): Hon. Speaker Sir, first of all, I thank you very much for giving opportunity to the Members to speak in their native languages. I think this will also be considered as a record in this Session. Hon. Speaker Sir, I want to thank the Ministry of Railways that amid the prevailing corona pandemic in our country and in the world, the Ministry is running special trains in the country. First of all, I would like to thank the Rail Ministry and the minister of railways that just vesterday one special train was announced from my Parliamentary constituency Kutch to Mumbai. Sir, there are good business relations between Kutch and Mumbai. Many trains are running between these two stations. But it is a demand of the people of my constituency to get one more super special train. Hon. Speaker Sir, through you, I want to submit that only one train is running between my parliamentary constituency Kutch and Delhi since many years i.e. Bhuj - Bareilly Express. Moreover, this train takes much travelling time and this causes inconvenience the passengers. Sir, through you I request to the Ministry of Railways to start one super fast train or Duranto Express train. Thank you.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री सी.पी. जोशी को श्री विनोद लखमशी चावड़ा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री प्रद्युत बोरदोलोई – उपस्थित नहीं।

डॉ. मोहम्मद जावेद जी।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुरजापुरी बिरादरी की तरफ से आपको बहुत-बहुत सलाम है। बिहार के सीमांचल के अतर्गत आने वाले सभी जिलों के सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को राज्य में बीसी-2 का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मेरे द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर भी केन्द्र में अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जो बहुत ही दुखद है।

इस जाति को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय के अंतर्गत इन्हें केन्द्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और एजुकेशनल पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दे, ताकि हम भी अपने मुल्क की तरक्की में शामिल हो सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री मलूक नागर को डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): बहुत-बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका ध्यान देश की बहुत महत्वपूर्ण और देश के भविष्य से जुड़ी हुई समस्या पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, लगभग आधे साल से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स बंद हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार तबाही पर आ गए हैं। गरीब आदमी को दो वक्त की रोटी कमाना भारी पड़ रहा है। इन स्कूलों के अंदर ट्यूशन फीस, मैनटेंनस फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और होस्टल फीस ली जा रही है, जिसको देना गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत से गरीब लोगों ने अपने बच्चों को घर बैठा लिया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ने इस आपदा में अवसर तलाश कर लिए हैं और उन्होंने लगभग दस परसेंट स्टाफ को हटा दिया है। अपने स्टाफ की सैलरी में 30 से 50 परसेंट की कमी कर दी है, लेकिन बच्चों से पूरी फीस वसूल रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दी है, उनको कोई हक नहीं है कि वे पूरी फीस वसूल करें। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार उन तमाम बच्चों की फीस प्राइम मिनिस्टर केयर फण्ड से जमा कराए, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। यह देश के भविष्य का सवाल है। इसमें हम और हमारी समाजवादी पार्टी के लोग, सभी लोग और अखिलेश जी चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों की 50 परसेंट फीस प्रधान मंत्री केयर फण्ड से या किसी और फण्ड से दी जाए। इससे अभिभावकों को भी रिलीफ मिलेग। ईमानदार संस्थाओं के स्टाफ की सैलरी भी देने का कष्ट करें ताकि स्टाफ को भी उनकी सैलरी मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री मलूक नागर को डॉ. एस.टी. हसन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर के बारे में बोलने की मुझे अनुमित दी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उदयपुर संसदीय क्षेत्र में चावण जो महाराणा प्रताप का निर्वाण स्थल है, जहां पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में इसका विकास हुआ था और द्वार और बगीचे बने थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उदयपुर में जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कुम्भलगढ़, गोगुंदा जहां उनका राजतिलक हुआ और उनकी निर्वाण स्थली चावण मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन सभी जगहों का विकास करने के लिए आपके माध्यम से टूरिज्म मिनिस्टर से मैं मांग करता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, जहां हाड़ी रानी सलुम्बर ...(व्यवधान) भील योद्वा का गढ़ बना हुआ है। इन सभी क्षेत्रों और केसरिया जी का जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है। उस स्थान को आदिवासी अपनी आस्था का केन्द्र मानते हैं। इन सभी स्थलों के निर्माण के लिए, उन सभी के विकास के लिए, जो भारत सरकार की योजना है, प्रसाद और दर्शन योजना से जोड़कर उस क्षेत्र का विकास करने के कार्य में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सर, 3 सितम्बर को अपर सुबनसिरि जिले से पांच अरुणाचल के लोगों को चीन की पीएलए ने अरुणाचल की टेरीटरी के 50-60 किलोमीटर के अंदर आकर से अबडक्ट किया। 12 तारीख को उनको रिलीज़ किया गया।

लेकिन मैं इस सदन, हमारी सरकार और मीडिया हाउसेज़ को यह बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना-तिब्बत की जो सीमा है, वहां पर कोई एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) नहीं है, वहां मैकमोहन लाइन है। सन् 1914 में ब्रिटिश इंडिया के हैनरी मैकमोहन और His

Holiness, the Dalai Lama Ji के रिप्रेजेन्टेटिव Paljor Dorje ने शिमला समझौता किया था। उस समझौते में चाइना नहीं था। सन् 1950 में चाइना आया और उसने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया।...(व्यवधान) महोदय, बस एक मिनट और दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब कनक्लूड कीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री तापिर गाव: महोदय, ग्लोबल टाइम्स में अरुणाचल प्रदेश को इंडियन टेरिटोरी नहीं माना गया है। या तो तापिर गाव इस सदन में झूठ बोल रहा है, या हमारे हिन्दुस्तान की इंटैलीजेन्स एजेन्सीज़ गलत रिपोर्ट दे रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाए। सन् 1962 से लेकर आज तक चाइना पीएलए ने हिन्दुस्तान टेरिटोरी की कई वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदिम्बका पाल (डुमिरयागंज): अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुज्ञा दी है। जब आज पूरी दुनिया में तनाव और हिंसा बढ़ रही है, तो गौतम बुद्ध आज और प्रासंगिक हो रहे हैं। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे वह आसियान हो, चाहे वह दावोस हो, चाहे वह यूनाइटेड नेशन्स हो, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि दुनिया ने तो युद्ध दिया होगा, लेकिन भारत ने हमेशा गौतम बुद्ध दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि शांति, अहिंसा, करुणा और ममता का संदेश पूरी दुनिया में जाता है।

यह सौभाग्य है कि गौतम बुद्ध जी से जुड़े हुए चार महत्वपूर्ण स्थान, वाराणसी का सारनाथ, कुशीनगर, जहां उनकी निर्वाण स्थली है, उनकी जन्मस्थली किपलवस्तु जो सिद्धार्थनगर में है और श्रावस्ती जहां उन्होंने अपने सबसे ज्यादा बसंत बिताए हैं। इन चारों महत्वपूर्ण स्थानों पर गौतम बुद्ध को मानने वाले दुनियाभर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आज वक्त का यह तकाजा है कि सारनाथ, कुशीनगर, किपलवस्तु और श्रावस्ती को फोर लेन के नेशनल हाइवे से जोड़ा जाए, तािक दुनियाभर से आने वाले पर्यटकों को सहूिलयत मिल सके । किपलवस्तु जो उनकी जन्मस्थली है, जहां भारत का एक संग्रहालय है, गौतम बुद्ध का अस्थि कलश जो यहां के एक संग्रहालय में रखा हुआ है, क्योंकि पर्यटक वहां पर आते हैं । वे उसका दर्शन कर सकें, तो उस जगह पर उसको स्थापित किया जाए । मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री मलूक नागर और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जगदिम्बका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर की पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार थी। उस समय कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना का एक डीपीआर बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था। उसमें कुछ संशोधन के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को वापस भेज दिया था। आज डेढ़ साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसको पूर्ण करके वापस नहीं भेजा है। जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने 7,681 करोड़ रुपये राजस्थान को भेजे हैं। उसकी सफलता तभी संभव है, जब इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना का काम पूरा हो पाएगा।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार से कहा जाए, उसके ऊपर बार-बार दबाव बनाए जाए कि वह उस डीपीआर को कंप्लीट करके वापस भेजे, तािक वहां पर पानी की समस्या का समाधान हो सके। आप जानते हैं कि कोटा के बाद सीकर शिक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। चाहे महिला शिक्षा हो, स्कूल एजूकेशन हो, या फिर कोचिंग हो। वहां पानी की बहुत आवश्यकता है। मैं यह आशा करूंगा कि भारत सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना और यमुना प्रोजेक्ट है, उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के सुपौल जिले के अंतर्गत छातापुर प्रखंड में आजादी से 72 वर्ष तक सुरसर नदी, गेरा नदी तथा बिलनिया नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है। फलस्वरूप प्रति वर्ष उन नदियों में डूब कर लोग मर जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत, नन्हीं टोला की सुरसर नदी के शिवनीघाट पर, लालगंज पंचायत के गेरानदी के परियाही घाट पर तथा तीसरा ग्वालपाड़ा पंचायत के बिलनिया नदी में रतनसार गांव के वार्ड नंबर 11 में अतिशीघ्र पुल का निर्माण कर यातायात की सुविधा बहाल कर लोगों के जान-माल की रक्षा करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, around 25,000 families in four districts of Kerala – Thrissur, Calicut, Malappuram and Ernakulam – are disappointed because of land acquisition for road widening project on National Highway-66 in coastal area of Kerala. In my Thrissur district, the project is between Punnayurkulam, Kappitrikkad, and Kodungallur, Kottappuram, with 43 km distance. It became a huge controversy in the fear that these 25,000 families would lose everything they have because the Government is not ready to ensure the protection mentioned in the 2013 Act to the affected people. This Land Acquisition Act provides the protection of fair compensation, rehabilitation, and resettlement as people's right.

I strongly demand from the Government that it should ensure a fair compensation and rehabilitation to the people during land acquisition under Land Acquisition Act, 2013. Any procedures of land acquisition should not be done until the rehabilitation facilities are ready for affected people.

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): सर, हम आपको बधाई देना चाहते हैं, हम तो सोचते हैं कि आप ग्रेट आदमी है। सर, हम थोड़ा बहुत फुटबॉल के लिए बोलेंगे। I am a football player. I am Indian captain, arjun awardee first footballer M.P. आपके माध्यम से मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब को बोलना चाहते हैं कि बंगाल में अभी बहुत सेंटिमेंट चल रहा है। वहां पर तीन फुटबॉल टीम – मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हैं। इनके एक करोड़ सपोर्टर दुनिया में हैं। सन् 1922 में जब अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने ऐसािकया था कि 01 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किसी मैदान में लाइट मत जलाओ और पूरा ट्रेन खोल देते थे। यह बर्बाद था। सन् 1947 में हम लोग सादीनाता से

मिले। उसके बाद भी अभी भी यही चल रहा है। इसके लिए बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम बंगाल में हो रही है। Everybody is very much disappointed. आप जानते हैं कि बंगाल और केरल में फुटबॉल बहुत चलता है। इन तीनों टीमों को अभी तक स्लेव समझा जाता है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि प्लीज़ उधर के जीओसी को ऑर्डर करें कि इन तीनों की यह चीज़ उठा लें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रसून बनर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री एवं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिंहत उत्तराखंड प्रदेश के पवर्तीय जिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल के अंतर्गत पूरे क्षेत्र में बीएसएनएल चैनल की इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से असंतोषजनक एवं खराब होने से जनता बहुत परेशान है। क्षेत्रीय जनता बहुत दूर-दराज गांवों से बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं विकास खंडों में अपने कार्यों को करने के लिए आती है, लेकिन उनको यह कह कर लौटा दिया जाता है कि नेट नहीं चल रहा है।

विगत कई महीनों से जनपद चमौली के थराली, देवाल, नारायणबगड़ क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस में काम बंद पड़ा है। इसी प्रकार जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र रिखणीखाल, धुमाकोट, जयहरीखाल, बीरोंखाल, पोखड़ा, एकेश्वर, थलीसेंण, खिर्सू सिहत पूरे क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था असंतोषजनक एवं खराब है। जनपद चमोली के दूरदराज क्षेत्रों में थराली के अंतर्गत कफोली, रुइसेण, घेस, कनोल, सुनल, गोरीकांडा, भैराणी आदि स्थानों पर अभी तक दूरसंचार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं ग्रामग्रेस, धारकोटवाला, देवाल, सतगाव और सोलाढूंगी, पटलियार आदि स्थानों में जियो कम्पनी द्वारा टावर बने हैं, लेकिन अभी प्रारम्भ नहीं किए हैं। वहीं कर्णप्रयाग विधान सभा के अंतर्गत चमोला, पखोली, सुमलखाल, सिलवाणा, मंगला, तेजाणी, पिंडवाली, पुनगाव, बिसुणा आदि स्थानों

पर अभी तक दूरसंचार की कोई व्यवस्था नहीं है और वहीं बद्रीनाथ विधान सभा के अंतर्गत सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि बॉर्डर के क्षेत्र हैं, नीति घाटी के 12 गाँवों तथा कलोट एवं पल्ला, भिमाणा, सलोन, पटेला, गोणा एवं पाणी-ईसाणी में दूरसंचार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज संचार क्रांति के युग में भी ये लोग पिछड़े हुए हैं। मेरा आग्रह है कि इन क्षेत्रों में दूरसंचार की व्यवस्था को सुदृढ करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): परम आदरणीय स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी ऑनरेबल मैम्बर्स के लिए कोरोना से बचने के लिए आपने जो सुविधा सदन के अंदर की है, उसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

सर, मैं बहुत ही दु:ख के साथ अंडमान और निकोबार की जनता की एक ऐसी प्रॉब्लम आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूँ, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आज हमारे पूरे देश के साथ-साथ अंडमान निकोबार आईलैंड कोरोना महामारी से पीड़ित है। अंडमान निकोबार की जनता कोरोना के साथ-साथ और भी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है और वह समस्या पानी की समस्या है। यह बहुत ही दु:ख की बात है कि हर साल तीन हजार मिलीमीटर बारिश होते हुए भी वहाँ पानी की समस्या है।

सर, हम सब को पता है कि अंडमान निकोबार सिस्मिक जोन-5 में आता है और वहां पर सुनामी, अर्थक्वेक और साइक्लोन हमेशा आता रहता है। वहां पर एक ही डैम है, भगवान न करे अगर वह डैम कभी टूट गया, तो वहां के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। जब मार्च से अगस्त तक लॉकडाउन था, तब कोरोना के साथ-साथ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को सात दिन में एक बार पानी मिलता था और वह भी पन्द्रह मिनट के लिए। लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाते थे।

सर, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्लड बे वाटर प्रोजेक्ट, जिसका सर्वे आज से करीब 22 साल पहले 1998 में 287 लाख रुपये से हुआ था, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब दो हजार करोड़ रुपये का फंड सैंक्शन किया जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार एडिमिनिस्ट्रेशन को भारत सरकार से हर साल करीब 5000 करोड़ रुपये का फंड मिलता है, जो बाकी कामों खर्च हो जाता है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए

20.09.2020

2000 करोड़ रुपये दिए जाएं, जिससे तीन लाख लोगों की 10 साल तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब को पता है कि अंडमान निकोबार एक टूरिज्म की जगह है और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार पिन्टू – उपस्थित नहीं।

श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में साउथ दिल्ली के अंदर फतेहपुर बेरी एक गाँव है। वे इस बात के लिए बहुत आभारी रहेंगे, वहां पर पानी डम्प होता है, पानी की निकासी नहीं है। मैंने 27 दिसम्बर, 2018 को नितिन गडकरी से निवेदन किया था। उन्होंने 'नमामि गंगे' से केजरीवाल की विज्ञान भवन में कान्फ्रेंस कराई, मीटिंग हुई। वहां 65 करोड़ रुपये भी दे दिया कि वहां 9 एसटीपी लगने चाहिए, जिससे सीवरेज निकलने की व्यवस्था हो जाए। वहां गाँवों का सीवर का पानी निकलता नहीं है और वहां आठ गाँव हैं। वहां 75 एकड़ कृषि जमीन है, जिसमें गंदा पानी इकट्ठा होता है। गांव के अंदर 35 लोग कैंसर के पेशेंट हो गए, चर्म रोग से भी लोग पीड़ित हैं।

सर, आपके माध्यम से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, विकास मंत्री या जल मंत्री, जो 65 करोड़ रुपये वर्ष 2018 में दिया था, उस पैसे से वहां पर, इसी प्रकार से नेब सराय में, जसोला में तालाब है, अगर उनकी भी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वहां पर फिल्टर वाटर की सप्लाई नहीं है। ग्राउंड का पानी लोग पीते हैं। वहाँ जहरीला पानी ऊपर आता है, जिससे कैंसर की बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। वहाँ पर बार-बार इंस्पेक्शन करने के बाद भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

महोदय, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से उस पैसे को लगवाने की व्यवस्था की जाए। केजरीवाल की मौजूदगी में मीटिंग होने के बाद भी, पॉलिटिकल राइवलरी के कारण वहाँ काम नहीं हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मलूक नागर और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम जी।

माननीय सदस्य तमिल भाषा में बोलना चाहते हैं।

*SHRI KARTI P.CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Hon. Speaker Sir, We have high regards for all the soldiers working in Indian Army. It is our prime duty to protect their families. But, in my Sivaganga constituency two months ago, the house of an Army Soldier named Stephen was burgled; his mother and wife were killed; and their money and jewels were taken away. One week after this incident, there was another incident of burglary in the house of an Ex-soldier of the Air Force in my constituency. The Tamil Nadu State police so far have not arrested anyone in connection with these burglaries. I urge upon the Hon. Minister for Defence, through you Sir, that a report on these incidents should be sought immediately from the State Government of Tamil Nadu and the culprits should be brought to book and arrested. As we have high regards for our Armed Soldiers, we are duty-bound to protect their families as well. Thank you.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, आज मैं सदन को अपने संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर एवं एनसीआर के 1,800 ईंट भट्टा स्वामियों की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ।

महोदय, एनजीटी के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजट नोटिफिकेशन कर ईंट के भट्टों को जिग जैग तकनीक में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। उन आदेशों का पालन करते हुए सभी ईंट भट्टा स्वामियों ने 40-50 लाख रुपये खर्चा कर अपने भट्टों को जिग जैग कर जीआरएपी यंत्र का उपयोग करके शुरू किया।

एनजीटी द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को एनसीआर के लगभग 1,800 ईंट भट्टों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके कारण एनसीआर के सभी ईंट भट्टा स्वामियों को बड़ा झटका लगा है। 40 से 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद, एनजीटी एवं सीपीसीबी के नियमों का पालन करने के बावजूद भट्टे बंद करने के आदेश से सभी भट्टा व्यापारियों में बड़ा रोष है।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम प्राधिकरण के चेयरमैन भट्टा स्वामियों को गलत नोटिस भेजकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। भट्टे बंद होने से एनसीआर का विकास भी प्रभावित हो रहा है। अगर ईंट नहीं बनेंगी तो माननीय प्रधान मंत्री जी का वर्ष 2022 तक हर गरीब को अपना घर देने का सपना कैसे साकार होगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि 1,800 ईंट भट्टा लघु उद्योगों को बर्बाद होने से बचाने के लिए एनजीटी के 15 नवम्बर, 2019 के आदेश को वापस कराने के निर्देश देने की कृपा करें, क्योंकि कोरोना महामारी में देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार गवाएं हैं। इन भट्टों के चालू होने से हजारों परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र अग्रवाल और मलूक नागर को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Sir, I would like to speak on the subject – 'Funds for building long-term disaster-resilient infrastructure in Odisha'. We all know Odisha is the most disaster and cyclone prone State in the country. In the last 100 years, over 260 cyclonic disturbances had their landfall along the Odisha coast. The major cyclones that have hit the State in the last two decades are the 1999 super cyclone, Phailin, Hudhud, Titli, and also Fani. Besides, it is also prone to floods and droughts.

Odisha, under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik Ji, has been hailed for its disaster management strategies and plans worldwide, including from the UN and the World Bank. Odisha's efforts at a well-targeted evacuation plan, which had involved moving more than one million people into storm shelters during Cyclone Fani have been applauded worldwide. Odisha has performed well in various parameters including risk minimisation, response, rehabilitation, and recovery but long-term infrastructure which is disaster-resilient is still a grey area considering the recurring nature of cyclones.

We request the hon. Minister of Home Affairs and hon. Minister of Finance to provide Odisha with a special fund for building long-term disaster-resilient infrastructure to minimize the need of the evacuation and also save on the systematic investments that are made when household assets are lost during a disaster. Our hon. Chief Minister of Odisha has also sought a long-term package of around Rs. 20,000 crore from the Centre to build disaster-resilient infrastructure in coastal embankment area.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity. The clock is going to strike twelve at midnight in another 20 minutes and you are still giving us an opportunity. I would like to draw the attention of the hon. Minister of Social Justice and Empowerment regarding the posts of Chairman and members of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which have remained vacant for more than four months. It is an important organization and a constitutional institution and the Ministry should know when these posts are getting vacant. Despite knowing all these facts, these posts are kept vacant. I urge you to get the attention of the Minister to see that these vacancies are filled. The regional offices of this organization are very ineffective because they are manned by middle-level and junior-level officers. I request the hon. Minister to get these positions filled by IAS cadre. These offices are very poorly staffed and provided with inadequate facilities. I request that these offices may be provided with adequate facilities to protect the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर, श्री गिरीश चन्द्र एवं श्री बी. मणिक्कम टैगोर को डॉ. के. जयकुमार के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, रात के बारह बज रहे हैं और सदन चल रहा है। कोरोना की इस विषम परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी सुविधाएं देश को मिली हैं। हमारे इन्दौर को भी केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, इसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, इन्दौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और एक मेडिकल हब भी है। कोरोना की इस महामारी के बीच मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन्दौर के आस-पास के क्षेत्रों के, जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ आदिवासी क्षेत्र, खंडवा, खरगौन, हरदा के लगभग डेढ़ करोड़ की जनसंख्या का भार इन्दौर के अस्पतालों पर पड़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दो मांग करना चाहता हूं। एक तो वहां आई.सी.यू. बेड्स और वेंटिलेटर्स की काफी आवश्यकता है। इन्दौर में तुरन्त 500 आई.सी.यू. बेड्स और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, यह मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि इन्दौर में एक एम्स अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एम.वाई. अस्पताल को एम्स की सुविधा मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शंकर लालवानी के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार और रोड-हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड्स, जिसमें ब्यास से डेरा बाबा नानक शाह, जहां पर गुरु नानक साहब गुरुद्वारा जाने का कॉरिडोर बना है, वह है और दूसरी रोड अमृतसर से डांडा वाया मेहता एवं श्री हरगोबिन्दपुर है और तीसरी रोड भटिण्डा से डबवाली है। ये पर्यटन, धर्म, व्यापार और सेना से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इन्हें फोर-लेन करने की मंजूरी दी गई है।

सर, वहां इसमें एक प्रॉब्लम यह आ रही है कि वहां लोगों की बहुत थोड़ी-थोड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं और कई ने उन पर अपने घर और दुकानें बनाई हुई हैं। जो ऑफिसर्स उसकी अवार्ड दे रहे हैं, उसके पैसे मार्केट रेट से बहुत ही कम हैं।

सर, उसका दो कारण हैं, एक तो वे लोगों को तंग करना चाहते हैं और दूसरा, उनको कोई लालच है। मैं आपको एक एग्जाम्प्ल दे रहा हूँ कि वहाँ एक हॉस्पिटल बना है, उसको उन्होंने रख लिया और उसके साथ जो पैलेस बना है, उसे छोड़ दिया। ऐसे भी डभवाली जो भटिंडा रोड है, उसके ऊपर पेट्रोल पंप बना है, रेस्टोरेन्ट बना है, उसे आगे रख लिया और वहाँ एक स्टील प्लांट है, उसे छोड़ दिया।

सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि हमें एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स लोगों को परेशान करते हैं, वहाँ के लोग अपना घर-बार तथा दुकान छोड़कर माइग्रेन्ट हो जाते हैं। आज उनको तंग किया जा रहा है। ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। यदि किसी गरीब आदमी की जमीन का मूल्य मार्केट से कम आँका जाता है तो उस ऑफिसर को बच के नहीं जाने दिया जाए। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Khagen Murmu – Not present.

DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): Sir, I thank you for allowing me to speak during 'Zero Hour'.

Sir, I had asked Unstarred Question No. 1299 from the Minister of Tribal Affairs regarding status of inclusion of Gangamath and its synonymous caste which is also known as Koli in the ST list. I have received the reply but it is partially satisfactory. The reply is that the matter regarding inclusion of Koli *samaj* in the ST list is under consideration. It is a long pending request. I would request that they should be included immediately. This community is educationally, socially, and economically very backward.

Recently, a community called Talwar community has been included in the list of ST. In my constituency, Gulbarga, Karnataka, this certificate is not being given, but in other parts of Karnataka, they are giving them certificate. So, there is a little bit confusion. I would request you to give direction to respective Departments for clearing the confusion and issue the certificates.

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. In order to review the origin and development of Indian Culture, a 16-member Committee has been constituted. This was stated by the Hon. Minister for Culture. This Committee is not multidimensional in character. There is no representation from persons belonging to South India, North Eastern part of our country, minorities, women and Dalit in this Committee. Hindu high caste people have found their representation. The Scholars from the recognized South Indian languages particularly from Tamil, which is declared as a classical language by the Union Government, do not have any representation in this Committee. But a leader of a particular caste finds a place in this Committee. Is there not any part of India found beneath the Vindhya Range of mountains? Is there not any civilization other than Vedic civilization? Is there not any other ancient language other than Sanskrit? Is this Committee formed to neglect the findings of the researches of veterans like John Marshal, Sumit Kumar Chatterjee, Iravadham Mahadevan, Tony Joseph, R. Balakrishnan and to declare Puranas as History of this country? You cannot see the roots deep under the soil by flying on an airplane. Similarly the Culture of our country cannot be rewritten by those connected to Castes and Communities. I therefore urge upon the Government that this Committee should be scrapped.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्री एस. वेंकटेशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, every time when we talk about our nation's security, protection or any big threat to our nation, the entire House and the entire nation speaks in one voice *i.e.*, Hind ki Sena or the Indian Army.

Sir, the Government's 2019 manifesto emphasized on re-settlement of our Armed Forces which will focus on skill development and transition to civil jobs post-retirement. The jawans of Armed Forces often retire early when they are in the prime of their lives. In reality, very little work has been done by the Central Government for their welfare in terms of re-settlement.

The Government also promised to appoint a Veteran Commission to address the grievances of our veterans but the National Commission for Ex-Servicemen Bill, 2015, is still pending and no action has been taken since then.

The Government should also increase allocation of funds in the Union Budget for skill development initiatives in the Indian Armed Forces. There are a few institutions which seek to provide management courses to a small portion of veterans, however it is restricted only to the higher rank officers. The welfare schemes for lower rank officers in the Armed Forces are restricted to poor level jobs like taking care of milk booths or Saffola outlets which provide no financial

stability. The implementation and regulation of the already existing welfare schemes is poorly managed and regulated. I would like to request the Government to form a National level data base which records the number of retired army personnel who have successfully re-settled to civil jobs after retirement. I would like to urge the Government to look into this issue of the resettlement of Armed Forces and to form a Central-level Authority for the veterans to look after it.

Thank you.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तोड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मक्का खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है । खरीफ की इस महत्पूर्ण फसल की राजस्थान में बहुत बंपर क्रॉप पैदा हुई है । समस्या यह है कि भारत सरकार ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर रखा है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एमएसपी के कारण गेहूं खरीदा और अन्य फसलें खरीदीं, लेकिन इसकी एमएसपी पर खरीद नहीं होने के कारण किसान को आधे से भी कम दाम में उसको बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है । कोरोना के कारण किसान संकट में है । राजस्थान की सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है, वीसीआर भर रही है, उससे किसान मरा सा जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, क्योंकि आप पर हमें विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार के पास बात पहुंचेगी। राजस्थान के किसान एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि खून पसीने से वे अपनी फसल को पैदा करते हैं। उसको खाद और बीज का पैसा भी नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे में आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मक्का के किसानों की एमएसपी के माध्यम से खरीद शुरू हो, ताकि किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिल सके। यही मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Hon. Speaker, Sir, the State of Assam is a land of rivers of varied sizes, including the mighty Brahmaputra. Apart from flood, erosion is the biggest danger as it keeps devouring the land every year. A lot of livestock, houses, and farmland are lost to river erosion as an annual ritual. In the process, according to figures of the Department of Water Resources,

Government of Assam, around 4.27 lakh hectares which is approximately 7.4 per cent of the State's land area has got eroded in the last 70 years.

The problem in my Parliamentary constituency is further compounded by the tributaries of Brahmaputra, namely, Beki, Manas and Aye rivers, in lower Assam. A vast area faces severe flood and erosion every year. Erosion of small river island (*char*) lead to migration of people every year. This migration of *char* area people has increased the workload of the Foreigners Tribunal and State Home Department.

Sir, therefore, I would urge upon the Minister of Jal Shakti to pursue the matter on a war footing; otherwise, much more of land and property will be lost because of flood and erosion in the area.

Thank you.

डॉ. अरिवन्द कुमार शर्मा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से प्रार्थना है कि इसका फीजिबिलिटी सर्वे लास्ट ईयर हुआ और फीजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट अभी कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में हमें मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता लगी। इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट में आया, जो डीएमआरसी ने वायबिलिटी रिपोर्ट दी है, कि यह प्रोजेक्ट इनवायबल है। ड्यूरिंग कोविड टाइम में, लॉकडाउन के समय में यह क्या ट्रांसपायर हुआ, किस तरह से इसका सर्वे किया गया?

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसमें इंटरिफयर करें और दुबारा से फिजिबिलिटी सर्वे कराया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, हजारों की संख्या में रोहतक और साम्पला से डेली पैसेजर्स आते हैं, महादेवगढ़ से साम्पला और साम्पला से रोहतक आते है, आप इस पर ध्यान दें और मिनिस्टर ऑफ अरबन डेवलपमेंट को इन्स्ट्रक्शन दें कि दुबारा से फिजिबिलिटी सर्वे कराया जाए।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मैंने कोरोना से संबंधित मुद्दे को पार्लियामेंट में 12 मार्च को उठाया था। अगर सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया होता तो जो मजदूरों की हालत हुई, वह न हुई होती और वे समय से अपने घर भेज दिए जाते। जब लॉकडाउन खुला तो वापस भी आ जाते, इन्फ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट चालू हालत में रहते और देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती। किसानों की तरफ भी अगर ध्यान दे दिया जाता तो जो फसल बर्बाद हुई, दूध बर्बाद हुआ, वह भी न हुआ होता। विदेशों से जो लोग आते थे उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता तो निजामुद्दीन की घटना भी नहीं होती और कोरोना नहीं फैलता। खैर, जो हो गया सो हो गया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाए, हमने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। बहन कुमारी मायावती जी ने उसका सपोर्ट किया। अभी पूरे वर्ल्ड में दुबारा से यूरोप के इटली से शुरूआत हो गई है, सरकार जागे ताकि दुबारा से देश की हालत ऐसी न हो जाए और एडवांस में जाकर कार्रवाई करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरिश चन्द्र को श्री मलूक नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से बाल्मीकीनगर के बैराज से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते गंडक नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से गंडक नदी का रिंग बांध तथा सारण तटबंध कई जगहों पर टूट गया है, जिससे हमारे क्षेत्र के छह प्रखंड के दो सौ गांवों की दो लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मेरे संसदीय क्षेत्र में गंडक नदी अस्सी किलोमीटर में बहती है जिसमें आठ डेंजर पाइंट्स हैं।

यदि बांध में बोल्डर्स लगा दिए जाएं और किनारों को सीमेंटेड कर दिया जाए तो कटाव को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि एक केन्द्रीय टीम भेज कर इसका स्थायी समाधान करने की कृपा करें, क्योंकि यह समस्या नेपाल से भी जुड़ी हुई है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं जो ईमानदारी से राजनीति करने के पर्याय थे। हम लोग उनको आदर्श मानकर चुनावी राजनीति में आए, दुर्भाग्य से वे आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, आज उनकी त्रयोद्वशी भी है। उनका नाम जमुना प्रसाद निगम था, लेकिन लोग उनको बोस जी के नाम से जानते थे और उनको 'बुंदेलखंड का गांधी' कहा जाता था। वह उत्तर प्रदेश सरकार में तीन-चार बार मंत्री रहे, बड़े सोशलिस्ट लीडर थे और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे।

सारे जीवन पॉवर में रहने के बाद भी वह किराये के घर में रहें, उनकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर रही लेकिन संतुष्टि भाव में रहे। चन्द्रशेखर जी के करीबी थे, एक बार उनको राज्य सभा लाने

की बात की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नौजवान पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ठीक हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है, वह कहा करते थे कि जनता के प्रति नेताओं की जवाबदेही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी जवाबदेही है। जब विधायिका में जनप्रतिनिधि लोग जनता की अदालत में जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते हैं तो पांच साल बाद उनको सजा मिल जाती है। वह न्यायपालिका के बारे में भी कहते थे कि जज किसी कारण से गलत काम करते हैं तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के तहत पार्लियामेंट को अधिकार है कि इम्पीचमेंट लेकर आ सकते हैं। मैं बहुत गहराई में नहीं जाउंगा, रात के बारह बजने जा रहे हैं और आप समय नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे एक मिनट का अतिरिक्त समय मांगूगा, आपकी कृपा होगी। मैं विस्तार में नहीं जाउंगा, वह बोलते थे, कार्यपालिका के बारे में वह कहते थे कि आर्टिकल 310 प्रसादपर्यन्तता के आधार पर जितने भी हमारे विरष्ठ अधिकारी हैं, जिनका चयन यूपीएससी के आधार पर होता है। अभी वर्तमान में मेरे क्षेत्र के एक एसएसपी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए और इससे बड़ी बदनामी हुई। अभी तक हमारे जनपद में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

जब मैं एक ईमानदार नेता का नाम लेकर अपनी बात शुरू कर रहा हूं तो मेरा भारत सरकार से यह निवेदन है कि एक यूपीएससी रिच्यू बोर्ड का गठन किया जाए। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं, वे तरक्की पाएं, जो गड़बड़ काम करते हैं, वे पिनश किए जाएं। जो अच्छे अधिकारी हैं, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी रिच्यू बोर्ड करे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बाहर निकालने का भी काम किया जाए। मैं समझता हूं कि यह श्री जमुना प्रसाद बोस जी के लिए सच्ची श्रद्धांजिल होगी। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि उनको लोग बोस जी क्यों कहते थे। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, वे विद्यालय में पढ़ते थे। वे बोस जी की चर्चा किया करते थे। लोगों ने उनका उपनाम बोस रख दिया और उनको बोस जी, बोस जी कहते रहे तो उन्होंने संकल्प

लिया कि जीवन पर्यंत खादी धारण करूंगा। जब इतने महान व्यक्ति के नाम से मेरा उपनाम रखा गया है तो मैं जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और ईमानदारी से काम करके अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पुकार दिल्ली के गरीब नागरिकों की भूख से जुड़ी है। क्योंकि, राशन वितरण की बदहाल व्यवस्था से दिल्ली में त्राहि-त्राहि मची हुई है। यों कहिए कि प्रधान मंत्री जी ने अपनी दिरयादिली से दिल्ली या देश को अनाज की जो खुशहाली दी थी, उसको दिल्ली सरकार ने गरीबों की थाली दिल्ली में खाली कर दी है। जहां-जहां हम लोग सुनवाई में जा रहे हैं, वहां एक ही दर्द हम लोगों के पास आता है। आपको याद हो, जब कोरोना के कहर से लॉकडाउन में देश परेशान था और मजदूरों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। उनके दर्द को बांटा, परन्तु दिल्ली सरकार ने ईमानदारी से जरूरतमंदों को राशन नहीं पहुंचाया, जिसके कारण मजदूरों का दर्दनाक पलायन इस देश ने देखा।

अध्यक्ष महोदय, आज भी दिल्ली में गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने न तो उनके राशन कार्ड बनवाए हैं और न ही ऐसे लोगों को पहचान कर सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उनको मुफ्त राशन दिया जा सके। मेरी मांग है कि दिल्ली के लाखों गरीबों की समस्या के निदान के लिए हस्तक्षेप कर वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना की दिल्ली में शुरुआत की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House towards the need to issue a commemorative postage stamp for Shri Mooloor S. Padmanabha Panicker. He was born in 1869 in Kerala and was a great genius whose influence brought fundamental changes in many fields. He was a Member of Sree Moolam Popular Assembly, the legislative body of erstwhile Travancore during the period from 1914 to 1928.

He was a great scholar, poet and social reformer. He fought against social injustices and worked towards upliftment of downtrodden classes of the society. He was the first Chief Editor of Kerala Kamudi, a daily started in 1911 to fight against social injustices and to strengthen the freedom movement. A proposal to issue a commemorative postage stamp has already been submitted to the Department of Posts. A postage stamp in his name would be an honour for such an eminent personality.

I request the Government to consider this proposal favourably and give direction to the concerned for necessary action.

20.09.2020 1107

*DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Thank you, Speaker Sir, and greetings to you.

The House is sitting so late tonight and I think that for the first time in the history

of 70 years, the Parliament is sitting on a Sunday. Congratulations to you sir for

this. My constituency Silchar is one of the most backward regions of Southern

Assam. There are more than 50,000 beneficiaries of CGHS and ECHS in that

region. Government of India had decided to open CGHS units in Guwahati,

Dibrugarh and Silchar. The units have already opened in Guwahati and

Dibrugarh. Six months ago, I wrote a letter to Hon'ble Health Minister Dr.

Harshavardhan requesting him to expedite the work of opening up of CGHS unit

in Silchar. He has replied to that letter assuring me of making it functional soon. I

believe that during this Corona pandemic, if we are unable to extend the facility to

the poor pensioners and many other needy people, we shall be failing in our

duties in some way or the other. Thank you.

24.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण. अगर सदन की सहमति हो तो क्या सदन का समय 12

बजकर 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है?

अनेक माननीय सदस्य : जी. हाँ।

^{*} English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री कृष्णपालिसंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गुना की ओर दिलाना चाहता हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र का अशोकनगर जिला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । यहां पर मात्र एक ही जिला अस्पताल है । यहां पर मरीजों की संख्या बहुत अधिक रहती है । अशोकनगर जिले में लगभग 200 से 250 किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी सुपर स्पेशिलस्ट हॉस्पिटल नहीं है । यहां के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है । कोरोना महामारी के दौरान कई मरीजों को बड़े शहरों में शिफ्ट करना पड़ा था । यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई मरीज बड़े शहरों के अस्पताल पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही स्वर्गवासी हो गए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अशोकनगर जिला मुख्यालय व गुना जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमिसंह नगर): मान्यवर, आपने मुझे अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कई मार्गों पर हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रारम्भ करवाई गई थीं, लेकिन वे बीच में ही रुक गई हैं और जो कुछ चल रही थीं, वे भी रुक गई हैं तथा कुछ प्रारम्भ ही नहीं हो पाई हैं, जबिक केन्द्र सरकार ने पूर्णत: स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

मान्यवर, उत्तराखण्ड की नियति में आपदाएं आना निश्चित हैं। वहां पर कभी बादल फट जाते हैं, कभी पहाड़ खिसक जाते हैं तो कभी निदयां उफान पर होती हैं। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वहां पर हेली-सर्विस चले। सभी हेलीपेड और एयपोर्ट्स बनकर तैयार हैं। केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। डीजीसीए हवाई सेवाएं क्यों प्रारम्भ नहीं कर रहा है, यह बहुत कष्ट की बात है।

मान्यवर, देहरादून-गौचर-देहरादून, देहरादून-चिन्यालीसौड़-देहरादून, हल्द्वानी-हरिद्वार-देहरादून-हल्द्वानी, हल्द्वानी-धारचूला-हल्द्वानी, पंतनगर-नैनीताल-पंतनगर, पंतनगर-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़, पंतनगर से पिथौरागढ़ और देहरादून से पिथौरागढ़ तथा हिंडन से पिथौरागढ़, ये सभी सर्विसेज स्वीकृत पड़ी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से एविएशन मिनिस्ट्री से निवेदन है कि तुरन्त इन सेवाओं को जो भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं, उनको प्रारम्भ करने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को एडवोकेट अजय भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े-बड़े वायदे कर भारी बहुमत से कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। परन्तु हमेशा की तरह सरकार ने वादा खिलाफी की और इसका नतीजा यह हो रहा है कि राज्य के युवाओं में, बेरोजगारों में, मजदूरों में, महिलाओं में, शासकीय कर्मचारियों में और पुलिसकर्मियों में घोर निराशा घर कर गई है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 233 किसानों ने, 329 बेरोजगारों ने 1679 दैनिक मजदूरों ने और इस तरह कुल 7629 लोगों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के मामले में देश में राज्य का नौवां स्थान आया है। आज राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। लोग परेशान हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि माननीय राज्यपाल से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाकर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश प्रसारित करें।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र किटहार पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर स्थित है तथा बिहार में एक महत्वपूर्ण जिला है। किटहार में सेना का रिक्रूटमेंट सेंटर है और रेलवे डिवीजन भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किटहार भारत सरकार के आकांक्षी जिलों में से एक है। यह जिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा जिला है, इसलिए मैं, आपके माध्यम से, माननीय रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि किटहार जिले में सेना का रिक्रूटमेंट ऑफिस है, इसलिए वहां भारत सरकार की तरफ से एक सैनिक विद्यालय बनाया जाए, ताकि वहां शिक्षा का स्तर आगे बढ़ सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सबसे पहले रविकिशन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और देश को केमिकल-ड्रग माफिया से मुक्ति की ओर सदन का ध्यान खींचा है, लेकिन इससे भी अधिक गंभीर मुद्दा है – बॉलीवुड का साम्प्रदायीकरण, जो पिछले कई दशकों से कटरपंथियों की सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को ईमान का पक्का और धार्मिक रूप दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को डकैत, बलात्कारी, अपराधी और गरीबों का शोषण करने वाला दिखाया जाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सिनेमा हमारे समाज का पथ-प्रदर्शक है। आज देश भर में जो 'लव जिहाद' के मामले सामने आ रहे हैं, इसके सूत्र भी कहीं न कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई प्रकार के प्रलोभन और साजिशों से गुमराह करके, दूसरे धर्म की लड़िकयों से शादी करके, उनका धर्म परिवर्तन कराकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जब सिनेमा जगत के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी करके धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह सब ठीक है। यही 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का काम करता है। 'लव जिहाद'के षडयंत्र में लड़िकयों को बेचने में और स्लेव बनाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित

कई शहरों में लगातार इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर अपनी पहचान छिपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन न करने पर लड़िकयों की हत्या तक कर दी जाती है। पिछले दिनों प्रसिद्ध एथलेटिक लड़िकी से पहचान छिपाकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन न करने पर उसका शोषण और अत्याचार करने पर यह मामला सामने आने पर देश का ध्यान इस ओर गया था। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 'लव जिहाद' को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही, दोनों पक्षों के माता-पिता और परिजनों की अनुमित के बिना दूसरे धर्म में शादी को देश भर में अवैध और दण्डनीय घोषित किया जाए। पहचान छिपाकर भ्रमित करने पर कठोर सजा का प्रावधान हो।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रिव किशन को श्री सुब्रत पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, Sir. I would like to raise a long-pending issue of construction of permanent building for KV, Jharasangam which falls under my Zahirabad constituency in Telangana. The work has already been allotted to CPWD, Hyderabad. They have already submitted all relevant documents for the construction of KV building to the Kendriya Vidyalaya Sangathan in New Delhi. When approached KV Sangathan, they said: "They do not have funds for the construction of building. You can contact the Ministry of Education for the same."

Sir, I request the hon. Minister for Education to kindly intervene in the matter and get the needful done at the earliest as it is a long-pending demand.

Thank you.

श्री रामिशरोमिण वर्मा (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मनरेगा मजदूरों और किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में मनरेगा मजदूर व किसान अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने देश के किसानों-मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी है। उनकी माली हालत बहुत ही खराब हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की खेती में सहयोग हेतु गेहूं, धान, गन्ना आदि फसलों की खेती मनरेगा मजदूरों के माध्यम से कराया जाए।

जिससे किसानों को सहयोग मिलेगा और उनकी लागत में कमी आएगी। आज जो किसान भुखमरी की हालत में हैं, उन्हें राहत मिल सकेगी और मजदूरों को भी मनरेगा के तहत काम मिल सकेगा। उसके साथ मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलने वाली सौ दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 365 दिन रोजगार गारंटी दी जाए। इससे एक तरफ मजदूरों को काम मिलेगा और दूसरी तरफ किसानों को सहयोग मिलेगा। इससे मजदूरों और किसानों की माली हालत में सुधार होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का वनांचल, बैतूल हरदा हरसूद जनजाति बहुत है। आजादी के 70 वर्षों से शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की अपेक्षा मेरे लोक सभा के सभी भाई बहन कर रहे हैं। आपके माध्यम से केंद्रीय एचआरडी मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि भैंसदेही में केंद्रीय विद्यायल की मांग 40 वर्षों से बनी हुई है। मुलताई और हरदा में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिए गए हैं, किंतु भवन आज तक नहीं बने हैं, जिसके लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। बैतूल बाजार में पर्याप्त कृषि भूमि है। कृषि महाविद्यालय की मांग पिछले 30 वर्षों से मेरे लोक सभा क्षेत्र में लिम्बत है। इसी तरह से बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालय की मांग अनेक वर्षों से लिम्बत है। मैं

आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से एवं केंद्र सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारी शैक्षणिक समस्याओं को संज्ञान में लेकर हमारे जनजातीय क्षेत्र को अनुग्रहित करने की कृपया करें तथा समाधान की पहल करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुर्गा दास उइके द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Speaker Sir, Thank you for allowing me to raise an important issue during this odd hour after midnight, at 12.15 hours. During the year 1949 when there was discussion on Official language in the Constituent Assembly, Revered leader Quaid-E-Millath raised his strong voice upholding the importance of his mother tongue Tamil which he said only had all the distinction of being the Official language of a multi-dimensional country like India. I, on behalf of Indian Union Muslim League, a party found by him, wish to raise an important issue in this august House.

In Tamil Nadu, the people are protesting against imposition of Hindi in several ways. Expressing deep concern many educationists in Tamil Nadu have views against the New Educational Policy which they think is aimed to encourage imposition of Hindi. No language should be imposed on any one. In a diverse country like India, every language should be given its due importance. Our mother tongue Tamil should be particularly given importance as it is an ancient language with a long history of thousands of years with rich grammar and literature. Anybody can learn any language. But you cannot directly or indirectly force a person to learn a particular language. It is highly condemnable to impose or enforce a particular language on a particular set of people without their wish.

Hon. Prime Minister's speeches have high praise for the language Tamil.

But it is doubtful as his action does not reflect what he says or feels about Tamil.

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

It is seen from the fact that the funds allocated for Sanskrit is more than that is allocated for Tamil. Therefore, Tamil Nadu government should respect the sentiments of the people of Tamil Nadu in this regard and act accordingly. In Oman, in the School run by the Indian Embassy there, Medium of instruction is not in Tamil. Along with the languages like Malayalam, Sanskrit and Hindi, Tamil should also be taught in the School run by Indian Embassy in the Sultanate of Oman. Students living there are not able to learn Tamil. I therefore urge that Tamil should be taught in the School run by Indian Embassy in Sultanate of Oman benefitting several thousands of Tamil families and students living there. This would be beneficial for continuing their education if such students return to India. Thank you, Sir.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आम आदमी को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु हर घर नल-जल योजना की घोषणा की थी। उसके बाद उससे शुद्ध पेय जल को लेकर एक आशा की किरण जागी थी। मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के 14 विकास खंडो में अधिकांश ऐसे गांव हैं, जो नदी के किनारे हैं। वहां का पानी इतना खारा है कि लगाए जाने वाले हैंड पंप्स भी दो से चार महीनों में गल कर खराब हो जाते हैं और बच्चे विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस परियोजना को मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में स्वीकृति के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद पूरे देश में पहला प्रोजेक्ट मेरे द्वारा मंत्रालय को सौंपा गया एवं उसके बावजूद भी लगभग 200 करोड़ रुपये धन की उपलब्धता राज्य सरकार के पास होते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई न होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आज सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे जनपद मुख्यालय से लगे हुए गांव खजुरनी, बाबा बेलखरनाथ धाम सिहत छोटी-छोटी निदयों के किनारे बसे गांवों में खारे पानी के कारण लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है, तो ऐसे में पेय जल योजनाओं को प्रथम-आगत, प्रथम स्वागत के आधार स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Thank you, Hon'ble Speaker Sir, if you permit, I would like to speak in Odia. Sir, the matter which I want to raise here today in Zero Hr. is related to my Parliamentary Constituency Bargarh. In Bargarh, there is a district called Jharsuguda which houses one of the nation's biggest Coal mines.

The Mahanadi Coal Company engaged in coal mining here since the 1980s. Mining of coal takes place on the basis of the following laws - (1) Land Acquisition Act and (2) Coal Bearing Act.

Whenever any litigation relating to Coal Bearing Act takes place the cases are referred to Dhenkanal dist. which is 300 kilometers away. If a person has to go Dhenkanal from Jharsuguda, first he has to go 50 kms. in Sambalpur, then 150 Kms. to Angul and then travel 70 km. to reach Dhenkanal. This is long- winding and time-consuming. My question here is if coal is extracted from my district, coal-bearing Act is implemented in my district and displaced persons are people of my district, why should they go all the way to Dhenkanal to solve their cases?

Through you, I want to request the Ministry of Coal & Ministry of Law to establish a court to settle disputes involving Coal Bearing Act. District Judge of Jharsuguda and Session Judge should be notified and a Tribunal should be constituted to settle all the dispute relating to Coal Bearing Act so that people of my district will be benefited. Thank you, Sir.

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो (पुरुलिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं कुर्मी जाति समुदाय का सदस्य हूं। मेरे लोक सभा तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों झारखंड एवं ओडिशा में भी इस जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं।

मान्यवर, 6 सितम्बर, 1950 को जब आजाद भारत में अनुसूचित जनजाति की सूची दोबारा बनाई जा रही थी, तब तत्कालीन 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची से हमारी कुर्मी जाति को बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के ही बाहर कर दिया गया। मान्यवर, गौरतलब है कि सन् 1931 की तत्कालीन सरकार ने भी जो 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची थी, उसमें हमारी कुर्मी जाति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दिनांक 2 मई, 1913 को तत्कालीन सरकार की गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची में हमारी कुर्मी जाति का नाम भी उल्लेखित था। परंतु 6 सितम्बर, 1950 को जब अनुसूचित जनजातियों की सूची दोबारा तैयार की जा रही थी, तब बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के ही 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची में से हमारी कुर्मी जाति को बाहर कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि दोबारा जल्द से जल्द हमारी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): अध्यक्ष महोदय, देश के गरीब परिवारों को इलाज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझा और उक्त ऐसे परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना को लागू किया है। वर्ष 2011 की सूची के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिला, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिह्नित परिवारों के अलावा, ऐसे पात्र परिवार, जो इस योजना से वंचित रह गये हैं, ऐसे परिवारों का भी सर्वे कराकर उनको इस लाभदायक योजना में शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग तीन महीनों तक लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से लोगों के व्यवसाय और कामकाज

पूरी तरह से बंद रहे। इसके कारण किसान, गरीब, श्रमिक और मध्यमवर्गीय आय वाले अभिभावकों को आर्थिक संकट के चलते अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। अभी भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले देश के सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इस बाबत 12 सितम्बर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सरकार से अपील की है कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से पूरे देश में व्याप्त आर्थिक मंदी के कारण भीषण बेरोज़गारी और जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों की स्कूल फीस जमा करना संगीन होकर अब आन्दोलनकारी हो गया है। उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं।

इस स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी या उसकी प्रतिपूर्ति करके आर्थिक सहायता देने अर्थात् व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल की फीस माफ कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन-बड़वानी, जो मध्य प्रदेश का एक जनजातीय लोक सभा क्षेत्र है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी असुविधाएँ हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने पिछली बार बड़वानी के जिला चिकित्सालय में 200 बेड्स बढ़ाने की माँग केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की थी और तत्काल इसकी स्वीकृति दी गई थी। मैं बड़वानी जिले की लाखों जनता की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ।

पुन: मैं एक और माँग करता हूँ, जिसकी काफी कमी मेरे जनजातीय क्षेत्र में है। बड़वानी और खरगौन लोक सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की माँग लम्बे समय से चली आ रही है। मेरे क्षेत्र की ओर से दोनों जिलों के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज शीघ्रातिशीघ्र खोला जाए।

आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह मेरी माँग है। आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया।

महोदय, यह सभी जानते हैं कि संसद का काम कानून बनाने का है। आम जनता अगर उस कानून से संतुष्ट न हो तो आन्दोलन करना उसका हक़ है।

कल बिल पास हुआ और आज किसान सड़कों पर हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसद ने सीएए कानून बनाया, उसके खिलाफ देश भर में आन्दोलन हुए। जामिया और जेएनयू विश्वविद्यालयों के काफी छात्रों ने आन्दोलन किए। लेकिन बदिकस्मती इस बात की है कि दिल्ली में और देश में शांतिपूर्ण आन्दोलन करने वालों के खिलाफ यू.ए.पी.ए. यानी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों के लिए बनाए गए इस कानून का दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल भेजा गया है। जामिया विश्वविद्यालय के एल्युम्नाई एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट शैफुर्रहमान हों या दूसरे छात्र हों या प्रो. अपूर्वानन्द जैसे लोगों को दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल बुलाकर ग्रिल करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी छुड़वाया जाए और चार्जशीट का जो समय होता है, उसको जानबूझकर दिल्ली

पुलिस नहीं फाइल कर रही है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा वक्त बिना ट्रायल के उन निर्दोष लोगों को जेलों में रखा जा सके क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं यहां पर और सरकार के मंत्रीगण खासकर स्मृति ईरानी जी लगातार बैठी हुई हैं, दादा गिरीराज सिंह जी, अनुराग ठाकुर जी और बाबुल सुप्रियो जी भी हैं। मैं इन चारों के प्रति शुक्रगुज़ार हूं कि आप और पूरी सरकार ज़ीरो ऑवर में सांसदों को कितना सीरियसली लेती है, यह दिखता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे बिहार के थे, उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, यह तो विवेचना का विषय है, इस पर केस चल रहा है। 14 जून को, जिस दिन उनकी आत्महत्या हुई, मैं पहला ऐसा सांसद था, जिसने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा हूं। उसके बाद मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, डॉ. सुब्रहृमण्यम स्वामी और उस सदन की रूपा गांगुली जी – ये सारे लोग इसके साथ आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी आई।

मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रगुज़ार हूं कि फाइनली कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इंक्वायरी हो गई, लेकिन इसमें जो बड़ा मुद्दा है - खासकर अनुराग सिंह ठाकुर जी यहां मौजूद हैं – वह यह है कि जो जांच चल रही है, मान लीजिए कि ड्रग्स की बात चल रही है। ड्रग्स, फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ जो स्कूल्स, कॉलेज़ेज़ और हाई-सोसायटीज़ हैं, उनमें और पूरे देश भर में यह एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि एनडीपीएस कानून को हमें मज़बूती से लागू करना चाहिए।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, जिससे उसमें ट्रांसपेरेंसी हो पाए और दाउद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों का फिल्म इंडस्ट्री में जो पैसा फंसा हुआ रहता है, वह ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आए। एक डायरेक्टर इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी में रेगुलेटर्स हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक रेगुलेटर हो।

इस कोविड-19 के कारण आपने बहुत पेन लिया और सारे सांसदों ने भी पेन लिया। हमने जितने कानून पास किए, वे कोविड-19 के लिए पास किए। सरकार के पास पैसे की कमी है, देश के पास पैसे की कमी है। टूरिज़्म इंडस्ट्री ज्यादा लोगों को रोज़गार देती है। फिल्म इंडस्ट्री जब शूटिंग करने के लिए कहीं जाती है तो वह लोकेशन टूरिज़्म के लिए अच्छी लोकशन बन जाती है।

अत: मेरी आपके माध्यम से सरकार से दूसरी मांग है कि फिल्म इंडस्ट्री को आगे आने वाले तीन सालों के लिए विदेशों में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिन्दुस्तान में ही दूसरी लोकेशंस पर उनको शूटिंग करने के लिए कहा जाए, जिससे हमारे देश की टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़े और लोगों को उससे रोजगार मिले।

धन्यवाद, सर।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय आज की कार्यवाही पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

...(<u>व्यवधान</u>)

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Speaker Sir, the people belonging to Devendrakula Vellalar community live in large number in the southern districts of Tamil Nadu. The people of this community are called in different names particularly in seven distinct names such as Pallar. Devendrakulathaar, Kudumbar, Kaaladi, Kadaiyar, Pannadi and Vadhiriyar. Basically they belong to the farming community. There is historical proof in the stone inscriptions that they were engaged in farming following efficient water management systems. This community is in the list of Scheduled Castes in Tamil Nadu. Their only and long pending demand is that all the seven names of their community should be merged as one and called as Devendrakula Vellalar. The Tamil Nadu Government had even constituted an one-man Commission in this regard and has received its Report. Shri Hansraj Varma IAS, the one-man Commission, has submitted his report to the Tamil Nadu Government. But the State Government of Tamil Nadu is delaying this matter. I therefore urge upon the Union Minister for Social Justice and Empowerment to intervene in this matter and ensure that the Tamil Nadu government makes an announcement in this regard at the earliest. Thank you.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

महोदय, हाल ही में भारतीय रेल ने मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर की प्रमुख ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है। इनमें से दो ट्रेनें हैं, जो निम्नवत हैं – हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस और फिरोज़पुर से धनबाद जाने वाली गंगा सतुलज एक्सप्रेस। इन ट्रेनों का जिले में स्टॉपेज खत्म कर दिए जाने के बाद अम्बेडकर नगर के मज़दूर, विद्यार्थी और आम जनता भारी संकट में आ गए हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है और सबका मानना है कि यदि ये ट्रेनें पुन: अकबरपुर और मालीपुर जंक्शन पर स्टापेज नहीं लेती हैं तो यह पूर्वांचल की जनता के साथ सरासर अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आसपास के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रवासी मज़दूरों और छात्रों की सुविधाओं के लिए इन दोनों रेलगाड़ियों का रूट वाया अम्बेडकर नगर से किया जाए और अकबरपुर और मालीपुर जंक्शन पर इन दोनों ट्रेन्स को तुरंत पुन: स्टापेज दिया जाए, ताकि वहां की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रिव किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे इस देश की बहुत गम्भीर समस्या पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने कहा था – 'बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ', मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उन बेटियों में एक बल आया, एक शिक्त आई। वह शिक्त ऐसी थी कि वह निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अपनी पीड़ा बयां करने लगी। समस्त भारत के सामने, मीडिया के सामने और सोशल मीडिया के सामने बेटियों को हमारी सरकार में बल मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मंच के माध्यम से आपका ध्यान अकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश में दुर्गा माता, गौ माता देवियों की तरह ही बेटियों को पूजा जाता है। यह हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्धा आया है और समस्त देश के चैनल्स में न्यूज चल रही है। एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, महोदय मैं एक मिनट एक्स्ट्रा चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग छोटे शहरों से मुंबई जाते हैं। मुंबई शहर सपनों का बहुत बड़ा शहर है और वहां सपने पूरे होते हैं। वहां कोई घर बेचकर जाता है, कोई मोटरसाइकिल बेचकर जाता है, कोई जेवर बेचकर जाता है, कोई बेटी या बेटा बैंक से लोन लेकर जाते हैं कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। क्रिकेट और सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है और 135 करोड़ जनसंख्या का बहुत बड़ा भोजन है। वे सपने लेकर उस शहर में जाते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और दफ्तर में उनकी एंट्री होती है। वहां उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। यह सौदेबाजी क्यों होती है? यह कहने का क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यह एक कॉम्प्रमाइज का सौदा है। हमारी बेटियों के साथ यह कब तक होगा?

महादेय, एक ऐसा कानून आए, जिससे ऐसा अत्याचार न हो। किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत न करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा, ऐसा किसी को अलाऊ न हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो, क्योंकि अब मोदी जी की सरकार है। बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। यही दुख है, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा कानून आए। ...(व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपकी बेटी नहीं है, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। जहां भी कोई कहेगा कि मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) आप गौर से सुनिए, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। कहीं पर किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में, मैं केवल फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा। हमारी बिच्चयों के साथ भारत में कोई अत्याचार हो और खासकर मोदी जी की सरकार में यह कतई नहीं होगा। आप ऐसा कानून लाइए, जिससे सब लोगों में एक भय पैदा हो।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रिव किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): अध्यक्ष जी, मैं आज सभी सांसदों की ओर से और मुझे यकीन है कि सभी सांसद इस बात का समर्थन करेंगे, रविवार की रात को 12.30 बजे तक आपने और आपके सान्निध्य में लोक सभा सेक्रेटरिएट के साथ-साथ ट्रांसलेशन टीम और गैलरी में उपस्थित कैमरा टीम ने, हम सभी सांसद आपके प्रति और आपकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपने सुचारू रूप से न सिर्फ नियम 193 पर डिस्कशन किया, चार बिल पारित किए तथा साथ ही आपने जीरो ऑवर में सभी सांसदों को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी। मैं सभी सांसदों की ओर से और मंत्रि परिषद के सभी नेताओं की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही आज सोमवार दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

00.35 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Monday, September 21, 2020/Bhadrapada 30, 1942 (Saka)